हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

09 मार्च, 2017

खण्ड–1, अंक–11

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 9 मार्च, 2017

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	5
कन्याओं के अपमान के सम्बन्ध में मामला उठाना	5
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	6
कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के जनसंचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान के प्राध्यापकों/विद्यार्थियों, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य तथा हरियाणा के भूतपूर्व राजस्व मन्त्री के सुपुत्र का अभिनन्दन	9
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	9
दैनिक ट्रिब्यून के भूतपूर्व सम्पादक का अभिनन्दन	16
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	17
नियम 45(1)के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	40
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	45

बैठकों का स्थगन	50
इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्यगण को नेम करना/बैठक का स्थगन	52
हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन	56
वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ एवं वित्त मंत्री द्वारा उत्तर	56
इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्यों के नेम करने के निर्णय को रद्द करना	71
वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) एवं वित्त मंत्री द्वारा उत्तर	72
बैठक का समय बढाना	93
वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) एवं वित्त मंत्री द्वारा उत्तर	93
बैठक का समय बढाना	116
वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) एवं वित्त मंत्री द्वारा उत्तर	116
बैठक का समय बढाना	128
वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा एवं वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भ)	129
बैठक का समय बढाना	139
वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा एवं वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भ)	140
बैठक का समय बढाना	152
वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा एवं वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भ)	152
बैठक का समय बढाना	167
वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा एवं वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भ)	167
वॉक– आउट	173
वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा एवं वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भ)	174

वर्ष 2017–2018 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान 174

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 9 मार्च, 2017

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

शोक–प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी शोक प्रस्ताव रखेंगे ।

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन विधायक श्री श्रीकृष्ण हुड्डा के भतीजे श्री सुरेन्द्र पाल; तथा पूर्व विधायक श्री राम कुमार गौतम की माता श्रीमती मरियां देवी के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है । यह सदन दिवंगतों के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुख्यमंत्री जी ने अभी सदन में जो शोक प्रस्ताव रखा है उस पर विभिन्न पार्टियों के सदस्यों ने अपनी संवेदना प्रकट की है मैं भी अपने आपको उनके साथ जोड़ते हुए अपनी संवेदना प्रकट करता हूं । हमारे सभी सांसदों और विधायकों के निजी संबंधियों के दुःखद निधन पर भी मैं अपनी तरफ से शोक प्रकट करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे ताकि उन दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्राप्त हो सके । मैं इस सदन की भावनाओं को इन सभी शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा । अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि उन महान आत्माओं की शान्ति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें ।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

कन्याओं के अपमान के सम्बन्ध में मामला उठाना

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, कल हरियाणा विधान सभा के बजट सत्र के दौरान प्रदेश में एक बहुत ही दुःखद घटना घटी है । मैं चाहता हूं कि पहले आप इस पर चर्चा करायें । अध्यक्ष महोदय, एक तरफ सरकार महिला दिवस मनाने और महिलाओं को सम्मान देने की बात करती है, दूसरी तरफ सरकारी कॉलेजों में बेटियों को अपमानित करने और उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनायें निरंतर बढ़ती जा रही हैं । डबवाली स्थित डॉ. भीम राव अंबेडकर राजकीय कॉलेज में कार्यकारी प्रिंसिपल राकेश वधवा वहां पर न सिर्फ बेटियों के खिलाफ गंदे कमेंट करते हैं बल्कि उन्हें यहां तक कहते हैं कि आप भेड़ बकरियां हो, केवल बच्चों को जन्म दे सकती हो । वह अपने आप को न सिर्फ सरकार के नजदीक बताता है बल्कि वहां

के छात्र–छात्राओं में उस कार्यकारी प्रिंसिपल पर संघ की विचारधारा जबरदस्ती थोपने को लेकर भी भारी गुस्सा है । छात्र–छात्राओं ने उस कार्यकारी प्रिंसिपल के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन करते हुए एस.डी.एम., डबवाली को एक ज्ञापन भी सौंपा है । सभी प्रमुख अखबारों में प्रिंसिपल के कारनामों के चर्चे आए दिन छप रहे हैं । क्या यह सरकार बेटियों को अपमानित करने वाले उस प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे तुरंत निलंबित कर दंडित करने का काम करेगी ताकि फिर कोई हमारी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार न कर सके ?

श्री अध्यक्ष : परमिन्द्र सिंह ढुल जी, यह समय प्रश्न काल के लिए निश्चित किया गया है । अतः आप इस विषय को प्रश्न काल के बाद जीरो ऑवर में उठाकर चर्चा कर लीजिए । फिलहाल प्रश्नकाल ही चलने दीजिए ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है ।

Construction of Bridge on Yamuna River

***1767. Sh. Udai Bhan. :** Will the Irrigation Minister be pleased to state:- whether there is any proposal under consideration of the Government to construct bridge on Yamuna river in village Hassanpur of Hodal Assembly Constituency; if so, the details thereof ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : हॉ, श्रीमान् जी। यह मामला सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ उठाया गया है।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि कुछ समय पहले जब के.एम.पी. एक्सप्रैस–वे के उद्घाटन के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आये थे तो उन्होंने 5 अप्रैल, 2016 को हसनपुर में यमुना पुल के निर्माण के लिए घोषणा की थी कि यहां यमुना नदी पर पुल बनाया जाएगा । इस घोषणा की संख्या 12530 थी । यह पुल बहुत ही ज्यादा आवश्यक है । यह होडल से सीधा अलीगढ़ के लिए

जाएगा । इससे लगभग 40–50 किलोमीटर के रास्ते की भी बचत होगी और दोनों प्रदेशों के व्यापार में भी लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा । इस घोषणा को हुए अभी एक साल हो गया है लेकिन इसकी प्रोग्रैस यह है कि अभी तक यह मामला परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को ही भेजा गया है । मैं पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की तरफ से एक साल के दरमियान इस पर क्या एक्शन हुआ ?

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इसकी लम्बाई तकरीबन 25 किलोमीटर है । यह 8 किलोमीटर हरियाणा में और 17 किलोमीटर यू.पी. में पड़ता है । अभी इसकी डी.पी.आर. तैयार की जा रही है ।

श्री उदय भान : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि अभी इसका न तो एस्टिमेट तैयार हुआ है और न ही इसके लिए जमीन अधिग्रहण की गई है । फिलहाल इस संबंध में उत्तर प्रदेश की सरकार से भी बातचीत होनी बाकी है और इसका एस्टिमेट बनना भी बाकी है । मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितना–कितना पैसा देंगी ? मैं पूछना चाहता हूं कि इसकी क्या रूप रेखा बनाई गई है ? अभी एक साल में महकमे द्वारा सिर्फ एक चिट्ठी लिखी गई है । मैं पूछना चाहता हूं कि इस पुल को बनाने में कितने साल लगेंगे ?

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने इस पुल के निर्माण के लिए दिनांक 8.12.2016 को माननीय केन्द्रीय मंत्री नितिन गड़करी जी को डी.ई.ओ. लैटर लिखा है । हमें उम्मीद है कि इसका काम जल्द ही शुरू हो जाएगा ।

.....

Pardhan Mantri Ujjwala Yojna

*** 2045. Shri Bhagwan Dass Kabirpanthi. :** Will the Food and Supplies Minister be pleased to state the number of Gas cylinders provided to the women of poor families by the State Government under the Pardhan Mantri Ujjwala Yojna togetherwith the extent of financial aid provided so far ?

खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री (श्री कर्ण देव कम्बोज) : गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (PMUY) के अन्तर्गत 1,80,848 गैस कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 82,304 गैस कनैक्शन उन बी.पी.एल. परिवारों को जारी किये गये जो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं थे, इन परिवारों को राज्य बजट में से 1600/– रूप्ये प्रति परिवार की सब्सिडी की लागत से 13,16,86,400/– रूप्ये की सहायता प्रदान की गई है और इसी प्रकार कुल कनैक्शन 2,63,152 की कुल लागत 42,10,43,200/–रूपये आई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 1,80,848 बी0पी0एल0 परिवारों को प्रदान की गई 28,93,56,800/–रूपये की वित्तिय सहायता भारत सरकार द्वारा वहन की गई है।

श्री भगवान दास कबीरपंथी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से गरीब परिवार हैं जो ना तो केन्द्र की बी.पी.एल. सूची में है और ना ही राज्य सरकार की बी.पी.एल. सूची में हैं। क्या सरकार ऐसा कोई सर्वे करवाने जा रही है कि उन गरीब आदमियों को भी इस योजना का लाभ मिल सके?

श्री कर्ण देव कम्बोज: अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य का अलग प्रश्न है। माननीय सदस्य का यह प्रश्न मेरे विभाग के अन्तर्गत नहीं आता है। फिर भी मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में पीछे मीटिंग में चर्चा हुई थी कि हरियाणा के अंदर अप्रैल या मई के अंदर सर्वे करवाया जाये ताकि जो लोग इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सके उनको इस स्कीम का फायदा पहुँच सके। अध्यक्ष महोदय, सर्वे करवाने का विचार सरकार के तौर पर अभी नहीं हुआ है।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उज्जवला योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों की महिलाओं को जो गैस सिलैण्डर दिए जाते हैं, क्या उन सिलैण्डरों की कीमत साधारण सिलैण्डर से कम है या वही है?

श्री कर्ण देव कम्बोज: अध्यक्ष महोदय, इन सिलैण्डरों की कीमत एक ही है और जब से यह योजना आधार कार्ड से लिंक हुई है तब से सब्सिडी सीधे उन्हीं उपभोक्ताओं के खाते में जाती है।

कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के जनसंचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान के प्राध्यापकों/विद्यार्थियों, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य तथा हरियाणा के भूतपूर्व राजस्व मन्त्री के सुपुत्र का अभिनंदन।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, इंस्टीच्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और मीडिया टैक्नॉलोजी कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्राध्यापक/विद्यार्थी दर्शक दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए आए हुए हैं। मैं सदन की तरफ से उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधान सभा के पूर्व विधायक श्री फूल सिंह खेड़ी वी.आई.पीज. गैलरी में सदन की कार्यवाही देखने के लिए आए हुए हैं। मैं सदन की तरफ से उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, पूर्व राजस्व मंत्री कंवर सूरजपाल सिंह के सुपुत्र श्री संजय सिंह वी.आई.पीज. गैलरी में सदन की कार्यवाही देखने के लिए आए हुए हैं। मैं सदन की तरफ से उनका भी हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ।

.....

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

To Start Bus Service

***1787. Shri Om Parkash Barwa.** : Will the Transport Minister be pleased to state whether it is a fact that there is no bus service of Haryana Roadways from Pilani City of Rajasthan to Hisar of Haryana; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to start Haryana Roadways Bus service on the said route?

परिवहन मंत्री (कृष्ण लाल पंवार) : श्रीमान जी, हरियाणा राज्य परिवहन की पहले से ही पिलानी (राजस्थान) – हिसार मार्ग पर एक बस सेवा चल रही है।

श्री ओम प्रकाश बरवा: अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पिलानी शहर से हरियाणा के हिसार तक हरियाणा रोडवेज की कोई बस सेवा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा रोडवेज बस सेवा कब तक शुरू हो जायेगी?

श्री कृष्ण लाल पंवारः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न में यह बात थी कि हरियाणा रोडवेज की चरखी दादरी डिपो की बस पहले से ही उप केन्द्र लौहारू से पिलानी, पिलानी से हिसार वाया लौहारू, तोशाम मार्ग पर चल रही है। अध्यक्ष महोदय, इस बस का पिलानी से चलने का समय प्रातः 6:30 बजे और लौहारू पहुँचने का समय शाम 7:10 बजे का है। इस मार्ग पर केवल हरियाणा रोडवेज की यही बस चलती है।

श्री राम चन्द कम्बोजः अध्यक्ष महोदय, माननीय परिवहन मंत्री से दो–तीन महीने पहले सिरसा, रानियां, कालांवाली, ढूढियां वाली, सहन पाल, नथौर आदि क्षेत्रों के लोग मिले थे और बस सेवा शुरू की थी। सिर्फ हरियाणा रोडवेज की एक महीने की सेवा देकर अब बंद कर दी है। क्या माननीय मंत्री जी इस बस सेवा को पुनः शुरू करवायेंगे?

श्री अनूप धानकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूँ कि जिन अधिकारियों ने हरियाणा रोडवेज की सेवा बंद कर दी उनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। (विघ्न)

श्री कृष्ण लाल पंवारः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपना प्रश्न लिख कर दे दें।

.....

तारांकित प्रश्न संख्या 1737

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री ललित नागर सदन में उपस्थित नहीं थे।)

To Lay Down the Sewerage Pipe Line

***1973. Shri Om Parkash Yadav. :** Will the Minister of State for Public Health Engineering be please to state the time by which the sewerage pipeline is likely to be laid down in all the colonies of Ateli Town of Mahendergarh district togetherwith the details thereof ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : श्री मान जी वर्तमान में अटेली शहर का 80 प्रतिशत क्षेत्र सीवरेज प्रणाली से लाभान्वित है। शेष क्षेत्र में सीवरेज सुविधा प्रदान

करने के लिए एक नया अनुमान बनाने की प्रक्रिया में है और बजट उपलब्ध होने के बाद कार्यान्वयन के लिए कम से कम दो साल का समय लग सकता है।

श्री ओम प्रकाश यादवः अध्यक्ष महोदय, जो बात मंत्री जी बता रहे हैं वहां पर सीवरेज पाइप लाईन डालने के लिए शहर में खुदाई की हुई है जिसके कारण सारा शहर प्रभावित हो रहा है। अटेली कस्बा व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कस्बा है और यह हमारी आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया बहन श्रीमती संतोष यादव का विधान सभा क्षेत्र भी है। उन्होंने भी इस बारे में कहा है कि सीवरेज लाईन डालने का कार्य दो साल से लंबित है। विभाग या तो सीवरेज लाईन डालने के लिए शहर में खुदाई नहीं करवाता और अगर खुदाई करवा दी है तो सीवरेज लाईन डाल देनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि बजट उपल्ब्ध करवाकर इस काम को दो–तीन महीने के अन्दर पूरा करवाया जाये ताकि वहां की जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह काम लगभग 2–3 महीने में तो पूरा नहीं हो सकता। इसलिए इस काम को अगले वित्त वर्ष में पूरा करने की कोशिश करेंगे।

.....

To Shift The Site of Primary Health Centre

***1837. Sh. Pawan Saini. :** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the site of Primary Health Centre in Pipli; if so, the time by which the new building of PHC is likely to be onstructed ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान जी।

डॉ0 पवन सैनीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री अनिल विज जी का काम करने का लक्ष्य भी है और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है। उसमें मंत्री जी का लक्ष्य भी उजागर हुआ है। सर्वे भवंतू सुखिनः सर्वे सन्तू निरामयम। पिपली में जो पी.एच.सी. है वह बहुत छोटी है और वह पी.एच.सी. की बिल्डिंग काफी जर्जर हालत में है और पी.एच.सी. के बराबर में पुलिस पोस्ट भी है। इसलिए वहां पर लोगों को यह पता नहीं चलता कि पी.एच.सी. कौन सी है और पुलिस पोस्ट कौन

सी है। पिछली सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। माननीय मंत्री जी ने पूरे हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में दवाईंयां उपलब्ध करवाई हैं तथा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई हैं। पिपली कस्बा हाईवे के ऊपर पड़ता है। इसलिए इस पी.एच.सी. को बनाने के लिए पिपली में हम जमीन उपल्बध करवाएंगे अगर पिपली में जमीन पर्याप्त नहीं होगी तो पिपली के पास गांव बोली पड़ता है उस गांव में विभाग को एक एकड., दो एकड़ जितनी जगह चाहिए उतनी जगह हम उपलब्ध करवाएंगे। इसलिए वहां के लोगों के लिए नई पी.एच.सी. बनवानें का कष्ट करें। जो लोग पिपली में जी.टी. रोड़ के पास रहते हैं उनको इलाज के लिए कुरूक्षेत्र के एल.एन.जे.पी. हास्पिटल में जाना पड़ता है जो वहां से काफी दूर है रोड़ पर भीड़ होने के कारण पेसन्ट को ले जाने में काफी परेशानियां होती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे पिपली में नई पी.एच.सी. बनवाने का काम करें।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय जी, इस सदन के माननीय सदस्य श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी अपनी सारी केन्द्रीय व्यवस्तताओं को छोड़कर इस सदन में आएं हैं यह सदन उनका स्वागत करता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी स्वागत कर रहे हैं उनका स्वागत सहर्ष स्वीकार है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): स्पीकर सर, जो बात माननीय सदस्य ने पिपली पी. एच.सी. के बारे में बताया है वह पी.एच.सी. काफी अच्छी चल रही है उसमें ओ.पी. डी. 18761 की हैं तथा आई.पी.डी 746 की हैं। वहां पर डाक्टर तथा स्पोर्टिंग स्टाफ भी पोस्टिड होना चाहता है परन्तु वहां पर जगह बहुत कम है। स्पीकर सर, हम इस पी.एच.सी. को बनाना चाहते हैं अगर माननीय सदस्य वहां पर जमीन उपलब्ध करवा देंगे तो हम इस पी.एच.सी. को बनवा देंगे क्योंकि यह पी.एच.सी. जी.टी. रोड़ पर स्थित है और कुरूक्षेत्र का अस्पताल बहुत अन्दर जाकर है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस यह आश्वासन भी देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य अगर वहां पर जगह उपलब्ध करवा देंगे तो हम वहां पर पी. एच.सी. के निर्माण का कार्य शुरू करवा देंगे। पहले पिपली बीर ने दो एकड़ जगह दी थी लेकिन वह प्रोटेक्टिड फोरेस्ट की जगह थी इसलिए वहां पर हम पी.एच.सी.

नहीं बना सके। अगर माननीय सदस्य जगह उपलब्ध करवा देंगे तो हम इस पी.एच. सी. के निर्माण का कार्य शुरू करवा देंगे।

डॉ0 पवन सैनीः अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी मांग स्वीकार की है। इसके साथ ही माननीय मंत्री जी से एक निवेदन और करना चाहता हूं क्योंकि यह पी.एच.सी. जी.टी. रोड़ पर है और इसके आस–पास 20 किलोमीटर तक कोई भी ट्रामा सैंटर नहीं है। अगर इस पी.एच.सी. के साथ ट्रामा सैंटर भी बनवा देंगे तो इसके लिए भी मैं मंत्री जी का आभारी रहूंगा।

श्री अनिल बिज : अध्यक्ष महोदय, वहां पर वाकई में कोई ट्रामा सैन्टर नहीं है और जी.टी रोड पर कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। इसलिए अगर वहां पर जगह उपलब्ध हो जाती है तो पी.एच.सी के साथ ट्रामा सैन्टर बनाने पर भी हम अवश्य विचार करेंगे।

.....

तारांकित प्रश्न संख्या – 1860

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्या श्रीमती नैना सिंह चौटाला सदन में उपस्थित नहीं थीं।)

तारांकित प्रश्न संख्या – 1848

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री उमेश अग्रवाल सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या – 2037

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री घनश्याम सराफ सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Gou- Samvardhan Centre in Badhara

*** 1855. Shri Sukhvinder. :** Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to State:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to establish Gou- Samvardhan Centre in

Badhara Assembly constituency; if so, the time by which it is likely to be established; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up sanctuary for stray cattle ?

कृषि मन्त्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) :

(क) नहीं श्रीमान जी ।

(ख) हां, श्रीमान जी दो गौ–अभ्यारण्य प्रत्येक 50 एकड भूमि पर एक गांव नैन, जिला पानीपत में तथा दूसरा गांव ढंडूर, नगर निगम, हिसार के क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे हैं।

श्री सुखविन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाढड़ा विधान सभा क्षेत्र में देशी गाय का एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की थी। माननीय मंत्री जी ने अनुसंधान केंद्र के बजाए एक गाय का संवर्धन केंद्र स्थापति करने की बात सदन में कही थी। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के गांव रुदरौल में पंचायत भूमि देने के लिए तैयार है इसलिए वहां पर विभाग की तरफ से एक गाय का संवर्धन केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया जाए। इसके साथ–साथ जो जिला स्तर पर अभ्यारण्य केंद्र बनाने की बात है, उसके लिए भी हमारी पंचायत भूमि देने के लिए तैयार है, इसलिए मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर अभ्यारण्य केन्द्र भी बनवाने का कष्ट किया जाए। धन्यवाद

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : माननीय अध्यक्ष जी, एक फिल्म आयी थी ''कभी हां कभी ना''। पिछली सत्र में जब इनका सवाल लगा था तो जब मैं सवाल का उत्तर दे रहा था उस समय माननीय सदस्य सदन से गायब हो गये थे, क्योंकि उस समय इस कार्य को करने के लिए इनकी 'न' थी और इस काम में उस समय विभाग को जमीन देने के लिए भी तैयार नहीं थे लेकिन आज माननीय सदस्य का जमीन देने के लिए मन बना है, इनकी पॉजिटिविटी है तो मैं भी विभाग को इस बारे में पॉजिटिव कहूंगा और इनके यहां उस कार्य को करवाने के लिए आगे प्रयास किये जायेंगे।

.....

One Way Road

***1946. Sh. Ranbir Gangwa. :** Will the PW(B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to make the Kaimri road One-way from camp chowk to corporation area; if so, the time by which the construction work of the said road is likely to be started ?

लोक निर्माण (श्री नरबीर सिंह मंत्री) : हाँ, श्रीमान् जी। यद्यपि, वर्तमान में सड़क को आरम्भ करने का समय नहीं दिया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो जवाब सदन के पटल पर रखा है, उस पर कोई समय–सीमा नहीं दी गई है, लेकिन मैं भाई को बताना चाहता हूं कि हम तकरीबन 6 महीने के अंदर इसको शुरू कर देंगे। जो इन्होंने सवाल किया था, उसमें यह पूछा था कि क्या ये रोड वन–वे किया जाएगा, बल्कि मेरे ख्याल से इनका सवाल यह होना चाहिए था कि क्या ये रोड फोर लेन किया जाएगा आधा रोड तो फोर लेन है, क्योंकि यह माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है इसलिए हम और 6 महीने में इस काम को शुरू कर देंगे।

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने 6 महीने का टाईम दिया और मेरे क्वैश्चन को समझने का भी काम किया। देशी भाषा में हम वन वे कह देते हैं, लेकिन बात डिवाइडर की थी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसके साथ–साथ मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जो कैमरी रोड पर इस समय ट्रैफिक की समस्या हो गयी है और वहां पर नहर से निकलते ही फाटक भी है और फाटक जब बंद होता है तो बहुत लम्बी लाईन लग जाती है उधर से जो साउथ बाई पास उसे मिनी बाई पास भी बोलते हैं और इधर से कैमरी रोड और नहर आ जाती है तो दोनों के कारण ट्रैफिक जाम हो जाता है। हम दिल्ली रोड के साउथ बाई पास से होकर शहर की तरफ जाते हैं तो बड़ी भारी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छा है कि आपने 6 महीने का टाइम दिया, इसके साथ–साथ आप कैमरी रोड के ऊपर लोगों की

दिक्कत और परेशानियों को देख के वहां पर आर.यू.बी या आर.ओ.बी जो भी वहां संभव हो, वह भी आप बनाने का काम करें।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस आर.ओ.बी. का माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं इस बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसका हम ट्रॉफिक वाल्यूम पता करवा लेंगे । अगर यह आर.ओ.बी. रेलवे के अनुसार ट्रॉफिक वॉल्यूम को पूरा करता होगा तो इसको जरूर बनवा दिया जायेगा ।

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमें विधायक बने हुए करीबन अढ़ाई साल हो गये । तब से हमारी मांग रही है कि राजगढ़ रोड़ जो बड़वा जी के गांव को भी जोड़ता है वहां पर काफी ट्रॉफिक हो गया है । जिसके कारण वहां पर काफी एक्सीडैंट होते हैं और कई मृत्यु भी हो चुकी हैं । उस रोड़ को बनाने के लिए मंत्री जी ने पैसे भी दे दिए हैं और उस पर काम भी शुरू हो गया है तथा कुछ रोड़ बन भी गया है । वहां पर जो ठेकेदार काम कर रहा है वह बहुत धीरे काम कर रहा है । उसने बड़वा गांव से गंगवा गांव तक कई दिनों में सड़क बनाई । वह ठेकदार एक दिन काम करता है फिर दो दिन काम नहीं करता जिसके कारण उस रोड़ का कार्य बहुत धीरे हो रहा है । वह रोड़ इतना खराब है कि वहां पर जो ट्रैक्टर ट्राली में चारा लेकर आते हैं वह ट्राली पल्ट जाती है जिसके कारण काफी एक्सीडैंट होते हैं जिसके कारण मेरे गांव के भी दो लोग मर चुके हैं । इस बारे में मंत्री जी पता लगवा सकते हैं । मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि उस रोड़ का कार्य जल्द पूरा करवा दिया जाये ।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उस रोड़ पर धीरे कार्य चल रहा है । अब हम जल्द ही उस रोड़ का कार्य पूरा करवा देंगे ।

.....

दैनिक ट्रिब्यून के भूतपूर्व सम्पादक का अभिनन्दन

शिक्षा मंत्री(श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आज की सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष गैलरी में श्री नरेश कौशल, दैनिक ट्रिब्यून के भूतपूर्व सम्पादक बैठे हुए हैं । मैं उनका अभिनन्दन करता हूं ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Reconstruction of Roads

***1805. Shri Pirthi Singh Namberdar.** : Will the Agriculture Minister be pleased to state—

(a) Whether it is a fact that the following roads in Narwana Assembly Constituency have been damaged badly:-

(i) Dhakal Head to village Hatho;

(ii) Ujhana to Koyal;

(iii) Rajgarh Dhobhi to Kalwan via Sulehra;

(iv) Ujhana to Dundwa;

(v) Badanpur to Sachakhera;

(vi) Kharal to Ujhana;and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to reconstruct the abovesaid roads togetherwith the time by which these roads are likely to be constructed ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

ब्यौरा

1. ढाकल हैड से गांव हथो :– प्रस्तावित सड़क की लम्बाई 3.46 किलोमीटर है। आर.डी. 0–1240 मीटर तक सड़क सिरसा ब्रांच नहर की पट्री पर प्रस्तावित है। जहॉ कोई राजस्व रास्ता उपलब्ध नही और आर.डी. 1240–3460 मीटर में रास्ता 5 करम उपलब्ध है। आर.डी. 0–1240 मीटर में राजस्व रास्ता उपलब्ध न होने के कारण यह बोर्ड की सड़क निर्माण निति के अंतर्गत नही आती। इसलिए इस सड़क की निर्माण की कोई योजना नही है।

2. उझाना से कोयल :– प्रस्तावित सड़क की लम्बाई 5.49 किलोमीटर है। आर. डी. 0–1280 मीटर में रास्ता 5 करम, 1280–2735 मीटर में 7 करम, 2735–3880 मीटर में 6 करम तथा 3880–5490 मीटर में 9 करम रास्ता उपलब्ध है। प्रस्तावित सड़क के बनने से समीपतम खरीद केन्द्र उझाना पहुचने के लिए कोई दूरी कम नहीं होती। यह सड़क बोर्ड की सड़क निर्माण निति के अंतर्गत नही आती। इसलिए इस सड़क की निर्माण की कोई योजना नही है।

3. राजगढ़ ढोभी से कालवन वाया सुलेहड़ा :– यह हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की एक मौजुदा सड़क है। जिसकी लम्बाई 6.45 किलोमीटर है। इस सड़क का निर्माण वर्ष 2002 में किया गया था। इसकी विशेष मुरम्मत 73 लाख रुपयें की राशि के खर्च से वर्ष 2012 में की गई थी। सड़क वाहन चलने योग्य है। फिर भी इस पर कुछ मामुली गड्डे बन गये है। जिनकी मुरम्मत 31.03.2017 तक कर दी जाएगी।

4. उझाना से ढुंढवा :– यह हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की एक मौजुदा सड़क है। जिसकी लम्बाई 7.90 किलोमीटर है। इस सड़क का निर्माण वर्ष 1992 में किया गया था। इसकी विशेष मुरम्मत कुछ हिस्सों में 58.88 लाख रुपयें की राशि के खर्च से वर्ष 2014–15 में की गई थी। घरों का पानी इकट्ढा होने के कारण दोनों गांवों की फिरनी क्षतिग्रत हो गई हैं। इसकी मुरम्मत के लिए 57.20 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति 20.02.2017 को दे दी गई है और टैंडर प्रक्रिया में है। मुरम्मत का कार्य अगले वित वर्ष में पूर कर लिया जाएगा।

5. बडनपुर से सच्चाखेड़ा :– प्रस्तावित सड़क की लम्बाई 4.26 किलोमीटर है। पूरी लम्बाई में उपलब्ध रास्ता 6 करम है। प्रस्तावित सड़क के बनने से समीपतम अनाज मंडी नरवाना पहुचने के लिए कोई दूरी कम नहीं होती। यह सड़क बोर्ड की सड़क निर्माण निति के अंतर्गत नही आती। इसलिए इस सड़क की निर्माण की कोई योजना नही है।

6. खरल से उझाना :– यह हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की एक मौजुदा सड़क है। जिसकी लम्बाई 6.30 किलोमीटर है। इस सड़क का निर्माण वर्ष 2003 में किया गया था। इसकी विशेष मुरम्मत 33.45 लाख रुपयें की राशि के खर्च से वर्ष 2010 में की गई थी। सड़क वाहन चलने योग्य है। फिर भी इस पर कुछ मामुली गड्डे बन गये है। जिनकी मुरम्मत 31.03.2017 तक कर दी जाएगी।

श्री पिरथी सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन गांवों के बीच में ज्यादातर ढ़ाणियां बनी हुई हैं और कच्चे रास्ते हैं । उन ढ़ाणियों के बच्चे भी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं और किसान भी अपनी फसल मण्डी में लेकर जाते हैं । वहां पर लोगों का रात दिन आना–जाना होता है । बरसात के दिनों में तो वहां पर रास्ते बिलकुल ही बंद हो जाते हैं । मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि उन सभी रास्तों को जल्द से जल्द पक्का किया जाये ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 6 मार्गों का जिक्र अपने प्रश्न में किया है । इस बारे में मैं उनको जानकारी देना चाहूंगा कि इनमें से राजगढ़ ढोभी से कालवन वाया सुलेहड़ा, उझाना से ढुंढवा और खरल से उझाना ये तीनों सड़कें पहले से ही मार्केटिंग बोर्ड द्वारा बनाई हुई हैं । इन सड़कों की मरम्मत के लिए राशि तय कर दी गई है और इन सड़कों की मरम्मत जल्द ही करवा दी जायेगी । इसके अतिरिक्त जो ढाकला हैड से गांव हथो का रास्ता है वह 5 कर्म से कम का है । मार्केटिंग बोर्ड की सड़क बनाने के लिए कम से कम 5 कर्म का रास्ता चाहिए । इसके अतिरिक्त जो उझाना से कोयल और बडनपुर से सच्चाखेड़ा के रास्ते हैं इन सड़कों के बनाने से समीपतम अनाज मंडी नरवाना पहुंचने के लिए कोई दूरी कम नहीं होती । मार्केटिंग बोर्ड वही सड़कें बनवाता है जिनसे मण्डी जाने की दूरी कम होती हो इसलिए इन रास्तों को पक्का हम नहीं करवा सकते । इन सड़कों को बनवाने के लिए हम लोक निर्माण मंत्री जी से प्रार्थना करेंगे ।

श्री पिरथी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो तीन सड़कें मार्केटिंग बार्ड ने बनवाई हुई हैं उनकी चौड़ाई 18 फिट की जाये ।

(इस प्रश्न का जबाव नहीं दिया गया)

.....

TO DEVELOP MORNI AS A TOURIST PLACE

***1923. Smt. Latika Sharma. :** Will the Tourism Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government develop the Morni area of Kalka constituency as Tourist spot; if so, the time by which the proposal is likely to be materialized?

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : श्रीमान् जी, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया है।

वक्तव्य

मोरनी क्षेत्र को पहले से ही एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा मोरनी में 'माउंटेन क्वैल' नाम से एक सुव्यवस्थित पर्यटन परिसर चलाया जा रहा है। जिसमें अतिथि कक्ष, रेस्तरां, लॉबी, सिटआउट टैरेस, सम्मेलन कक्ष आदि की सुविधाएं है। टिक्करताल में पर्यटन विभाग द्वारा दूसरा पर्यटन परिसर विकसित किया गया है जिसमें कमरें, कैफेटेरिया, भोजन कक्ष, कैंपिंग साईट, मनोरम पहाडों को निहारने के लिए व्यूइंग डैक की सुविधा उपलब्ध है।

मोरनी क्षेत्र में साहसिक खेलों को बढावा देने के लिए खेल एंव युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा इस क्षेत्र में हरियाणा साहसिक खेल अकादमी खोली जानी है। इसके संचालन के लिए हरियाणा साहसिक खेल अकादमी के नाम से एक सोसाईटी का गठन एंव पंजीकरण हरियाणा रजिस्ट्रेशन एण्ड रैगुलेशन ऑफ सोसाईटीज़ एक्ट, 2012 के तहत किया जा चुका है। प्रस्तावित साहसिक गतिविधियों जैसे कैंपिंग, ट्रैकिंग आदि के लिए मोरनी में उपयुक्त स्थलों के चुनाव का कार्य प्रगति पर है।

इसके अतिरिक्त, वन विभाग हरियाणा द्वारा मोरनी किले में एक प्राकृतिक संग्रहालय एंव जागरूकता केन्द्र (नेचर म्यूजियम एंव अवेयरनैस सैंटर) विकसित किया जा रहा है। इस क्षेत्र की जैवविविधता को बचाने और उसे संवंर्धित करने के लिए मोरनी में एक विश्व हर्बल वन बनाने का कार्य पतंजलि अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार के तकनीकी मार्गदर्शन में किया जाना प्रस्तावित है।

अध्यक्ष महोदय, मोरनी क्षेत्र को पहले से ही एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया हुआ है । वहां पर माउंटेन क्वैल नाम से सुव्यवस्थित पर्यटन स्थल हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा चलाया जा रहा है । इसके अतिरिक्त टिक्करताल में भी पर्यटन निगम द्वारा परिसर विकसित किया हुआ है । इसी तरह से वहां थापला में मार्शल आर्ट के नाम से केन्द्र विकसित करेंगे ।

श्रीमती लतिका शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं । मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि मोरनी में जंगली मुर्गे का प्रजनन स्थल है । जंगली मुर्गा देखने में बहुत सुंदर होता है । इसी तरह से गिद्ध का प्रजनन केन्द्र भी मोरनी में है । हमारे केन्द्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावेड़कर और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मोरनी में गिद्ध कार्यक्रम में आये थे। इसके अलावा हर्बल पार्क भी हमारे पास है। थापली में नेचर केयर कैम्प जिसमें देशी–विदेशी अतिथि आते हैं। इसमें इसका जिक्र तक नहीं है। स्वर्ण जयंती प्रोजैक्ट में मोरनी का किला, त्रिफला प्रोजैक्ट, हर्बल फॉरैस्ट जो कि आचार्य राम देव व आचार्य बालकृष्ण के सहयोग व मार्गदर्शन में नम्बर एक पर आने वाले हैं। मोरनी हरियाणा प्रदेश का एकमात्र पहाड़ी और पर्यटक स्थल है। वहां पर भारत ही नहीं बल्कि विश्वस्तरीय हर्बल पार्क बनने जा रहा है। इसका परिणाम आने वाले 6 महीने के अंदर दिखने लगेगा। मेरा पिछले दो साल से सरकार व विभाग से यह आग्रह रहा है कि स्पोर्टस एडवैंचर जिसके लिए सवा दो से अढ़ाई करोड़ रूपया स्वीकृत है लेकिन अभी तक भी अधिकारियों की सुस्ती की वजह से काम शुरू नहीं हो पाया। वहां पर अभी तक जमीन देखने का भी काम नहीं हुआ है। जंगली मुर्गा, गिद्ध नेचर कैम्प का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ये सारे ऐसे काम हैं जो हमें भारत के मैप पर लाते हैं। ये सभी अभूतपूर्व हैं लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये काम अभी तक शुरू नहीं हो पाये हैं। इस प्रश्न में उसका जिक्र तक नहीं आया है। सबसे बड़ी बात मोरनी के लिए यह है कि मोरनी में फॉरेस्ट की लैंड है। सरकारी योजनाओं में मिलने वाले पैसे में से 20 प्रतिशत राशि मोरनी के स्थायी निवासियों को मिलती थी। चाहे कांग्रेस का राज रहा और चाहे इनेलो का राज रहा यह पैसा मोरनी के निवासियों को नहीं मिला। हमारी सरकार आने के बाद वहां पर बंदोबस्त अधिकारी ने लागों को पैसा देना शुरू किया। ए.जी. ऑफिस ने भी इस पर आपत्ति लगाई है कि यह पैसा कहां जाता है? वहां बंदोबस्त अधिकारी कोई काम नहीं कर रहा है। अभी हमारी सरकार ने यह अभूतपूर्व निर्णय किया है कि मोरनी क्षेत्र के लोगों को जो पैसा मिलना चाहिए था वह अब मितेगा। माननीय मंत्री जी का मैं अपने हल्के के लोगों की तरफ से बहुत–बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, जैसा कि माननीय सदस्या जी ने बताया मोरनी हरियाणा के लिए विशेष महत्व का स्थान है। अभी हरियाणा सरकार ने बाबा राम

देव जी के साथ जड़ी–बूटी युक्त फॉरेस्ट डिवैल्प करने के लिए एक एम.ओ.यू. साईन किया है। इस पर बहुत जल्दी काम शुरू हो गया है। जो बंदोबस्त अधिकारी की ये बात कर रहे हैं। यह बात सच है कि पिछली सरकारों के समय में इस सम्बन्ध में बहुत अनदेखी हुई थी। अब हमारा हर विभाग चाहे वह फॉरेस्ट डिपार्टमैंट है, चाहे पर्यटन विभाग है और चाहे आयुष है मोरनी इस समय हमारे सभी विभागों का कार्य क्षेत्र हुआ है। पर्यटन के साथ–साथ जैसे गिद्ध वाला मामला है हम उसका अलग से संज्ञान लेकर जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेंगे। मैं इस सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि it is the only research centre in India. हमारा विभाग इस दिशा में विशेष रूप से कार्य कर रहा है। जैसा विधायक जी चाहती हैं हम प्रत्येक क्षेत्र में मोरनी का विकास करेंगे।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मुझे बहुत खुशी हुई जब लतिका जी ने यह प्रश्न उठाया।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आप कृपा बैठे अभी लतिका जी कुछ और पूछना चाहती हैं। इसलिए आप उन्हें बोलने दें। उनके बाद आप बोल लेना।

श्रीमती लतिका शर्मा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक बात और कहना चाहूंगी कि जो मेरा कालका विधान सभा क्षेत्र है यह पर्यटन की दृष्टि से एक नम्बर पर है। वहां पर पिंजौर गार्डन है जहां पर हर साल मेला लगता है। वहां पर पानी की बावड़ियां भी है। इसके साथ ही साथ वहां पर धारा मण्डल है। मेरी माननीय मंत्री जी से रिकवैस्ट है कि इन सभी स्थानों को आपस में रोप–वे के माध्यम से जोड़कर मोरनी तक ट्रॉली सिस्टम शुरू किया जाये। जिस प्रकार से हमारी सरकार ने कुरूक्षेत्र के धार्मिक महत्व के कारण पूरी तरह से डिवैल्प किया है उसी प्रकार से मेरे कालका विधान सभा क्षेत्र को भी विशेष ध्यान देकर पर्यटन की दृष्टि से डिवैल्प किया जाये ताकि मोरनी के पर्यटक क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा डिवैल्प हों।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मोरनी में हमारी सरकार की बहुत सी योजनाओं पर काम प्रारम्भ हो गया है। इसी प्रकार से कुछ पर काम प्रारम्भ होने वाला है। मोरनी हरियाणा के लिए शिमला जितना महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र विकसित करने जा रहे हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहती हूं कि मोरनी का विकास तो पहले ही कांग्रेस सरकार के समय में हो चुका था । लतिका जी जिस गिद्ध केन्द्र की बात कर रही हैं वह हमारी सरकार के कार्यकाल में बना था और जो पहला विलुप्त जाति का गिद्ध था उसका नाम विभू रखा गया था । यह सभी काम उस समय हुये थे जब मैं पर्यटन मंत्री थी इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि कांग्रेस सरकार में कोई काम नहीं हुआ । मोरनी फोर्ट को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का पूरा काम कांग्रेस सरकार के समय में हुआ था । मैं मंत्री जी से सप्लीमैंट्री पूछना चाहती हूं कि बाबा रामदेव को मोरनी के क्षेत्र में जो जमीन दी जा रही है उससे हरियाणा सरकार को क्या फायदा होने वाला है? वे वहां पर स्वयं जड़ी–बूटियां उगायेंगे और बाहर ले जायेंगे तो फिर सरकार को उससे क्या फायदा होगा?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बहन किरण चौधरी ने एक जिज्ञासा प्रकट की है और वे इस पर्यटन विभाग की मंत्री भी रही हैं और उनकी पर्यटन में बहुत रूचि भी है । हमने बाबा रामदेव जी से आग्रह किया था कि मोरनी में हर्बल फोरेस्ट विकसित किया जाये क्योंकि वहां की जो मिट्टी है उसमें आयुर्वेदिक जड़ी–बूटियां स्वयं उग जाती हैं और उनकी बहुत आयुर्वेदिक उपयोगिता है । हरियाणा सरकार ने बाबा रामदेव को हरियाणा का योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और मोरनी में केवल पर्यटन ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक जड़ी–बूटियों का भंडार विकसित होने वाला है उससे हरियाणा को बहुत लाभ होगा ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, पर्यटन मंत्री जी ने जो जवाब दिया है मैं उसमें कुछ एड करना चाहता हूं । मोरनी में विश्व का पहला हर्बल फोरेस्ट बनने जा रहा है । दुनिया में हर्बल पार्क तो बहुत होंगे लेकिन हर्बल फोरेस्ट सारे विश्व में नहीं है । अगर कोई गूगल में हर्बल फोरेस्ट ढूंढेगा तो हर्बल पार्क तो मिल सकता है लेकिन हर्बल फोरेस्ट नहीं मिलेगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सप्लीमैंट्री नहीं पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठिये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, सरकार का कोई भी मंत्री जवाब दे सकता है और मैं जवाब ही दे रहा हूं ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि बाबा रामदेव को जो मोरनी की जमीन दी गई है उसके लिए क्या सरकार की तरफ से ग्लोबल टैंडर मांगे गये थे?(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : करण जी, आप बैठिये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ***

श्री अध्यक्ष : श्री करण सिंह दलाल जी बिना अनुमति के बोल रहे हैं इसलिए इनका बोला हुआ रिकॉर्ड न किया जाये ।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, साथी करण दलाल जी ने बाबा रामदेव जी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है । आज पूरी दुनिया बाबा रामदेव जी की दवाइयों से ठीक हो रही है । आज पूरी दुनिया में भारतीयता का, आयुर्वेद का, विज्ञान का और प्राणायाम का डंका बज रहा है । इस प्रकार से बाबा रामदेव जी न केवल हरियाणा के बल्कि पूरी दुनिया के योग के ब्रांड एम्बेसडर बने हुये हैं ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : अध्यक्ष महोदय, श्री करण दलाल जी का दिमाग खराब हो चुका है इसलिए इनका दिमाग चैक करवाया जाये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : करण दलाल जी, प्लीज आप बैठिये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः श्री करण दलाल, यह जीरो ऑवर नहीं है । आपको बोलने का आगे बहुत समय मिलेगा आपके आगे ऑल इण्डिया प्रवक्ता बैठे हैं ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस की नॉलिज में लाना चाहता हूं कि हरियाणा के लिये यह इतना बड़ा प्रोजैक्ट बन रहा है । जिसमें लगभग 25 हजार मेडिसिनल प्लांट लगाए जा रहे हैं जो पूरे हिन्दुस्तान में पैदा किये जा सकते हैं । जिनके यहां पर कलस्टर लगाए जाएंगे और लगभग 17 एकड़ जमीन में यह पार्क, ये फोरेस्ट बनाया जाएगा । जहां तक हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी यह कहते हैं कि सरकार ने बाबा रामदेव को जमीन दी है। अब पता नहीं कि इनको बाबा रामदेव से इतना डर क्यों लगता है । (शोर एवं व्यवधान)

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठिये । मंत्री जी अपना जवाब दे रहे हैं इनको अपनी पूरी बात कह लेने दो। इस तरह तो कोई जवाब ही नहीं आएगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, सरकार की बाबा रामदेव से जमीन देने की कोई बात नहीं हुई है । सर, वे हमारे ब्रांड अम्बैस्डर हैं इसलिये हम उनसे केवल नॉलिज लेते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण दलाल : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब सरकार देगी । ये क्यों जबाव दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, जवाब तो कोई भी दे सकता है । इसमें कोई दिक्कत नहीं है । (शोर एवं व्यावधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, फोरेस्ट तो उनका भी नहीं है। इन्होंने फोरेस्ट की बात की है । इनको तो केवल टूरिजम तक के प्रश्न पूछने चाहिए थे । फोरेस्ट तो उनका भी नहीं है । (शोर एवं व्यवधान) सर, मैं वही तो बता रहा हूं । इसके बारे तो कोई भी मंत्री बता सकता है ।

श्री अध्यक्ष : जवाब तो कोई भी दे सकता है । इसमें आपकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं । सरकार की तरफ से कोई भी जवाब दे इसमें आपको क्या दिक्कत है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ये जानना ही नहीं चाहते । जब ये मेडिशनल पौंधों का फोरेस्ट बनेगा तो यहां सारे विश्व से टूरिस्ट आएगा । अगर कोई भी मैडिशनल प्लांट की स्ट्डी करने वाला स्टुडैंट्स किसी एक जगह पर सारे मैडिशनल प्लांट देखना चाहेगा तो वह मोरनी में आएगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि कौन से कानून के तहत सरकार ने बाबा रामदेव को जमीन दी है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जब मंत्री जी कह रहे हैं कि बाबा रामदेव को कोई जमीन दी ही नहीं गई है । (शोर एवं व्यवधान) दलाल जी, आप बिना बात के ऐसा कह रहे हो । (शोर एवं व्यवधान) दलाल साहब, जब मंत्री जी स्वयं फलॉर ऑफ दि हाउस कह रहे हैं कि बाबा रामदेव को कोई जमीन दी ही नहीं गई है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमने बाबा रामदेव जी को कोई जमीन नहीं दी । (शोर एवं व्यवधान) कहीं कोई तय नहीं हुआ कि हम जमीन देंगे । हमने तो इसके बारे में उनसे केवल मार्गदर्शन लेने का एम.ओ.यू. साईन किया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, यह तो प्लांट लगाने की बात हो रही है जिसमें उनसे मार्गदर्शन लेने की बात है ।(शोर एवं व्यवधान) आप ये दिखाईये कि कहां जमीन दी गई है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हमने कौन से कानून को ताक पर रख कर जमीन दी है । जो चीज हुई ही नहीं है आप यह कैसे कह रहे हैं । You are mis-leading the House. Dalal ji, you are always mis-leading the House. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, अगर आपके पास इस तरह का कोई कागज पत्र है तो आप वह कागज पत्र दिखा सकते हो । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इनको अपने दिमाग का ईलाज कराने के लिये बाबा रामदेव जी के पास ही जाना पड़ेगा क्योंकि इनके दिमाग का ईलाज उन्हीं के पास है । (शोर एवं व्यवधान) दलाल साहब, मैं आपका ईलाज मुफ्त में करवा दूंगा । **(शोर एवं व्यवधान)**

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर) :अध्यक्ष महोदय, आप इनको * सदन से बाहर निकाल दो। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य सदन की वैल में आ गये।)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप सभी अपनी–अपनी सीट पर जाईये ।

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप इनके खिलाफ निन्दा प्रस्ताव लाईये । हम बोलें तो हमारे खिलाफ तो निन्दा प्रस्ताव और ये चाहे कुछ भी बोलत रहें । इनके खिलाफ कुछ भी नहीं । (शोर एवं व्यवधान) आप इनके खिलाफ निन्दा प्रस्ताव

.....

*** चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।**

लाईये । **(शोर एवं व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, हमने तो अपने शब्द वापिस ले लिये थे ।

श्री मनीष कुमार ग्रोवर : अध्यक्ष महोदय, इनको * सदन से बाहर निकाल देना चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को उंगली करके इशारा नहीं करना चाहिए। इन्हें अपनी उंगली हटा लेनी चाहिए और सदन में अनपार्लियामैंटरी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अनपार्लियामैंटरी शब्दों का प्रयोग किया है इसके लिए इन्हें पूरे सदन से माफी मांगनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, जब तक मंत्री जी के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव नहीं आता तब तक हम शांत होकर बैठने वाले नहीं हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष कुमार ग्रोवरः अध्यक्ष महोदय, जब श्री कुलदीप शर्मा द्वारा इसी तरह के शब्दों का प्रयोग हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज के खिलाफ किया गया तब तो इन कांग्रेस वालों को कोई दर्द नहीं हुआ अब जब यही बात मैंने कह दी तो इनको दर्द हो गया है। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य संसदीय सचिव (डॉ0 कमल गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, कुलदीप शर्मा ने अनिल विज के लिए कहा था कि जब कांग्रेस शासन काल में वह स्पीकर थे तो अनिल विज को * सदन से बाहर निकाल दिया करते थे। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य वैल में आ गए। कुछ सदस्य श्री अध्यक्ष की चेयर के सामने खड़े होकर तर्क वितर्क करने लगे जबकि कुछ सदस्य सत्ता पक्ष के सदस्यों पर आरोप–प्रत्यारोप लगाने लगे।)

श्री मनीष कुमार ग्रोवरः अध्यक्ष महोदय, सीधी सी बात है जैसा बोओगे–वैसा काटोगे? जब कुलदीप शर्मा ने अनिल विज के खिलाफ इन शब्दों का प्रयोग किया

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

तो तब इन्हें इस तरह की स्थिति के बारे में सोचना चाहिए था। (शोर एवं व्यवधान) यह कुलदीप शर्मा का बोया हुआ बीज है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अपने द्वारा कहे गए इस तरह के शब्द वापिस ले लिए थे। अतः मनीष ग्रोवर के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव लाया जाये और इन शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाला जाये?(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कुलदीप जी, आज जब कांग्रेस के सदस्यों को बोलने का समय दिया गया था तब यह आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने वाली स्थिति उभरकर आई है। देखिये जिन आपत्तिजनक शब्दों से कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को आपत्ति है, उन शब्दों को सदन की कार्यवाही में रिकॉर्ड पर लिया ही नहीं गया है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, मनीष ग्रोवर के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव लाया जाये? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, मनीष ग्रोवर के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव लाया जाये और सदन से माफी मंगवाई जाये? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं अतः आपका व्यवहार दोनों पक्षों के प्रति बराबर होना चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, जब कुलदीप शर्मा ने अनपार्लियामैंटरी शब्दों का प्रयोग इस सम्मानित सदन में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के खिलाफ किया था तब इनकी गैरत कहां चली गई थी? यह लोग यहां वैल में आकर खड़े होकर आपसे तर्क–वितर्क कर रहे हैं, यह कौन सा मर्यादित आचरण है?(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष कुमार ग्रोवरः अध्यक्ष महोदय, सदन में कुलदीप शर्मा की बात का जवाब उसी के शब्दों में दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, मनीष ग्रोवर छटी क्लॉस पास हैं इनको पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाना चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, यह * बाहर निकालने वाली बात एक महिला के लिए कही गई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिये, यह बात किसी महिला सदस्या के लिए नहीं कही गई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस के सदस्यों ने अनपार्लियामैंटरी शब्दों का प्रयोग किया था तब इन कांग्रेसियों की गैरत कहां थी? कल जब कुलदीप शर्मा ने इन शब्दों का प्रयोग किया था तब एक भी कांग्रेसी सदस्य नहीं बोला था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सुरजेवाला जी, देखिये असल बात तो यह है कि यह * निकालने वाली बात आप लोगों ने ही सिखाई है?(शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, जैसा कोई बोएगा वैसा काटेगा? (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री कमल गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, कल कुलदीप शर्मा जी ने हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को कहा था कि वह अपने कांग्रेस पार्टी के शासन काल में अनिल विज को * बाहर निकला दिया करता था। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, जब सदन में कुलदीप शर्मा के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव लाया जा सकता है तो मनीष ग्रोवर के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव क्यों नहीं लाया जा सकता? (शोर एवं व्यवधान)

श्री शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, आपत्तिजनक शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाला जायें।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, आपत्तिजनक शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाला जाये।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिये, इन आपत्तिजनक शब्दों को सदन की कार्यवाही का हिस्सा ही नहीं बनाया गया है अतः निकालने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता?(शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री मनीष कुमार ग्रोवरः अध्यक्ष महोदय, कुलदीप शर्मा की वर्डिंग थी कि वह अपने स्पीकर काल में श्री अनिल विज को * सदन से बाहर निकाल दिया करते थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, आप ही बतायें कि क्या मनीष ग्रोवर द्वारा गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है?(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिये, अब मैं इस मामले में स्वयं संज्ञान लूंगा और आप सबको आश्वासन देता हूँ कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा? (शोर एवं व्यवधान) इस तरह की चीजों का दोनों पक्षों को ध्यान रखना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) जो कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपत्तिजनक शब्दो ं का प्रयोग किया गया था वह जानबूझकर किया गया कार्य था। (शोर एवं व्यवधान) निन्दा प्रस्ताव के बाद और बार–बार टोकने के बावजूद भी आप लोगों द्वारा इसी प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री जी से कहें कि महिला सदस्यों के खिलाफ प्रयोग किए गए आपत्तिजनक शब्दों को वापिस लें?(शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चन्द गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, कुलदीप शर्मा ने जैसा बोया है–वह वैसा ही काटेगा। जब उन्होंने इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था तो एक भी कांग्रेसी ने उसका विरोध न करते हुए, समर्थन ही किया था? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, क्या इसको वाजिब ठहराया जा सकता है कि एक मंत्री, महिला सदस्यों को * सदन से बाहर निकालने की बात कहे? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सुरजेवाला जी, मंत्री जी ने किसी महिला सदस्य के खिलाफ किसी प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आपत्तिजनक शब्दों को सदन की कार्यवाही से बाहर निकाला जाये?(शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्षः बहन जी, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इन आपत्तिजनक शब्दों को सदन की कार्यवाही का हिस्सा ही नहीं बनाया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, कुलदीप शर्मा ने कहा था कि जब वह स्पीकर हुआ करता था तो अनिल विज को * सदन से बाहर निकाल दिया करते थे। क्या इस तरह की लैंग्वेज एक पूर्व स्पीकर को शोभा देती है?(शोर एवं व्यवधान) आज भी सदन में कुलदीप शर्मा जी इस बात को खुद मान रहे हैं कि कल उन्होंने सदन में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। यह बात उन्होंने एक दफा नहीं चार दफा कही थी?(शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैंने वह शब्द वापिस ले लिए थे।(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष कुमार ग्रोवरः अध्यक्ष महोदय, इनका इलाज रामदेव से कराना पड़ेगा और उसी का तेल भी इनके कानों में डलवाना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, सरकार के मंत्री को अपने पद की मर्यादा का भी ख्याल नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) यह लोग रामदेव की पिट्ठू हैं, हम नहीं हैं और एक चीज याद कर लें मंत्री जी अपनी जुबान ठीक करके बोल?(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष कुमार ग्रोवरः अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उसके बावजूद उस व्यक्ति की सदन में बात की जा रही है। कांग्रेस ने तो रामदेव के साथ धोखा करने का काम किया था। जब सच बात कही जाती है तो इनको दर्द होता है और उंची आवाज में बोलने लगते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, मैं इसी तर्ज में बोलूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता इस तरह से बोलने के लिए? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, क्या यह सदन का मर्यादित आचरण है। सरकार के मंत्री तक सदन में अमर्यादित आचरण कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, यह बात सिखाई किसने है? आप लोग इस सदन के बहुत ही सीनियर मैम्बर्ज हैं और जब आप लोग ही गलत बात सिखायेंगे तो संभव सी बात दूसरे सदस्य भी इसी तरह का व्यवहार करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) क्या आप लोग अब सदन में सही बर्ताव कर रहे हैं?(शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि आप इस संबंध में अपनी रूलिंग दें? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, वर्तमान परिस्थिति में मेरी आप सब सत्ता पक्ष व विपक्ष से अनुरोध है कि दोनों पक्षों में से कोई भी अपनी हदें पार न करे। सत्ता पक्ष व विपक्ष कोई भी अनपार्लियामैंटरी शब्दों का प्रयोग न करे। यदि किसी की भी तरफ से अनपार्लियामैंटरी शब्दों का प्रयोग किया जायेगा तो वह गलत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चन्द गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य इस सदन का सदस्य नहीं है उसके बारे में इस सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को उनके द्वारा कहे गए शब्दों को वापिस लेना पड़ेगा और अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए माफी मांगनी पड़ेगी।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिये, मेरी आप सभी कांग्रेस के साथियों से अनुरोध है कि आप सभी अपनी सीटों पर जाईये और वहीं से अपनी बात रखिये। निःसंदेह आपकी किसी बात की कोई भी अनदेखी नहीं की जायेगी।(शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, हमारा अनुरोध है कि मत्री जी के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव लाया जाये और उनसे, उनके द्वारा कहे गए शब्दों के लिए माफी मंगवाई जाये। (शोर एवं व्यवधान) हम अपनी सीटों पर जाते हैं लेकिन यदि हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम फिर अपनी सीटों से खड़ें हो जायेंगे। इस समय हम किसी अन्य की बात नहीं सुनेंगे केवल आपकी बात ही सुनेंगे।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः रणदीप जी, आप प्लीज बैठिए। आप बहुत अनुभवी सदस्य हैं, निःसंदेह आपको दोबारा से उठकर बोलने से कोई नहीं रोक सकता।(शोर एवं व्यवधान)

(इस समय श्री अध्यक्ष के आश्वासन पर इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य अपनी–अपनी सीटों पर चले गए और वहीं से सत्ता पक्ष के सदस्यों पर आरोप–प्रत्यारोप लगाने लगे।)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, बाबा रामदेव सदन में उपस्थित नहीं हैं। उसके बारे में कांग्रेस के लोगों ने गलत शब्दों का प्रयोग किया है। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सत्ता पक्ष व विपक्ष के लोगों से आग्रह है कि वे सभी शांत हो जाये और अपनी सीटों पर बैठें।(शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, आपने हमें यह आश्वासन दिया है कि कांग्रेस के सदस्य अपनी सीटों पर जाकर अपनी बात कहें और आप हमारी बात सुनेंगे। हम आपका सम्मान करते हैं । (शोर एवं व्यवधान) आप हमारे बुजुर्ग हैं।(शोर एवं व्यवधान) आप एक बार हमारी बात तो सुनिए। (शोर एवं व्यवधान) आप इतना पक्षपात पूर्ण रवैया मत अपनाईये। (शोर एवं व्यवधान) You are the custodian of the House. आपको हमारी बात सुननी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, एक सम्मानित मंत्री जिनका हम बड़ा आदर करते हैं वह इस तरह के अनपार्लियामैंटरी शब्दों का प्रयोग करे, बहुत गलत बात है। (शोर एवं विघ्न)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, ...(शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, क्या यह कोई तरीका है?(शोर एवं व्यवधान) क्या हाउस इस तरह चला करता है? (शोर एवं व्यवधान) आपने मुझे बोलने के लिए परमिट किया है और माननीय वित्त मंत्री जी बीच में उठकर बोलने लग गए हैं? (शोर एवं व्यवधान) Have you not permitted me? आपने मुझे बोलने के लिए परमिट किया है तो क्या स्पीकर की रूलिंग का भी कोई महत्व नहीं है।(शोर एवं व्यवधान) जब आपने मुझे बोलने के लिए परमिट किया है तो वित्त मंत्री जी बीच में उठकर क्यों बोलने लग गए हैं?(शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ एक लाईन का निवेदन है और उसके बाद मैं अपनी सीट पर बैठ जाउंगा।(शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए परिमट किया है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः रणदीप जी, यदि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि वे एक लाईन में अपनी बात पूरी कर देंगे तो एक बार उन्हें अपनी बात कह लेने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रख लेना?(शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय साथी श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी सदन में बहुत कम आये हैं। आपने जिस प्रकार बड़े ही सौहादपूर्ण वातावरण में सदन की कार्यवाही को चलाया है, इस चीज का ज्ञान उनकी जानकारी में नहीं है। मैं उनकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि सदन में एक बार भी ऐसा समय नहीं आया जब कभी आपकी तरफ से सदन में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया हो? (शोर एवं व्यवधान) मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आपकी तरफ से कभी भी पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया गया है? उनके द्वारा चेयर के विरूद्ध इस प्रकार के आक्षेप लगाना गलत बात है? (शोर एवं व्यवधान) उनकी तरफ से चेयर के विरूद्ध इस प्रकार के आक्षेप नहीं लगाने चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य एक बार फिर से वैल में आ गए और श्री अध्यक्ष के साथ तर्क–वितर्क करने लगे।)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, आपका सत्ता पक्ष पर नियंत्रण नहीं है। सत्ता पक्ष के लोग चेयर को कुछ भी नहीं समझते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के सदस्य चेयर के बारे में टिप्पणी करते हैं और स्वयं चेयर को कुछ नहीं समझते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के सदस्य हमें सलीका ना सीखाएं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के सदस्य चेयर को धमकी दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) आज सदन में गैस्ट के तौर पर आएं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सुरजेवाला जी, मुझे लगता है कि आपके पास कहने के लिए कोई बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मैं सुरजेवाला जी को कहना चाहता हूं कि वे सदन में हर रोज आयें और यह देखें कि चेयर की तरफ से हाउस कैसे चल रहा है। पिछले 10 वर्षों का इतिहास तो आपको मालूम ही होगा कि कैसे सदन चलाया जाता था।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, पहले आप माननीय मंत्री जी पर नियंत्रण कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यगण, कृपया करके बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं। आप विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों के अधिकारों के सरंक्षक भी हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें मालूम है कि आपकी एक नजर सत्ता पक्ष की तरफ जा रही है परंतु फिर भी हम चेयर से उम्मीद रखेंगे कि एक नजर विपक्ष की तरफ भी जरूर रखेंगे। हमारे अधिकारों का हनन नहीं करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी): अध्यक्ष महोदय, सुरजेवाला जी ने पंजाब में जाकर कहा था कि एस.वाई.एल. कैनाल का एक बूंद पानी भी हरियाणा में नहीं जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, बीच में टोकने का यह क्या तरीका है? (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यदि कोई भी सदस्य आपकी बात ही नहीं सुनता तो इस चेयर पर भी एक प्रश्न चिन्ह् लगता है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सदन से वॉक–आउट करना हर माननीय सदस्य का अधिकार होता है। एक दलित महिला सदस्या जो इस सदन की पूर्व मंत्री रही है और फिर एक और दलित सदस्या को * पकड़कर सदन से बाहर करने की धमकी दी जा रही है। (शोर एवं व्यवधान) इससे ज्यादा इस हाउस का अपमान नहीं हो सकता। (शोर एवं व्यवधान) हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष कुमार ग्रोवरः अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इस पर माफी मांगे। (शोर एवं व्यवधान) इस तरह से हाउस की कार्यवाही नहीं चलेगी। (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री मनीष कुमार ग्रोवरः अध्यक्ष महोदय, किसी भी महिला को नहीं कहा गया है। (शोर एवं व्यवधान) सुरजेवाला जी आज सदन में आकर सदन को गुमराह कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा अपमान नहीं हो सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष कुमार ग्रोवरः अध्यक्ष महोदय, तीन साल में पहली बार सदन में आएं हैं और सदन को गुमराह कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) हमने सिर्फ करण सिंह दलाल जी को कहा है। जब विज साहब जवाब दे रहे थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चन्द गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, महिलाओं को आड़ बनाकर सदन को गुमराह किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, करण सिंह दलाल जी एक सीनियर नेता हैं। माननीय मंत्री जी ने आपके सामने स्वीकार कर लिया है कि करण सिंह दलाल जी को कहा है। (शोर एवं व्यवधान) जो इस सदन में सम्मानित सदस्य रहे हैं उनके बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष कुमार ग्रोवरः अध्यक्ष महोदय, सुरजेवाला जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को माफी मांगने के लिए आदेश दें। यह उचित नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) इस प्रकार से सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, किसी भी महिला के बारे में नहीं कहा है। यह सिर्फ सदन को गुमराह किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, यह बात तो हाउस को पता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, आप अपनी रूलिंग दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मेरी रूलिंग यह है कि दोनों ही पक्षो को संयम बरतना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) दोनो तरफ से आज और कल अभद्र शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष की तरफ से तीन बार अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया

गया है। आपको इस बात को स्वीकार करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) अभद्र शब्दों के इस्तेमाल से किसी भी माननीय सदस्य की गरिमा नहीं बढ़ती है। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय हमारे किसी भी माननीय सदस्य ने गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया।(विघ्न)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अगर 4 बार का चुना हुआ प्रतिनिधि इस प्रकार का व्यवहार करे तो यह ठीक बात नहीं है। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, इस तरह की अनर्गल भाषा का प्रयोग किया गया है जो सदन की गरिमा के खिलाफ है। (विघ्न)

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमती सीमा त्रिखा): अध्यक्ष महोदय, महिलाओं को ढाल बनाया जा रहा है।(विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, क्या महिला सदस्यों को गाली दिलवाएंगे। (विघ्न)

श्री नायब सैनीः अध्यक्ष महोदय, सुरजेवाला साहब के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव लाया जाना चाहिए।(विघ्न)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी): अध्यक्ष महोदय, हमारे कांग्रेस के सदस्य पहले माफी मांगे। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है। अगर किसी माननीय सदस्य को ऐसा लगता है तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं।(विघ्न)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी): अध्यक्ष महोदय, क्रांग्रेस पार्टी के सदस्यों को प्रदेश की ढाई करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिए। यह हरियाणा के हितों के साथ कुठाराघात है।(विघ्न)

श्री नायब सैनीः अध्यक्ष महोदय, ऐसे सदस्य के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव लेकर आएं। इन्होंने पंजाब में जाकर यह बयान दिया कि हरियाणा को एस.वाई. एल. नहर का एक बूंद पानी भी नहीं देंगे।(विघ्न)

श्री कृष्ण कुमार बेदीः अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य एस.वाई.एल. पर राजनीति कर रहे हैं। (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के सदस्य जाना चाहते हैं इनको जाने दें। (विघ्न)

श्री कृष्ण कुमार बेदीः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सदस्य अगले चुनाव में 15 से 5 पर आ जाएंगे जिस तरह 400 में से 40 रह गये हैं। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, बाबा रामदेव बी.जे.पी. का बाबा है।

श्री राम बिलास शर्माः स्पीकर सर, माननीय सुरजेवाला व किरण जी को कहें कि ये सभी माननीय सदस्य अपनी सीटों पर बैठ जायें।(विघ्न)

श्रीमती शकुंतला खटकः बेदी भाई, क्या यह जिम्मेदारी आपकी है ? (विघ्न)

श्री कृष्ण कुमार बेदी : हां । (विघ्न)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल साहब ने कल ऐसे ही कहा था।(विघ्न)

श्री कुलदीप शर्माः आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आर.एस.एस. की विचारधारा के कारण महात्मा गांधी का कत्ल हो गया। अगर आर.एस.एस. की विचारधारा नहीं होती तो महात्मा गांधी जी का कत्ल नहीं होता। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल वरिष्ठ नेता हैं इन्हें सदस्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. की सरकार के ढाई साल और बचे हैं।(विघ्न)

श्री कृष्ण कुमार बेदी : मैडम, मैं वायदा करता हूं। फिर इसी सदन में बैठूंगा।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, बाबा रामदेव बी.जे.पी. का बाबा है। (शोर एवं व्यवधान)

11:00 बजे **श्री राम बिलास शर्माः** स्पीकर सर, बाबा रामदेव पूरे देश के बाबा हैं।

श्री अनिल विजः करण सिंह जी, मैं आपका ईलाज मुफ्त में करवा दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप इतना अच्छा सदन चला रहे हैं। माननीय विपक्ष के नेता, माननीय कांग्रेस के नेता और हम सभी ने आज श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो कांग्रेस पार्टी के नेशनल लीडर हैं, उनका सदन में आने पर अभिनंदन किया। उनके सदन में आने पर यह हम सोच रहे थे कि आज तो सदन की कार्यवाही में चार चांद लगने वाले हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। (विघ्न)

श्री अनिल विज : राम बिलास शर्मा जी, चांद को ग्रहण लग गया।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कैसी भी भाषा बोल देते हैं, आप उन्हें बोलिए कि वे अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें।

श्री अध्यक्ष : सुरजेवाला जी, वे तो सदन की कार्यवाही के बारे में कह रहे हैं कि चांद में ग्रहण लग गया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, रणदीप सुरजेवाला जी का मैं बहुत रिगार्ड करता हूं। वे इस सदन में हर जिम्मेदारी को बड़े अच्छे ढंग से निभाते हैं। रणदीप जी के अब्बू जान चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी के साथ मैंने इस सदन में काम किया है। उनके रिगार्ड के प्रति हमारी कोई किसी तरह की दूसरी भावना नहीं है। मैंने सम्मानजनक भावना से खड़े होकर उनका स्वागत किया। स्पीकर सर, सदन में हम सब अपनी–अपनी पार्टी को रिप्रजेंट करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि ये सब कांग्रेस के जिम्मेदार विधायक हैं। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों आग्रह करता हूं कि वे सदन की कार्यवाही को चलने दें। किसी से जाने–अनजाने में कोई बात हुई हो तो उसको दरकिनार करें और कार्यवाही को आगे चलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

***1791 Sh. Jasbir Deswal. :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to regularize the services of Guest Teachers in State?

शिक्षा मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्रीमान जी, अतिथि अध्यापकों को नियमित करने का मामला ग्रुप बी व सी कर्मचारियों/मजदूरों को नियमित करने की नियमितीकरण नीति दिनांक 07.07.2014 के अन्तर्गत विचाराधीन है। परन्तु इस विषय पर अन्तिम निर्णय लम्बित मुकद्दमों के निपटान पर ही किया जा सकता है।

.....

Construction of Bye Pass

***1889.Sh. Kehar Singh. :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state the time by which the construction work of Bye-Pass of Hathin town in Hathin Assembly Constituency is likely to be started as the proposed Bye-Pass was announced by the Hon'ble Chief Minister in the year, 2015?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : श्रीमान् जी, भूमि–अधिग्रहण के अनुभाग 11 की अधिसूचना दिनांक 14.06.2016 को प्रकाशित कि जा चुकी हैं और अनुभाग 19 की अधिसूचना तैयार कि जा रही है। यद्यपि, वर्तमान में कार्य के आरम्भ करने का समय नहीं दिया जा सकता।

.....

Number of Announcements

***1893. Sh. Naresh Kaushik. :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of announcements have been approved out of the announcements made on dated 24th July, 2016 in Bahadurgarh togetherwith the details of the

announcements on which the work is in progress alongwith the announcements which have been fulfilled and the time by which the work on the remaining schemes is likely to be completed.

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 24 जुलाई, 2016 को की गई सभी 16 घोशणाएं मुख्यमंत्री जी द्वारा मंजूर की गई हैं। इनमें से एक घोशणा जो कि हुडा स्टेडियम का नाम बदलकर डा0 भीम राव अम्बेडकर के नाम पर रखने बारे दिनांक 28.10.2016 को पूर्ण हो चुकी है तथा वर्तमान में 2 घोशणाऐं जोकि बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांवो के विकास कार्यों के लिए 10.00 करोड रू0 की राषि जारी करने (10.37 करोड रू0 की राषि 13.01.2017 को 65 कार्यों के लिए स्वीकृत की जा चुकी हैं) तथा बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 10 गांवों में आधा एकड जमीन पर ग्राम सचिवालय बनाने हेतू कार्य प्रगति पर है। शेष 13 घोशणाओं में से 11 घोशणाऐं विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वित की जा रही है जैसे भूमि का विष्लेशण, सीमांकन, अनुमानित राषि का ब्यौरा तैयार करके स्वीकृत करवाना तथा राषि जारी करना। जहां तक 2 घोशणाओं का संबंध है तो उनपर 11. 68 करोड रू0 की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। प्रत्येक घोषणा के जल्द निष्पादन के लिए समय–समय पर सभी सम्बन्धित विभागों की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

.....

To Open a Bus Depot

***1901. Shri. Naseem Ahmed. :** Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open Bus Depot in Firozpur Jhirka Assembly Constituency; if so, the time by which it is likely to be opened?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : श्रीमान् जी, नहीं।

.....

***2001. Sh. Rajdeep Phogat. :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the time by which the construction of the Park in Dadri City is likely to be started in the memory of former Chief Minister Master Hukum Singh as per the announcement of the Hon'ble Chief Minister of Haryana?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री कविता जैन) : श्री मान् जी, मुख्य मंत्री की घोषणा दिनांक 27.02.2015 के अनुसार सरकार ने चरखी दादरी के रोज गार्डन का नाम पूर्व मुख्य मंत्री, स्वर्गीय श्री हुकम सिंह के नाम पर रखे जाने का अनुमोदन कर दिया है।

.....

To Take Action Against Kapur Industry

***1935. Sh. Ravinder Machhrouli. :** Will the Agriculture Minister be pleased to state-

(a) whether the Government is aware of the fact that due to installation of 9-10 tubewells fitted with the 35HP/40HP Motor in the Kapur Industry (Textile Mill) in Samalkha Assembly Constituency, the under ground water level has depleted very low in the adjacent villages; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to take action against the abovesaid Mill togetherwith the details thereof?

कृषि मन्त्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्री मान्जी, यह ब्यान सदन के पटल पर रखा गया है।

ब्यान

(क) यह तथ्य है कि समालखा ब्लॉक, जिला पानीपत, हरियाणा में भू–जल स्तर घट रहा है। कृषि, पीने के पानी और घरेलू उपयोग तथा उद्योगिक क्षेत्रों के संयुक्त भू–जल

निकासी के कारण भू–जल स्तर घट रहा है। कृषि विभाग के नोडल अधिकारी (जल वैज्ञानिक, भू–जल कोष, कृषि एवं किसान कल्याण, करनाल) द्वारा कपूर उद्योग (कपड़ा मिल) का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि मील में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 5 नलकूप लगाए गए है, जिसमें 3 नलकूप 15 एच0पी0 की बिजली मोटर तथा 2 नलकूप 20 एच0पी0 की बिजली की मोटर के साथ लगे हुये है। भू–जल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2011 के अनुसार कुल भू–जल निकासी में से 0.75% औद्योगिक क्षेत्रों जबकि 99.25% निकासी कृषि/सिंचाई प्रयोग हेतु की गई है।

(ख) हरियाणा राज्य में नोटिफाईड ब्लॉक में भू–जल नियमन का कार्य केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सी0जी0डब्ल्यू0ए0), नई दिल्ली द्वारा जिले के प्रशासनिक मुखिया (उपायुक्त 'प्राधिकृत अधिकारी' के रूप में) तथा संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाता है। भू–जल विकास में पाई जाने वाले गैर कानूनी मामलों में उपायुक्त सी0जी0डब्ल्यू0ए0, नई दिल्ली के दिशा–निर्देश के अनुसार कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। भू–जल विकास नियमन करने हेतू वर्ष 2006 में समालखा ब्लॉक जिला, पानीपत को सी0जी0डब्ल्यू0ए0, नई दिल्ली द्वारा नोटिफाईड किया किया गया है। कपूर उद्योग (कपड़ा मिल) में समालखा ब्लॉक की अधिसूचना से पहले वर्ष 2000 में अस्तित्व में आया था और सभी नलकूप 2000–2001 के दौरान स्थापित किये गये थे।

.....

Number of Schools In Haryana

***1961 Smt. Geeta Bhukkal. :** Will the Education Minister be pleased to state: -

(a) the district wise number of Schools (Primary Middle, High and Sen. Sec. Schools) in state of Haryana ;

(b) district wise details of Schools (Primary, Middle High, and Senior Secondary Schools) opened, closed and upgraded from November, 2015 till to date; and

(c) the action/steps being taken to improve the buildings of Government Schools?

शिक्षा मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा): श्रीमान जी,

(क) हरियाणा राज्य में जिलानुसार प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और वरिश्ठ माध्यमिक विद्यालयों का विवरण परिषिश्ट–I के रूप में संलग्न है।

(ख) नवम्बर 2015 के बाद कोई भी राजकीय विद्यालय खोला नहीं गया है। एक नया राजकीय आदर्ष संस्कृति वरिश्ठ माध्यमिक विद्यालय, सैक्टर–55, फरीदाबाद और एक नया राजकीय कन्या वरिश्ठ माध्यमिक विद्यालय, ढिगांव जाटां, भिवानी, नवम्बर 2015 के बाद खोले गए। 1 कि0मी0 की परिधि में 1/2/3 अध्यापकों और 60 विद्यार्थियों से कम प्रवेष वाले 368 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को 168 विद्यालयों में समेकित कर दिया गया है और एक ही परिसर में चलने वाले 8 विद्यालयों को 4 विद्यालयों में समेकित कर दिया गया है परन्तु कोई भी राजकीय उच्च/वरिश्ठ माध्यमिक विद्यालय नवम्बर 2015 के बाद बंद नहीं किया गया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटापुरी, खण्ड जाटू साणा, जिला रेवाड़ी और राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुमोखेड़ी, खण्ड जाटू साणा, जिला रेवाड़ी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुमोखेड़ी और जाटूसाणा के रूप में स्तरोन्नत कर दिया गया है और आगामी षैक्षणिक सत्र में 16 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालय के स्तर तक स्तरोन्नत किए जाने की संभावना है।

(ग) विभाग के बजट में किए गए 30 करोड़ रूपए के बजट प्रावधान में से 28.5 करोड़ रूपए राजकीय प्राथमिक विद्यालयों व राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की मुरम्मत और रखरखाव के लिए जिला मौलिक षिक्षा अधिकारियों को जारी किए गए हैं। 17 करोड़ रूपए की राषि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण और मुरम्मत के लिए राज्य परियोजना अधिकारी, हरियाणा विद्यालय षिक्षा परियोजना परिशद् और जिला मौलिक षिक्षा अधिकारियों को जारी की गई है।

शिक्षा विभाग ने राजकीय विद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। चालू वित्त वर्श 2016–17 में प्लान, नॉन प्लान, एस0एस0ए0 और नाबार्ड (NABARD) योजना के माध्यम से विद्यालय भवनों की मुरम्मत एवं रखरखाव के लिए और भवनों के निर्माण के लिए कुल 137.56 करोड़ रूपए की ग्रांट जारी की गई है।

23 फरवरी 2017 अनुसार राजकीय विद्यालयों का कैटेगरी वाईज विवरण								
अम्बाला	481	138	72	83				**774**
भिवानी	657	156	131	177	2	2	1	**1126**
फरीदाबाद	239	42	38	51				**370**
फतेहाबाद	386	86	69	75	5	5		**626**
गुड़गांव	363	91	48	70				**572**
हिसार	504	98	134	134	6	4		**880**
झज्जर	297	53	44	132				**526**
जींद	432	98	108	101	3	3		**745**
कैथल	372	73	53	93	3	3		**597**
करनाल	488	122	76	92				**778**
कुरुक्षेत्र	489	185	49	65				**788**
महेन्द्रगढ़	472	132	50	94	1	1		**750**
नूंह मेवात	481	262	39	41	5	5		**833**
पलवल	360	143	50	53	4	1		**611**
पंचकूला	274	82	23	38				**417**
पानीपत	244	56	31	90	1			**422**
रिवाड़ी	403	98	60	89				**650**
रोहतक	211	36	45	117				**409**
सिरसा	524	122	96	86	6			**834**
सोनीपत	427	81	82	127				**717**
यमुनानगर	601	238	56	55				**950**
कुल	**8705**	**2392**	**1354**	**1863**	**36**	**24**	**1**	**14375**

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

To open an ITI in the village Madhmadhvi and Manheru

464. Sh. Ghanshyam Saraf. : Will the industrial training Minster be pleased to state whether it is a fact that an announcement was made by the Hon'ble Chief Minister to open and ITI in Madhmadhvi and Manheru villages of Bhiwani Assembly constituency: if so, the time by which is it likely to be opened?

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री (श्री विपुल गोयल) : श्रीमान जी,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गांव माधमधवी तथा मनेहरू विधानसभा क्षेत्र भिवानी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने बारे कभी भी कोई घोषणा नहीं की गई है

गांव माधमाधवी तथा मनहेरू, भिवानी जिले के भिवानी विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के भिवानी विकासखण्ड में स्थित है और गांव माधमाधवी तथा मनहेरू, में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने बारे कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

माधमाधवी तथा मनहेरू से 30 कि0 मी0 के दायरे में 2 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व 5 प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निम्नवर्णित चल रहे है :–

क0	विकासखण्ड का नाम	संस्थान का नाम	स्वीकृत सीटें	गांव माधमाधवी से अनुमानित दूरी (कि0मी0)	गांव मनहेरू से अनुमानित दूरी (कि0मी0)
1.	भिवानी	1. राजकीय औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान, भिवानी	795	17	17
		2. राजकीय औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान (महिला), भिवानी	292	17	17
		3. आर्दश मैडीकल प्राईवेट औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान, उत्तम नगर, भिवानी	277	17	17
		4. रवि प्राईवेट औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान, अटेलीकलां, भिवानी	236	22	27
		5.बी0टी0आई0एस0 प्राईवेट औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान, भिवानी	105	17	17
		6. महाऋषि दयानन्द प्राईवेट औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान, निमरीवाली, भिवानी	200	15	13
		7. बालाजी प्राईवेट औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान, कुसुभी मोड, गांव देवसर, भिवानी	208	27	25

Reconstruction of Roads

455. Shri Rajdeep Phogat. : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state the time by which the reconstruction work of the following roads is likely to be started which have been damages completely in Dadri assembly constituency :-

(a) Sanjarwas to Achina via Ranila;

(b) Ranila to Oun;

(c) Dadri, Bhiwani main road to Charkhi Link road;

(d) Imlota to Kanheti;

(e) Dadri, Rohtak main road to Kamod Bus stand;

(f) Village Loharwara to Bhiwani via Sanwar, Hindol; and

(g) Dadri Bhiwani main road to Akhtyarpura?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : श्रीमान जी, सड़क अनुसार वर्णन सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

क्र0 सं0	सड़क का नाम	सड़क भाग	लम्बाई कि0मी0 में	मलकियत	उत्तर
क	सांजरवास से अचीना वाया रानीला	–	10.19	लोक निर्माण विभाग	नहीं, श्रीमान् जी। सड़क की स्थिति सन्तोषजनक है। यद्यपि, सड़क का मजबुतीकरण विचाराधिन है। वर्तमान में, सड़क के पुनर्निमार्ण की समय सीमा नही दी जा सकती।
ख	रानीला से ऊन	–	5.40	हरियाणा राज्य कृषि विप्णन बोर्ड़	हां, श्रीमान् जी। इस सड़क की मरमत हरियाणा राज्य कृषि विप्णन बोर्ड़ द्वारा 30.03.2017 तक किए जाने की सम्भावना है।
ग	दादरी भिवानी मुख्य सड़क से चरखी योजक सड़क	–	1.10	लोक निर्माण विभाग	हां, श्रीमान् जी। इस सड़क की मरमत का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा आबटिंत कर दिया है तथा इसे 30.06.2017 तक पूर्ण किए जाने की सम्भावना है।
घ	इमलोटा से कनहेटी	कि0मी0 0.00 से 0.90	0.90	हरियाणा राज्य कृषि विप्णन बोर्ड़	हां, श्रीमान् जी। इस सड़क की मरमत हरियाणा राज्य कृषि विप्णन बोर्ड़ द्वारा 30.03.2017 तक किए जाने की सम्भावना है।
		कि0मी0 0.90 से 3.76	2.86	हरियाणा राज्य कृषि विप्णन बोर्ड़	नहीं, श्रीमान् जी। सड़क की स्थिति सन्तोषजनक है।

ड	दादरी रोहतक मुख्य सड़क से कमोद बस स्टैण्ड	–	1.00	लोक निर्माण विभाग	हां, श्रीमान् जी। इस सड़क की मरमत का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा आबटिंत कर दिया है तथा इसे 30.06.2017 तक पूर्ण किए जाने की सम्भावना है।
च	गाँव लोहरवाडा से भिवानी वाया सांवड , हिन्डोल	लोहरवाडा से सांवड़	10.80	लोक निर्माण विभाग	हां, श्रीमान् जी। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस सड़क की मरमत का कार्य प्रगति पर है। तथा इसे 30.06.2017 तक पूर्ण किए जाने की सम्भावना है।
		सांवड से मानेहरू	9.10	लोक निर्माण विभाग	श्रीमान् जी। सड़क कि स्थिति सन्तोषजनक है। गाँव मानेहरू मे निर्मित क्षेत्र के सिवाय सड़क की आगामी वित्तिय वर्ष 2017–18 में मरमत किए जाने की सम्भावना है।
		मानेहरू से कोंट	9.20	लोक निर्माण विभाग	नही, श्रीमान् जी। सड़क की स्थिति सन्तोषजनक है।
		कोंट से भिवानी	3.5	लोक निर्माण विभाग	नही, श्रीमान जी। सड़क कि स्थिति सन्तोषजनक है।
छ	दादरी भिवानी मुख्य सड़क से अख्तयार पुरा	दादरी भिवानी मुख्य सड़क से पैन्तावास कलां	0.48	लोक निर्माण विभाग	हां, श्रीमान् जी। इस सड़क की मरमत का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा आबटिंत कर दिया है तथा इसे 31.05.2017 तक पूर्ण किए जाने की सम्भावना है।
		पैन्तावास कलां से अख्तयारपुरा	1.80	लोक निर्माण विभाग	नही, श्रीमान् जी। सड़क की स्थिति सन्तोषजनक है।

To Set Up a 33 K.V. Sub-Station

465. Shri Ghanshyam Saraf. : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that an announcement was made by the Hon'ble Chief Minister to set up a 33 K.V. Sub-Station in village Madhmadhvi (Manheru) of Bhiwani Constituency; if so, the time by which it is likely to be set up ?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, नहीं। इसलिए, प्रश्न का अन्य भाग उठता ही नहीं है।

.....

To Lay Down Pipe Line

456. Shri Rajdeep Phogat. : Will the Minister of State for public Heatth Engineering be pleased to state the time by which the work to lay down pipe line is likely to be started from Loharu canal to water Houses of villages Misri, Lamba, Kohalwas and Sanwar of Dadri Assembly Constituency ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (डा0 बनवारी लाल) : श्री मान् जी, लोहारू फीडर से मिसरी तथा लाम्बा गांवों के दो जलघरों के लिए कच्चे पानी का प्रबन्ध करने के लिए 219.70 लाख रूपये की लागत का एक अनुमान पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। लोहारू फीडर पर नहरी पानी को पम्प करने के लिए बनाई जाने वाली संरचनाओं के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध न होने के कारण इस अनुमान के विरूद्ध कार्य रुका हुआ है। पमपिंग स्टेशन के लिए भूमि मिलने के पश्चात कार्य तुंरत आरंभ कर दिया जाएगा। लोहारू फीडर से कोहलवास तथा सांवर गांवों के जलघरों तक पाईप लाईन बिछाने की कोई प्रस्ताव नहीं है।

.....

To Open A Government Girl School

463. SH. Ghanshyam Saraf. : Will the Education Minister be pleased to state whether it is a fact that an announcement was made by the Hon'ble Chief Minister to open a Government Girls School in Bhiwani; if so, the time by which it is likely to be opened ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : हाँ, श्रीमान जी। चूंकि प्रस्तावित विद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, इसलिए जिला प्रषासन के माध्यम से भूमि उपलब्धता की संभावना को तलाषा जा रहा है। जैसे ही भूमि उपलब्ध होगी, प्रस्तावित विद्यालय को स्थापित कर दिया जाएगा।

.....

बैठकों का स्थगन

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अभी राम बिलास शर्मा जी कह रहे थे कि बड़े दिनों बाद हमने विधानसभा में जो सीनियर सदस्य हैं उनका स्वागत किया है। शर्मा जी को स्वागत करने से पहले एक बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए था कि पंजाब में जब चुनाव हो रहे थे और उस समय अलग–अलग पार्टियों का मैनीफेस्टो जब जारी हो रहा था ..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इनको जो व्यक्तिगत तकलीफ है वह मैं खत्म नहीं कर सकता । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इनको सदन से बाहर निकाला जाये । यह प्रदेश का गुनाहगार है । (शोर एवं व्यवधान) ऐसे व्यक्ति के साथ दूसरे सदस्यों को नहीं बैठना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान) राम बिलास शर्मा जी ने इनका सदन में आने पर स्वागत करके सदन का अपमान करने का काम किया है । (शोर एवं व्यवधान) इस आदमी ने सारे हरियाणा के हित्तों को बेच दिया । (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नैशनल लोक दल के सदस्य अपनी–अपनी सीटों पर खड़े होकर नारे–बाजी करने लगे ।)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनी जाये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप सभी बैठें । (शोर एवं व्यवधान) किरण जी आप भी बैठें । (शोर एवं व्यवधान) रणदीप जी आप भी बैठें । (शोर एवं व्यवधान) मैंने अभय जी को एक मिनट का समय दिया है । (शोर एवं व्यवधान) पहले आप उनकी बात सुनो । उसके बाद आपकी बात सुनी जायेगी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप इनको बैठायें । मैं आपकी इजाजत से खड़ा हूं । (शोर एवं व्यवधान) जो लोग प्रदेश के गुनाहगार हैं उन्हें सदन से बाहर निकाला जाये । (शोर एवं व्यवधान) ये एस.वाई.एल. कनाल के गद्दार हैं । (शोर एवं व्यवधान) यह एस.वाई.एल. के विरोधी हैं और हरियाणा का विरोधी है । (शोर एवं व्यवधान) इनको सदन से बाहर करना चाहिए ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इनको सदन से बाहर निकाला जाये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रणदीप जी, प्लीज आप बैठें । आपको अपनी बात कहने का अवसर दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इनको पहले सदन से बाहर निकाला जाये। ये प्रदेश के गुनाहगार हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रणदीप जी, प्लीज आप बैठें । मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा । (शोर एवं व्यवधान) रणदीप जी आप बैठें । उसके बाद इनैलो के साथी भी बैठ जायेंगे । यदि आपको अभय जी की बात पर कुछ आपत्ति हो तो आप बोल लेना । (शोर एवं व्यवधान) सारा सदन एक ही है, प्लीज आप बैठें । (शोर एवं व्यवधान) रणदीप जी, आप बैठें । उसके बाद मैं सभी को बैठा दूंगा । उनको बैठाना मेरी जिम्मेवारी है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में इनके बारे में अभी सारी जानकारी देता हूं और इनकी पोल खोलूंगा । (शोर एवं व्यवधान) उसके बाद ये मेरी बात का जवाब दे दें । मुझे कोई दिक्कत नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ...(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रणदीप जी, प्लीज आप बैठें । अगर आपको इनकी बात सही नहीं लगे तो उसका जवाब आप बाद में दे देना । (शोर एवं व्यवधान) अगर आपको लगता है कि इनकी बात सही नहीं है तो आप जवाब दे सकते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इनैलो पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये प्रदेश के गद्दार हैं इन्हें सदन से बाहर निकाला जाये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रणदीप जी, प्लीज, आप बैठें । यह बात केवल एक–दो मिनट में खत्म हो जायेगी। ऐसे तो बहुत समय लगेगा । (शोर एवं व्यवधान) एक मिनट में ये

अपनी बात कह लेंगे उसके बाद एक मिनट में आप जवाब दे देना । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः स्पीकर सर, पहले आप श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला को सदन से बाहर निकालें तभी हम सदन की कार्यवाही आगे चलने देंगे। (शोर एवं व्यावधान)

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य अपनी–अपनी सीटों पर खेड़े होकर रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सदन 20 मिनट के लिए स्थगित किया जाता है।

(तत्पश्चात् सदन 20 मिनट के लिए स्थगित हुआ तथा दोपहर 11:30 बजे पुनः समवेत हुआ)

(इस समय उपाध्यक्ष महोदया चेयर पर आसीन हुई।)

उपाध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण, अब सदन पुनः 30 मिनट के लिए स्थगित किया जाता है।

(तत्पश्चात् सदन 30 मिनट के लिए पुनः स्थगित हुआ तथा दोपहर 12:00 बजे पुनः समवेत हुआ।)

इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्यगण को नेम करना/बैठक का स्थगन

12:00बजे

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हाउस को एडजर्न करने के बाद अब हम दोबार बैठे हैं । मेरा सबसे अनुरोध है कि विपक्ष की दोनों पार्टियों के जो भी सदस्य सदन में बैठे हैं वह इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें । जिससे सदन की कार्यवाही में इतना बड़ा व्यवधान डले । इसलिये मेरा अनुरोध है कि कोई भी सदस्य अन पार्लियामैंट्री शब्द न कहे क्योंकि ऐसे शब्द आपकी गरिमा के अनुकूल भी नहीं है । अगर आप कोई ऐसा शब्द कहते हैं और हमें मजबूरन कहना पड़ता हैं कि इस शब्द को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए । इसका मतलब यह है कि वह शब्द आपकी गरिमा के अनुकूल नहीं है । इसलिये मेरा दोनों ही पक्ष, सत्ता पक्ष के सदस्यों से और विपक्ष के सदस्यों से निवेदन है कि आप सही शब्दों का प्रयोग करें क्योंकि हरियाणा की ढ़ाई करोड़ जनता ने हमें यहां चुनकर भेजा है । उनका आपके प्रति यही विश्वास है कि आप यहां सदन में उन्हीं विषयों की चर्चा करेंगे जो उनके हित में हैं । अगर हम इस तरह से छोटी–छोटी बातों पर हाउस की गरिमा

को भंग करेंगे तो मेरे ख्याल से उनको भी कुछ निराशा होगी । मेरा बस आपसे इतना ही निवेदन है कि अब आगे से ऐसा प्रदर्शन न करें ।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आप अभी बैठिए । माननीय सदस्यगण मुझे श्री जाकिर हुसैन विधायक तथा दो अन्य विधायकों (श्री रणबीर सिंह गंगवा तथा श्री केहर सिंह) द्वारा प्रदेश में गऊ तस्करी बारे ध्यानाकर्षण सूचना नं0 9 प्राप्त हुई है । मैंने उसको स्वीकार कर लिया है । श्री जाकिर हुसैन, विधायक प्रथमहस्ताक्षरी होने के नाते अपनी सूचना पढ़ें । सदस्य के द्वारा अपनी सूचना पढ़ने के बाद श्री रणबीर सिंह गंगवा, विधायक, श्री केहर सिंह, विधायक भी इस पर सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं। **(शोर एवं व्यवधान)**

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, आपने नेता प्रतिपक्ष को पहले ही बोलने का समय दिया हुआ है इसलिए आप पहले उन्हें अपनी बात कह लेने दें। **(शोर एवं व्यवधान)**

श्री अध्यक्ष : मैंने नेता प्रतिपक्ष को जो समय दिया था वह हाउस एडजर्न होने से पहले दिया था । उसके बाद हाउस एडजर्न हो गया था। उसके बाद फिर पहले वाला कोई समय नहीं होता । अभी जब आप बजट पर बोलोगे तब आप अपनी बात रख लेना । (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, यह नेता प्रतिपक्ष हैं इनकी बड़ी जिम्मेवारी है । आपने नेता प्रतिपक्ष को बोलने का समय दिया था । आप इनको बोलने की इजाजत दें । (शोर एवं व्यवधान) आप इनकी बात तो सुन लो । इनको दो–चार मिनट अपनी बात तो कहने दो । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप उनको बोलने की इजाजत दें क्योंकि आपने पहले इनको बोलने की इजाजत दे रखी है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जाकिर हुसैन जी, आप अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ेंगे या मैं अपनी अगली कार्यवाही शुरू करूं । (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, बोलने को तो हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी बोलेंगे । लेकिन पहले आपने नेता प्रतिपक्ष को समय दिया था । आप इनको बोलने की इजाजत दें । (शोर एवं व्यवधान) हमारी जरूरी मांग है ।

श्री अध्यक्ष : अभी जब आप बजट पर बोलोगे तब आप अपनी बात रख लेना । देखिये जब हाउस एडजर्न कर दिया तो फिर क्या इजाजत रह गई ? (शोर एवं व्यवधान) आपकी मांग तो ठीक है लेकिन उस मांग को मानना या न मानना तो मेरी मर्जी है ।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी आपने बजट पर काफी समय बोलना है तब आप अपनी बात रख लेना । उस समय मैं आपको समय दे दूंगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी हाउस के अन्दर एक बात कही कि हाउस के अन्दर एक–दूसरे सदस्य पर कोई ऐसी टिप्पणी ना करें जिसकी वजह से हाउस का माहौल खराब हो ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, आपने हाउस में यह बात कही थी कि इस हाउस में एक दूसरे पर कोई ऐसी टिप्पणी न करें जिसकी वजह से हाउस का माहौल खराब हो और आपने यह भी कहा था कि आपको उन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए जो प्रदेश के साथ जुड़े हुए हैं । मैंने जिस वक्त खड़े होकर आपसे बोलने के लिए समय मांगा था उस वक्त जब आपने समय दिया तो वह एस.वाई. एल. कैनाल के विषय पर दिया था । यह इस प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ विषय है और एस.वाई.एल. कैनाल हमारे प्रदेश की जीवन रेखा है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, अब स्थिति बदल चुकी है । हाउस एडजर्न होने के बाद स्थिति बदल चुकी है । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, वह व्यक्ति अभी भी यहीं बैठा हुआ है । (विघ्न) वह आदमी अभी भी हाउस में मौजूद है । हम इस विषय पर आपसे जवाब लेना चाहेंगे क्योंकि यह हरियाणा प्रदेश के हित का मामला है । (विघ्न) हम इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जाकिर हुसैन जी, आपके कॉलिंग अटैंशन मोशन को मैंने स्वीकार कर लिया है । अतः अब आप उसे पढ़िये । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस बात का जवाब आना चाहिए क्योंकि इन्होंने पंजाब में जाकर हरियाणा के हितों को बेचने का काम किया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष जी, मैं अपनी कॉलिंग अटैंशन मोशन बाद में पढ़ूंगा । पहले आप नेता प्रतिपक्ष श्री अभय सिंह चौटाला की बात सुनिये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं जाकिर हुसैन जी, आप अपना कॉलिंग अटैंशन मोशन पढ़िये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप पहले नेता प्रतिपक्ष की बात सुनिये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जाकिर हुसैन जी, अगर आप अपने कॉलिंग अटैंशन मोशन पर नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा प्रारम्भ करवा दूंगा । (विघ्न)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष जी, आप हमारी बात सुनिये । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ होगा । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, आप हमारी बात सुनिये । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, अब आप प्लीज बैठ जाइये । ज्ञान चन्द गुप्ता जी, अब आप बजट पर चर्चा शुरू कीजिए ।

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नैशनल लोकदल के सभी सदस्यों ने अपनी सीटों पर खड़े होकर सदन में नारेबाजी करनी शुरू कर दी ।)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आपको इस विषय पर बोलने का समय दिया जाएगा । अब जीरो ऑवर नहीं है इसलिए आप बैठ जाइये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट 2017–18 के अनुमानों पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । मैं माननीय वित मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी को शानदार बजट प्रस्तुत करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं । (विघ्न)

श्री जाकिर हुसैन: अध्यक्ष महोदय, आप हमारे नेता की बात तो सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष : जसविन्द्र सिंह संधू अगर आप अपनी सीटों पर नहीं बैठते हैं तो मैं माननीय सदस्यों सर्वश्री अभय सिंह चौटाला, अनूप धानक, बलवान सिंह दौलतपुरिया, केहर सिंह, मक्खन लाल सिंगला, ओम प्रकाश बड़वा, परमिन्द्र सिंह ढुल, पिरथी सिंह, राजदीप सिंह फौगाट, राम चन्द कम्बोज, रणबीर गंगवा, रविन्द्र बलियाला, वेद नारंग और जाकिर हुसैन को नेम करता हूं और इन सभी से निवेदन करता हूं कि वे हाउस से बाहर चले जाएं ।

(इस समय इण्डियन नैशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने नारेबाजी की ।)

श्री अध्यक्षः आपको नेम किया जा चुका है इसलिए अब आप हाउस से बाहर चले जाएं

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के नेम किए हुए सभी सदस्य सदन से बाहर चले गए।)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन 15 मिनट के लिए ऐडजर्न किया जाता है ।

(The Sabha then adjourned at 12:09 P.M. and re-assembled at 12:24 P.M.)

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधान सभा के पूर्व विधायक श्री लीला राम गुज्जर वी.आई.पीज. गैलरी में सदन की कार्यवाही देखने के लिए आए हुए हैं। मैं सदन की तरफ से उनका अभिनन्दन करता हूँ।

.....

वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ एवं वित्त मंत्री द्वारा उत्तर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब श्री ज्ञान चंद गुप्ता, विधायक वर्ष 2017–18 के सामान्य बजट पर चर्चा का पुनरारम्भ करेंगे।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता (पंचकूला): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वर्ष 2017–18 सामान्य बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने 1 लाख करोड़ रूपये से ज्यादा का

ऐतिहासिक बजट सदन में पेश किया है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, पंजाब से बड़ा और प्रगतिशील बजट है। यह बजट कृषि, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, शिक्षा स्वास्थ्य महिला सशक्तिकरण युवा और भारतीय संस्कृती के विकास आधारित बजट है। अध्यक्ष महोदय, यह बजट पारदर्शी प्रशासन, जवाबदेही प्रशासन और भ्रष्टाचार प्रशासन की ओर व्यवस्था परिवर्तन है। हमारी सरकार ने जो पिछले दो वर्षों में कार्य किए हैं, जिस प्रकार से पारदर्शिता से कंप्यूट्राइजेशन और डिजिटलाईजेशन किया और उस कंप्यूट्राइजेशन के परिणाम बहुत अच्छे साबित हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, पहले जो पैंशन दी जाती थी, चाहे वह बुढ़ापा पैंशन हो, चाहे विधवा पैंशन हो और चाहे विकलांग पैंशन हो बहुत से लोग गलत तरीके से पैंशन ले रहे थे जो उसके हकदार नहीं थे। लेकिन कंप्यूट्राइजेशन की वजह से हर वर्ष में लगभग 571 करोड़ रूपये की सरकार के खजाने में वृद्धि हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी उपलब्धि कोई भी नहीं हो सकती है क्योंकि 571 करोड़ रूपये उन लोगों को दिए जा रहे थे, जो पैंशन के हकदार नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, आज पारदर्शिता के तरीके से एच.सी.एस. और पुलिस विभाग में जो भर्तियां हुईं और ऑनलाइन टीचर्स की ट्रांसफर्ज हुईं हैं, वह अपने आप में एक मिसाल है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा को बधाई देता हूँ कि उनके सहयोग से सिर्फ एक क्लिक से हजारों टीचर्स की ट्रांसफर्स हुई है, जिसका सभी अध्यापकों ने स्वागत किया है। पहले अध्यापक अपनी ट्रांसफर के लिए जगह–जगह घूमता–फिरता रहता था और लोगों से प्रार्थना करता रहता था। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने सभी अध्यापकों से ऑप्शन लेकर के ट्रांसफर की है। आज एच.सी.एस. और पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में पारदर्शिता देखने को मिली है। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि पंचकुला की एक ऐसी गरीब लड़की जो दलित परिवार से संबंध रखती थी, उसने मुझे बताया कि मैंने तीन बार टेस्ट पास किए हैं लेकिन साक्षात्कार में मुझे फेल कर दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, उस लड़की ने कहा है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस सिस्टम में सुधार किया है। अध्यक्ष महोदय, यह हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सी.एम. विंडो हरियाणा के हर व्यक्ति के लिए एक राहत का काम कर रही है। कोई भी व्यक्ति जिसकी कोई नहीं सुनता था, जो दर–दर की ठोकरें खाता–फिरता था, आज उसको सी.एम. विंडो के जरिए न्याय की आश होने लगी है। अध्यक्ष महोदय, आज सी.एम. विंडो के जरिए लोगों को न्याय मिल

रहा है। सी.एम. विंडो के जरिए लगभग दो लाख प्राप्त शिकायतों में से लगभग डेढ़ लाख शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं समझता हूँ कि यही पारदर्शिता है जो हमारी सरकार लेकर आई है। आज सरकारी कार्यालयों के अंदर बायोमीट्रिक के जरिए कर्मचारियों की हाजिरी लगती है जिससे कार्यालय में काम करने का माहौल पैदा हुआ है। आज कर्मचारी काम करने के लिए तत्पर हुए है और आज समय पर कर्मचारी अपने कार्यालयों में समय पर आने लगे हैं। इस प्रकार से सरकार ने कार्यालयों में काम करने का एक वातावरण तैयार किया है। हमारी सरकार ने 170 ई सेवा केन्द्रों की सेवाएं जो सरकार ने डिजिटाईजेशन और कंप्यूट्राइजेशन के जरिए की हैं। मैं समझता हूं कि इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। व्यवस्था का महत्वपूर्ण उदाहरण 'सबका साथ सबका विकास' और हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कोई क्षेत्रवाद नहीं किया, कोई परिवारवाद नहीं किया, कोई जातिवाद नहीं किया और कोई इलाकावाद नहीं किया। हरियाणा प्रदेश की ढाई करोड़ जनता के हर 90 विधान सभा क्षेत्रों में जाकर उन्होंने उन लोगों के दुःख, तकलीफ और उनकी जरूरतों को समझा है। इसी कारण सबको समान पैसा दिया गया। डिवलपमैंट के काम के लिए पैसा दिया ताकि पूरे हरियाणा का विकास हो सके। हमारे प्रदेश की पुरानी सरकारों के समय की एक झलक आपको बताना चाहता हूं । मैं पंचकूला से विधायक हूं आदरणीय चौधरी श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा यहां सदन में नहीं बैठे हैं उनके 10 साल के कार्यकाल में हुड्डा साहब ने पंचकूला में एक भी ईंट नहीं लगाई। (शोर एवं व्यवधान) मैं बता रहा हूं 10 साल के शासनकाल में पंचकूला में एक भी ईंट नहीं लगायी गई और न ही कोई एक भी प्रोजेक्ट वहां पर शुरू किया गया। हां, पत्थर उखाड़ने का काम जरूर किया गया। वर्ष 2004 में आदरणीय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी जब प्रदेश के मुख्य मंत्री थे उस समय उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय का नींव पत्थर, माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के प्रांगण में जरूर लगाया था और डा0 मुरली मनोहर जोशी उस महाविद्यालय का शिलान्यास रखने के लिए आए थे ज्यों ही हुड्डा साहब की सरकार आयी उन्होंने उस पत्थर को भी उखाड़ने का काम किया और वह पत्थर आज तक नहीं मिला है। अब हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी दोबारा से वहां पर पत्थर लगाकर शिलान्यास करेंगे जहां पर संस्कृत महाविद्यालय बनेगा। आदरणीय हुड्डा साहब को पता नहीं पंचकुला जिले से क्या नफरत थी उन्होंने पंचकूला जिले में कोई भी कार्य नहीं करवाया इसका कारण यह हो सकता है

क्योंकि कुमारी शैलजा जी उस समय अम्बाला से मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट थीं वह एक दलित की बेटी थी, दलित होने के कारण ही उनका विरोध करना, हुड्डा साहब की मानसिकता को दर्शाता है। शायद उसके कारण पिछली सरकार ने पंचकूला जिले को इगनोर किया अन्यथा और कोई कारण नहीं था।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बार–बार आपतिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः नहीं बहन जी, आप तो एक्सपर्ट हैं ये तो सीख रहे हैं।

श्री आनंद सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, यही बात सीख रहे हैं तो बोलने दें।

श्री ज्ञानचन्द गुप्ताः अध्यक्ष महोदय मैं तो बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कोई विकास का कार्य नहीं किया हमारी सरकार विकास के कार्य कर रही है। यह भी बताउंगा कि पंचकूला के लिए क्या–2 किया।

श्री अध्यक्षः बहन जी, आपको बोलने का समय दिया जाएगा। उस वक्त आप अपना वक्तव्य दे सकती हैं।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ताः अध्यक्ष महोदय जी, आज हमारी सरकार ने युवाओं के प्रोत्साहन के लिए, खेलों के प्रोत्साहन के लिए खेल नीति, 2015 बनायी है ताकि युवा अपने प्रदेश का अपने देश का नाम रोशन करें। इसी नीति के तहत हमारी सरकार ने गांव और हर जिले में 10–10 योगशालाएं बनवायी। इसके अतिरिक्त ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में जो खिलाड़ी जीतकर आएंगे। उनके प्रोत्साहन के लिए हमारी सरकार ने राशि बढाकर छः करोड़ गोल्ड मैडल के लिए, चार करोड़ सिल्वर मैडल के लिए और ब्रांज मैडल के लिए ढाई करोड़ रूपये की राशि मंजूर की है तथा हरेक पार्टिसिपेट के लिए खेलने की पूरी व्यवस्था की गयी है।

श्री अध्यक्षः ज्ञानचन्द जी, जल्दी कीजिए टाईम बहुत हो चुका है। आप वाईंड अप करें।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ताः अध्यक्ष महोदय जी, हमारी सरकार ने बजट में खेलों के लिए 59 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। पहले के बजट में खेल के लिए 70–80 करोड़ रूपये का बजट रखा जाता था लेकिन हमारी सरकार ने 535.16 करोड़ रूपये का बजट खेलों के विकास के लिए रखा गया है। हरियाणा प्रदेश पहला राज्य है जहां पर पुलिस कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गयी है। अध्यक्ष

महोदय जी, बहुत से कार्यों में हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। होमगार्ड के कर्मचारी जिनको पहले की सरकारें 250 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से देती थी हमारी सरकार ने उस राशि को बढाकर प्रतिदिन 572 रूपये देने का प्रावधान किया है। जो पुलिस कांस्टेबल का न्यूनतम वेतन है, उसके बराबर अब यह तनख्वाह बनती है। 5000 होमगार्डों को इससे फायदा मिलने वाला है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक नया विभाग हमारी सरकार बनाने जा रही है और शहीदों के परिवारों को जो राशि मिलती है वह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है, यह हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं। उपलब्धियां तो ऐसे बहुत है पर मैं छोटी–छोटी उपलब्धि आपको बता रहा हूं। यह जो बजट है यह टैक्स फ्री बजट है। इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, उल्टा बॉयो डीजल और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सोलर उपक्रमों एवं कल–पुर्जों में छूट दी गई है, यह इस बजट की खासियत है। जी.एस.टी बिल जो बहुत सालों से पैंडिंग है, काफी सालों से इस देश के व्यापारी इस देश के उद्योगपति जी.एस.टी को लेकर देख रहे हैं कि कब जी.एस.टी बिल आयेगा, कब हमारा उद्धार होगा। देश का आज तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म जो हमारे आदरणीय केन्द्रीय वित्त मंत्री जी लेकर आ रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि 1 जुलाई के पश्चात इस देश में तथा इस प्रदेश में जी.एस.टी लागू होगा, जिससे जो व्यापारी, उद्योगपति हैं, उनको राहत मिलेगी। मैं कह रहा हूं कि मलिक साहब उस समय बोल रहे थे कि अच्छे दिन कब आयेंगे तो मैं मलिक साहब को बताना चाहता हूं कि अच्छे दिन आ चुके हैं, आपको शायद उसकी जानकारी नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि उस दिन जो मलिक साहब बता रहे थे कि मूंग की दाल 180 रुपये किलो है, लेकिन शायद इनको पता नहीं केवल 80 रुपये किलो है, जो चने की दाल 180 में बिकती थी वह आज 80 रुपए में बिकती है, जो बेसन 160 रुपए बिकता था उसकी कीमत आज 80 रुपए और 85 रुपए पर आ चुकी है। यह जो बजट है, वह गरीबों के लिए है और उनके अच्छे दिन आ गए, लेकिन कुछ लोगों के लिए बुरे दिन भी जरूर आ गए हैं, जिनके पास कालाधन है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नोटबंदी की उसको लेकर कुछ लोगों के लिए बुरे दिन आ गाए हैं, इसलिए इनको अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे हैं। हमारी सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत 2,63,512 लोगों को गैस सिलेंडर दिए गए। आज मैं पंचकुला की कुछ मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा। पंचकुला में बहुत काम किए हैं, बहुत सारी योजनाएं

आदरणीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं, मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूं। पंचकुला में देश का पहला आयुष आयुर्वेदिक संस्थान 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है। पंचकुला में ही नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ फैशन टैक्नोलॉजी जो देश का 17वां संस्थान है, इसकी आधारशिला रख दी गई है। पंचकुला में ही पौलिटैक्निक का मल्टी स्किल सेंटर बनने जा रहा है, उसकी भी आधारशिला रख दी गई है। पंचकूला एक ऐसा जिला था जहां पर हरियाणा रोड–वेज का डिपो नहीं था, लेकिन आज पंचकूला में हरियाणा रोडवेज का डिपो बनने की घोषणा हो चुकी है और जिसका कुछ दिनों में शिलान्यास होने जा रहा है । इसी तरह से पंचकूला के अंदर संस्कृत महाविद्यालय भी बनने जा रहा है । इसी तरह से पंचकूला शहर और पंचकूला जिले के गांवों में पिछले दो साल के दौरान बहुत सी सड़कें बनाई गई हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का नारा है कि सबका साथ–सबका विकास । इसी बात को मुख्यमंत्री जी ने चरितार्थ करते हुए जितना पैसा शहरों के विकास के लिए दिया है, उतना ही पैसा गांवों के विकास के लिए भी दिया गया है । हमारे पंचकूला शहर के विकास के लिए 15 करोड़ रुपये दिए गए हैं और उतना ही पैसा पंचकूला जिले के गांवों के विकास के लिए दिया गया है । इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, अब आप वाईंड–अप करें ।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट का समय और दिया जाये । अध्यक्ष महोदय, मैं विकास की बात कर रहा था । पंचकुला जिले में पिछले दो साल से बहुत से विकास के कार्य हुए हैं और सड़कों पर विकास देखने को मिल रहा है । एजुकेशन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पंचकूला जिले में विकास देखने को मिल रहा है । हमारे पंचकूला के सिविल हॉस्पिटल को देश के अंदर दूसरी बार सबसे बढ़िया हास्पिटल चुना गया है । यह केवल मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रयासों के कारण ही हुआ है जो उनके कामों को दर्शाता है । अध्यक्ष महोदय, मेरे पंचकूला जिले में दो–तीन छोटी–छोटी समस्याएं हैं उनके बारे में मुख्यमंत्री जी और वित्तमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पंचकूला के अंदर जो झुग्गी–झोपड़ियों में रहने वाले करीबन 40 हजार लोग हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाये। प्रश्नकाल में भी मैंने यह बात उठाई थी । इसके अतिरिक्त जो कालोनीज में रहने वाले लोग हैं उनको बिजली–पानी तो मिल रहा है लेकिन वहां पर गली, नाली और सड़कों की प्रोपर व्यवस्था नहीं है । इसलिए पंचकुला के अंदर

जो कालोनीज हैं उनमें गली, नाली और सड़कों की व्यवस्था करने के लिए बजट में पैसे का प्रावधान किया जाये ताकि वहां रहने वाले लोगों की लाईफ में सुधार हो सके । अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपका दोबारा से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया और मैं बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

मुख्य संसदीय सचिव (डॉ0 कमल गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं । आज अच्छा मौसम है लेकिन गर्म हो गया ।

हर फूल है, खुशबू है, इस रसवन्ती मौसम में,
पेश हुआ है प्रदेश का बजट, बहुत सुहाने मौसम में ।
वित्तमंत्री जी ने निज कौशल से कर दिया देखो कमाल,
जन कल्याण को ध्यान में रखकर, सबको कर दिया माला माल ।

इस बजट में मुझे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के समाजवाद की कल्पना राम राज्य पर आधारित नजर आती है । आज यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे वित्तमंत्री जी ने उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए पूरे समाज के लिए हितकारी बजट पेश किया है । इसी तरह से हमारे आदरणीय पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जिनकी एकात्म मानववाद एवं अंत्योदय की विचारधारा थी और जो समाज के अंतिम व्यक्ति गरीब, असहाय, विधवा तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए कृत संकल्प थे उनकी बात को भी ध्यान में रखते हुए माननीय वित्तमंत्री जी ने सराहनीय बजट पेश किया है । इसी तरह से हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मूल मंत्र हैं कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ–सबका विकास इन मंत्रो को भी ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी बजट बनाया गया है । जो दसों दिशाओं के लिए हितकारी है । जैसा कहा जाता है कि–

दसो दिशाओं में जाए दल बादल से छा जाएं,
उमड़ घुमड़ कर हर धरती को नन्दन वन सा सरसांए ।

वित्तमंत्री जी ने ऐसा बजट पेश किया है जो दसों दिशाओं और सभी लोगों के लिए हितकारी है । अध्यक्ष महोदय, बजट को जन कल्याणकारी बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है । मेरे विपक्ष के साथी जो इधर–उधर की बातें

कर रहे थे और सदन में ** सरकार, ** पकड़कर निकालने वाली जैसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे । अध्यक्ष महोदय, इस पर आपने कहा कि हम सभी लोगों को हरियाणा प्रदेश की अढ़ाई करोड़ जनता देख रही है । वह हमारा व्यवहार देख रही है और हमारे जैसे जो नये–नये लोग यहां पर भविष्य में आयेंगे वे इन्हीं वरिष्ठ सदस्यों से ही सीख लेंगे। जो शब्द यहां पर पांच–पांच बार चुनकर आये हुए माननीय सदस्यों द्वारा यूज़ किये जायेगें तो हम भी उन्हें ही सीखेंगे। हमारी आने वाली संतानें हमारी इन भूलों के लिए हमें कभी माफ नहीं कर पायेंगी। मैं आज बजट के बारे में बोलना चाहता हूं कि बजट की अच्छाई और बुराई उसकी ग्रोथ पर निर्भर करती है। आज बजट में 9 परसैंट की ग्रोथ है और यह 9 परसैंट की ग्रोथ केवल एक क्षेत्र की ग्रोथ नहीं है। इसमें तीनों क्षेत्रों की ग्रोथ शामिल है। प्राईमरी सैक्टर जिसमें एग्रीकल्चर सैक्टर एवं अलाईड सविर्सिज आती हैं, दूसरा सैकेण्डरी और तीसरा टर्सरी क्षेत्र। सैकेण्डरी में उद्योग आता है और टर्सरी में सर्विसिज आती हैं। इन तीनों सैक्टर्स में जो ग्रोथ का इनक्रीज हुआ है वह काबिले तारीफ है। वर्ष 2014–15 में प्राईमरी सैक्टर की ग्रोथ –2 परसैंट थी। यह कितनी विचित्र बात है। वर्ष 2015–16 में 3.2 परसैंट ग्रोथ रिकार्ड की गई है। इसी प्रकार से वर्ष 2016–17 में यह ग्रोथ 7 परसैंट हो गई है। इसी प्रकार से अगर हम सैकेण्डरी सैक्टर की बात करें तो वर्ष 2014–15 में सैकेण्डरी सैक्टर की ग्रोथ 2 से 3 परसैंट थी। इसी प्रकार से वर्ष 2016–17 में यह ग्रोथ 6.1 परसैंट हो गई है। इसी प्रकार से टर्सरी सैक्टर की ग्रोथ में भी काफी वृद्धि हुई है। पहले यह ग्रोथ 10.3 परसैंट थी और अब यह 10.6 परसैंट है। इस प्रकार से सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व ग्रोथ की है। इससे स्पष्ट होता है कि यह बजट बहुत अच्छा और प्रगतिशील है। इसमें किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं है। अब मैं प्रदेश की पर–कैपिटा इन्कम के बारे में बात करना चाहूंगा। देश की जी.डी.पी. 6 लाख 18 हजार करोड़ रूपये है। हरियाणा प्रदेश की पर–कैपिटा इन्कम 1 लाख 80 हजार रूपये है। इसी प्रकार से इंडिया की पर–कैपिटा इन्कम 1 लाख 03 हजार रूपये है। पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा अखबारों और टेलीविजन पर हरियाणा नम्बर एक से सम्बंधित विज्ञापनों पर बहुत बड़ी मात्रा में धन खर्च किया गया था लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं हरियाणा नम्बर एक दिखाई नहीं दिया।

.....

***चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।**

अगर हरियाणा नम्बर एक था तो प्राथमिक क्षेत्र में हरियाणा की ग्रोथ –2 परसैंट क्यों थी। देश की पर–कैपिटा इन्कम जो 1 लाख 03 हजार है वह भी इस कारण है क्योंकि जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां की पर–कैपिटा इनकम बहुत ही कम है। हरियाणा की उच्चतम पर–कैपिटा इनकम को देखते हुए भी हम कह सकते हैं कि हरियाणा का बजट बहुत ही अच्छा है। अब मैं रेवेन्यू डैफिशिट के बारे में बात करना चाहूंगा। मैं आंकड़ों के साथ बजट पर बोलना चाहता हूं। रैवेन्यू डैफिसिट का मतलब होता है रैवेन्यू एक्सपैंडीचर माईनस रैवेन्यू रिसीट्स। अब मैं इसकी तुलना करना चाहूंगा कि पहले हमारा रेवेन्यू डैफिसिट कितना था और अब कितना है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारा रैवेन्यू डैफिसिट विद् उदय स्कीम कितना था और विद्–आऊट उदय स्कीम कितना था। वर्ष 2015–16 में हमारा रैवेन्यू डैफिसिट विद् उदय स्कीम 2.41 परसैंट था। उसके बाद वर्ष 2016–17 में हमारा रैवेन्यू डैफिसिट विद् उदय स्कीम घटकर 2.23 परसैंट आया। वर्ष 2017–18 में हमारा रैवेन्यू डैफिसिट विद् उदय स्कीम घटकर 1.8 परसैंट आने की सम्भावना है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह बताना चाहता हूं कि यह 1.8 रैवेन्यू डैफिसिट विद् उदय स्कीम है। अगर उसे घटा दिया जाये तो हमारा यह रैवेन्यू डैफिसिट है यह .94 परसैंट है। हमारे वित्त मंत्री बड़े काबिल हैं इसलिए हमें उम्मीद है कि आने वाले दो वर्षों में हम इस रैवेन्यू डैफिसिट को जीरो परसैंट पर ले आयेंगे। यह बड़ी खुशी की बात है। किसी स्टेट का रैवेन्यू डैफिसिट जीरो पर आ जाना सरकारी काबलियत का परिचायक है। अध्यक्ष जी, अब मैं फिस्कल डैफिसिट की बात करना चाहूंगा। अगर टोटल एक्सपैंडीचर में से रैवेन्यू रिसीट्स घटा दी जायें तो जो बचता है उसको हम फिस्कल डैफिसिट कहते हैं और बड़े–बड़े इकॉनोमिस्ट जब बजट पेश करते हैं तो वे कहते हैं कि अच्छी सरकारों के लिए और जिसको अच्छी डिवैल्पमैंट करनी है उसका फिस्कल डैफिसिट जी.डी.पी. का 3 प्रतिशत तो होना ही चाहिए। जिसका फिस्कल डेफिसिट 3 प्रतिशत नहीं होता, 0 प्रतिशत होता है वे सरकारें निकम्मी होती हैं । इसका मतलब यह है कि वे काम ही नहीं कर रही हैं इसका मतलब वे कोई इन्वैस्टमैंट नहीं करना चाहती । आज यदि हमें प्रदेश की प्रोग्रैस करनी है तो फिस्कल डैफिसिट 3 प्रतिशत तक होने में कोई नुकसान नहीं है। फिर भी हमारा फिस्कल डैफिसिट 2015–16 में विद उदय स्कीम 6.49 प्रतिशत था फिर यह 2016–17 में 4.27 प्रतिशत आया और 2017–18 का जो ऐस्टीमेट है

उसमें 2.84 प्रतिशत है यह विद उदय स्कीम है और बिना उदय स्कीम यह 2.61 प्रतिशत है । मेरा आदरणीय वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि फिस्कल डैफिसिट जो 2.61 प्रतिशत है इसको बढ़ा कर हम 3 प्रतिशत तो ले जा सकते हैं । अगर हम इसको और अधिक ले जायेंगे, हम इन्वैस्टमैंट के काम करेंगे तो हमारे प्रदेश में डिवैल्पमैंट के काम होंगे । फिस्कल डैफिसिट के बाद मैं डैट के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं । हमारे विपक्ष के साथी डैट के बारे में चिंता व्यक्त करते हुये कह रहे थे कि पहले कर्जा कम था और आज कर्जा ज्यादा हो गया है । मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि जो डैट होता है वह फिस्कल डैफिसिट नहीं होता है । फिस्कल डैफिसिट अलग बात होती है और डैट अलग बात होती है । डैट हमारी जी.डी.पी. का 25 प्रतिशत तक हो सकता है । आज के दिन यह जो डैट है यह लगभग 18 प्रतिशत है । मैं वित्त मंत्री जी से फिर यह प्रार्थना करता हूं और यह सुझाव देता हूं कि यह डैट हम 7 प्रतिशत और बढ़ा कर तथा और कर्जा लेकर उससे और डिवैल्पमैंट के काम करें । चाहे वह इस प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो चाहे और अन्य बातें हों या किसी भी तरह की डिवैल्पमैंट की बातें हैं उसके लिए हमें डैट में बढ़ोतरी करनी चाहिए। हम जितनी इन्वैस्टमैंट करेंगे, जितनी डिवैल्पमैंट करेंगे, जितनी रेलों का काम करेंगे उससे हमें अधिक इन्कम होगी । जब हमारी इन्कम बढ़ेगी तो जो हमारा जो पिछला काम है, पिछला डैट है, पिछला फिस्कल डैफिसिट है और पिछला सारा जो कर्जा है वह सारा उतर जायेगा और हमें लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा । मैं मोदी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने नोटबंदी जैसा साहसिक कदम उठाया है । आज तक नोटबंदी जैसा साहसिक कदम पूरे संसार में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं उठा सका । आज हमारे विरोधी भाई कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार ने नोटबंदी करके लोगों को लाइन में लगा दिया, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि हमारे देश का नौजवान बॉर्डर पर, सीमाओं पर खड़ा है और वह बर्फ पर खड़ा है, वह धूप में खड़ा रहता है। वह 24–24 घंटे महीनों खड़ा रहता है । वह देश के सुख चैन और अमन के लिए खड़ा रहता है, देश में शांति रहे इसलिए खड़ा रहता है तो आज हमारे देश का मजदूर, देश का कोई भी आदमी बैंक में जा कर दो–चार घंटे खड़ा हो गया तो कोई फांसी नहीं आ जाती । आज इस नोटबंदी की वजह से देश में आतंकवाद खत्म हुआ है, नक्सलवाद खत्म हुआ और भ्रष्टाचार खत्म हुआ है । आज हमारा देश डिवैल्पमैंट की ओर अग्रसर हुआ है । जो विकसित देश होते हैं वहां पर

करेंसी पूरे खर्च का 5 से 7 प्रतिशत होती है । वहां करैंसी कोई जेब में नहीं रखता है । वहां पर चोरी डकैती नहीं होती, यहां लोगों की जेब कटती हैं वह इसीलिए कटती हैं कि जेब में लाखों रूपये होते हैं । आज जब हम कैशलैस की तरफ अग्रसर हो रहे हैं तो ये जो नम्बर 2 की कमाई है और नम्बर 2 का काम है हम इसको बंद करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं । यह नोटबंदी का कमाल है । वेनेजुएला एक छोटा सा देश है उसने जब करैंसी बंद करने का ऐलान किया तो 3 दिन में वहां पर गृहयुद्ध हो गया । हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश की 85 प्रतिशत करैंसी यानि जो 15 लाख करोड़ रूपया लोगों के घरों में रखा था । जो पैसा स्टोरों में रखा था । वह पैसा अब बैंकों में आ गया है । अब उस पर कितना रैवेन्यू बढ़ेगा, कितना मनी सर्कुलेशन में आ गया और कितना इसका रैवेन्यू आएगा । यह देखने वाली बात है । हमारी सरकार ने पूरे संसार को, पूरे देश को एक मैसेज दिया है । हमारी सरकार ने पूरे संसार को एक यह मैसेज भी दिया है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कितने बोल्ड हैं । वह कोई भी स्टैप जो अच्छा समझते हैं और जो सामाजिक कल्याण के लिये है, कालेधन को लाने का है वह उठा रहे हैं। जो लोग कश्मीर में सेना पर पत्थर फैंकते थे और उनको आतंकवादी हजार–हजार रूपये का नोट देते थे । लेकिन आज कोई पत्थर नहीं फैंकता है । हम कितनी तरक्की की ओर जा रहे हैं । मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि आज पूरे प्रदेश में आधार कार्ड शुरू करने का काम जिस गति से हमारी सरकार ने किया था । आज उस कार्य को हमारी सरकार ने 99 प्रतिशत कवर किया है । आज हमने आधार कार्ड को जन्म से जोड़ा है । आज हमने आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ा है, राशन कार्ड से जोड़ा है, गैस के रजिस्ट्रेशन से जोड़ा है और पैंशन के खाते से जोड़ा है । पहले हमारे प्रदेश में अनेकों लोग डबल पैंशन ले लेते थे लेकिन आज हमारे प्रदेश में कोई डबल पैंशन नहीं ले सकता । हमारे स्कूलों में जो घपले हुआ करते थे, जो मिड–डे–मील के लिये एक–एक बच्चा दो–दो, तीन–तीन स्कूलों में दाखिला ले लेता था और उसका वह मिड–डे–मील खा लिया जाता था । आज वह नहीं खाया जा सकता । रामचरित्र मानस में तुलसीदास जी ने कहा है जिसमें तुलसीदास जी ने राम राज्य की कल्पना के लिये एक चौपाई लिखी है कि किस प्रकार का राम राज्य होता है । उसके लिये कैसा बजट होना चाहिए उसके बारे में लिखा है । उन्होंने लिखा है कि– 'दैहिक, दैविक, भौतिक तापा । राम राज्य नहीं काहूं व्यापा । उन्होंने तीन शब्दों का वर्णन किया है ।

दैहिक का मतलब होता है स्वास्थ्य । सरकार को लोगों के स्वास्थ्य की चिन्ता करनी चाहिए । दैविक का मतलब जितनी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उन आपदाओं से है । जैसे ओलावृष्टि हुई, सफेद मक्खी ने फसल को नष्ट किया और अनेक प्रकार के आतंकवाद, अनेक प्रकार के झगड़े । पिछले साल कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रदेश में उद्धम मचाकर लोगों के घर जलाए । ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में जो लोगों का ध्यान रखता है उसकी बात की गई है । भौतिक में लोगों के सुख का, सड़क का, बिजली का, पानी का, आवागमन का और घर का जिक्र किया गया है । इन तीनों चीजों का जो विकास करता है । उसमें ऐसे राम राज्य की कल्पना की है। मैं स्वास्थ्य की बात करता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य में क्या–क्या प्रगति की है। मैं हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज को बधाई देता हूं कि जब से वे इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं तब से हालांकि हमें डॉक्टरों की कमी विरासत में मिली है क्योंकि दस साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा उन्होंने कितने डॉक्टर भर्ती किये थे यह सभी जानते हैं। आज वह हमें अस्पतालों को विद्आउट डॉक्टर के सौंप कर चले गये । उन अस्पतालों में भी ढ़ाई साल का रिकॉर्ड है कि हमारी सरकार ने नं0 ऑफ सिविल अस्पताल, नं0 ऑफ सी.एच.सीज., पी.एच.सीज. और सब सैंटर्ज, इन सभी में बढ़ोतरी की है।

श्री अध्यक्ष : डॉ0 साहब, आप अपनी बात को दो मिनट में खत्म कीजिए । आप बोल तो बहुत अच्छा रहे हैं लेकिन समय का अभाव है ।

डॉ0 कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो बढ़ोतरी की है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : डॉ0 साहब, बहुत अच्छा बोल रहे हैं लेकिन मुझे टाईम को देखना पड़ता है ।

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमती सीमा त्रिखा): अध्यक्ष महोदय, मेरे बोलने का समय भी डॉ0 साहब को दे दिया जाए ।

3:00 बजे

डॉ0 कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो ओ.पी.डी. की संख्या है। जो हमारे यहां इंडौर की संख्या है और नं0 ऑफ डिलीवरीज की संख्या है । उस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि पहले इंस्टीच्यूशनल डिलीवरी कितनी होती थी । आप कहो तो मैं इन सबके आंकड़े पढ़ सकता हूं । मेरे पास सबके आंकड़े हैं । आज बधाई की बात है कि हमारी सरकार एम.आर.आई. और सी.टी.स्कैन जैसी सुविधा पूरे प्रदेश के 6 जिलों में और 3 मेडिकल कॉलेजों में दे रही है। यह सुविधा गवर्नमैंट के

जो ऑफिसिज हैं सरकार को जनता दे रही है । यह एक बहुत बड़ी बात है। हमारी सरकार के पिछले अढ़ाई साल के कार्यकाल में मलेरिया और डेंग से कोई डैथ रिपोर्टिड नहीं हुई है। आज जे.ई. (जापानीज इंसिफलाइटिस) जो कि एक किस्म का बुखार होता है, इससे भी कोई डैथ हरियाणा प्रदेश में नहीं हुई है। यह सब सरकार की अचीवमैंट की बातें हैं। प्रदेश की जनता की सहायता के लिए हीमोडायलेसिस व डॉयलेशिश की सुविधा से सुसज्जित तीन इंस्टीट्यूशंज गुरूग्राम, जींद और सिरसा में शुरू किए गए हैं। आज अस्पतालों में सफाई के लिए हमारी सरकार ने नई चीज शुरू की है और वह यह है कि हरियाणा प्रदेश के हस्पतालों में हर रोज सोमवार से लेकर रविवार तक तक अलग–अलग कलर्ज की बैड शीट्स बिछाने का प्रावधान किया गया है। यह वीजन की बात है। पहले अस्पतालों में सफेद चद्दर मरीज के नीचे बिछाई जाती थी और वह कईं–कईं दिनों तक बिछी रहती थी लेकिन हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही प्रदेश के अस्पतालों में हर दिन एक नये कलर की चद्दर बिछाने का प्रावधान किया है जिसकी वजह से अब मरीज को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसके नीचे की चद्दर बदल दो क्योंकि हर दिन की एक विशेष कलर की चद्दर बिछानी अनिवार्य बनाई गई है, जिसकी वजह से हर रोज मरीज के नीच चद्दर बदलना अस्पताल प्रशासन के लिए अनिवार्य हो गया है। इस सुविधा की वजह से एक तो अस्पताल में सफाई अच्छी रहती है और दूसरा रेट ऑफ इंफैक्शन कम हो जाता है। (इस समय सदन में मेजें थपथपाई गई।) अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। कांग्रेस के राज में जब बाहर से आए आतंकवादी हमारी सेना के दो सैनिकों के सिर काटकर ले गए थे तो कांग्रेस सरकार ने इसे आपसी झगड़े की संज्ञा दी थी और कहा था कि सिर काटने का कार्य पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने नहीं किया है और दूसरी तरफ जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 28 सितम्बर, 2016 की रात को 12.30 और 2.30 बजे के बीच 150 जवानों ने आतंकवाद का जवाब देते हुए पाकिस्तान की सीमा में घुसकर, आतंकवादियों की छाती पर चढ़कर 38 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया और उनके आतंकी अड्डों को उड़ा दिया तो कांग्रेस के लोग उसका प्रूफ मांगते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सदन में विषय से हटकर बात करने लग गए हैं। इन्हें मूल विषय पर बात करनी चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, माननीय सदस्य हिंदुस्तान की सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकी अड्ड़ों को उड़ाने वाले मिशन की ही बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? क्या आप भारतीय सेना के इस आपरेशन का समर्थन नहीं करती ? सेना कुछ करेगी वह तो आपका और हम सबका सम्मान है।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मुझे बीच में इंट्रप्ट किया गया इसलिए मैं फिर उसी विषय पर आता हूँ। 150 भारतीय जवानों ने अपनी जान को खतरे में डालकर और देश में अमनशांति के लिए 38 आतंकवादियों को उनकी सर–जमीन पर जाकर मौत के घाट उतारा। जब हमारी सरकार द्वारा यह कहा गया कि हमने आतंकवाद का मुकाबला करते हुए इस तरह के आप्रेशन को अंजाम दिया है तो हमारे कांग्रेस के भाई कहते हैं कि हमारे को इस बात का प्रूफ दो कि पाकिस्तान की सीमा के अन्दर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के लोगों द्वारा इस तरह से प्रूफ की बातें करना बहुत ही शर्मनाक है? (शेम–शेम की आवाजें) यह लोग अखंड भारत की बात नहीं करते है? जब देश की सीमाओं पर आक्रमण होता है तब भी कोई बात नहीं करते हैं लेकिन एक आपसी परिवार का झगड़ा है जैसे एस.वाई. एल. कैनाल का झगड़ा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर अपना फैसला दे दिया है और बावजूद इसके कस्सी और फावड़ा उठाकर हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर जाकर सड़क तोड़ने का ड्रामा करके, अपना श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, वह बहुत शर्म की बात है? बात करनी है तो आतंकवाद पर कीजिए ? अखंड भारत पर कीजिए? और भी अन्य बहुत सी बातें हैं? भाई–भाई के एस.वाई.एल. कैनाल के झगड़े वाले केस में कस्सी व फावड़ा उठाकर, सड़क को तोड़ना और वाहवाही लूटने का प्रयास करना, यह मजाक नहीं तो और क्या है ? मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया है । देश की आजादी के बाद हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जी ने कश्मीर के मुद्दे को अटका दिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक कलम से 562 रियासतों को अखण्ड भारत में मिला दिया । जवाहर लाल नेहरू जी ने कश्मीर का मसला यू.एन. ओ. में ले जाकर फंसा दिया । आज मोदी जी ने ब्लूचिस्तान में रैफ्रेंडम की बात उठाई है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य डॉ. कमल गुप्ता जी तो कांग्रेस पार्टी की ही तारीफ कर रहे हैं । फर्क इतना है कि ये पटेल जी की तारीफ कर रहे हैं । इससे तो

कोई प्रोब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि पटेल जी और नेहरू जी दोनों ही कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे । इससे तो कांग्रेस पार्टी को खुश ही होना चाहिए ।

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं अब वाइंड अप करता हूं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रोहतक से महम जाने वाली रेलवे लाइन का हांसी और जींद तक विस्तार करने के लिए केन्द्रीय रेलवे मंत्री से बात की है । इस रेलवे लाइन से ये शहर वैल कनैक्ट हो जाएंगे । जब हरियाणा में रेलवे का जाल बिछेगा तो इससे हमारे हरियाणा के शहरों की आपस में वैल कनैक्टिविटी हो जाएगी । माननीय वित्त मंत्री जी ने हिसार में इंटरनैशनल एविएशन के लिए 50 करोड़ रूपये और उसकी मेंटेनेंस के लिए 20 करोड़ रूपये मंजूर किये हैं । आज हमारे हिसार में आकर एयरपोर्ट देखिये । आज वहां पर 13–14 हवाई जहाज रिपेयर होने के लिए खड़े हैं । इसके अतिरिक्त वहां पर एक नया हवाई जहाज भी बन गया है । आज डाबड़ा पुल का दोहरीकरण किया जा रहा है जिसका बजट 19 करोड़ रूपये है । इसके अतिरिक्त 18 किलोमीटर लम्बा साउदर्न बाइपास कम्पलीट किया गया है । इसका काम पिछले 5 साल से ठप्प पड़ा हुआ था । माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसको पूरा करवाया है । हमारा अनेक वर्षों से रेलवे वॉशिंग यार्ड बनाने का जो सपना था वह पैंडिंग पड़ा था । आज वहां पर दो–तीन महीने में रेलवे वॉशिंग यार्ड कम्पलीट होने वाला है । हमारे शहर में सकाडा का वाटर वर्क्स बन रहा है । यह वहां का तीसरा वॉटर वर्क्स होगा । आप हिसार का 40 एम.एल.डी. का एस.टी.पी. देखिये । हरियाणा के हिसार शहर में कोई एस.टी.पी. नहीं था लेकिन आज वहां पहली बार नौ एकड़ जमीन लेकर 40 एम.एल.डी. का एस.टी.पी. बनाया जा रहा है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने नगर निगम के कार्यों के लिए पिछले हफ्ते 37 करोड़ रूपये दिए हैं । इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं । उन्होंने सभी सड़कों को साउदर्न बाइपास से जोड़ने का काम किया है । हमारी सरकार ने गौ अभ्यारण्य के लिए 50 एकड़ जमीन और दस करोड़ रूपये दिये हैं । हम इस गौ अभ्यारण्य में पूरे शहर के जो नन्दी हैं उन नन्दियों को इकट्ठा करके वहां रखेंगे । इसके अतिरिक्त हमने लुढ़ास में गौ अभ्यारण्य बनाने के लिए 1000 एकड़ जमीन देकर उसको स्थापित करने का काम किया है । अंत में मैं बजट से संबंधित दो पंक्तियां कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा –

बजट की तारीफ में
जिस वक्त मैं सब कुछ कह गया ।
मुझसे दिल कह रहा है,
बाकी बहुत कुछ रह गया ।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं ।

Smt. Kiran Choudhry: Speaker Sir, I am going to speak on the budget and on many other issues. अध्यक्ष जी, इनको जितना टाइम दिया गया है मुझे उससे ज्यादा समय मिलना चाहिए । (विघ्न) हमने चुपचाप सभी की बात सुनी है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपके पास 20 मिनट हैं । उसमें चाहे आपकी पार्टी के 2 सदस्य बोल लें या 4 सदस्य बोल लें । यह एडजस्टमैंट आपको खुद करनी पड़ेगी । (विघ्न)

इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्यों के नेम करने के निर्णय को रदद करना

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, आपने बड़ी उदारता से सभी सदस्यों को सदन में बोलने का मौका देकर हरियाणा विधान सभा के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू किया है और आपने स्पीकर की कुर्सी की गरिमा को बढ़ाया है। आज सुबह सदन में एक अनफोर्चयुनेट–सा एटमोसफेयर बन गया था । मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि उन मित्रों को भी सदन में बुला लिया जाए जिनको आपने नेम किया हुआ है । आज बजट पास होने वाला है और आपकी अध्यक्षता में सदन में उदारता के बहुत अच्छे–अच्छे उदाहरण प्रस्तुत हुए हैं । उनको देखते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उन माननीय सदस्यों को भी वापिस सदन में बुला लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है राम बिलास जी, आपके विनम्र अनुरोध पर हम उनको भी सत्र में भाग लेने के लिए वापिस बुला लेते हैं ।

.....

वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, ...।

श्री अध्यक्षः किरण जी, आज अपनी बात 20 मिनट में पूरी कर लें।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात 20 मिनट में पूरी नहीं कर सकती, इससे अच्छा है कि मैं बजट पर ही ना बोलूं।

श्री अध्यक्षः किरण जी, माननीय सदस्यों को बोलने के लिए 10 मिनट और पार्टी लीडर के लिए 20 मिनट का समय निर्धारित किया हुआ है।

Smt. Kiran Choudhry: This Budget document is a completely visionless and hallow document. It does not talk about the available resources which should be put into gainful use and it also does not give any direction towards a proper economy. It is like a ship which is sailing on the rough seas and it shows completely fiscal mismanagement. As it is completely rudderless, there is no encouragement in it. Sir, the Budget which has been presented in the Assembly is very unfortunate one. Sir, especially that it neither contains any provisions and nor reflects any thinking how to come out from the the huge debt of Rs.141854.33 crores which Haryana is reeling under. Sir, this causes a great concern because we are heading towards a debt trap. If we are not going to keep this intact in the next few years, this debt trap is going to gulp us. And unfortunately what is happening that the Hon'ble Finance Minister says that economy is in the pink health. I do not understand how this economy can be in the pink health when we have got so much of debt burden on us. There are few options. He has to depend more on borrowing because of rising in expenditure. Sir I would like to point out here that we definitely achieved the dubious distinction of leaving the neighbouring Punjab which is far behind in the debt burden. Last year, I remember, during his first budget speech, I had said the same thing to the Hon'ble Finance Minister to which he had replied that we had left him in a big fiscal mismanagement which is

inherited. Now, this is the third Budget which has been presented by him and I am sure you cannot hide behind the wail of same thing of being inheritance.

Finance Minister (Capt. Abhimanyu): You will be enlightened to my response.

Smt. Kiran Choudhary: Yes, I am glad because I am going to ask a few questions from the Hon'ble Finance Minister. He may kindly note them down so that he can reply to me when the time comes. Sir, today we all see that the 25% budget is going to be spent on salaries and pensions and 16.36% is going to be spent on interest. I want to know from the Government how with the 50% budget which is just left, you are going to make developments. Are you going to borrow more as one of your MLA has said? If that is the case, then I am sure you must know what is awaiting you. At the same time, I must compliment the Hon'ble Finance Minister, Sir, for trying to make the best of bad job. I must compliment him in the way he used the entire vocabulary in the manner he presented such a rosy picture which is actually not the case. Here I would like to bring this thing forward. Let me prove my point. For example, the GSDP constant price in 2011-12 which is registered growth at 9% in 2015-16 has declined to 8.7% in 2016-17. Similarly the per capita income which grew at 7.5% in 2015-16 is expected to dip to 7.2% in 2016-17. Sir I have not coined these figures. These figures I have been taken out from the budget. I would ask the Hon'ble Finance Minister to take a note of it and he can reply to me.

Similarly, the Secondary Sector which is the industry it locked the growth at 7.7% in 2015-16 but it has fallen to 6.1% in 2016-17 and also in the tertiary services sector which registered the growth at 10.9% in 2015-16 has locked a modest decline of 0.1% in 2016-17 at 10.8%. He may reply on this issue also.

As far as public sector undertakings are concerned, I would like to open a window even on that score. Sir, out of 23 public sector undertakings, some of them had made modest profit of Rs. 307 crores last year while many of them had incurred losses of Rs.2126 crores. The Power DISCOMS has registered losses of Rs.2000 crore including 1730 crore on account of failure to check transmission losses. So, what does this show? This clearly shows that there is complete inadequacy and complete incompetency as far as government is concerned. I would like to know on these major issues also. Now, Sir, I am going to make comparison of the Budget which was passed during the last year and this year and what they had promised during the last year and what has been done in this year. Kindly note them. Last year, the Hon'ble Finance Minister talked about PPP mode. According to paragraph No.33, the Government had to propose that a panel of transactions advisors is being constituted to help the department to formulate a request for proposal that means PPP mode, which was to be done in six core sectors i.e. road, transport, tourism, urban local bodies, drinking water supply scheme, education and skill development which were identified by the Government to be done in the PPP mode. Sir, what has happened today, I want to know. Nothing has been mentioned about the last year's proposal. There is no mention at all. Hon'ble Finance Minister must clarify as far as this scheme is concerned. Has this been abandoned? Let us know. What is happening? In the 22 districts, only 3 medical colleges are there in which MRI and CT scan machines have been put in. No private players have come forward. The government had tom tom this issue that the Government is going to get lot of investments in the PPP mode. But unfortunately nothing of that has come forward. What is about the urban infrastructure? I would like to know that also. Has any player in the PPP mode come forward for the development of drinking water purposes because, as you know, half of Haryana i.e. especially

southern Haryana is reeling under the dark zone and water is becoming a big problem. But there is no proposal for these major issues.

Similarly, on agriculture and allied sector, last year in the budget they had promised for Soil Health Cards which were to be given to the farmers and for which Rs.15.2 crores were allocated and put aside. This year the present budget shows that only 1.80 lacs Soil Samples have been collected. The funds which were supposed to be given in last year, I want to know that what has happened those funds? I do not see anything of being talked about here how the funds are being utilized.

Now, I would like to talk about Horticulture sector. You said Horticulture University was to be started and Rs.50 crores was put aside for that purpose. Now, Sir, in the present Budget the Hon'ble Finance Minister simply says that Horticulture University is being established in the name of Maharana Pratap. What happened to the allocation of 50 crores? I would like to know. Between then and now, it has taken more than a year, the University is still being established. What he has talked about in the last budget, similar thing he is talking in the same manner and in the same way in this present Budget. So the Budget of last year has lapsed but nothing has been done. Sir, on the Fasal Bima Yojana, we all know, how the Government has mismanaged the entire thing. The cup of woes of farmers are brimming over completely. Sir, I want to talk about the electricity for farmers. You had promised in the last year's budget Rs. 6800 crore as subsidy which was to be given to them. But this is year you have reduced the subsidy from 6800 to 6300 crores and the farmers are not getting electricity what does it mean. Farmers are working with their instruments through diesel. So as I said earlier, cup of woes of the farmers has completely brimmed over. They are in a bad shape. Nothing has been done on the Swaminathan Report for which the BJP has sworn earlier, and has not talked about it at all this time. As far as SYL issue is concerned, I am glad that 100 crores have

been set aside for it. It is much talked issue. Everyone is trying take credit for it. I am not talking about in terms of credit today. Sir, we all know the entire facts.

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, बहन किरण जी जो बात कह रही है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं सदन से यह निवेदन करता हूं कि मंत्री जी इस बात का पता करें कि जब चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे तो पलवल के अंदर भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी आये और उन्होंने वहां एलान किया कि SYL is a central project now. (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि करण दलाल जी ये चाहते नहीं थे कि एस.वाई.एल के निर्माण के लिए हरियाणा सरकार कोई कदम उठाए, उसके लिए अलग से कोई बजट का प्रावधान रखे। हमारे काबिल वित्त मंत्री ने कहा है कि अगर 100 करोड़ रुपए हम एलाट करते हैं या अगर हजार करोड़ या उससे ज्यादा की भी जरूरत पड़ी तो वह भी देने का हम काम करेंगे। करण दलाल जी मुझे लगता है इस बात से राजी नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यही बात कह रही हूं कि जो करण दलाल जी ने एस.वाई.एल के बारे में कही है कि आज के दिन Hon'ble Supreme Court has already adjudicated upon the SYL issue. The order has been given in our favour. And not once but twice-thrice the Supreme Court has reiterated that the SYL Canal is to be made. Now, what I am only trying to ask is that more than six months have lapsed, why the politics is being played on this. Why the work is not being started? When our own farmers, they have tears in their eyes but there is no water in that canal. So, Sir, I would request that keeping money aside as a separate issue, but as far as this canal is concerned we should start digging it immediately because this is our life-line. And also the Supreme Court has given us our right and we should not delay on that matter at all.

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, पहले किरण चौधरी जी डिसाइड कर लें कि वे पानी हरियाणा को देना चाहती हैं या पंजाब को देना चाहती हैं,

क्योंकि सुरजेवाला जी तो कह रहे हैं कि पंजाब को (विघ्न) पहले आप लोग आपस में फैसला कर लें और हुड्डा साहब कहते हैं हरियाणा में बाढ़ आ जाएगी।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, देखिए, अनिल विज जी बीच में बोल रहे हैं, मैं कभी बीच में नहीं बोली। अध्यक्ष जी, ये आपके मंत्री हैं, आप इनको संभालिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : किरण जी, आप तीनों बैठकर फैसला तो कर लें कि आप लोग करना क्या चाहते हों। (शोर एवं व्यवधान)

Smt. Kiran Choudhry : Speaker Sir, is this the way? what is this? अगर इस तरह से शोर होगा तो मैं कुछ बात नहीं करूंगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप लोग बैठ जाइए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : किरण जी, पहले आप तीनों मिलकर ये फैसला कर लीजिए Sir, why Madam Kiran Choudhry is getting irritated? She is misleading the House. Why she is unnecessarily getting irritated?

Smt. Kiran Choudhry : Speaker Sir, the Minister does not know what to say. He is trying to put other things while I am speaking. कृपया इन्हें आप बैठने के लिए कहें।(शोर एवं व्यवधान)

Shri Anil Vij : Sir, why Kiran Choudhry Ji is getting irritated? What wrong I am saying?

Smt. Kiran Choudhry : Speaker Sir, I am not getting irritated.

Shri Anil Vij : What wrong I am saying? Sir, I have said nothing wrong. Surjewala says every drop should go to Punjab and Bhupinder Singh Hooda says that flood will come if SYL water comes to Haryana. (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ये कोई बात करने का तरीका नहीं है ये हमारे मंत्री हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ये कांग्रेस वाले हमें तय करके बता दें कि आखिर करना क्या है? नहर खोदनी है, पंजाब को पानी देना है या हरियाणा को देना है, ये फैसला करके बात दें। वरना, इसके बारे में हम जाने और हमारा काम जाने, इन्हें उससे कुछ लेना–देना नहीं है। (हंसी)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से यहां पर बहुत पार्टिसन की बात हो रही है। मैंने यहां पर कोई ऐसी बात नहीं कही, लेकिन इस तरह का प्रॉवोकेशन करा जा रहा है। (विघ्न) जो मैंने अभी कहा वह मंत्री जी को समझ तो आती नहीं है He has not understood.

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आप ऐसी बात कहिए ही नहीं जो किसी को समझ नहीं आती हो। (हंसी) आप ऐसी बात कहिए जो हाउस के सभी सदस्य को समझ आये।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूं।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आप मंत्री जी को ये सब बातें कहना चाहती हैं और मंत्री जी को भी समझ नहीं आ रही है। जब मंत्री जी को समझ नहीं आ रही तो बाकी हाउस को कहां से समझ आयेगी, तो आप वही भाषा बोलिए, जो हाउस को समझ में आये।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जिसको समझना है, उनको समझ आ जायेगी, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूं। अनिल विज जी, हर चीज में ऐसे खड़े हो जाते हैं, ये गलत बात है। अध्यक्ष जी, वर्तमान सरकार के पिछले बजट में हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक खेत को पानी देने की बात कही गई थी and Rs.143 crores were allocated to improve the capacity of JLN Canal. Now, the Finance Minister has said that the approval has been accorded. (Interruption) Speaker Sir, please bring the House in order. अध्यक्ष जी, मेरी आपसे रिकवैस्ट है कि मुझे बोलते हुए कोई माननीय सदस्य डिस्टर्ब न करे। इनको रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है यहां पर अगर किसी माननीय सदस्य को उसकी समझ नहीं है तो यह उसकी समस्या है और उसी को ही अपने स्तर पर इसका समाधान करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष जी, आप इनको मुझे डिस्टर्ब करने से रोकिए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष जी, यह क्या

बात हुई ? आप इनको समझायें कि हाउस की कार्यवाही ऐसे नहीं चलती है। Speaker Sir, please bring the House in order. (Interruption) Sir, I was talking about 'हर खेत को पानी।' Now, the Finance Minister has said that the approval has been accorded to this, costing rupees 143 crores. सर, इसका मतलब यह हुआ कि No progress has been made since last year. (Interruption) I want the Finance Minister to answer this. (Interruption) Sir, I am asking a question and on that the Finance Minister has to answer not a Member.

डॉ. अभय सिंह यादव : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। श्रीमती किरण चौधरी जी हाउस में गलत फैक्ट्स रख रही हैं। मेरा आपके माध्यम से इनको अनुरोध है कि वे वरिष्ठ सदस्या हैं और पूर्व मंत्री भी हैं इसलिए इनको ऐसा नहीं करना चाहिए।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मैं हाउस में कभी भी गलत फैक्ट्स नहीं रखती और जब भी फैक्ट्स रखती हूं वे सही होते हैं। You can rebut the facts when go get a chance to speak. अब ये लिफ्ट इरीगेशन की बात कर रहे हैं। (विघ्न)

Finance Minister (Captain Abhimanyu) : Speaker Sir, when Hon'ble CLP Leader has been reminded that an action has been taken on all these things and still she is insisting that the facts given by her are correct. I think when she is reminded and she is told that the action has been taken, she should withdraw her statement. This is OK that she is enlightened. She should not insist upon what she is saying. I am just request for the benefit of the House.

Smt. Kiran Chaudhry : Speaker Sir, the Finance Minister can rebut my statement during his address, but not a Member.

(Interruption) I have not rebutted anything. I am going to say what I have to say. What I am saying is according to my knowledge. What I am saying, Hon'ble Finance Minister should reply to this during his address, not a Member. So, Sir, as far as the Lift Irrigation System and rehabilitation of 565 water courses is concerned, an amount of rupees 300 crores was allocated.

Education Minister (Shri Ram Bilas Sharma) : Speaker Sir, on a point of order. स्पीकर सर, बहन किरण चौधरी सी.एल.पी. की लीडर हैं। आज कांग्रेस के ऑल इंडिया लीडर भी यहां उपस्थित हैं। यहां श्री करण सिंह दलाल जी भी हैं जो इस सदन में पलवल को रिप्रेजैंट करते हुए पांचवी बार सदस्य चुनकर आये हैं। हमने तो कल भी श्री कुलदीप शर्मा जी को क्षमा मांगते हुए बताया था कि श्रीमती किरण चौधरी जी को अंग्रेजी भाषा का बहुत ही अच्छा ज्ञान है। उनका अंग्रेजी का जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय वाला प्रोनउनसेशन है अर्थात जो एक्सैंट है वह भी बहुत अच्छा है परन्तु इसके मायने ये नहीं कि श्री करण सिंह दलाल जी ने यह जिज्ञासा प्रकट की थी कि श्रीमान् राजीव गांधी की उपस्थिति पलवल के अंदर एक कार्यक्रम का उल्लेख करके सबसे बड़ा फैक्टर और क्या हो सकता है। हमें शकुंतला बहन जी के हाव–भाव से यह लग रहा है कि जैसे वे कह रही हैं कि किरण चौधरी जी की अंग्रेजी भी उनकी समझ में नहीं आ रही है। (शोर एवं व्यवधान) Let me speak. (Interruption)

श्रीमती शकुन्तला खटकः अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनें।

श्री अध्यक्ष : शकुंतला जी, यह कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि मैंने भी यह स्वीकार कर लिया है कि किरण चौधरी जी की इंग्लिश मेरे समझ में भी नहीं आ रही है। (शोर एवं व्यवधान) मेरी समझ में यह बात भी नहीं आ रही है कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतनी बड़ी जिद क्यों कर रही हैं। (शोर एवं व्यवधान) शकुंतला जी, मैं आपको यह बात भी स्पष्ट भी कर देना चाहता हूं कि इंग्लिश समझ में आना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। इसलिए आप कृपया करके शांत हो जायें और अपनी सीट पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटक : स्पीकर सर, मैं आपसे केवल मात्र यही जानना चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी ने मेरा नाम कैसे और क्यों लिया? (शोर एवं व्यवधान) मुझे सारी की सारी अंग्रेजी भाषा समझ में आती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं यह स्वीकार करता हूं कि बहन किरण चौधरी जी की इंग्लिश स्पीच बहन शकुंतला जी की समझ में आ गई। इसलिए मैं अपने पूर्व में कहे गये शब्द वापिस लेता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप सभी अपनी–अपनी सीटों पर जायें । शर्मा जी ने अपने शब्द वापिस ले लिये हैं । (शोर एवं व्यवधान) इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि शर्मा जी अपने शब्द वापिस लेते क्योंकि यह कुछ भी बात नहीं थी । फिर भी शर्मा जी ने शकुंतला जी का मान–सम्मान करते हुए अपने शब्द वापिस ले लिए हैं। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप लोग अपनी–अपनी सीटों पर जायें । (शोर एवं व्यवधान) क्या आप भी ऐसा ही चाह रहे हैं कि जिस तरह से इण्डियन नैशनल लोक दल के सदस्यों को नेम किया गया था उसी तरह आपको भी नेम कर दिया जाये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, 26 अक्तूबर, 2014 को हमारी सरकार बनी थी । जे.एल.एन. कैनाल से दक्षिणी हरियाणा को पानी जाता है और ओम प्रकाश धनखड़ जी सिंचाई मंत्री हैं । वह जे.एल.एन. कैनाल गाद से भरी हुई थी जिसकी सफाई करवाने के लिए सिंचाई मंत्री जी ने 143 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जिसकी सफाई के लिए टैण्डर हो चुके हैं और जल्द ही उसकी सफाई हो जायेगी। उसके बारे में भी किरण चौधरी जी ये कहें कि nothing has been done, यह ठीक नहीं है। ये अपनी बात को दुरुस्त करें ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं नहीं कह रही हूं । ये सरकार के आंकड़े कह रहे हैं । ये ही कह रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान) मैं पिछले बजट का कंपरीजन कर रही हूं । (शोर एवं व्यवधान) मंत्री जी, आप इसको पढ़ लीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप सभी बैठें । किरण चौधरी जी आप अपनी स्पीच कंटीन्यू करें ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप अपनी रूलिंग दें कि क्या सत्तापक्ष के सदस्य इस तरह से किसी महिला के बारे में बात कर सकते हैं ? (विघ्न) इन्होंने हमारी माननीय सदस्या श्रीमती शकुंतला खटक के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपको सदन में महिला–पुरूष की बात नहीं करनी चाहिए। इस महान सदन में सभी बराबर हैं । (विघ्न) यदि किसी को कोई छोटी–मोटी बात कह दी जाती है तो उसको महिला या पुरूष को कहने वाली बात नहीं करनी चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई फालतू की बात नहीं कह रही हूं । (शोर एवं व्यवधान) सत्तापक्ष के सदस्यों को मुझे इस तरह से बीच में इंट्रप्ट नहीं करना चाहिए । इनका कभी कोई विधायक खड़ा हो जाता है, कभी कोई खड़ा हो जाता है । (शोर एवं व्यवधान) जब सत्तापक्ष के साथी बोल रहे थे उस समय हम खड़े नहीं हुए । इनको हमारी बात सुननी चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप सभी बैठें । किरण जी को अपनी स्पीच कंटीन्यू करने दें । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने प्रदेश में इण्डस्ट्रीज लाने के लिए हैपनिंग हरियाणा समिट किया था । Rs.9.50 crores were spent on that and MoUs of Rs.5.84 lac crores were signed during that summit. I would like to ask the Hon'be Finance Minister that what the investment proposals that have been finalized are. उस बारे में माननीय मंत्री जी अपने जवाब में जरूर बतायें कि कितना इनवैस्टमैंट प्रदेश में हपनिंग हरियाणा समिट में आया है। पिछले वर्ष हपनिंग हरियाणा के नाम पर इन्होंने 9.50 करोड़ रुपये वेस्ट कर दिया था । (विघ्न) Speaker Sir, I think it is a very said state of affairs that the Minister of the Government has to do these sorts of things. This is unfortunate (Interruption) This is not the way.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, सर्कस में एक आध * रखा जाता है । वैसे ही विज साहब को भी * रखा हुआ है।

श्री अनिज विज : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं बल्कि ये स्वयं * हैं । He is a *.

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब ने जो अनपार्लियामैंट्री शब्द कहे हैं वे रिकार्ड न किए जायें ।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब और अनिल विज जी ने जो अनपार्लियामैंट्री शब्द कहे हैं, वे रिकार्ड न किए जायें ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, साढ़े 9 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद सरकार को केवल 3 निवेशक मिले और केवल 1 कम्पनी ने निवेश किया है वह भी केवल डेढ़ करोड़ रुपये का we are headed towards the debt trap. दो करोड़ से भी ऊपर हमारा लोन हो चुका है इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं थी । यह सब करने की क्या जरूरत थी और अगर करते तो ऐसी जगह करते जहां से हमें राजस्व प्राप्त होता A kingdom of dreams को 32 करोड़ रुपया राजस्व देना है । आपको प्रवासी दिवस मनाने के लिए क्या और कोई जगह नहीं मिली, क्यों, यह तो अब भगवान ही जाने । हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि आपके ऑफिसर कौन कहां लगा हुआ है, क्या कर रहा है तथा उनमें से जो दोषी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई? अध्यक्ष महोदय, पिछली साल सरकार ने Swaran Jayanti Fiscal Policy Institute करने की बात कही थी जिसमें Public Finance and Policy, policy makers को अपोर्च्यूनिटी देनी थी । उस Swaran Jayanti Fiscal Policy के बारे में बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया है । क्या वह गायब हो गई है क्योंकि उसके लिए बजट में कोई फंड्स प्रोवाइड नहीं करवाया गया है । अध्यक्ष महोदय, केवल बोलने से काम नहीं चलता, लोग देखते भी हैं कि वित्त मंत्री जी ने पिछली बार क्या कहा था और इस बार क्या कहा है और वह इम्पलीमैंट भी हुआ है या नहीं ? इसी प्रकार से अब मैं शिक्षा के बारे में अपने विचार रखना चाहती हूं । शिक्षा में ए.एस.सी.आर. सर्वे करवाया गया and if you

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

read this ASCR survey on Education, Sir, you will be shocked to know that these are like the litaneys of what the Government schools are not doing. सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है । It exposes the total failure of the Government to do anything in the education sector. Last year the Government have talked about giving the dual-desks. आज तक वे डुअल डैस्क स्कूलों में नहीं पहुंचे हैं । सरकार द्वारा केवल 11 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है जबकि हमारी सरकार के समय में हम हर साल लगभग 100 स्कूल अपग्रेड किया करते थे । हम जब भी मंत्री जी को यह बात बताते हैं तो मंत्री जी कहते हैं कि स्कूल्स अपग्रेडेशन के नॉर्म्स पूरे नहीं करते हैं । बहुत से स्कूल्स ऐसे भी हैं जो नॉर्म्स पूरे करते हैं लेकिन उनको अपग्रेड नहीं किया गया। मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में कैरू गांव में स्कूल को अपग्रेड करने के लिए मैं मंत्री जी को लिखित में भी दे चुकी हूं और वह अपग्रेडेशन के नॉर्म्स भी पूरे करता है लेकिन उसको अपग्रेड नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, स्कूलों को अपग्रेड केवल वहीं पर किया जाता है जहां पर लोग अपग्रेडेशन के लिए धरने पर बैठ जाते हैं और आंदोलन तथा प्रदर्शन करते हैं । जहां पर धरने प्रदर्शन होते हैं उन स्कूलों को तो नॉर्म्स पूरे किये बिना भी अपग्रेड कर दिया जाता है जो कि अच्छी बात नहीं है। If the digital Haryana has to be made a reality, we have to bring up the education level of our government. Otherwise our boys and girls are not going to be able to compete at the national level. इसी प्रकार से कॉलेजों के बारे में सरकार की तरफ से कहा गया था कि जहां पर 50–60 किलोमीटर के दायरे में महिला कॉलेज नहीं है वहां पर सरकारी महिला कॉलेज जरूर बनाये जायेंगे । मैंने भी इस बारे में मंत्री से सवाल पूछा था और मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था लेकिन आज तक पोखरवास में महिला कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ है । वहां पर 60 किलोमीटर के दायरे में कोई महिला कॉलेज नहीं है । मैं केवल एक ही बात कहना चाहती हूं कि अगर सरकार कोई काम नहीं करना चाहती है तो न करे लेकिन बात वही कहनी चाहिए, जो वे कर सकते हैं । स्कूलों में सुविधाओं का बहुत अभाव है A Sir, 16.6% schools have no facility of drinking water. 2.9% schools have no provision of separate toilets for boys and girls and 18.4% schools do not have computers for children and there is no library in the 16.18%

schools. अगर हम इस स्टैंडर्ड को रेज नहीं करेंगे तो मेक इन इंडिया और मेक इन हरियाणा प्रोग्राम कैसे सफल हो पायेगा? मेक इन हरियाणा तो सफल हो ही नहीं सकता है । अध्यक्ष महोदय, अब मैं हैल्थ सैक्टर के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगी । सरकार ने एक प्रपोजल तैयार की है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जायेगा लेकिन हमारी सरकार के कार्यकाल में भिवानी में चौधरी बंसी लाल जी के नाम से एक मेडिकल कॉलेज दिया गया था । आज सरकार के दो साल पूरे हो गये हैं और दो साल के बाद माननीय वित्त मंत्री जी अपने बजट में लिख कर दे रहे हैं कि DPR has been approved for Government College, Bhiwani. जो कॉलेज हमारी सरकार के समय में एप्रूव हो चुका था अब दो साल के बाद तो उसकी डी.पी.आर. एप्रूव हुई है । फिर कब तो उसकी बिल्डिंग बनेगी और कब उसमें बच्चे प्रशिक्षण लेंगे । इसके साथ ही मैं एक बात पर वित्त मंत्री जी को प्वायंट आऊट करती हूं कि आपने अपने बजट के अन्दर चौधरी बंसी लाल जी का नाम डालना चाहिए था । Speaker Sir, they did not bring the name of Ch. Bansi lal Ji.

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहन किरण चौधरी जी को कहता हूं कि वह सुनना भी सिख लें। आप ** के साथ बैठकर वैसे ही न बन जाओ । **(शोर एवं व्यवधान)**

श्री अध्यक्ष : श्री अनिल विज जी द्वारा कहे गये अनपार्लियामैंट्री शब्द को रिकॉर्ड न किया जाए।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, बहन जी, जिस मैडिकल कॉलेज, भिवानी की बात कर रही हैं वह हमारी सरकार के समय में एप्रूव हुआ था । सर, इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया था । वह ऐसे हुआ था कि ये शोर ज्यादा करती थी इसलिये हुड्डा साहब ने इनका मुंह बन्द करने के लिये खाली एक चिट्ठी लिख दी थी । **(शोर एवं व्यवधान)** अब मैं बोल रहा हूं तो आप सुनना भी सिखो । या आपके कानों में रामदेव का तेल डालूं । (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, केन्द्र सरकार की जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने की एक योजना

*** चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।**

है जिसके लिये केन्द्र सरकार द्वारा 189 करोड़ रूपया दिया जाता है। सर, हमारी सरकार आने के बाद हमने केन्द्र सरकार से बात करके वह पैसा लेने के लिये इनीशियेट किया था । अब हम डी.पी.आर. बनाकर भेजेंगे और तब केन्द्र सरकार से पैसा आएगा । पहले की सरकार के समय में कुछ भी नहीं हुआ था । जो बात मैंने आपको पहले बताई है कि इसके लिये खाली एक चिट्ठी लिखी गई थी और कुछ नहीं हुआ था । वह बात आप समझ लो ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, विज साहब मंत्री बनकर जब पहले साल भिवानी में गये थे तो इन्होंने कहा था कि इस साल वह कॉलेज शुरू हो जाएगा । सर, भिवानी के अन्दर ये इनके खुद के शब्द है और आज ये डी.पी.आर. को लेकर बैठ गये। यही तो मैं कह रही हूं कि ये जो बात ढ़ाई साल पहले कह रहे थे । आज के दिन भी वही बात कह रहे हैं और वही बात मैं कह रही हूं । मैं इनकी ही की बात को आगे बढ़ा रही हूं । उसके साथ–साथ (शोर एवं व्यवधान) विज साहब, प्लीज आप बैठिये मुझे बोलने दीजिये ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यहां सदन में लिखा हुआ है कि बोलो तो ठीक बोलो । यह नहीं है कि उल्ट–सुल्ट बोलते रहो ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने उल्ट–सुल्ट कभी नहीं बोला और न ही मैं कभी उल्ट–सुल्ट बोलती हूं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यहां सदन में लिखा हुआ है कि गलत बोलने से दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी बनता है । बहन जी, क्या आपने इसको पढ़ा ।

श्रीमती किरण चौधरी : विज साहब, क्या आपने पढ़ा है इसको । आप पढ़ लीजिये। If you can understand what is written there तो आप अब बीच में बिल्कुल व्यवधान नहीं डालेंगे ।

श्री अनिल विज : अगर हमें समझ आती तो आप जो ये अंग्रेजी में गलत फलत बोल रही हैं वह नहीं बोलती ।

श्रीमती किरण चौधरी : विज साहब, आपको तो समझ आती नहीं है। इसलिये तो मैंने हिन्दी में बोलना शुरू कर दिया ताकि आपको समझ तो आ जाए । अध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली विभाग की बात करती हूं कि पिछले साल सरकार ने वर्ष

2015–16 में 'म्हारा गांव, जगमग गांव' नामक एक स्कीम को लॉंच किया था । उस स्कीम में टोटल 6840 गांवों में से 297 गांवों में अन इंट्रप्टिड पॉवर सप्लाई की बात कही थी । आज आप एक साल बाद भी कह रहें हैं कि जो 24 घण्टे बिजली की सप्लाई है वह 165 गांवों को दी जा रही है। इसका मतलब ये है कि ऐसे तो आप मैक्सीमम केवल 350 गांवों में ही बिजली दे पाएंगे । तो हमारे जो 6460 गांव बाकी रह गये हैं उनका क्या हाल होगा ? यह तो बिल्कुल स्पष्ट दर्शाता है कि इसके अन्दर there is so much laxity on the part of the Government. Sir, in the name of waiver scheme, the Government collected Rs.400 crores. Inspite of getting so much money, more than 90% line losses are still on. That shows that no improvement has been made. I would like to Finance Minister to make a statement on that. सर, एक पिल्लर बॉक्स स्कीम थी जिसके लिये फरीदाबाद और गुड़गांव के लिये 500 करोड़ रूपये के मीटर खरीदे गये थे जिसका यहां सदन में भी मुद्दा उठा था । उसके बारे में माननीय मंत्री जी जरूर बताएं कि उसके ऊपर क्या कार्यवाही की गई । उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया और एक्शन नहीं लिया गया तो किसके दबाव में आकर एक्शन नहीं लिया गया । जहां तक पीने के पानी की बात है उसमें सरकार ने कहा है कि Government is emphasizing to strengthen the existing drinking water supply through digging of additional tubewells. अध्यक्ष जी, हमारा सदर्न इलाका पूरा डॉर्क जोन के अंदर आ गया है। 33000 ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन अभी पैंडिंग हैं और उन्हें पूरे का पूरा बैन कर दिया गया है। सरकार कोई ऐसी प्रोपोजल नहीं बता रही है कि जो डॉर्क जोन है where the water has become saline, where it has become impossible for the farmers to draw water from the wells. What is the Government trying to do? Where these poor farmers have to go if you will not give them tubewell connections? How these poor farmers will irrigate their fields? अर्बन डिवेलपमैंट में आपने लास्ट इयर क्लेम किया था कि a Real Estate Regulatory Act will be made to protect the interests of the consumers. मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वह एक्ट बन गया है । अध्यक्ष महोदय, क्या बात है, इस साल उस एक्ट की कोई बात ही नहीं की जा रही है? क्या सरकार पर बिल्डर लॉबी का प्रभाव पड़ गया है कि जिस रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से कंज्यूमर का प्रोटैक्शन करना था, आज उस एक्ट की

बात तक नहीं की जाती? अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी को इस पर रोशनी डालने की जरूरत है? इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया था कि दीन दयाल जन आवास योजना is being implemented under "Housing for All" Scheme by the year 2022 लेकिन आज तक इसके लिए कोई जमीन आईडेंटीफाई तक नहीं हुई है। इस योजना के तहत 23 लाईसेंस दिए हैं और इससे संबंधित 250 एप्लीकेशंज अभी भी पैंडिंग पड़ी हुई है। गवर्नमैंट ने पिछली बार सदन में Transited Oriented Development Policy for upgradation and providing of infrastructure for metro routes के बारे में कहा था. अध्यक्ष महोदय, इस बात को हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सरकार द्वारा कहा गया था। मैं गुरूग्राम की बात बताती हूँ। यहां पर जो टी.ओ.डी. पॉलिसी बनाई गई थी। उस दिशा में आज तक क्या प्रोग्रैस हो पाई है, शायद भगवान ही जानता है? अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक काम जरूर हुआ है कि मास्टर प्लॉन में जो सैक्टर 75–ए का एरिया है, जिसको इंस्टीट्यूशनल एरिया माना गया है, के मास्टर प्लॉन को बदलते हुए इस इंस्टीट्यूशनल लैंड को मिक्सड लैंड यूज में डाल दिया गया है और जिसकी वजह से लोगों ने ओने–पोने दामों पर यह जमीन खरीद ली। आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि किन–किन लोगों ने यह जमीन खरीदी हैं? जमीन के लैंड यूज के मास्टर प्लॉन में चेंज होने के बाद अब यह जमीन 70 प्रतिशत कमर्शियल के रूप में प्रयोग की जायेगी और इसके 30 प्रतिशत भाग पर रेजिडेंशियल एरिया बनेगा और इस प्रकार जो जमीन किसी भाव की ही नहीं थी आज वह अरबो–खरबों के भाव में आ गई है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के भ्रष्टाचार के काम सरकार की जानकारी में हो रहे हैं और बार–बार हो रहे हैं तथा सरकार की नाक के नीचे हो रहे हैं। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जो यह भ्रष्टाचार के काम हो रहे हैं, इनको सरकार के द्वारा क्यों नहीं रोका जा रहा है? जहां तक यहां के मैट्रो रूट की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही कि सरकार ने मैट्रो का रूट नहीं बदला है बल्कि इस मैट्रो रूट को केवल मोड़ा है, उस परिपेक्ष्य में मुझे मोड़ने का मतलब और बदलने का मतलब तनिक भी समझ में नहीं आया है? अध्यक्ष महोदय, मोड़ने का मतलब तो बदलना ही होता है? बदलने का मतलब यही होता है कि मास्टर प्लॉन बदला गया? जब मैं यह बात कह रही हूँ तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष की तरफ से यह बात आ सकती है कि कांग्रेस के समय में भी तो मास्टर प्लॉन बदला गया था, इस बारे में मैं इस महान सदन को

बताना चाहती हूँ कि जब हमारे समय में इस तरह का कोई बदलाव किया जाता था तो उसके लिए पूरी हियरिंग वगैरह का प्रोसैस एडॉप्ट किया जाता था लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में कोई हियरिंग वगैरह को अंजाम ही नहीं दिया गया है और बावजूद इसके मैट्रो का रूट बदला गया ताकि निजी लोगों को उसका फायदा पहुच सके। अध्यक्ष महोदय, सरकार बार–बार भ्रष्टाचार पर जीरो टौलरेंस की बात करती है लेकिन आज वह जीरो टौलरेंस की बात कहां पर चली गई। इसी तरह मैं एक चीज अखबार में पढ़ रही थी कि लैंड मोर्टगेज बैंक, गुरूग्राम की जमीन की मार्किट वैल्यू बहुत ज्यादा है और इसका किराया करीबन 40 लाख रूपये प्रति महीना आ सकता है उधर गुरूग्राम म्युनिसिपल कमेटी का आफिस किराये पर चल रहा है यदि लैंड मोर्टगेज बैंक, गुरूग्राम की जमीन म्युनिसिपल कमेटी को ही दे दी जाती तो सरकार को राजस्व प्राप्त होता लेकिन ऐसा न करके यहां पर कोई दीप माला साड़ी सैंटर बना दिया गया। अध्यक्ष महोदय, निजी हाथों में सरकार द्वारा इस प्रकार की चीजें देने का सीधा सा मतलब है कि सरकार की जीरो टौलरेंस की पॉलिसी को हवा लग गई है और यह जीरो टौलरेंस की पॉलिसी कहां चली गई है इसका कोई पता ही नहीं चल रहा है? अध्यक्ष महोदय, अब मैं सरकार के द्वारा बनाई गई ऐक्साईज पॉलिसी पर बात रखना चाहूँगी। हमारे वित्त मंत्री जी एक्साईज मिनिस्टर भी हैं। हमारी कांग्रेस की सरकार ने बड़ी मेहनत के साथ एक्साईज पॉलिसी बनाई थी और यह पॉलिसी इस तरह से बनाई थी कि जो कार्टलाईजेशन है उसको हम तोड़ें और जो बड़े प्लेयर्ज हैं या जो बड़ी फिश थी which used to gobble up the smaller fishes उन बड़े प्लेयर्ज को हटाकर हरेक आदमी को एक्साईज पॉलिसी का लाभ मिले और वह आराम से अपना काम धंधा कर सके। लेकिन मेरे को यह देखकर बड़ा दर्द हुआ । हमने इतनी मेहनत से यह पॉलिसी बनाई थी और यह पॉलिसी बहुत ही सक्षम पॉलिसी थी । हमारी सरकार के दौरान इससे बहुत फायदा हुआ था । उस समय इसके एम्बेट में बहुत–से लोग आये थे । आज उसी पॉलिसी का आप दोबारा से कार्टलाइजेशन कर रहे हैं और इसे दोबारा से उनके हाथ में देने जा रहे हैं जो केवल अपना ही अपना उल्लू सीधा करेंगे तथा दूसरों को बाहर कर देंगे । आम आदमी जो है वह इस पॉलिसी के तहत पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा । फिर सरकार जॉब्स की बात करती है । मैं पूछती हूं कि जॉब्स कहां से आएंगे ? सरकार एक–एक जॉब अपोरच्यूनिटी को खत्म करती जा रही है । इसके साथ–साथ एस.सी./एस.टी. के नाम पर वैंड दिये जाते थे ।

दुर्भाग्य की बात है कि एस.सी./एस.टी. के नाम पर जो वैंड दिये जाते थे उनको गोलमाल कर दिया गया है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपको बोलने के लिए 20 मिनट दिये गए थे जबकि आपको बोलते हुए 40 मिनट हो गये हैं । अब आप वाइंड अप कीजिए । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मुझे सिर्फ दो प्वायंट्स पर बोलना है इसलिए मुझे सिर्फ दो मिनट का समय दिया जाए । अभी सरकार को सी.एस.डी. कैंटीन के बारे में भी जवाब देना पड़ेगा । हम सबको फौजी भाइयों के प्रति हमदर्दी है । इस सरकार ने सी.एस.डी. कैंटीन में उनकी शराब को भी महंगी कर दिया है । अरे, कम से कम फौजी भाइयों को तो छोड़ देते । अध्यक्ष जी, अब मैं अपनी कांस्टीच्यूएंसी की बात करना चाहती हूं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से तोशाम के खानक में माइनिंग के बारे में बताना चाहती हूं । वहां पर एच.एस.आई.आई.डी.सी. के जरिये माइनिंग हो रही है । वहां पर जो माइनिंग हो रही है उसमें वहां के खान मजदूरों को किसी भी तरह से काम करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है । मैं वहां की पूरी लिस्ट लेकर आई हूं । मेरे पास पूरी लिस्ट है । इसे मैं सदन के पटल पर रखती हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री जी ने मजदूर की बात कही है कि कोई भी मजदूर बेरोजगार नहीं रहेगा । मैं चाहती हूं कि कोई भी मजदूर बेरोजगार न रहे क्योंकि इनकी रोजी–रोटी इसी माइनिंग पर डिपैंड करती है । अध्यक्ष जी, अंत में मैं एक चीज और कहती हूं । अभी माननीय मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं । ये कहते हैं कि हम एक भी गड्ढा नहीं छोड़ेंगे । सरकार का कहना है कि आप हमें वॉट्स एप करो और इसके 75 घंटे के अन्दर सारा काम सही हो जाएगा । मैं सरकार से कोई नई सड़कें नहीं मांग रही हूं । मैंने दो साल पहले माननीय मुख्य मंत्री जी को 32 सड़कों के बारे में चिट्ठी लिखी थी । मैंने इसमें लिखा था कि They are in a very bad and dilapidated condition. Kindly have the potholes removed. आज उस चिट्ठी को लिखे हुए दो साल हो गये हैं मगर आज तक इनके ऊपर कार्यवाही नहीं हुई है । अतः मैं इसे भी सदन के पटल पर रखना चाहती हूं । अंत में मैं बस एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगी । (विघ्न) सरकार ने गड्ढों को ठीक करवाने के लिए वॉट्स एप का नंबर सही नहीं दिया है । मैं पूछती हूं कि वह वॉट्स एप नम्बर कहां है ? जो नंबर है ..... (विघ्न) वॉट्स एप का नम्बर केवल अखबार में है । मैं तो सरकार के उस वॉट्स एप नंबर को ढूंढती ही रह गई । मुझे बताइये कि सरकार का वॉट्स एप का नम्बर क्या है

ताकि मैं माननीय मंत्री जी को गड्ढों के बारे में वॉट्स एप करूं । मुझे अभी तक वॉट्स एप का नंबर ही नहीं मिला है । मैं कहना चाहती हूं कि वह वॉट्स एप नम्बर केवल अखबारों के लिए है । अंत में मैं एक ही बात कहूंगी । (विघ्न) अब मैं एक पोयट्री सुनाना चाहूंगी । (विघ्न) अध्यक्ष जी, मैं अपनी पॉयट्री फरमाती हूं –

इन झूठी उपलब्धियों पर यूं न इतना गुरूर कीजिए हुजूर
हकीकत के धरातल पर आइये और लोगों के दुःख–दर्द भी जानिये हुजूर
आंकड़ें और घोषणाएं कर ली आपने बहुत
जरा अपने वायदों का भी हिसाब दीजिए हुजूर
स्वामीनाथन रिपोर्ट, पंजाब स्केल, पक्की नौकरियां मिली नहीं
वायदे क्या आप भूल गए हुजूर ?
हिसाब आपके भी कर्मों और वायदों का होगा यहीं
थोड़ा और इंतजार कीजिए हुजूर । (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं –

न जाने कौन है अपना और कौन बेगाना
कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना ।

प्रो. दिनेश कौशिक (पुन्डरी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस गरिमामयी सदन में बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस स्वर्ण जयंती वर्ष के बजट सत्र में सदन के सम्मानित सदस्यों ने चर्चा में भाग लेकर बहुत ही मूल्यवान एवं रचनात्मक विचार प्रकट किए हैं। मैं भी इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को साधूवाद देना चाहता हूँ कि उनकी सरकार की दूरदृष्टि, सकारात्मक सोच तथा पारदर्शी कार्यप्रणाली के द्वारा ''सबका साथ सबका विकास'' इस सिद्धांत के माध्यम से भ्रष्टाचार के प्रति ''जीरो टॉलरेंस'' की नीति तथा महिलाओं की सुरक्षा एवं शिक्षा नीति के प्रति सकारात्मक कदम बढ़ाते हुए सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। सरकार की ऐसी सोच से प्रदेश के हर वर्ग के लोगों में सरकार के प्रति नई उम्मीदें जगी हैं तथा प्रदेश की जनता में विश्वास एवं भरोसा बढ़ा है। इसी कड़ी के तहत भविष्य में हरियाणा प्रदेश विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्तमंत्री महोदय के द्वारा प्रस्तावित बजट के सरकार की लोक हितैषी तथा सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए बधाई देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2017–18 के बजट अनुमानों में कोई नया कर न लगाने तथा वर्तमान दरों में वृद्धि न करके सरकार के परोपकारी फैसले का पुनः स्वागत करता हूँ। पिछले वर्ष

के मुकाबले इस वर्ष में लगभग 13 प्रतिशत परिव्यय की वृद्धि सरकार की सकारात्मक सोच को दर्शाती है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017–18 के प्रस्तावित बजट में विभिन्न क्षेत्रों में परिव्यय की व्यापक बढ़ोतरी सरकार की दूरगामी एवं विकासशील सोच को दर्शाता है। ग्रामीण विकास, सामुदायिक विकास तथा पंचायतों के लिए वर्ष 2017–18 के बजट में 56.69 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि सरकार की प्रगतिशील सोच का प्रमाण है। कृषि क्षेत्र के लिए इस बजट में वर्ष 2016–17 की तुलना में 18.79 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। बजट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 15.52 प्रतिशत की वृद्धि शिक्षा के क्षेत्र में 18.43 की वृद्धि तथा सिंचाई एवं जल संसाधनों के लिए 13.62 प्रतिशत की वृद्धि सरकार की सकारात्मक सोच व विकास के क्षेत्र में दृढ़ ईच्छा शक्ति को प्रदर्शित करती है। शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए परिव्यय संशेधित अनुमान वर्ष 2016–17 की तुलना में 45.93 प्रतिशत अधिक है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए ''मंगल नगर विकास योजना'' तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ''दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना'' की शुरूआत करके समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए महाविद्यालय और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का सरकार का सराहनीय कदम है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए अधिक बजट का आबंटन सरकार के अंतोदय सिद्धांत के अनुरूप लिया गया उचित फैसला है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार ने उत्तरदायी, पारदर्शी, जवाबदेही और भ्रष्टाचार मुक्त शासन उपलब्ध करवाकर व्यवस्था परिवर्तन के नए युग का सूत्रपात किया है। अध्यक्ष महोदय, पढ़ी लिखी पंचायतों का चुनाव, सरकारी नौकरियों में पूर्णतः योग्यता के आधार पर पारदर्शी भर्ती, ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पॉलिसी व सी.एम. विंडो के माध्यम से लोगों की शिकायतों का निवारण महत्वपूर्ण कदम है। अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित करते हुए सरकार ने केन्द्र सरकार की तर्ज पर सातवें वेतन आयोग को लागू किया है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार ने पंच, सरपंच, नम्बरदार, चौंकीदार, पंचायत समिति, जिला परिषद् चेयरमैन, वाईस–चेयरमैन एवं सदस्यों का मानदेय बढ़ाकर सभी को सम्मान प्रदान किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर पुण्डरी विधान सभा क्षेत्र को दूसरी बार प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, आजाद विधायक से लोगों को सीधा सम्पर्क एवं संबंध होने के नाते अपेक्षाएं भी बहुत अधिक होती हैं।

बैठक का समय बढाना

14:00बजे **श्री अध्यक्षः** यदि सदन की सहमति हो तो बैठक का समय एक घंटे के लिए बढा दिया जाये।

आवाजेः ठीक है, जी।

श्री अध्यक्षःठीक है, बैठक का समय एक घंटे के लिए बढाया जाता है।

वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) एवं वित्त मंत्री द्वारा उत्तर

श्री दिनेश कौशिकः जिन्हें केवल सरकार के सहयोग एवं आर्शिवाद से ही पूरा किया जा सकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र पुण्डरी में आदरणीय मुख्यमंत्री जी 31 मई 2015 को एक विशाल रैली को संबोधित करने के लिए गये थे। लोगों के प्यार एवं स्नेह को देखते हुए मुख्य मंत्री जी ने हल्के की लगभग सभी मांगों को मानते हुए 200 करोड़ से भी ज्यादा की घोषणाएं वहां की थी। मैं आपके एवं सदन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन घोषणाओं में 90 प्रतिशत कार्य या तो पूरे हो चुके हैं या उन पर कार्य चल रहा है। मुख्य मंत्री जी का विशेष स्नेह एवं आशीर्वाद मिलने से मैं भी स्वंय को सरकार का एक हिस्सा मानता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में विकास की गति को निरन्तर बनाये रखने के लिए कुछ अति आवश्यक कार्यों की तरफ आपके एवं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्षः दिनेश जी, इसको कार्यवाही में शामिल करवा दें।

श्री दिनेश कौशिकः अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में फतेहपुर और पुंडरी गांवों की आबादी लगभग 80 हजार है तथा दोनों गांव एक दूसरे से सटे हुए हैं लेकिन इतनी ज्यादा आबादी के बावजूद भी फतेहपुर व पुंडरी में लड़कियों के लिए अलग से एक भी गवर्नमैंट गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल नहीं है। इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र के दो बड़े गांव ढांड व हाबड़ी में भी लड़कियों के लिए उच्चतर शिक्षा के लिए अलग से गर्ल्स कालेज बने हुए हैं लेकिन गवर्नमैंट गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल नहीं हैं। मैं आपके व सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि उपरोक्त चारों गांवों में इसी सत्र से गवर्नमैंट गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूलों को उपग्रेड किया जाए ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी के 'बेटी बचाओं, बेटी पढाओं' के

सपने को साकार किया जा सके। आदरणीय मुख्यमंत्री जी 31 मई, 2015 को मेरे पुंडरी हल्के में एक विशाल रैली को संबोधित करने के लिए गये थे उन्होंने 50 बेड का सामान्य अस्पताल अपग्रेड करने की घोषणा की थी वह अस्पताल अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अस्पताल वहां पर बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में हजवाना से हाबड़ी गांव जाने वाला रास्ता कच्चा है जिसकी लम्बाई लगभग दो किलोमीटर है। इस रास्ते की चौड़ाई 33 फीट से ज्यादा है तथा सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानदंड पूरा करता है। दोनों गांवों के लोगों को इस कच्चे रास्ते के कारण बहुत असुविधा होती है। इसी प्रकार गांव डीग से रमाणा जाने वाला रास्ता कच्चा है और यह रास्ता भी सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानदंड पूरा करता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त दोनों सड़कों का निर्माण करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के ढांड व पाई बड़े गांव हैं तथा दोनों गांव में पी.एच.सी. हैं। ढांड पी.एच.सी की अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है। वर्तमान समय में पी. एच.सी. किराये की बिल्डिंग में चल रही है। आपसे अनुरोध है कि सरकार ढांड पी. एच.सी. की नई बिल्डिंग का निर्माण अति शीघ्र करवाने का कष्ट करें तथा सरकार से अनुरोध है कि पी.एच.सी. पाई का दर्जा बढाकर सी.एच.सी. बनाई जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में अधिकांश लोग गांव में रहते हैं इन गांवों की अधिकांश आबादी खेतों में डेरों के रूप में रहती है। डेरों पर जाने वाले रास्ते कच्चे होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि डेरों पर जाने वाले कच्चे रास्तों को पक्का किया जाए ताकि यहां पर रहने वाले लोगों की इस मुख्य समस्या को दूर किया जा सके। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करवाया जाए। अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महान सदन में बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री जसबीर देसवाल जी पांच मिनट में अपना वक्तव्य दें।

श्री जसबीर देसवाल (सफीदों): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है यह आम आदमी के लिए, व्यापारी, कर्मचारी, किसान व मजदूर के हक का बजट है क्योंकि इसमें एक भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। अध्यक्ष महोदय, हम वर्ष 1966 में अपने हरियाणा राज्य के गठन के 50 वर्ष पूरे होने पर यह वर्ष

स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इस शुभ वर्ष 2017–18 के लिए 102329.35 करोड़ रूपये के बजट का प्रस्ताव किया गया है जो कि संशोधित अनुमान 2016–17 के 90412.59 करोड़ रूपये पर 13.18 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। ऐसा पहली बार हुआ है जब खाद्यान के खरीद कार्यों को छोड़कर बजट ने एक लाख करोड़ रूपये का आंकड़ा पार कर लिया है। अध्यक्ष महोदय, 102329.35 करोड़ रूपये के बजट परिव्यय में 22393.51 करोड़ रूपये का पूंजीगत खर्च और 79935.84 करोड़ रूपये का राजस्व व्यय शामिल है जो कि क्रमशः 21.88 प्रतिशत और 78.12 प्रतिशत है। अध्यक्ष जी, इस बजट में शहरों की तर्ज पर नयी योजनाओं की पहल की गयी है। तीन वर्ष के अन्दर चरणबद्ध तरीके से आवश्यक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचनाएं सुविधाएं उपलब्ध करवाकर 3000 से 10,000 तक की आबादी वाले 1500 गांवों के विकास के लिए बजट का प्रावधान भी किया गया है। इन गांवों के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपये के व्यय से हरियाणा के महान नेता रहबरे आजम स्वर्गीय चौधरी छोटू राम जी के नाम पर दीनबन्धु हरियाणा ग्राम उदय योजना के नाम से एक नई योजना शुरू की गई है, यह योजना नाबार्ड से वित्त पोषित होगी। वर्ष 2017–2018 के लिए इस योजना हेतु 1200 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव किया गया है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में आधुनिक अवसंरचना के सृजन और मौजूदा अवसंरचना के रख–रखाव के लिए हरियाणा के महान नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय डा0 मंगल सेन जी के नाम से नई योजना 'मंगल नगर विकास योजना' शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2017–2018 में इस योजना के लिए आरम्भ में 1000 करोड़ रुपये का परिव्यय आबंटित करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2017–2018 के लिए सिंचाई और जल संसाधनों के लिए परिव्यय को संशोधित अनुमान 2016–2017 के 2397.68 करोड़ रुपये से 13.62 प्रतिशत बढ़ाकर 2724.26 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2017–2018 के दौरान ग्रामीण विकास, सामुदायिक विकास तथा पंचायतों के लिए 4963.09 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव किया है जो कि संशोधित अनुमान 2016–2017 के 3167.55 करोड़ रुपये पर 56.69 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि है। वर्ष 2017–2018 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 3839.90 करोड़ रुपये आवंटन करने का प्रस्वाव किया गया है। जो कि संशोधित अनुमान 2016–2017 में 3323.95 करोड़ रुपये के परिव्यय से 15.52 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वर्ष 2016–2017 के दौरान 33 राजकीय मिडल एवं हाई स्कूलों को वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का दर्जा

दिया गया है और दो नए स्कूल भी खोले गए। इन सभी स्कूलों में कला, विज्ञान और वाणिज्य विषयों की शिक्षा की सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं और इन विषयों के लिए अध्यापकों के पद भी स्वीकृत किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ मैं अपने सफीदों हल्के की बात करना चाहूंगा जो बहुत पिछड़ा हुआ है हल्का है। सफीदों ही नहीं पूरा जींद जिला ही पिछड़ा हुआ है। उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात सदन के सामने रखना चाहूंगा। 24 मई, 2015 को सफीदों में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक जलसा करवाया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 करोड़ रुपया इलाके की सड़कों के लिए, स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए दिया गया और दो स्कूल अपग्रेड भी किए गए। इससे मुझे काफी सहयोग माननीय मुख्यमंत्री जी का मिला, लेकिन मेरे हल्के में कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जो अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। सफीदों हल्के में दो ब्लॉक हैं एक पिल्लू खेड़ा ब्लॉक है और दूसरा सफीदो ब्लॉक है। पिल्लू खेड़ा ब्लॉक जींद और सफीदो के बीच में पड़ता है, यह जींद से भी 22 किलोमीटर पड़ता है और सफीदों से भी 22 किलोमीटर पड़ता है। पिल्लूखेड़ा में एक कन्या महाविद्यालय की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी से निवदेन करूंगा कि पिल्लूखेड़ा में एक कन्या महाविद्यालय में खुलवाया जाए। मेरे हल्के का खेड़ा खेमावती गांव भी बहुत बड़ा गांव है जिसकी आबादी 7,000 से भी ज्यादा की है, उस गांव में एक हाई स्कूल है और यह गांव सफीदों से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्कूल को अपग्रेड करने के लिए माननीय मंत्री जी यह कंडीशन लगाते हैं कि इस स्कूल की दूरी सफीदों से बहुत कम है। उस गांव की पॉपुलेशन ज्यादा है, स्कूल में बच्चों की संख्या पूरी है। मेरा मंत्री जी से निवदेन है कि खेड़ा खेमावती गांव में जो स्कूल है, उस स्कूल के नॉर्म्स में रिलैक्सेशन देकर उस स्कूल को भी अपग्रेड किया जाए। बुढ़ाखेड़ा गांव जो सफीदो से लगभग 18–19 किलोमीटर दूर पड़ता है, इस गांव में लड़कियों के लिए एक हाई स्कूल है, इस स्कूल को अपग्रेड करके +2 किया जाए। सफीदों विधानसभा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त एरिया है, इसलिए सभी ड्रेनों की खुदाई व सफाई की जाए। सफीदों विधानसभा क्षेत्र में एक गांव भागखेड़ा पड़ता है, बरसात के वक्त गांव व खेत बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। भागखेड़ा गांव के लिए एक पम्प हाऊस लगाया जाए, इसकी प्रपोजल बनकर तैयार हो गई है। सफीदों विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव मुवाना है। जिसकी आधे गांवों की जमीन नहर के पानी से वंचित रह जाती है, इसलिए एक नई माईनर की स्वीकृति

दी जाये। सफीदों विधानसभा क्षेत्र के अधिकतर गांवों में पानी भर जाता है गांवों की पानी की समस्या को देखते हुए, इस समस्या का समाधान किया जाये। पानीपत से जींद रोड को फोरलेन बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी व माननीय श्री गडकरी जी परिवहन मंत्री भारत सरकार द्वारा मंजूर किया था और पिछले बजट में हरियाणा सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन इस फोर–लेन पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। इसी प्रकार से सफीदों विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में बिजली के पुराने तार और ट्रांसफार्म बदले जाएं और तीन 33 के.वी.ए के नये पावर हाऊस बनाये जाएं ताकि लुदाना, बागडु कलां, बागडु खुर्द और करसिन्धू इन तीनों गांवों की बिजली की समस्या का समाधान हो सके। सफीदों शहर के बीचो–बीच 33 के.वी.ए सब–स्टेशन की लाईन गुजरती है। यहां पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, इस लाईन को सफीदों शहर से बाहर किया जाए। इस लाईन को हटाने के बारे में सी.एम साहब ने भी घोषणा की थी। हांसी ब्रांच से लेकर सफीदो–जींद रोड बाईपास तक चार मार्गीय रास्ता बनाये जाए, क्योंकि इस मार्ग पर गाड़ियों, बसों, स्कूल बसों और ट्रक ट्रॉलियों से अनाज मण्डी में जाम लगा रहता है। इस समस्या के समाधान के लिए चार मार्गीय सड़क बनाई जाए। सफीदों विधानसभा क्षेत्र कुछ सड़कों पर गाड़ियों, बसों, ट्रैक्टरों का ज्यादा आना जाना रहता है, इसलिए इन सड़कों को चौड़ा किया जाये। हाट गांव से गांगोली तक की सड़क को चौड़ा किया जाए। सफीदों जींद रोड से सिंघाना मुवाना तक की सड़क को भी चौड़ा किया जाए। सफीदों–पानीपत रोड से निमनाबाद और डिडवाड़ा सालवन तक की सड़क को भी चौड़ा किया जाये। सफीदों में कोई भी ऐसी जगह नहीं है, जिसमें कोई संस्कृति कार्यक्रम कराया जा सके इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सफीदों शहर में एक ऑडिटोरियम बनाने की स्वीकृति प्रदान की जाए। वर्ष 2015 में सफीदों में सी.एम साहब ने ग्रामीण विकास के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की थी, जिसमें से 8 करोड़ रुपये की भी राशि अभी तक खर्च की गई है। इस पूरी राशि को लगाने के लिए डी.सी जींद को आदेश दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं पेयजल योजना के बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि पिल्लूखेड़ा ब्लोक के 15–20 गांवों कां ग्राउंड वाटर खारा है । वहां पर पीने के पानी की सप्लाई के लिए हमने 29 ट्यूबवैल मंजूर करवाये थे लेकिन वहां के अधिकारियों ने रिपोर्ट दी कि वहां पर कैनाल वेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम के तहत पीने का पानी दिया जा रहा है । मैंने इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के ई.आई.

सी. से बात की और उन्हें बताया कि पिल्लूखेड़ा ब्लॉक में जो वाटर टैंक बनाये हुए हैं उनमें 20 साल से पानी नहीं आया है । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि पिल्लूखेड़ा ब्लॉक में पीने के पानी की व्यवस्था की जाये । हमारे मुख्यमंत्री जी 24 मई, 2015 को सफीदों गये थे और 6.20 करोड़ रुपये की जलापूर्ति की घोषणा करके आये थे। वह पैसा पिछले कार्यों में एडजस्ट कर दिया गया । मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी ने जो 6.20 करोड़ रुपये की घोषणा की थी उस पैसे से वहां पर जन स्वास्थ्य का कार्य करवाया जाये । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मेरी परिवहन मंत्री जी से प्रार्थना है कि सफीदो का बस अड्डा शहर के अंदर है इसको बाई पास पर बनवाया जाये और जो बस अड्डे की जगह है वहां पर आई.टी.आई. बनवाई जाये। इसी तरह से सफीदो विधान सभा क्षेत्र के अंदर भम्भेवा बहुत बड़ा गांव है जहां की 400–500 एकड़ जमीन बरसात के दिनों में पानी में डूबी रहती है । वहां पर घड़वाल सीमा पार ड्रेन है । उस ड्रेन में पानी निकालने की व्यवस्था की जाये ताकि उस 400–500 एकड़ जमीन को बाढ़ से बचाया जा सके । घड़वाल (सोनीपत) ड्रेन में पानी डालने के लिए सरकार ने जमीन भी एक्वायर कर रखी है और लोगों ने मुआवजा भी लिया हुआ है लेकिन 15–20 एकड़ जमीन पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है । वह कब्जा हटाकर उस ड्रेन में पानी डाला जाये, जिससे और किसानों को नुक्सान से बचाया जा सके और किसान फसल उगा सकेंगे । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं । जय हिन्द ।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास (रेवाड़ी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा की अनुमति चाहता हूं । मैं गरिमामयी इस महान सदन को अपना शीश झुकाता हूं। ये बजट बड़ा अनोखा है, ना इसमें कोई धोखा है । हरियाणा के इतिहास में पहला बजट ये ऐसा आया है । एक लाख करोड़ से उपर का बजट बनाया है । वित्तमंत्री अभिमन्यु श्री मित्रसेन का जाया है । स्वर्ण जयन्ती पावन वर्ष पर हरियाणा ने ये तोहफा पाया है । बजट ये कल्याणकारी है, सर्वजन का हितकारी है । सबका साथ–सबका विकास की आई अब बारी है । हरियाणा में सड़क बनी फट–फटा–फट, फर–फर–फर, इन सड़कों पर गाड़ी चलती सर–सर–सर । राव नरबीर सिंह ने सड़क बनाई । कर दी सब की मन की चाही । बजट में कोई प्रावधान कराओ, चार करम के रास्ते बनवाओ । शिक्षा को लेकर बजट में गंभीरता बड़ी दिखाई है । पिछले बजट की तुलना में 19 प्रतिशत की वृद्धि पाई है । इसी

बजट में शिक्षा के लिये 14 हजार करोड़ की राशि बताई है इसके लिए राम बिलास शर्मा जी को हो बधाई । देखो खेलों का कमाल खिलाड़ी हो रहे मालामाल । खेल नीति ऐसी बनाई, जो दुनियां में जाये सराही । 59 परसेन्ट की वृद्धि से 535 करोड़ की राशि है पाई । **(इस समय उपाध्यक्ष महोदया चेयर पर आसीन हुई ।)** लिंगानुपात का अंतर मिटाकर एक चमत्कार दिखलाया है। गांव का विकास होगा, सीवर, पानी का इंतज़ाम होगा, योजना है अब ऐसी भाई हो जायेगी अब मन की चाही। बढ़ता घाटा कम हो जायेगा, घटकर एक परसैंट रह जायेगा। यो है पारदर्शी सरकार मिटाये पूरा भ्रष्टाचार। व्यवस्था का परिवर्तन होगा, नवयुग का निर्माण होगा, एक योजना और जोड़ना। व्यवस्था का परिवर्तन होगा, नवयुग का आरम्भ होगा। दीन बंधू ग्राम योजना और मंगल नगर विकास योजना। एक योजना और जोड़ना इसमें राव तुला राम का नाम खोजना। स्वतंत्रता सेनानियों का मान बढ़ेगा और सैनिकों का सम्मान बढ़ेगा। जब होगा अच्छी चिकित्सा का इंतज़ाम तभी होगा बढ़िया काम। हर जिले में मेडिकल कॉलेज का प्रावधान तभी इलाज का पुख्ता होगा काम, स्वास्थ्य व खेल मंत्री विज साहब करेंगे पुख्ता इंतज़ाम। उन्नत बीज लाओ, मिट्टी की जांच करवाओ। खेत में बिजली पानी का समुचित इंतज़ाम होगा, साथ में फसल बीमा योजना का प्रावधान होगा। फिर सारी की सारी शक्ति लगाकर सरकार की, किसान की आमदनी को डबल करने का इंतज़ाम होगा। यह बजट है कल्याणकारी, सर्वहितकारी, मंगलकारी, उन्नतकारी और परोपकारी। कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने खेली बहुत अच्छी पारी।। अब सुनियो सदन महान मेरे हल्के की बारी आई है। गौरवमयी इतिहास हमारा, सन् 1962 में चीन से हुई लड़ाई है और रेजांगला की चोटी पर कुदरत ने बर्फ बिछाई है। 18000 फुट की ऊंचाई पर माइनस ज़ीरो तापमान बताया है, ना खाद्यान्न था, न कपड़े थे और हथियारों का भी अभाव पाया है। पर भारतीय सेना की कुमाऊं टुकड़ी ने गजब की करी लड़ाई थी। चीन पापी ने धोखा कर दिया, 11000 सेना भिजवाई थी, खूब लड़े मर्दाने यादव छाती में गोली खाई थी। जब ये लड़ाई चल रही थी कवियों ने गाने गाये थे और चलती–चलती लड़ाई में वीर जवानों ने गाना गाया था – वतन की आबरू खतरे में है तैयार हो जाओ। कार्तिक बदी अमावस्या थी और दिन था खास दिवाली का पता लगा जब शहादत का लता मंगेशकर ने गाना गाया था – ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, जो माननीय सदस्य श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास जी ने कुमाऊं रैजीमैंट की बात कही है मैं इस बारे में पूरे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि यह जो कुमाऊं रैजीमैंट थी उस समय उसको मेरे पूज्य पिता जी ब्रिगेडियर आत्मा सिंह जी कमांड कर रहे थे। He was Commandant at that time.

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास : उपाध्यक्ष महोदया, इसके लिए मैं इनको ऐप्रीशिएट करता हूं। मैं इसके लिए आपको भी बधाई देना चाहता हूं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपने क्षेत्र की कुछेक डिमाण्ड रखना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी धारूहेड़ा में उपमण्डल बनवा दो, साथ में एक ब्लॉक खुलवा दे। औद्योगिक क्षेत्र धारूहेड़ा की सड़कों का जर्जर हाल है, सन् 1977 के बाद रिपेयर नहीं हो पाई यही मलाल है, हुडा इस औद्योगिक क्षेत्र को एच.एस.आई.आई.डी.सी. को सौंपेगा, कब सौंपेगा बहुत ढीली चाल है। रेवाड़ी के बाई–पास की लम्बित बात पुरानी है, प्रावधान कर दो इसी बजट में ताकि सुलट जाये कहानी है। जी.एच., रेवाड़ी की दो साल से बिल्डिंग तैयार है, बनी–बनाई उस बिल्डिंग में रैम्प का इंतज़ार है।

माजरा श्योराज गांव ने 27 एकड़ जमीन दिये 10 साल हो गये,

पूर्व सरकार में घोषित मेडिकल कॉलेज खोलने के दस्तावेज कहां खो गये ।

अब मनोहर लाल जी आप ही करो सुनवाई है ।

उद्योगों में इज ऑफ डूईंग बिजनेस में सरकार का सहयोग है ।

स्थानीय बच्चों को मिले नौकरी में रोजगार देने में सहयोग है ।

करो कुछ सार्थक उपाय,

सोचो करो उपाय ।

सभी कर्मचारियों का कर लो ध्यान, पंजाब समान कर दो वेतनमान ।

हमारी अस्मिता का सवाल,

नहरी पानी का सवाल,

दक्षिणी हरियाणा का बुरा हाल ।

नई नहरों का इंतजाम करा दो, बजट में 2700 करोड़ का प्रावधान दिखा दो ।

स्पीड बढ़ा कर इस योजना को आगे और बढ़ा दो,

अगर हम लेट करायेंगे तो धोखेबाज कहलायेंगे ।

सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद मनायेंगे, एस.वाई.एल. का पानी पायेंगे ।

प्रेजिडेंशियल रेफ्रैंस 13 वर्ष से लम्बित थी, की पैरवी करी,

हरियाणा की जनता के हित की बात करी ।

एक ध्यान मैं और दिलाता हूं, मैं सच्ची बात बताता हूं ।

कालोनियों का डिवैल्पमैंट चार्ज, हजारों रुपये की गिर गई गाज ।

जनता पुकार लगाती है, इसे बहुत घटवाना चाहती है ।

गरीब जनता को न्याय मिले, प्रदेश में फिर से कमल खिले ।

उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

श्री मूल चन्द शर्मा (बल्लभगढ़) : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । मैं वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने हरियाणा प्रदेश के लिए पंजाब से भी बड़ा बजट पेश किया है । 01 नवम्बर, 1966 को अलग हरियाणा का गठन हुआ था तथा श्री धर्मबीर जी हरियाणा प्रदेश के पहले राज्यपाल बने । आज हम उस दिन को याद करते हैं जब लोग कहा करते थे कि राजस्थान से लगता हुआ ये इलाका अमन और शांति में पंजाब से आगे निकल जायेगा । आज वह बात सत्य साबित हो गई है क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश का बजट पंजाब से अधिक हो गया है। यह काम यहां की ढ़ाई करोड़ जनता, यहां के उद्योगपतियों, यहां के व्यापारियों, यहां की ईमानदारी तथा यहां की सरकार के कारण हो पाया है और मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को भी बधाई देना चाहता हूं। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है । इस बजट में सड़क, शिक्षा, कल्चरल अफेयर तथा खेल पर विशेष ध्यान रखा गया है उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इससे कांग्रेस के समय में जो काम रूके हुये थे उन पर काम शुरू

हो सकेगा । आज तक जिन सड़कों पर नाम था आज उन पर काम हो रहा है । आज आप सोनीपत, गुड़गांव या पलवल में देख लीजिए, हर तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है । इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में जो लोग सीवरेज लाइन और पानी के लिए तरसते थे आज वहां पर बहुत तेजी से काम हो रहा है । उपाध्यक्ष महोदया, इसी प्रकार से अब मैं नहरी पानी के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं। हमारे दक्षिण हरियाणा गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और मेवात में जो नहरी पानी जाता है वह आगरा कैनाल से जाता है । मैंने पिछले सत्र में भी यह बात कही थी कि आज हरियाणा में जो सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं वे गुड़गांव, फरीदाबाद और मेवात के क्षेत्र में हैं । उसका मुख्य कारण यह है कि दिल्ली का सीवरेज का पानी बिना ट्रीटमैंट हुये उस एरिया में जाता है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला खटकः उपाध्यक्ष महोदया, आप मेरी बात भी सुनिए।

उपाध्यक्ष महोदयाः शकुन्तला जी, अभी आप बैठिए।

श्री मूल चन्द शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, हमारे हरियाणा प्रदेश में उद्योगों का जो विकास है वह पूरे हरियाणा प्रदेश में समान रूप से किया गया है । भाई विपुल गोयल के नेतृत्व में फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात में उद्योगों को जो बढ़ावा मिला है। उसके लिये मैं सरकार का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं । हरियाणा प्रदेश में उद्योगों के बजट की तुलना में सैंटर में रेल का अत्यधिक बजट हुआ करता था । आज पहली बार सैंटर के रेल का बजट और हरियाणा प्रदेश का उद्योगों का बजट एक हुआ है । इस बजट में रेल के लिये हमारे वित्त मंत्री जी ने जो 80 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है उसके लिये मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि जो हरियाणा प्रदेश के लोग अपनी बात को सैंटर गवर्नमैंट में नहीं कह पाते थे । अब वह बात हरियाणा प्रदेश की सरकार को कह सकते हैं । उसमें चाहे कोई स्टेशन बनाने की बात है, चाहे रेलवे लाईन बनाने की बात है । इसके लिये जो कार्य जिलावार होने हैं और उसके लिये सरकार ने जो प्रावधान रखा है । उसके लिये मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । हमारे मुख्यमंत्री जी ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश बेटियों के नाम से पहले सबसे नीचे था लेकिन हमारी सरकार आने के बाद आज सबसे ऊपर है । इस बात के लिये हरियाणा सरकार को मैं बधाई देता हूं । इसके साथ ही मेरे क्षेत्र की छोटी–छोटी समस्याएं हैं जिनके समाधान के लिये मुख्यमंत्री जी ने हमें डेढ़ सौ

करोड़ रूपये दिये हैं । जिसमें हमारे क्षेत्र की सड़कें, सीवरेज और नालियों का काम होना है । हमने अपने क्षेत्र के लिये न तो कोई यूनिवर्सिटी मांगी, न कोई मेडिकल कॉलेज मांगा, न आई.टी.आई. मांगी और न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज मांगा है क्योंकि हमारे क्षेत्र में कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं है । वहां तो तमाम भारत के लोग रहते हैं और वह 50 गज, 80 गज, 100 गज और 150 गज के मकान में रहने वाले लोग हैं । मेरी विधान सभा में सिर्फ 100 लोग ऐसे होंगे जो 500 गज के मकान में रहते हैं । उसके अलावा 60, 80, और 100 गज के मकानों में रहने वाले लोग रहते हैं। हमारी विधान सभा में एग्रीकल्चर लैंड नहीं है । हमारे क्षेत्र के लोग तो यह चाहते हैं कि उनके लिये पीने का पानी हो, चलने के लिये सड़क हों, सीवरेज हों, नाली हों और उनके हाथ के लिये रोजगार हों । मेरे बल्लभगढ़ विधान सभा के साथ चन्दावली में जो आई.एम.टी. है वहां के लोग यही चाहते हैं कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और हमारे लोगों को हाथ का दस्तकार मिले क्योंकि वहां इस तरह के लोग रहते है जो रोजाना कमाते खाते हैं । मुख्यमंत्री जी ने 6 फरवरी, 2016 को हमें उनके विकास के लिये 100 करोड़ रूपये दिये हैं । उसके लिये मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इसमें हमारा 30–40 प्रतिशत काम लोकल बॉडी विभाग से संबंधित है । इसके लिये हम बहन कविता जैन जी से हस्ताक्षर करवाते रहे हैं। फरीदाबाद से फाईल लेकर हम बहन कविता जैन जी के पास जाते रहे और बहन कविता जैन जी फाईलों पर हस्ताक्षर करती रही है। उसके लिये मैं बहन कविता जैन जी का भी धन्यवाद करता हूं । हमारे पास निगम के अलावा और कोई फंड नहीं है । न पंचायती राज है और न कोई दूसरा फंड है । केवल एक लोकल बॉडी विभाग का फंड है । इसके अलावा जिसकी मैं बात कर रहा था वह गुड़गांव कैनाल है। यहां श्री करण दलाल जी बैठे हैं, भाई ललित जी यहां बैठे हैं, टेक चन्द शर्मा जी बैठे हैं । ये सारे चाहे अलग–अलग पार्टियों में हों लेकिन हमारे तीन जिलों फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात की जो हालत है उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि आगरा कैनाल में जो पानी बहता है उसमें दिल्ली की फैक्ट्रियों का अनट्रीटिड पानी डाला जाता है । उस पानी को हमारे पशु पीते हैं या हमारे किसान उसमें फसल उगाते हैं । जिससे कैंसर को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलता है । आज सभी सदस्यों ने पानी के लिये एस.वाई.एल. नहर की बात की है । हम तो यह कहते हैं कि आज हमारे इलाके में पानी की इतनी बड़ी किल्लत है कि उसके समाधान के लिये आगरा कैनाल के पानी को साफ करके ही हमारे नालों में डाल

दो । हमारे इलाके की यह हालत है । दिल्ली देश की राजधानी है जिसका सारा अनट्रीटिड पानी गुड़गांव कैनाल में डाला जाता है जो मेवात में जाता है जिसको मेवात के लोग ट्रीट करके पीते हैं । आप यह समझ सकते हैं कि वहां के लोगों की क्या हालत है । पिछले दस सालों में कांग्रेस की सरकार वहां के लोगों को बहकाती रही कि हम आपके क्षेत्र के लिये पानी लेकर आएंगे । श्रीमती सोनिया गांधी ने भी यहां पर रैली की थी जिसमें यह कहा था कि मैं एस.वाई.एल. नहर का पानी लेकर आऊंगी लेकिन आज तक उन लोगों को पानी नहीं मिला । इस बात को कहते हुए न जाने कितनी राजनीतिक पार्टियां बदल गई । एस.वाई.एल. नहर के नाम पर बहुत से लोगों ने यह कहा है कि हम भाखड़ा का पानी लेकर आएंगे । जिसको हमने बचपन में सुना था कि भाखड़ा का पानी मिलेगा लेकिन आज तक भी हमारे दक्षिण हरियाणा के इलाके के लोगों को पानी नहीं मिला है । उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रदेश में हर जिले की अपनी–अपनी समस्या है । हमारे इलाके के लोग केवल पानी मांगते हैं । वहां के लोग सरकारी नौकरियां भी नहीं मांगते क्योंकि वहां प्राईवेट उद्योग बहुत हैं । नोएडा हमारे जिले से बिल्कुल सटा हुआ है । हमारे राव नरबीर मंत्री जी बैठे हुए हैं । मैं उनको कहना चाहूंगा कि हमारा तिगांव विधान सभा और पृथला विधान सभा में मंझावली गांव में एक पुल बना हुआ है जो ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है और जो ग्रेटर नोएडा जाने के लिये वहां के लोग कालिंदी कुंज से होकर निकलते हैं । हमारे वहां पर एक भी सड़क फोर लेन की नहीं है । जो तिगांव विधान सभा क्षेत्र है वहां से केन्द्रीय मंत्री श्री कृष्ण पाल गुज्जर जी विधायक भी रहे हैं और अब केन्द्रीय मंत्री हैं । वहां का एक भी रास्ता ऐसा नहीं है जो फोर लेन का हो । यह मान कर चलो कि तिगांव गांव से मंझावली तक का रास्ता बहुत खराब है। वहां महीने में कम से कम 20 मौतें एक्सीडैंट से होती हैं । इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि उस रोड़ को चौड़ा करवाने का काम करें । ग्रेटर फरीदाबाद के रास्तों की यह हालत है कि वहां से निकलना भी नागवार हो चुका है, अतः इनको बाई–पास से जोड़ने की बहुत जरूरत है। लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई को अपना आशियाना खरीदने में लगा दिया है लेकिन जिन बिल्डिंगों में यह लोग रहते हैं, उनमें सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है और इन बिल्डिंगों में हालत इस तरह खराब हो चुके हैं कि लोगों के लिए न तो पीने के पानी की व्यवस्था है और न ही सीवरेज की कोई व्यवस्था की गई है। भारत के दूसरे प्रांतों से भी लोग

ग्रेटर फरीदाबाद में बसने के लिए आये हैं। इन लोगों ने बिल्ड़रों के पास अपनी जीवन भर की कमाई देकर आशियानें खरीदे हैं और आज सुविधाओं के लिए त्राही–त्राही करते फिर रहे हैं। आज बिल्ड़रों ने फरीदाबाद की यह हालत कर दी है कि आम व्यापारी, कर्मचारी और आम जन रोता फिर रहा है कि बिल्डरों ने सारा धन भी खसोट लिया और बावजूद इसके उन्हें मकान भी नहीं दिए जा रहे हैं। दुकानदारों ने अपनी दुकान बेच कर और कर्मचारियों ने अपनी रिटायरमैंट पर मिले पैसे से अपना आशियाना खरीदने के लिए पैसे लगाये थे लेकिन उनके पैसे भी लूट लिए गए हैं और मकान भी नहीं दिया है। अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि फरीदाबाद के बे–लगाम बिल्ड़रों पर लगाम लगाने का काम किया जाये। फरीदाबाद के इन बिल्डरों ने कम से कम 4000–5000 करोड़ रूपये ब्याज के रूप में मकान की चाह रखने वाले से वसूल कर लिए है और बावजूद इसके मकान न देकर मकान खरीदने वालों के साथ धोखा किया जा रहा है। अतः सरकार को इन बिल्ड़रों पर लगाम लगानी चाहिए। अगर आम आदमी की गाढ़े खून पसीने की कमाई हुई पूंजी को इस तरह बिल्ड़रों द्वारा हड़प लिया जायेगा तो लोग कहां जायेंगे? इतनी विकट हालत आज फरीदाबाद की हो गई है। इसके अतिरिक्त दिल्ली से लेकर फरीदाबाद व पलवल तक यमुना के किनारों पर अवैध खनन हो रहा है और माफिया दिन प्रतिदन पनपता ही जा रहा है। जब हरियाणा प्रदेश में चौधरी बंसी लाल की सरकार थी तो जब उन्होंने प्रदेश में शराब बंदी लागू कर दी तो प्रदेश में बहुत बड़ा शराब माफिया पैदा हो गया था और इन शराब माफियाओं को हरियाणा प्रदेश से निकालने में बहुत लंबा समय लगा था। एक बार माफिया जब पैदा होते हैं तो वह पैसे के बल पर बहुत बड़े व्यापारी बन जाते हैं और क्रिमिनल बन जाते हैं। आज यमुना के किनारों पर जो रेत की स्मगलिंग की जा रही है, वहां पर 5000 रूपये में रेत का ट्रक भरा जाता है। रात को पुलिस के नेतृत्व में पलवल और फरीदाबाद में 350–400 बड़े–बड़े ट्रक और डम्पर और ट्रैक्टरों की तो कोई गिनती नहीं, लाईन लगाकर रेती व बजरी की स्मगलिंग के काम में लगे रहते हैं। कहते हैं कि पंचकूला में इन खनन माफियाओं पर लगाम लगी है, मुझे इस बात का पता नहीं है लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि यदि इन खनन माफियाओं पर लगाम नहीं लगाई गई तो यह बेलगाम हो जायेंगे और एक दिन सत्ता पर हावी होकर देश और प्रदेश को गर्त में ले जाने

का ही काम करेंगे। मेरा पुरजोर अनुरोध और विनती है कि सरकार इन खनन माफियाओं पर लगाम लगाने का कार्य करे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मूल चंद शर्मा जी से निवेदन है कि क्यों न सदन में उन माफियाओं के नाम बता दिये जायें?

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, ऐसे बीच में इंट्रप्ट करना ठीक नहीं है, आप प्लीज बैठिए।

श्री मूलचंद शर्माः अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में पहले से जो कॉलोनियां है उनमें ही डिवैलपमैंट नहीं है और इसके अतिरिक्त 10–10 एकड़, 20–20 एकड़ तथा 100–100 एकड़ में और भी अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। जब पूर्ववर्ती कॉलोनियों में ही बेसिक सुविधायें उपलब्ध नहीं हो सकी है तो फिर इन अवैध कालोनियों का निर्माण कहीं न कहीं लोगों में असंतोष पैदा करने का ही काम करेगा। अतः सरकार को अवैध कॉलोनाइजर्स पर भी लगान लगाने की जरूरत है। सत्ता का आना–जाना तो लगा ही रहता है, यदि इस तरह की एक्टिविटीज पर रोक नहीं लगाई गई तो लोग सदा अपने जनप्रतिनिधियों के पास पानी, सीवरेज व अन्य दूसरी प्रकार की सुविधाओं के लिए आते ही रहा करेंगे। आज प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनसे अवैध कॉलोनियों के लिए मनमाने ढंग से पैसे वसूल किए जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा कॉलोनियां गुरूग्राम, फरीदाबाद, करनाल, सोनीपत, पानीपत व रोहतक में स्थित हैं। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि हरियाणा में स्थित कालोनियों के डिवेल्पमैंट, पानी, सीवरेज, बिजली, सड़कें व अन्य सुविधाओं को प्रदान कराने की दिशा में मजबूती से कार्य किया जाये। उपाध्यक्ष महोदया, फरीदाबाद की कुल जनसंख्या तकरीबन 22 लाख है। पुराने फरीदाबाद के हिस्से में चार इलाके आते हैं जिनको क्रमशः इलाका संख्या–1, 2, 3 व इलाका संख्या–4 के नाम से जाना जाता है। यहां पर पाकिस्तान से माईग्रेटिड हुए लोग रहते हैं। यह एक भीड़–भाड़ वाला इलाका है और उद्योग भी यहां पर बहुत बड़ी संख्या में है। फरीदाबाद दो हिस्सों में बंटा है। फरीदाबाद का एक भाग रेलवे लाईन के साथ लगता है जबकि दूसरा भाग यमुना नहर के साथ लगता है। फरीदाबाद में तीन आर.ओ.बीज. हैं। 22 लाख की जनसंख्या वाले इस शहर को मात्र इन तीन आर.ओ.बीज. का प्रयोग करके एक दूसरे भाग में जाना पड़ता है। केवल मात्र तीन आर.ओ.बीज. होने की वजह से पुलों पर घंटों जाम की

स्थिति बनी रहती है और आम जन–जीवन थम सा जाता है और चलने तक के लिए रास्ता नहीं बचता है। अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि यहां पर और ज्यादा आर.ओ.बीज. बनाने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदया, वर्तमान में केन्द्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तासीन है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तासीन है। आम आदमी ने भारतीय जनता पार्टी को दिल खोलकर खुले मन से वोट दिए थे और उनका मान रखते हुए हमारी प्रदेश सरकार ने भी सत्ता में आते ही सबका साथ–सबका विकास और हरियाणा एक–हरियाणवी एक की मूर्त अवधारणा पर चलने का काम किया है। अब यह नहीं हो रहा है कि केवल मात्र रोहतक व झज्जर में ही विकास हो रहा हो, जबकि पहले जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व शासन में होता था, केवल उसी का विकास होता था। जैसे यदि शासन में प्रतिनिधित्व झज्जर का था तो अकेले झज्जर में ही 14 कॉलेज खोल दिए गए थे, अगर शासन में प्रतिनिधित्व महेन्द्रगढ़ जिले का था तो महेन्द्रगढ़ में 16 कॉलेज खोल दिए गए और यदि शासन में प्रतिनिधित्व नहीं होता था तो उसके उदाहरण के रूप में फरीदाबाद को देखा जा सकता है जहां पर महज 4 गवर्नमैंट कॉलेज ही हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐजुकेशन के नाम पर भी असमानता करने का प्रयास होता रहा। प्रदेश के जिस क्षेत्र से मुख्यमंत्री बना उसने अपने जिले में कोई कमी नहीं छोड़ी और जिस क्षेत्र का नेतृत्व कमजोर रहा, उस क्षेत्र के लोगों को न कॉलेज मिला, न कोई यूनिवर्सिटी मिली, न कोई आई. टीज. मिली और न कोई इंजीनियरिंग कालेज ही मिला। उपाध्यक्ष महोदया, आज दक्षिण हरियाणा में पीने का पानी बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। गुरूग्राम और फरीदाबाद के ज्यादातर हिस्से का पानी लगभग खारा हो चुका है। यमुना नदी के साथ–साथ किसानों के खेतों में जो ट्यूबवैल्ज लगाये गए हैं उनके पानी का स्तर भी 40 फीट नीचे चला गया है। वहां का किसान रोता है कि हमारे क्षेत्र में सैकड़ो ट्यूबवैल्ज लगाकर हमारे पानी को मेवात, गुड़गांव और फरीदाबाद के क्षेत्र में लेकर चले गए और हमारी हालत यह कर दी कि वहां का पानी जो दस फूट पर था..... (विघ्न) मैं सिर्फ दो शब्द और कहूंगा । डिप्टी स्पीकर महोदया, जब तक यमुना नदी पर बैराज नहीं लगेगा तब तक वहां के किसानों को ठीक ढंग से पानी नहीं दिया जा सकेगा । वहां के किसानों के खेतों से पीने का पानी लिया जा रहा है । यमुना के किनारे पहले 20 फुट पर पानी निकलता था लेकिन आज 70–80 फुट पर पानी मिल पा रहा है । हमारे क्षेत्र से पीने का पानी भी ले लिया गया और यमुना नदी से

जो पानी हमारे क्षेत्र में आता है उसमें बहुत ज्यादा बीमारी है क्योंकि यमुना नदी में दिल्ली का तमाम गंद बहता है । यमुना नदी पानी के साथ–साथ दिल्ली का गंद भी हमारे खाते में आता है । दिल्ली के दूसरी तरफ जो नीला पानी है वह दूसरों के खाते में जाता है । अतः दक्षिणी हरियाणा की बहुत बुरी हालत है । डिप्टी स्पीकर महोदया, रिवाड़ी और महेन्द्रगढ़ की हालत तो आप जानती ही हैं । हमने बचपन में सुना था कि दक्षिणी हरियाणा में पानी लाएंगे । कितने मुख्यमंत्री आए और चले गए लेकिन वहां पानी नहीं आया । मुझे उस दिन बड़ी खुशी हुई थी जिस दिन माननीय सदस्य डॉ. अभय सिंह यादव ने एक सर्वे करवाया था । उस सर्वे में इन्होंने दो महीने लगाए थे । अब एक विधायक दल की मीटिंग में माननीय सदस्य डॉ. अभय सिंह यादव ने दक्षिणी हरियाणा के लिए जो ड्रेनेज की योजना बनाई थी उसके लिए हमें 27 करोड़ रूपये मिलेंगे । मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कुछ लोग दक्षिणी हरियाणा का पानी मांगते हैं । दक्षिणी हरियाणा के लोग सेना और नौकरियों में सबसे आगे हैं । अगर इन्हें पीने का शुद्ध पानी मिल जाए तो उस इलाके का उद्धार हो जाएगा । आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । जय हिन्द । जय भारत ।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल) : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । जब माननीय सदस्या किरण चौधरी जी बोल रही थी तो मैंने माननीय वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को एक बात याद दिलाई थी । मैं उसे रिपीट करता हूं । इन्होंने बजट में एस.वाई.एल. कैनाल के लिए सौ करोड़ रूपया निर्धारित किया है । जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो वे पलवल में आये थे । माननीय मंत्री जी अपने अधिकारियों या गवर्नमैंट से इस बात का पता करें कि जब चौधरी बंसीलाल जी मुख्य मंत्री थे तो वहां भारत सरकार ने यह एलान किया था कि भविष्य में जब भी एस.वाई.एल. कैनाल का निर्माण होगा उसका तमाम खर्चा भारत सरकार देगी । जब भारत सरकार ने इस एस.वाई.एल. नहर के निर्माण का खर्च अपने ऊपर लेने की घोषणा की हुई है तो अब उसका पैसा उनको देना चाहिए । एक नीतिगत तौर पर यह फैसला हो चुका है । मैं पूछना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार बिना वजह अपने खजाने से सौ करोड़ रूपये निकालकर क्यों दे रही है ? मैं कहता हूं कि हरियाणा सरकार को भारत सरकार की वह घोषणा याद दिलानी चाहिए । हरियाणा सरकार के रिकॉर्ड में से वे दस्तावेज निकालें और चैक करें कि यह भारत सरकार ने एलान

कर रखा है कि जब भी एस.वाई.एल. कैनाल बनेगी तो उसका तमाम का तमाम पैसा भारत सरकार देगी । इससे सरकार उन सौ करोड़ रूपयों को कहीं और इस्तेमाल कर सकती है । अभी हैल्थ मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे नहीं है । डिप्टी स्पीकर मैडम, मैं आपके मार्फत सदन को बताना चाहता हूं कि एक क्लीनिकल इस्टैबिलशमैंट ऐक्ट, 2013 पास हुआ था । जो प्राइवेट हौस्पिटल्ज हैं, उन्होंने इतने मनमाने तरीके से लोगों को लूटने का इंतजाम किया हुआ है कि कोई एक दफा वहां चला जाए फिर वे आदमी का नहीं उसकी जेब का इलाज करते हैं । वे तीन–तीन लाख, चार–चार लाख और कइयों का तो 15–15 लाख रूपये का बिल बना देते हैं । अगर उनका कोई समाधान है तो इस क्लीनिकल इस्टैबिलशमैंट एक्ट, 2013 में है । इसमें यह प्रोविजन है और एक डिक्लेरेशन भी है । महामहिम राज्यपाल जी ने उस एक्ट को पारित किया हुआ है । उसमें डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर लेवल पर अथॉरिटीज कांस्टीच्यूट होनी हैं जिसमें कुछ प्राइवेट लोग और कुछ गवर्नमैंट के होंगे । अगर किसी व्यक्ति को किसी क्लीनिक या हॉस्पिटल ने ज्यादा बिल दे दिया और उसे इलाज का कोई शिकवा–शिकायत है तो वह केस उस अथॉरिटी के सामने रिप्रैजेंट किया जाएगा । वह अथॉरिटी तय करेगी कि ये कितना पैसा ज्यादा ले रहे हैं और अगर इलाज ठीक नहीं हुआ है तो उसकी जिम्मेवारी भी किसके ऊपर है ? अब हैल्थ मिनिस्टर साहब सदन में बैठे नहीं हैं । वे बातें बहुत लम्बी–चौड़ी करते हैं । (विघ्न) मैं जानना चाहता हूं कि हैल्थ मिनिस्टर साहब उन अथॉरिटीज को क्यों नहीं बना रहे हैं जबकि मेरे सवाल के जवाब में विधान सभा में उन्होंने हां भी की हुई है कि वे उन अथॉरिटीज को कांस्टीच्यूट करेंगे । अतः वे इसको जल्दी से जल्दी बनाएं जिससे कि फरीदाबाद, गुड़गांव और हरियाणा के चारों तरफ उद्योगपतियों ने बड़े–बड़े अस्पताल खोलकर लोगों को लूटने का जो एक धंधा बनाया हुआ है उससे लोगों को राहत मिल सके। पिछले दिनों हुडा प्लॉटस के बारे में अखबार में पढ़ा है कि सरकार ने ई–ऑक्शन के जरिए काम शुरू किया है। उपाध्यक्ष महोदया, शायद सरकार के संज्ञान में नहीं है कि पिछले दिनों पंचकुला में रिहायशी प्लॉटों का जो ई–ऑक्शन हुआ वह केवल मात्र एक दिखावा था। सरकार के अधिकारियों की लॉटरी लगी हुई है क्योंकि वे अपने रिश्तेदारों और चहेतों को हुडा के प्लॉट अलॉट करने में लगे हुए हैं। चाहे सरकार इस बात की इन्क्वॉयरी करवा लें कि इस प्रक्रिया में क्या–क्या धांधलियां हुई हैं? अगर कोई यह कहता है कि यह ई–ऑक्शन प्रक्रिया ठीक है तो मेरा ऐतराज यह है

कि जब पहले हुडा कांस्टीच्यूट अथॉरिटी हुआ करता था, वह प्रॉफिट अर्निंग अथॉरिटी नहीं बल्कि वह लोगों को नो प्रॉफिट नो लोस पर मकान बनाने के लिए गठित हुआ था। आज जैसे माननीय सदस्य मूल चंद शर्मा जी ने भी कहा कि जो गरीब आदमी हुडा विभाग के सैक्टरों में बसना चाहते हैं तो सरकार को ई–ऑक्शन की प्रक्रिया को समझना चाहिए क्योंकि सरकार के खजाने को लूटा जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदया, जो व्यक्ति इसके हकदार हैं उनको प्लॉट देने की बजाय सरकार के अधिकारी अपने चहेतों और रिश्तेदारों को प्लॉट दे रहे हैं। इस पर सरकार अपना वक्तव्य जरूर दे। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और बजट में भी पंचकुला जिले के मोरनी में विश्व हर्बल फॉरेस्ट पार्क विकसित करने के लिए बाबा रामदेव और पतंजलि को जमीन देने की बात कही गई है। उपाध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मेरा इसके बारे में यह कहना है कि पंचकुला शहर के साथ लगते मोरनी की जमीन वेशकीमती है और दुनिया भर के इंटर–प्रिन्योर्स की नजरें उस जमीन पर हैं जिससे हरियाणा का भला हो सकता है। यह सरकार इस वेशकीमती जमीन को केवल बाबा रामदेव को ही इसलिए दे रही है क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी के बाबा है। इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन सरकार को चाहिए कि इस वेशकीमती जमीन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर टैंडर आमंत्रित करें ताकि बाबा रामदेव से भी बढ़िया विश्व हर्बल फॉरेस्ट पार्क स्थापित करने वाले मिल सके। उपाध्यक्ष महोदया, सरकार अपने ही ब्रांड अम्बेसडर बाबा रामदेव का ही फेवर कर रही है, इस पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि यह भ्रष्टाचार का जरिया है।

डॉ. अभय सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदया, आज सुबह भी बाबा रामदेव के बारे में अपशब्द बोले गए थे। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव ना तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ना ही कांग्रेस पार्टी के हैं और ना ही किसी अन्य पार्टी के हैं, वे सिर्फ विश्व प्रख्यात योग गुरू हैं। बाबा रामदेव ने हर्बल के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल को आज सुबह भी बता दिया था कि बाबा रामेदव को कोई जमीन हस्तांतरित नहीं की गई है। सरकार ने पंचकुला जिले के मोरनी में विश्व हर्बल फॉरेस्ट पार्क विकसित करने के लिए बाबा रामदेव और पतंजलि के साथ एम.ओ.यू. साईन किया है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं नहीं समझता कि हर्बल के क्षेत्र में बाबा रामदेव से ज्यादा कोई जानकार

विश्व में होगा। मेरा माननीय सदस्य भाई करण सिंह दलाल जी से अनुरोध है कि राजनीति करने के लिए और बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन इस अच्छी चीज पर राजनीति न करें, हर्बल फॉरेस्ट पार्क को प्रदेश में स्थापित होने दीजिए।

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में यह भी कहना चाहता हूँ कि मनरेगा के तहत जो पंचायते काम करवाती हैं उनकी कई साल से पेमैंट नहीं हो रही है, जिससे लोगों में काफी नाराजगी है और पंचायतों को भारी नुक्सान हो रहा है। इसकी भी जांच करवाकर इस बात का भी पता लगवाया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदया, भाई डॉ. अभय सिंह यादव ने कहा है कि बाबा रामदेव को जमीन हस्तांतरित नहीं की गई है बल्कि हर्बल पार्क स्थापित करने के लिए सिर्फ एम.ओ.यू. साईन हुआ है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके मार्फत भाई यादव जी से कहना चाहता हूँ कि एम.ओ.यू. की भी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में आप दूसरे लोगों को भी मौका दीजिए, हो सकता है कि वह बाबा रामदेव से भी बढ़िया हर्बल पार्क प्रदेश में स्थापित कर दें। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूँ कि दिनांक 3 मार्च, 2017 को अंग्रेजी के दि ट्रिब्यून अखबार में एक आर्टिकल ''Remembering khizar Hayat Tiwana'' छपा है। ये आजादी से पहले हमारे हरियाणा के प्रीमियर हुआ करते थे, उसके बारे में लेख छपा है। उपाध्यक्ष महोदया, वे इतने ईमानदार मुख्यमंत्री थे कि उनके मंत्री मण्डल के किसी सदस्य ने कहा था कि मेरे बेटे को नौकरी दी जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी बच्चे मेरे बेटे हैं, इसलिए आपके बेटे को बिना टैस्ट पास हुए या बिना नियमानुसार नौकरी नहीं दी जा सकती। इस बात पर नाराज मंत्री ने मंत्री पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी तो उन्होंने इस बात की कभी परवाह नहीं की। इसी तरह जब वह शिमला गए तो शिमला में जो उनकी रॉल्स रॉयस कार थीं। उस कार को खड़ा करने के लिए और रिज पर जाने के लिए उनके ओ.एस. डी. ने वहां के डिप्टी कमीश्नर से इजाजत मांगी तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि चाहे ये प्रीमियर हैं या कोई भी हो हम गाड़ी वहां पर ले जाने की परमीशन नहीं देंगे। इसके बाद उन्होंने लाहौर जाकर उस डिप्टी कमीश्नर की तारीफ की चिट्ठी में यह लिखकर भेजा कि आपने मेरा भी गलत आदेश नहीं माना। इस देश को ऐसे ही ईमानदार अधिकारियों की आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, अगर आप ईजाजत दें तो मैं यह रिकार्ड पर लाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदयाः जी ठीक है। श्री ओमप्रकाश यादव जी आपको बोलने के लिए सिर्फ तीन मिनट समय दिया जाता है।

श्री ओम प्रकाश यादव (नारनौल): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं इस बजट पर बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर एक उत्तरदायी, पारदर्शी और जबावदेह शासन देने के लिए कटिबद्ध है। हमारी सरकार ने अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाते हुए एक नये युग का सूत्रपात किया, पढी लिखी पंचायतें बनवाई, गौ–संवर्धन गौ संरक्षण देश में बनाकर हरियाणा प्रदेश ने नम्बर एक स्थान प्राप्त किया है। इस तरह से हरियाणा प्रदेश को अगले पायदान पर लाकर खड़ा किया। आज इस साल के बजट पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं तो सरकार की इस उपलब्धि पर धन्यवाद करता हूं। पिछले 12 साल की इस प्रदेश की जीवन रेखा थी एस.वाई.एल. नहर की योजना जो लम्बित पड़ी थी। हमारी सरकार के प्रयासों से 12 सालों से उलझी हुई गुत्थी का प्रेजिडेंशियल रिफरेंस के रूप में फैसला हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में अपना फैसला दिया इसके लिए मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट और हमारी सरकार का धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस लगन और तत्परता से चेष्टा करके यह फैसला करवाया इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। पिछली सरकारों ने एस.वाई.एल. नहर का मुददा जान बूझकर लटकाये रखा क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी भी रूप में इसका फैसला हो और हरियाणा प्रदेश को इस नहर का पानी मिले। आज भी हमारे एक माननीय साथी इधर से कह रहे थे कि एस.वाई.एल. नहर के लिए 100 करोड़ रूपये रखे गये हैं उनकी रखने की क्या आवश्यकता थी। मैं इसके लिए अपने आदरणीय वित्त मंत्री जी और हमारी सरकार का धन्यवाद करता हूं क्योंकि इससे हमारी सरकार की मंशा साफ नजर आती है कि वे चाहते हैं की प्रदेश की जनता को एस.वाई.एल. नहर का पानी मिले। इसके लिए हमे जैसे ही मौका मिलेगा हम नहर खुदवायेंगे और इसके लिए हर तरह से अगर केन्द्र से पैसा मिलेगा तो वहां से भी लेंगे अगर कुछ ढील हुई तो भी हमारी सरकार पैसे के कारण इस काम को रूकने नहीं देगी। इस बारे में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है और जो कटिबद्धता उन्होंने इस विषय पर दिखाई है उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं ज्यादा समय न लेता हुआ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने जनता की भलाई के लिए

अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाई हुई हैं। हमारे जिले में एक बागवानी का उत्कृष्टता केन्द्र खोलकर हमारे किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कदम उठाया गया है। इसके लिए भी मैं हरियाणा सरकार और हमारे माननीय कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। यह हमारे माननीय कृषि मंत्री जी की इच्छा–शक्ति और दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि जिस प्रकार से हमारे प्रदेश की खेती की जमीन घटती जा रही है और आबादी बढती जा रही है इसके बावजूद भी उन्होंने उन लिमिटिड साधनों में हम किस प्रकार से पैदावार का संतुलन बना सकते हैं इस बात पर विशेष ध्यान दिया है। जमीन में माइक्रो न्यूट्रीयैंट्स की कमी लगातार बढ़ती जा रही है इसके लिए हमारी सरकार ने विशेष लैब खोलकर उसमें सॉयल सैंपल टैस्ट करवाकर एक सॉयल हैल्थ कार्ड हर किसान के घर तक भिजवाया है। इससे किसान यह समझ सकेंगे कि उनकी जमीन में किन–2 पोषक तत्वों की कमी है ताकि उनको समय पर पूरा किया जा सके। इस प्रकार से हमारी सरकार द्वारा अनेक छोटी–2 लेकिन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी सरकार ने फसल बीमा योजना लागू करके जिस प्रकार से किसान को एक तरह से सिक्योर किया है, यह एक बहुत बड़ा और अच्छा कदम है। आज के युग में और इस आर्थिक दौर के युग में अगर थोड़ा सा भी झटका किसान को लगता है तो वह असहनीय होता है। बीमा योजना के माध्यम से किसान का सिक्योर होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। उपाध्यक्ष महोदया जी, शायद आप यह कहना चाह रही हैं कि मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करूं इसलिए मैं अब ज्यादा न बोलते हुए लिफ्ट इरीगेशन के बारे में बात करना चाहूंगा कि अभी जो चर्चा हो रही थी, जिसमें विपक्ष की नेता श्रीमती किरण चौधरी जी कह रही थी कि इसके लिए 143 करोड़ रुपया दिया और अभी तक काम नहीं हुआ है। मैं सरकार का धन्यवाद करते हुए इस सदन के बीच में खड़ा होकर यह कहता हूं कि चूंकि लिफ्ट इरीगेशन का यह कार्य हमारे क्षेत्र में हो रहा है। उसका 50 प्रतिशत के करीब काम पूरा हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले एक साल में लिफ्ट इरीगेशन का यह कार्य जिसके लिए सरकार द्वारा 143 करोड़ रुपया दिया गया था, उसका सारा काम पूरा हो जाना चाहिए, काम प्रोग्रेस में है। आज मैं थोड़ा सा माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि महामहिम गवर्नर जी ने अपने भाषण में जिक्र किया कि वैस्टर्न कैनाल, यमुना कैनाल से और लिफ्ट इरीगेशन तक सारी कैनालों की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए

2 हजार करोड़ रुपये की पिछले एक साल से घोषणा भी कर रखी थी, लेकिन बजट में मैंने उस बारे में कहीं कोई हवाला नहीं पाया। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह किस तरह से रह गया, कैसे रहा है या उस पैसे को कहीं दूसरी जगह इधर–उधर तो नहीं दर्शाया गया है। इस बात की मुझे समझ नहीं आई। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस 2 हजार करोड़ रुपये को लगाकर हमारी नहरों के सुदृढ़ीकरण का काम करवायें। हम चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी शिक्षित हो और सदाचारी हो, स्वस्थ हो, कुशल हो इस बात के लिए हमारी सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और उनको सशक्त बनाने के लिए उनको डिजिटल टूल दिया। ये सरकार का बहुत ही प्रशंसनीय कार्यक्रम है। कर्मचारियों को और पैंशन भोगियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू किया, इसके लिए मैं सरकार का बार–बार धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा सरकार पहला प्रदेश बना जिसने केन्द्र के बाद अपने कर्मचारियों और पैंशन भोगियों को भी सातवां वेतन आयोग की सुविधाएं दी। मैं अंत में एक बात और कहूंगा कि हमारी सरकार ने जो सबसे अभूतपूर्व कार्य किया है वह यह है कि पहले सभी हमारे संत, महात्मा, महापुरुष जो इस समाज को सुधारने में आदर्श माने गए हैं। हम उनको भगवान की तरह पूजते हैं, चाहे वे कबीरदास जी हों, रविदास जी हों, बाल्मीकि जी हों उन सबकी जयंतियों को मनाने की जो प्रक्रिया शुरू की है, यह हमारी सरकार का एक बहुत ही अभूतपूर्व और प्रशंसनीय कदम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और उससे भी बड़ा काम जो उन्होंने किया, जिसकी बदौलत आज हम यहां इस हाउस की कार्यवाही देख रहे हैं, चला रहे हैं और शहीदों व बलिदानियों को सम्मान देकर हमारी सरकार ने एक बहुत ही अनूठा काम किया है। पिछली सरकारें तो इंदिरा और नेहरू से बाहर नहीं निकली। उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि कौन था गुरू गोविंद सिंह, कौन थी रानी लक्ष्मीबाई, कौन थे सुभाष चंद्र बोस हमारी सरकार ने शहीदों को सम्मान देने की कड़ी में गुरू गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के रूप में मनाकर और उसके आयोजन के लिए अलग से बजट रखकर केन्द्र में भी और हरियाणा प्रदेश में भी मनाया गया है यह देश भक्ति का बहुत ही सराहनीय काम है इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी और सरकार को बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं । इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं कहना चाहूंगा कि 1857 की आजादी की लड़ाई में हमारे प्रदेश के वीर भी शहीद हुए थे हमारी सरकार उनकी याद में भी अम्बाला में शहीद स्मारक बनाने जा रही है जिसके लिए

बजट में पैसे का भी प्रावधान किया गया है जो कि बहुत ही सरानीय कार्य है । उसी लड़ाई में समस्त उत्तरी भारत में नसीपुर, नारनौल में तलवारों से लड़ाई हुई जिसमें 5 हजार जवान शहीद हुए । यह गांव मेरे हल्के में पड़ता है । आज भी जब वहां बरसात होती है तो धरती लाल हो जाती है । वहां पर भी विशेष शहीद स्मारक राव तुला राम जी के नाम से बनाने के लिए बजट में पैसे का प्रावधान किया गया है इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का बार–बार धन्यवाद करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदया : ओम प्रकाश जी, आप वाईंड अप करें ।

श्री ओम प्रकाश यादव : उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात कह कर वाईंड अप करता हूं । हमारी सरकार का नारा है कि हर जिले में एक मैडिकल कालेज होगा । वित्तमंत्री जी ने तीसरा बजट पेश किया है लेकिन महेन्द्रगढ़ जिले में मैडिकल कालेज बनाने का कोई प्रावधान बजट में नहीं किया गया और न ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की कोई घोषणा की है । सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश हमारे क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि न तो वहां पानी है और मिट्टी भी रेतीली है । वहां पर सिंचाई का पानी तो दूर की बात है लोगों के लिए पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है । हमारा क्षेत्र पहाड़ों से घिरा हुआ है । उपाध्यक्ष महोदया, आप को तो इन सभी बातों की जानकारी है । आप भी वहीं से हैं। इस समय सदन में बहुत से सदस्य और मंत्रीगण बैठे हुए हैं । उन सभी के माध्यम से मैं अपनी बात मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हरियाणा का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर मैडिकल की सुविधा आधे घंटे से ज्यादा की दूरी पर हो लेकिन हमारे महेन्द्रगढ़ जिले में मैडिकल की सुविधा किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेने के लिए 3 घण्टे 50 मिनट से ज्यादा का समय लग जाता है । उपाध्यक्ष महोदया, बहुत सी बीमारी ऐसी होती हैं यदि समय पर मरीज को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाये तो ईलाज हो सकता है । पैरालाईसिज और हार्ट अटैक ऐसी बीमारियां हैं यदि समय पर मरीज को ईलाज न मिले तो देर हो जाती है यानि समय पर इन बीमारियों का ईलाज हो जाये तो मरीज बच सकता है । हमारे महेन्द्रगढ़ जिले पर कुदरत की मार तो पहले से ही है इसलिए सरकार को वहां पर मैडिकल कालेज की सुविधा अवश्य दी जाये । श्री राम बिलास शर्मा जी भी उसी जिले से हैं और सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं । मैं उनके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि महेन्द्रगढ़ जिले में मैडिकल कालेज की सुविधा दी जाये । जब सारे कार्य हमारी सरकार अच्छे कर रही है तो महेन्द्रगढ़ जिले को मेडिकल कालेज

की जरूरत है, यह सुविधा वहां पर दी जाये । उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं ।

बैठक का समय बढ़ाना

उपाध्यक्ष महोदया : यदि सदन की सहमति हो तो सदन का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये ।

आवाजें : ठीक है, जी ।

उपाध्यक्ष महोदया : ठीक है, सदन का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है ।

वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य (पुनरारम्भ) चर्चा एवं वित्त मंत्री द्वारा उत्तर

15:00 बजे

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : मैडम डिप्टी स्पीकर महोदया, इससे पहले कि श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ अपने से सम्बंधित विषय पर जवाब देना शुरू करें मैं सिर्फ सी.एल.पी. नेता को एक निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कल प्रैस कांफ्रैंस में यह पीड़ा जाहिर की है कि अभी तक इनको इस बजट अभिभाषण पर बोलने का मौका नहीं दिया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनका हरियाणा की सरकार को 10 साल तक चलाने का अनुभव है। अगर सी.एल.पी. नेता उनके बोलने के लिए आपको सिफारिश कर दें और आप उनको 10 मिनट का समय दे दें तो उनके 10 वर्ष के अनुभव का लाभ हमें मिल जायेगा। हमें उनसे कुछ न कुछ अच्छा सीखने को ही मिलेगा। हम उनसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। वे हाउस में ही हैं इसलिए उनको बुलाकर बोलने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाये। अपनी स्पीच के दौरान अगर वे बजट के पूरे प्रावधानों पर प्रकाश डालेंगे हमारे ऊपर बहुत कृपा होगी। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को बजट पर बोलने के लिए समय देने का निवेदन करता हूं।

श्रीमती किरण चौधरी : डिप्टी स्पीकर महोदया, इस सम्बन्ध में मैं यह बात स्पष्ट करना चाहूंगी कि वे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं वे जब भी जिस विषय पर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। अखबार की जिस खबर का यहां पर जिक्र किया गया है वह बात को घुमा–फिराकर लिखा गया है। इस तरह का कोई इशू नहीं है।

He can speak anytime when he wants to speak. यहां पर उनको बोलने से कौन रोक सकता है?

कैप्टन अभिमन्यु : मैडम डिप्टी स्पीकर महोदया, यह खबर अखबार में आई है कि यहां पर बजट भाषण पर बोलने के लिए उनके नाम की सिफारिश सी.एल.पी. लीडर द्वारा नहीं की गई है। इसलिए अगर किरण जी श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को बजट पर बोलने की अनुमति दें तो आप उनको बजट पर बोलने के लिए कम से कम 10 मिनट का समय अवश्य दें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री कृष्ण कुमार बेदी : डिप्टी स्पीकर मैडम, अगर कांग्रेस के माननीय सदस्य किसी अखबार की खबर का जिक्र करते हैं तो वह ठीक है और अगर हमारी तरफ से किसी सम्बन्ध में अखबार की किसी खबर का जिक्र किया जाता है तो वह गलत है। इस प्रकार की बातें करने के बाद ये प्रैस गैलरी की तरफ देखते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : डिप्टी स्पीकर महोदया, जहां तक हमारे फॉर्मर सी.एम. की बात है Number one he can speak anytime when he wants to speak. दूसरी बात यह है कि जो मंत्री जी ने कहा है ऐसी कोई बात नहीं है अर्थात उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है यह बात मैं यहां पर व्द जीम सिववत वि जीम भ्वनेम कह रही हूं। (शोर एवं व्यवधान) डिप्टी स्पीकर मैडम, यह बात मैं सदन के पटल पर कह रही हूं। मेरे विचार से इससे बढ़कर और कोई सबूत नहीं हो सकता।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : डिप्टी स्पीकर मैडम, किरण चौधरी जी इस सम्बन्ध में यह बोल दें कि अखबार ने यह खबर गलत लिखी है। अगर ये यह कह देती हैं तो मामला क्लीयर हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, कृपया करके सभी बैठ जायें और संसदीय कार्य मंत्री जी को अपनी बात कहने दें।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : डिप्टी स्पीकर मैडम, ऑनरेबल फाईनैंस मिनिस्टर ने इंग्लिश ट्रिब्यून की एक खबर का यहां पर किसी परिप्रेक्ष्य में हवाला दिया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि The Tribune is a very prominent news paper. हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी

इस सदन के माननीय सदस्य हैं। सदन की बैठक आज भी है और कल भी है। अगर बजट के ऊपर वे अपने विचार रखना चाहें तो सम्पूर्ण सत्ता पक्ष इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। Madam Deputy Speaker, through you this is our offer to him.

उपाध्यक्ष महोदया : किरण जी, इस सम्बन्ध में आपकी पूरी बात रिकार्ड पर आ गई है इसलिए अब आप कृपया करके बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) सभी माननीय सदस्य, कृपया सदन की गरिमा का ध्यान रखें।

श्री कृष्ण कुमार बेदी : डिप्टी स्पीकर मैडम, अगर किरण चौधरी जी हुड्डा जी को बजट पर बुलवाना चाहती हैं तो इन्हें उनको यहां पर बुला लेना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : बेदी जी, आप भी कृपया करके बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) सभी माननीय सदस्यगण, कृपा करके बैठ जायें और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। सभी माननीय सदस्य, कृपया सदन की गरिमा का ध्यान रखें।

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : डिप्टी स्पीकर मैडम, ये सभी कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य अनेक विषयों के बारे में अखबारों की छोटी–छोटी कटिंग्स लेकर आते हैं। अगर हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने किसी मामले में अखबार की एक खबर का हवाला दे दिया तो उसको ये मानने से इंकार कर रहे हैं। इनका यह व्यवहार इनके दोगले चरित्र को ही ब्यान करता है। (शोर एवं व्यवधान) इनकी पार्टी के माननीय सदस्य श्री जगबीर सिंह मलिक बहुत से अखबारों की कटिंग्स यहां पर लेकर आते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : नायब जी, इस सम्बन्ध में किरण जी ने अपनी बात कह दी है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री भी इस सम्बन्ध में अपना पक्ष रख चुके हैं। इसलिए अब आप बैठ जायें। सभी माननीय सदस्य, कृपया सदन की गरिमा का ध्यान रखें। श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी आप कृपया करके कंटीन्यू करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदी : डिप्टी स्पीकर मैडम, यह बात जगजाहिर है कि मैडम किरण जी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी से विचार नहीं मिलते हैं इसलिए ये उनको बजट पर बुलवाना नहीं चाहती हैं। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : बेदी जी, इस बारे में विस्तार से बात हो चुकी है इसलिए अब आप भी बैठ जायें और श्री धनखड़ जी को बोलने दें। सभी माननीय सदस्य, कृपया सदन की गरिमा का ध्यान रखें। आप सभी को चेयर के आदेशों का पालन करना चाहिए। न तो किसी को बिना चेयर की परमीशन के खड़ा होना चाहिए और न ही बिना चेयर की परमीशन के किसी को बोलना चाहिए। धनखड़ जी, आप कृपया कंटीन्यू करें।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : उपाध्यक्ष महोदया, इस बेहतरीन बजट की बहुत सारे सदस्यों ने बहुत प्रशंसा की है और बहुत सारे सवाल भी उठाये हैं । निश्चित रूप से सभी सवाल इसलिए उठाते हैं ताकि हमारी स्पष्टता बढ़े और हम और बेहतरी की तरफ जायें और संतुलन बना रहे । मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत सारी चीजों को विजन के साथ आगे बढ़ाया है । इस सरकार का जो विजन है... (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : उपाध्यक्ष महोदया, कृषि मंत्री जी किस विषय पर बोल रहे हैं ? क्या बजट पर डिस्कशन समाप्त हो गई है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, मेरे विभाग के जो सवाल कुछ सदस्यों ने उठाये गये हैं मैं उनका जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

उपाध्यक्ष महोदया : दांगी जी, उनके विभाग की कुछ क्वैरीज थी वे उनकी क्लैरिफिकेशन का जवाब दे रहे हैं । बजट पर डिस्कशन समाप्त हो चुकी है । इसके बात वित्त मंत्री जी बजट पर हुई डिस्कशन का जवाब देंगे । आप प्लीज बैठिये।

श्री आनन्द सिंह दांगी : उपाध्यक्ष महोदया, अगर बजट पर डिस्कशन समाप्त हो चुकी है तो फिर वित्त मंत्री जी जवाब दें न कि कृषि मंत्री ।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, कृषि मंत्री जी बोल लें हम उससे इन्कार नहीं कर रहे हैं लेकिन बजट पर यह परम्परा रहती है कि बजट पर डिस्कशन के बाद सिर्फ वित्त मंत्री द्वारा ही जवाब दिया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदया : मैडम किरण जी, इनके विभाग की कुछ क्वैरीज थी ये तो उनकी ही क्लैरीफिकेशन दे रहे हैं ।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : उपाध्यक्ष महोदया, इस देश के संविधान के अनुसार संसदीय लोकतंत्र, संसदीय परम्पराओं और मर्यादाओं से चलता है और माननीय सी.एल.पी. लीडर साहिबा तो दिल्ली विधान सभा की उपाध्यक्ष भी रही हैं । पूरे देश में संसद से लेकर देश की विधान सभाओं में बजट पर चर्चा के बाद यही परम्परा है और हम उन परम्पराओं को आगे बढ़ा रहे हैं । जब माननीय सदस्य बजट पर चर्चा करते हैं तो उसके बाद वे अपनी डिमांड्स का नम्बर बता कर उस डिमांड से संबंधित अपने सुझाव या सवाल उठा सकते हैं । उसके बाद डिमांड्स पर जो कुछ चर्चा होती है, उसका संबंधित विभाग का मंत्री जवाब देते हैं । उसके बाद वित्त मंत्री पूरे बजट अभिभाषण पर अपना जवाब देते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस महान सदन में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने सत्रावधि को बढ़ाया है, सत्र की अवधि बढ़ी है । नई परम्पराएं चलाई गई हैं और पुरानी परम्पराओं को सुधारने का भी काम किया है । राजस्थान की विधान सभा में तो एक–एक महीने तक बजट पर चर्चा होती है । हमें लगता है कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है तथा एक–एक बात का जवाब देना वित्त मंत्री के लिए सम्भव नहीं हो सकता है, फिर वे बातें अधूरी रह जायेंगी। उपाध्यक्ष महोदया, ज्यादातर विषय कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों के लिए थे इसलिए मैंने स्वयं कृषि मंत्री जी से आग्रह किया था कि वे इस पर क्लैरीफिकेशन दे दें । सरकार अपना उत्तरदायित्व समझते हुये आगे बढ़ कर उत्तर देना चाहती है । उपाध्यक्ष महोदया, मुझे हैरानी तो इसलिए हो रही है कि हम विपक्ष को बुलवाना चाहते हैं लेकिन वे बोलना नहीं चाहते। हम जवाब देना चाहते हैं और वह जवाब सुनना नहीं चाहते । उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि माननीय मंत्री जी अपना उत्तर दें और उसके बाद मैं वित्त मंत्री के नाते जवाब दूंगा ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि अगर बजट पर डिस्कशन हो रहा है तो उसका जवाब वित्त मंत्री ही देंगे । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : हमें उस बात पर नहीं जाना । आगे किसानों का सुधार हो हमने उस पर जाना है ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : धनखड़ साहब, मैं आपके हित की बात करूंगा । आपके विभाग की बात करूंगा । अब तक एग्रीकल्चर के ऊपर कोई नहीं बोला है । मैं दो

हफ्ते से यहां बैठा हूं । आप लोगों ने तो केवल भजन गाया है । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : अभी डिमांड्स भी आयेंगी । आप उनके ऊपर बोल लेना ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : मुख्यमंत्री जी, आपको तो मेरी सपोर्ट करनी चाहिए । आप तो मेरे हल्के से संबंध रखते हो और वहीं आपका जन्म हुआ है और आप मेरे गांव के भानजे भी हो और भी सारी बातें हैं। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे कोई कन्ट्रोवर्सी पैदा हो । न मैंने अब तक कोई ऐसी बातें की हैं और न कोई ऐसी बातें अब करूंगा ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : उपाध्यक्ष महोदया, श्री दांगी साहब ने जो कहा उसको मैं स्पष्ट करता हूं कि अगर कोई सामूहिक चर्चा होती है और सामूहिक चर्चा में बहुत से विषय अलग–अलग विभागों के आते हैं जिसकी वजह से बीच–बीच में संबंधित विभाग के मंत्री उनका उत्तर देते रहे हैं । अगर उत्तर देने के बीच में अपने विषय पर या किसी और विषय पर संबंधित मंत्री उत्तर देते रहे हैं । वैसे तो अंत में फाईनल उत्तर वित्त मंत्री का ही होना चाहिए । मानो आज तक यह परम्परा नहीं बनी है तो मैं समझता हूं कि इस परम्परा को बनाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । आखिर सरकार उत्तर दे रही है । कोई मंत्री अपना कोई नया विषय रख रहा है ऐसा नहीं है । जो विषय अभी तक डिस्कशन में आए उनमें से मान लो कोई संबंधित विभाग का मंत्री अपनी तरफ से उसका उत्तर दे देता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है । वित्त मंत्री उसका आखिर में उत्तर देंगे ही ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : मुख्यमंत्री जी, मेरी एक प्रार्थना है कि मैं एग्रीकल्चर पशु पालन और विकास केवल इन्हीं बातों पर ही बोलूंगा । जिनका धनखड़ साहब इक्ट्ठा जवाब दे देंगे । **(शोर एवं व्यवधान)** मैं विषय से हट कर कोई बात नहीं करूंगा ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदया, दांगी साहब को धनखड़ साहब के बोलने पर एतराज नहीं है । वह तो अपनी गैया नहीं रो रहे, वह तो जेठ की गैया रो रहें हैं । वह तो ये कह रहें हैं कि पहले उनको बुलवाओ और फिर धनखड़ जी उसका जवाब देंगे । वह निदाना के थ्रू अपनी बात कहना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : शर्मा जी, आपको तो बस ये जलेबी बनानी आती हैं । आप बात इस तरह से घुमा देते हो और इधर–उधर की बात लगाते हो । सदन का समय खराब करते हो और जरूरी बातों पर कभी डिस्कशन में नहीं आते । आपको सारी दूसरी तरह की बात आती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदया : दांगी जी, अब आप सदन का समय वेस्ट क्यों कर रहे हो । आप अपनी बात को कॉन्टीन्यू करें ।

श्री आनन्द सिंह दांगी (मेहम): उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिये आपका धन्यवाद । मैं यह कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय, ने 6 तारीख को अपना बजट पेश किया और उसमें उनके पास जो भी मसाला था वह बड़े खुले मन से प्रस्तुत किया । उन्होंने बड़े प्रवाह के साथ भाषण दिया और बिना कोमा तथा फुलस्टॉप के भाषण दिया । उसके लिये मैं वित्त मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं लेकिन मैं बजट के संबंध में एक बात कहना चाहता हूं कि सारा बजट अनुमानित और संभावनाओं पर आधारित है । इस सरकार का यह तीसरा बजट है । इससे पहले दो बजट आ चुके हैं और अब तीसरा बजट 6 तारीख को माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है । पिछले जो दो बजट थे उनमें जो भी मद, प्रोग्राम, डिवैल्पमेंट, काम धन्धे, घोषणाएं जिस प्रकार की सरकार की होती रही उनका रिपार्ट कार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी माना है और रोजाना अखबारों में भी छपता है । पिछले ढाई साल में जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, उनमें से 40 प्रतिशत पर काम नहीं हुआ है और 60 और 65 प्रतिशत घोषणाएं तो केवल कागजों में रखी हुई हैं । अलावा आज तक प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ है । इसलिये ये बजट संभावनाओं पर आधारित है ।

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदया, श्री दांगी साहब ने जो कहा मैं उनकी बात का उत्तर देते हुए कहना चाहूंगा कि विषय ऐसे रखे जाएं जो तथ्यों पर आधारित हों । हमारी घोषणाएं हैं क्योंकि पहले वर्ष में तो कोई घोषणाएं होती नहीं हैं । पहले वर्ष में चीजों की योजनाएं बनती हैं, नीति बनती हैं फिर भी हमने पहले वर्ष में जाकर के 30 या 35 प्रतिशत घोषणाएं की थी । उपाध्यक्ष महोदया, मेरा इस सदन के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि सदन में तथ्यों पर आधारित विषय ही रखे जाने चाहिएं। सब जानते हैं कि पहले वर्ष में किन्हीं चीजों की योजनायें और नीतियां बना करती है लेकिन बावजूद इसके हमने जो भी घोषणाएं

की है उन घोषणाओं में 35–40 प्रतिशत घोषणाएं सरकार के पहले वर्ष के कार्यकाल के लिए थी और बाकी 60 प्रतिशत घोषणाएं सरकार के दूसरे वर्ष के कार्यकाल के लिए नियत थी। पहले वर्ष की घोषणाएं तकरीबन–तकरीबन पूरी हो चुकी हैं और यदि आंकड़े के हिसाब से कुल घोषणाओं के लागू होने के बारे में देखा जाये तो साढ़े अठ्त्तीस प्रतिशत घोषणायें पूरी हो चुकी हैं और केवल मात्र साढ़े इक्सठ प्रतिशत घोषणायें अभी पाईप लाईन में हैं। यह सर्वविदित है कि जब भी कोई घोषणा लागू की जाती है तो लागू होने से पहले उस घोषणा के लिए कम से कम छह महीने का प्रोसैस तो रहता ही रहता है। इस प्रोसैस में कहीं जमीन ट्रांसफर करनी पड़ती है, कहीं बजट बनाना पड़ता है तो कहीं डी.पी.आर. बनाई जाती है और असलीयत में घोषणा पर काम उस दिन शुरू होता है जिस दिन किसी चीज का टैंडर हो जाता है। टैंडर से पहले हम किसी भी घोषणा को इनप्रोग्रेसिव नहीं मानते हैं। जिस दिन टैंडर हो जाता है उस दिन से कोई घोषणा विधिवत चैनल में आ जाती है। अतः मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि बाकी बची साढ़े इक्सठ प्रतिशत घोषणाएं भी चैनल में आ गई हैं और चूंकि सरकार का यह तीसरा साल क्रियान्वयन का वर्ष है इसलिए इस वर्ष हमारी तकरीबन सारी घोषणाओं पर काम शुरू हो जायेगा लेकिन किसी भी सूरत में यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि अभी हमारी सरकार के अढ़ाई साल का समय बाकि बचा है? **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)**

श्री आनन्द सिंह दांगी: अध्यक्ष महोदय, अभी सदन के नेता ने जो कुछ भी कहा है, उस परिपेक्ष्य में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की शुभकामनाएं आपकी सरकार के साथ हैं और उम्मीद है कि सरकार ने जनता के साथ जो वायदे किए हैं, उन वायदों को पूरा करने में सरकार अहम भूमिका निभायेगी। अध्यक्ष महोदय, कुछेक बातें समाज से व लोगों से जुड़ी हुई होती हैं और इस समाज में भी कुछेक ऐसी मदें होती हैं जिन पर सारा दारोमदार होता है। यह मदें हैं कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण और आजकल गंगा है, गांय है, गीता है, सरस्वती है, नोटबंदी है तथा कैशलेस आदि बातें हैं। इन सभी बातों को सरकार की तरफ से माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बजट में रखा है। चाहे यह बातें जनहित के लिए कही गई हों या फिर अपनी प्रसिद्धि के लिए कही गई हों लेकिन इनको बजट में रखा जरूर गया है? मैं सबसे पहले कृषि की बात करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान

प्रदेश है और यहां की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर रहकर अपनी रोजी–रोटी कमाती है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी वर्ग से हो उसको खेती की वजह से काम मिलता है। किसान के खेत में अगर कुछ पैदा होता है तो हर किसी को काम मिलता चला जायेगा। खेती की वजह से दुकानदार की दुकानदारी चलती है, व्यापारी का व्यापार चलता है, हाथ का काम करने वालो को हाथ का काम मिलता है, मजदूर को मजदूरी मिलती है और उसके साथ–साथ सबका पेट भरता है। चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन आज किसान की हालत बहुत खराब हो चुकी है। पहले भी बजट में कृषि के लिए जिस प्रकार से धन का आबंटन किया गया था, वह धन कहां पर खर्च हुआ, यह धरातल पर बिल्कुल नज़र नहीं आता है और न ही खर्च किए गए इस पैसे से किसी को फायदा होता हुआ दिखाई देता है। किसान हर तरफ से पिटा हुआ है। चाहे वह भाव की बात है, चाहे वह किसान की दूसरी सुविधाओं की बात हो किसान को कहीं पर भी कोई फायदा हुआ नज़र नहीं आता है। कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने आज मुझे सैकिंड एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट के आयोजन में शामिल होने संबंधी एक कार्ड दिया। संभव है कि इसी तरह का एक कार्यक्रम पिछले साल भी आयोजित किया गया था और शायद करोड़ों रूपये इस प्रकार के आयोजनों पर खर्च भी होते होंगे लेकिन इतना खर्च होने के बावजूद आम किसान को कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछेक सरकार से संबंधित लोग और थोड़े बहुत आदरणीय लोग ही इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और कार्यक्रम की समाप्ति की अवधि के बाद जिस मकसद के लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, उन पर फुलस्टॉप लग जाता है। जैसे सैकिंड एग्रीकल्चर लीडरशिप कार्यक्रम की समाप्ति की तारीख 20 है तो संभव सी बात है कि 20 तारीख के बाद कार्यक्रम के उद्देश्य में कोई प्रोग्रैस नहीं हो पायेगी। अध्यक्ष महोदय, कृषि का डिपार्टमैंट बहुत बड़ा डिपार्टमैंट है और इसका स्टाफ बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। कृषि डिपार्टमैंट में ए.डी.ओ. से लेकर इंस्पेक्टर तक तमाम तरह के कर्मचारी काम करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो यह ए.डी.ओ. या इंस्पेक्टर स्तर के कर्मचारी है, क्या कभी जिन गांवों में उनकी ड्यूटी लगी होती है या जहां पर वे पोस्टिड हैं, क्या वे किसानों के साथ बैठकर कभी किसी गोष्ठी का आयोजन करते हैं? मेले आयोजित करके जिम्मेदारी से नहीं बचा सकता। मैं किसान हूँ, खेतीबाड़ी करता हूँ और 90 प्रतिशत गांव में रहता हूँ और रोजाना खेत में जाता हूँ। अगर चण्डीगढ़ में कोई मीटिंग हो तो दूसरी बात है अदरवाईज मैं डेली खेत में

जाता हूँ लेकिन आज तक किसी एग्रीकल्चर महकमे का कोई कर्मचारी, बागवानी महकमे का कोई कर्मचारी मैंने नहीं देखा जिसने कृषि विभाग की विभिन्न प्रकार की स्कीमों के बारे में किसानों के खेत में आकर कोई गाईडलाईन्ज दी हों? मैंने अपने खेत में नैट हाउस भी लगा रखा है थोड़े से फलदार पौधे भी लगा रखे हैं। (विघ्न) मैं किसान हित की जनरल बात कर रहा हूं । देखिये, मैंने एक ही बात कही है । मैं इस विषय पर बहुत बोल सकता हूं और मैं सब तरह की बात कह सकता हूं लेकिन फिर भी मैं लाइन से हटकर बात नहीं करना चाहता । अगर आप किसान हित की बात का भी मजाक करते हो तो फिर भगवान आपका भला करें । अरे, रोटी उसकी खाते हो, कमाई उसकी खाते हो, अपने सारे साधन उसकी कमाई से जुटाते हो और फिर उसी की नुक्ताचीनी करते हो यह गजब की बात है । मैं कृषि के बारे में एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूं । ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर महोदय ने सब्जी, बागवानी इत्यादि के बारे में एक स्कीम बनाई है । कल हमारे विपक्ष के सदस्यों ने किसान की जीन्स जैसे गेहूं, बाजरा, आलू, मटर, गोभी आदि के बारे में काफी विस्तार से बात की । मैं किसान की फसल बिक्री के बारे में एक बात कहना चाहता हूं । मैं अब बाजरे की फसल के बारे में एक बात कहना चाहता हूं । आपने बाजरे की खरीद पर लिमिट लगा दी है और कहा है कि हम इससे ज्यादा बाजरा नहीं खरीद सकते । एक तरफ तो हम किसान को प्रोत्साहित करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फसल पैदा करो और जब उसने पर्याप्त अनाज पैदा कर दिया तो फिर उसे कहते हो कि इससे ज्यादा अनाज नहीं खरीदा जाएगा । मैं पूछना चाहता हूं कि किसान उसे बेचने के लिए कहां जाएगा ? मैं कहना चाहता हूं कि आप किसान का अनाज खरीदिये क्योंकि आपके पास बहुत साधन हैं । आपके पास मतस्य भी है, मुर्गियां भी हैं और इसके अतिरिक्त अनेकों साधन हैं । आपके पास हैफेड है जिससे हम चावल मंगवाते हैं और फिर उससे खीर बनाते हैं । हम अगर किसान की जीन्स को नहीं खरीदेंगे तो वह बेचारा पिटता ही चला जाएगा और वह आज भी पिट रहा है । सब्जी चाहे कोई भी है आज उसकी बड़ी दुर्गति हो रही है । आज 50 रूपये में आलू की एक बोरी बिक रही है । इसी प्रकार टमाटर, गोभी और फूल की भी यही हालत है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दांगी साहब, आप अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए क्योंकि आपको बोलते हुए काफी टाइम हो गया है ।

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि आप मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए । इसके लिए आप बेशक बैठक का टाइम बढ़ा लीजिए ।

श्री अध्यक्ष : दांगी जी, हम बैठक का टाइम आखिर कब तक बढ़ाते रहेंगे ? मैंने ऑलरेडी सदन की बैठक का समय दो घंटे बढ़ा दिया है । (विघ्न)

डॉ. पवन सैनी : अध्यक्ष महोदय, क्या यहां पर गदर मचा हुआ है जो माननीय सदस्य श्री आनन्द सिंह दांगी कह रहे हैं कि मैं जितनी देर तक बोलना चाहूंगा उतना बोलूंगा । यहां दूसरे विधायक भी बोलने के लिए बैठे हैं । सभी को बोलने के लिए 5–5 मिनट समय की आवश्यकता होती है । सदन में अपनी बात रखने का यह कोई तरीका नहीं है । (विघ्न)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं कोई गलत बात कह रहा हूं ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दांगी साहब, सही और गलत का इशू नहीं है । (विघ्न)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने का पूरा हक और अधिकार है । माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें सारी चीजों का जिक्र किया गया है । हमारी सरकार को एम.एस.पी. के हिसाब से गेहूं की तरह फ्रूट्स और सब्जी की खरीद का भी इंतजाम करना चाहिए । सरकार का कहना है कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे और किसानों के हित के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे । हमारी सरकार के समय इसे लागू करवाने के लिए माननीय कृषि मंत्री जी ने एजिटेशन भी किये, साइकिल पर भी चले, नंगे पैर भी चले और पैदल भी चले । इसके लिए इन्होंने अपनी आवाज को बड़ा बुलन्द किया था लेकिन जब से इन्होंने ये रंग–बिरंगी जैकेट पहननी शुरू की हैं तब से यह सब कार्यक्रम खत्म हो गया । अब इस बारे में ये कुछ भी नहीं बोलते । (विघ्न) सरकार को किसान के हित के लिए बजट में प्रावधान करने चाहिए । इस सरकार का कहना है कि हम वर्ष 2022 तक किसान की आय दोगुनी कर देंगे । इस पर मेरा कहना है कि अगर यह सरकार इसी लाइन पर चलती रही तो वर्ष 2022 तक तो क्या वर्ष 2032–2042–2052 तक भी किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाएगी । मैं पूछना चाहता हूं कि आप इस बजट को किस लाइन पर खर्च करना चाहते हो ? आपने किसान और कृषि के लिए बजट प्रस्तुत किया है। आज के दिन खाद, बीज, दवाई, पैस्टिसाइड्स आदि बहुत ज्यादा महंगी हैं ।

किसान को इन्हें खरीदने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है । अतः आपको इन चीजों पर सब्सिडी अवश्य देनी चाहिए । आज खेत में डाली जाने वाली कीटनाशक दवाइयां हजार, डेढ़ हजार या 2 हजार रूपये से कम दाम में नहीं मिलती । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दांगी साहब, अब आप प्लीज वाइंड –अप कर लीजिए ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं किसान को सब्सिडी देने के अतिरिक्त डीजल की भी बात करना चाहूंगा । डीजल को ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों जैसे इंजन इत्यादि में प्रयोग किया जाता है । (विघ्न) डीजल में भी किसान के लिए स्पैशल सब्सिडी दी जा सकती है। (विघ्न) खेती के औजारों पर जो सब्सिडी दी जाती है, उसका फायदा अग्रणी किसान ही उठाते हैं आम किसान तक वह सब्सिडी पहुँच ही नहीं पाती है। किसानों के हितों और खुशहाली के लिए इस बजट में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्षः दांगी जी, आप जल्दी कन्क्लूड कीजिए।

श्री घनश्याम दासः अध्यक्ष महोदय, दांगी साहब ने सब्जियों के समर्थन मूल्य पर चिंता व्यक्त की है लेकिन पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उससे पहले इनैलो की सरकार थी, उस समय उन्होंने सब्जियों के समर्थन मूल्य के बारे में न तो आवाज उठाई और न ही सब्जियों का समर्थन मूल्य घोषित किया। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जो पेरिशेबल गुड्स (खराब होने वाली) होती हैं, जिनको सरकार खरीदकर स्टोर नहीं कर सकती या जिनको हम किसी भी माध्यम से खरीदवा नहीं सकते, उसका समर्थन मूल्य कैसे घोषित किया जा सकता है, इस बात को भी दांगी साहब सदन में स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्षः दांगी साहब, इस विषय पर इस हाउस में श्री घनश्याम दास से अच्छी जानकारी किसी को भी नहीं है क्योंकि इनसे अच्छा किसान ही नहीं है। (विघ्न)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, एक बात और आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूँ कि मैं हर साल 22–23 एकड़ में धान की पैदावार करता हूँ। कांग्रेस के राज में मेरे धान की कीमत 14–15 लाख रूपये हुआ करती थी लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से उसकी कीमत साढ़े सात लाख रूपये या पौने आठ लाख रूपये रह गई। धान की फसल का कर्जा और

खर्चा भी पूरा नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दी जाये ताकि वे अपनी फसल का खर्चा और पूरा दाम प्राप्त कर सके। अध्यक्ष महोदय, किसी भी गरीब आदमी का दूसरा साधन पशुपालन है। पशुपालन करके ही वह अपनी रोजी–रोटी चलाता है और अपने बच्चों का पालन–पोषण, पढ़ाना–लिखाना आदि कार्य करता है लेकिन सरकार ने पशुपालन की जो स्कीम पहले चली आ रही थी, उसमें काफी बदलाव कर दिया है। पहले यदि भैंस 12 किलो दूध से ऊपर 18 या 20 किलो दूध देती थी तो सरकार की तरफ से इनाम दिया जाता था लेकिन अब उस मद को खत्म करके जो भैंस 18 किलो से ऊपर दूध देगी, उसे इनाम दिया जायेगा। इस तरह से किसानों के साथ धोखा हुआ है क्योंकि आज किसानों के पास 15–20 लाख रूपये की भैंस खरीदने की हैसियत नहीं है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक बात आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से सिविल अस्पतालों में फ्री में दवाइयां दी जाती हैं उसी तरह से पशु अस्पतालों में भी पशुओं के लिए फ्री में दवाई उपलब्ध होनी चाहिए ताकि गरीब आदमी अपने बीमार पशु का इलाज करवा सकें।

श्री अध्यक्षः दांगी साहब आपको बोलते हुए 16–17 मिनट हो गये हैं। अब आप वाईंड अप करें।

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, उस वक्त एस.वाई.एल. नहर के पानी के लिए डा0 रधुबीर सिंह कादियान, पंडित रामबिलास शर्मा और चौधरी देवी लाल जी के साथ मिलकर हम सबने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं।(विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः यदि सदन की सहमति हो तो बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढा दिया जाये।

आवाजेः ठीक है, जी।

श्री अध्यक्षः बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढाया जाता है।

वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा एवं वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री विक्रम सिंहः अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने हल्के के लिए पांच मिनट बोलने के लिए समय दें। (विध्न)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, मुझे भी अपने हल्के की बात कहनी है।

श्री अध्यक्षः दांगी साहब, आप अपने हल्के की बात नोट करवा दें। अब दांगी साहब जो कुछ बोल रहे हैं उनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए।

श्री आनंद सिंह दांगीः *********

श्री अध्यक्षः विक्रम सिंह जी दो मिनट में अपने हल्के की बात पूरी करें।

श्री विक्रम सिंह (कोसली): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यह वितीय बजट स्वर्ण जयंती वर्ष में आया है हमारी सरकार इस वर्ष को हरियाणा स्वर्ण जयंती के रूप में मना रही है और इस शुभ वित्त वर्ष 2017–18 के लिए वित्त मंत्री महोदय ने एक लाख दो हजार करोड़ रूपये से ज्यादा का बजट पेश किया है और माननीय मुख्य मंत्री की घोषणाओं को क्रियान्यवन करने के लिए विशेष बजट पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। हमारी सरकार ने पढी लिखी पंचायतों का चुनाव करवाना व पंचों से लेकर जिला पार्षद तक के मानदेय बढाने का बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। स्वर्ण जयंती वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वर्गीय चौधरी छोटूराम जी के नाम पर दीन बंधू हरियाणा ग्राम उदय योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव रखा है जो कि सराहनीय कार्य है तथा दूसरी और हरियाणा के महान नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉ0 मंगल सैन जी के नाम से नई योजना मंगल नगर विकास योजना शुरू कर प्रदेश के विकास में बढावा दिया है। हमारी सरकार ने किसानों को गन्ने का देश में सर्वाधिक मूल्य जो कि 320/315/310 रूपये प्रति क्विंटल देकर किसानों में सराहनीय कदम उठाया है।

श्री अध्यक्षः विक्रम जी, आप अपने हल्के की डिमांड रखें।

---

*चेयर के अनुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री विक्रम सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलबध कराने के साथ सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवाईयां उपलब्ध कराई जा रहीं हैं राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक मैडिकल कॉलेज खोलने जा रही है जो बहुत ही सराहनीय कदम है। हमारी सरकार झज्जर के सिवानी केशों और रेवाड़ी जिले के जैनाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन तैयार करवा चुकी है और इसी वर्ष में इन कालेजों में कक्षाएं आरम्भ कर दी जाएंगी जोकि युवा पीढी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। हमारी सरकार ने 2015 में जो खेल नीति बनाई है जिसमें सभी गांवों में योगशाला एवं व्यायामशाला खोलने का निर्णय लिया है। यह निर्णय हमारे गांवों के नौजवानों के लिए बहुत अच्छा कदम है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का अपने हल्के की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हल्का कोसली में 20 नवम्बर 2015 को सहकारिता दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं में से काफी घोषणाएं अभी क्रियान्वित नहीं हुई हैं। ग्राम पंचायत कोसली व ग्राम पंचायत, भाकली को मिलाकर नगर पालिका का दर्जा दिया जाने की घोषणा की गई थी। उसको आगे बढाया जाए उसी के साथ मिल्क चिलिंग सैंटर, जाटूसाना का दर्जा बढाकर मिल्क प्लांट में परिवर्तित किया गया है, उसके काम को भी आगे बढाया जाए। ग्राम सहादत नगर में नर्सिंग कालेज की स्थापना की घोषणा को भी क्रियान्वित किया जाए। सहकारिता विभाग की आई.सी.डी.पी. स्कीम की जिला रेवाड़ी में शुरूआत करने की घोषणा को भी लागू किया जाए। उसी के साथ ग्राम जाटूसाना में हैफेड का कैटल फीड प्लांट लगाने का निर्माण भी शुरू किया जाए। मैं माननीय सहकारिता मंत्री से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज हैफेड और मिल्क प्लांट दोनों संस्थाएं लाभ में हैं। इसलिए इन दोनों योजनाओं को लागू करने में सरकार को भी कोई परेशानी नहीं होगी। भाकली नाहड़ रोड पर रेलवे लाइन को पार करने के लिए ओवर ब्रिज के साथ–साथ अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए। कोसली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भिवानी बोर्ड की तर्ज पर जेबीटी कक्षाओं की शुरूआत करने के काम को इसी साल लागू किया जाए। माननीय परिवहन मंत्री जी से निवेदन है कि रोडवेज सब– डिपो, कोसली जो रेवाड़ी डिपो के अन्दर आता है, उसको सरकारी तौर पर बनाया जाए न की पी.पी.पी़ मोड पर बनाया जाए। साल्हावास रोड से नाहड़ रोड़ तक बाई–पास का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि यह कार्य जल्दी ही शुरू

किया जाएगा इसको लेकर जनता में काफी जोश था कि हमारा बाई–पास का कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हल्का कोसली में की गयी इन सभी घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं।

श्री घनश्याम सराफ (भिवानी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए जो समय दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह बजट हरियाणा की ढाई करोड़ जनता और हमारी सरकार के ''सबका साथ, सबका विकास'' इस नारे के मद्देनजर जनता के विकास कार्यों को लेकर बनाया गया है। सरकार ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और किसान, मजदूर व्यापारी, कर्मचारी व कमजोर वर्ग को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया है। अध्यक्ष महोदय, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि सरकार ने 2 वर्षों के दौरान राज्य में 8,600 किलोमीटर लम्बी सड़कों का मजबूतीकरण, सुधारीकरण, चौड़ा करने पर और निर्माण पर लगभग 4,700 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। कई वर्षों से अधर में पड़ा कुंडली–मानेसर पलवल एक्सप्रेस–वे परियोजना का कार्य शुरू किया गया है। इसके साथ हमारे भिवानी में भी खैरड़ी मोड़ सीमा से भिवानी होते हुए चरखी दादरी एन.एच रोड का निर्माण कार्य वर्ष 2017–2018 में शुरू करने का बजट में प्रावधान किया गया है। इसके लिए माननीय वित्त मंत्री के साथ–साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं लोक निर्माण मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। इसके साथ मैं भिवानी में तिगड़ाना मोड़ से कालवास होते हुए रोहतक रोड तक एवं गांव देवसर से तिगड़ाना मोड़ तक के बाई–पास को बनाने का आपसे अनुरोध करता हूं। यह काम माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं में शामिल है। इसको भी शीघ्र पूरी करने का मैं आपसे अनुरोध करता हूं। आज माननीय पूर्व परिवहन मंत्री जी सदन में आये थे, उनके पास मैंने चार लेटर लिख कर भेजे थे और जवाब में हमें यह मिलता था कि हमारे पास बजट नहीं है, उनके पास भिवानी की सड़कों के लिए बजट नहीं होता था। बिजली सम्प्रेषण और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है, विभिन्न क्षमताओं के 73 सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है और 1300 किलोमीटर लम्बी बिजली की लाईन बिछाई गई है। सरकार ने 3 चरणों में 1 लाख सोलर आधारित होम सिस्टम प्रदान करने के लिए कुल 230 करोड़ रुपये की लागत से मुख्यमंत्री जी के नाम से मनोहर ज्योति स्कीम लागू की गई है, जिससे जनता को

पूरा लाभ होगा। 157 बस्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है और वर्ष 2017–2018 में 250 बस्तियों को यह लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में नाबार्ड की वित्तीय सहायता से 7 जिलों महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार, सिरसा, भिवानी, फरीदाबाद और पलवल में 359 गांवों और 52 ढाणियों में जल आपूर्ति की वृद्धि के लिए 750.29 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 11 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से 10 हजार तक की आबादी के गांवों को शहरी तर्ज पर सुविधाएं दी जायेंगी । इसके लिए 1461 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत 2016–17 से 2020–2021 तक 5 वर्षों में पूरी कर ली जायेगी । अध्यक्ष महोदय, जहां तक शहरी विकास योजना की बात है इसके लिए 4973.58 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है । इससे शहरी विकास को एक नई दिशा मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पहली बार 4 जिलों में डायलैसिस सेवा शुरू की गई है । जिससे गरीब लोगों को बहुत लाभ हो रहा है । पिछली सरकार के समय की तुलना में स्वास्थ्य में काफी सुधार देखने को मिल रहा है । मेरे भिवानी विधान सभा क्षेत्र में मैडिकल कॉलेज की स्वीकृति के लिए बजट में दर्शाया गया है इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : घनश्याम जी, आप एक मिनट में वाईंड अप करें ।

श्री घनश्याम शराफ : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में वाईंड–अप करता हूं । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सरकार ने हरियाणा से ओलंपिक तथा पैरालंपिक खेलों में पदक विजेताओं और प्रतिभोगियों के लिए स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 6 करोड़ रुपये की घोषणा की है । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से युवा पीढ़ी को शिक्षित, सदाचारी, स्वस्थ और कुशल बनाने के लिए सरकार गंभीर है । शिक्षा के सभी स्तरों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए सरकार बल दे रही है । अध्यक्ष महोदय, भिवानी नगर परिषद में तकरीबन 250 गलियों का निर्माण हो चुका है और करीब 400 कच्ची व टूटी हुई गलियां हैं जिनको पक्का करवाना बहुत जरूरी है । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से भिवानी के 4 जौहड़ो का सौन्दर्यीकरण करने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी । उनके लिए बजट में पैसे का प्रावधान करके काम करवाया जाये । अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं वित्तमंत्री जी को बहुत–बहुत मुबारकवाद देता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया ।

श्री बिशंबर सिंह बाल्मिकी (बवानी खेड़ा) (एस.सी.) : स्पीकर सर, आपने मुझे वर्ष 2017–18 के बजट अनुमानों पर बोलने का मौका दिया सबसे पहले तो इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं इस बजट को हरियाणा की समस्त जनता के लिए अनमोल सौगात मानता हूं और हरियाणा प्रदेश के सभी वर्गों के लिए परम हितैषी एवं परम कल्याणकारी बजट पेश करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2017–18 के लिए हरियाणा के इतिहास में पहली बार करीब एक लाख करोड़ रूपये के बजट का प्रस्ताव किया है जो कि हरियाणा प्रदेश के समग्र विकास को और अधिक मज़बूत गति प्रदान करेगा। महोदय, सरकार द्वारा इस बार हरियाणा प्रदेश के लिए दो खास योजनाओं की शुरूआत की गई है। शहरी क्षेत्रों की तर्ज़ पर प्रदेश के लगभग 1500 गांवों के लिए 5000 करोड़ रूपये की लागत से हरियाणा के महान नेता चौधरी छोटू राम जी के नाम पर दीन बंधू ग्राम उदय योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2017–18 के दौरान इस योजना के लिए 1200 करोड़ रूपये आबंटित किये जायेंगे। मुझे विश्वास है कि इस योजना से गांवों में विकास की गति को और ज्यादा बल मिलेगा। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों के समग्र और सर्वांगीण विकास के लिए हरियाणा के महान नेता पूर्व उप–मुख्यमंत्री डॉक्टर मंगल सैन जी के नाम से 'मंगल नगर विकास योजना' नामक एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2017–18 के दौरान इस योजना के लिए 1000 करोड़ रूपये की राशि का आबंटन किया गया है। इन दोनों योजनाओं के अलावा भी सरकार ने वर्ष 2017–18 के दौरान ग्रामीण विकास, सामुदायिक विकास एवं पंचायतों के लिए 4963.09 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया है जो कि 2016–2017 संशोधित अनुमानों से 3167.55 करोड़ रूपये पर 56.69 रूपये की एतिहासिक वृद्धि है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर अपनी बात रखने के लिए कम समय दिया है इसलिए अब मैं आपके माध्यम से अपने हल्के की कुछ डिमाण्ड्स माननीय मुख्यमंत्री एवं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरे पहले माननीय साथी श्री धनश्याम सर्राफ जी ने भी इस बात का जिक्र किया है और मैं भी इस बात को कहना चाहता हूं कि एक फोर–लेन सड़क जिसका निर्माण रोहतक से खैरड़ी मोड़ तक किया गया। खैरड़ी मोड़ तक रोहतक जिले की सीमा है इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी द्वारा किसी राजनीतिक दुर्भावना के चलते इस फोर–लेन सड़क को खैरड़ी मोड़ तक बनाया गया हो।

इसका कारण श्रीमती किरण चौधरी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी हो सकती है जिस कारण इस फोर–लेन सड़क को भिवानी तक न बनाकर सिर्फ खैरड़ी मोड़ तक ही बनाया गया। खेरड़ी मोड़ से आगे मेरा गांव खरक पड़ता है। हम तो यह समझते हैं कि पता नहीं किन ज्ञात व अज्ञात कारणों से इस सड़क के निर्माण कार्य को खैरड़ी मोड़ से आगे ऐसे रोक दिया गया जैसे कि आगे पाकिस्तान या किसी अन्य देश का बॉर्डर लगता हो। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। जैसे कि हमारे साथी ने कहा कि रोहतक से भिवानी फोर–लेन सड़क के निर्माण कार्य को खैरड़ी मोड़ से आगे रोक दिया दिया। इस बारे में मैं इनके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि यह रोड एन.सी.आर. प्लॉनिग बोर्ड के तहत बनी थी और उस समय तक एन.सी.आर. की सीमा रोहतक जिले तक ही थी। इसलिए इस सड़क के निर्माण का कार्य खैरड़ी मोड़ से आगे नहीं हो पाया था। इसके साथ ही मैं पूरे सदन के साथ–साथ इनको यह बताना चाहूंगा कि अब एन.सी.आर. में भिवानी जिला भी आ गया है इसलिए इस फोर–लेन सड़क का निर्माण कार्य भिवानी तक हो सकता है। अगर सरकार चाहे तो इस फोर–लेन सड़क को भिवानी तक जल्दी से जल्दी बनाया जा सकता है। बाद में हमारी सरकार ने भिवानी को भी एन.सी. आर. में शामिल करवा लिया था इसलिए अब इस फोर–लेन सड़क के भिवानी तक निर्माण में कोई परेशानी नहीं होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बिशंबर सिंह बाल्मिकी : स्पीकर सर, मैं तो हुड्डा जी को यही कहना चाहूंगा कि अगर ये इस फोर–लेन सड़क को उसी समय भिवानी तक बना देते तो इसके बनने से वहां पर जो आये दिन भयंकर एक्सीडैंट्स हुए हैं वे न होते और न ही सैंकड़ों लोगों की जानें जाती।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, हमारी सरकार ने ही भिवानी के साथ–साथ महेन्द्रगढ़ को भी एन.सी.आर. में शामिल करवाया था।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, जैसा कि मैंने बताया जिस समय इस फोर–लेन सड़क का निर्माण हो रहा था उस समय तक एन.सी.आर. की सीमा रोहतक जिले तक ही थी लेकिन बाद में हमारी सरकार ने प्रयास करके भिवानी को भी वर्ष 2014 में एन.सी.आर. में शामिल करवा लिया था। जब वर्ष 2014 में एन.सी.

आर. का एरिया बढ़ा उस समय एन.सी.आर. में भिवानी, महेन्द्रगढ़ और करनाल शामिल हो गये थे। इसलिए अगर सरकार चाहती तो सत्ता सम्भालने के बाद अब तक अढाई साल के शासनकाल के दौरान इस सड़क का निर्माण भिवानी तक करवा सकती थी। यह काम अब भी करवाया जा सकता है क्योंकि अब इस सड़क को एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड के तहत भिवानी तक फोर–लेन बनवाने में कोई परेशानी नहीं होगी।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, विशम्बर जी बाल्मिकी ने श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल की एक घटना का जिक्र किया है। श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को अपने कार्यकाल का सब कुछ याद है यह बहुत ही अच्छी बात है। यह बात सच है कि खैरड़ी मोड़ पर रोहतक जिला समाप्त होता है और भिवानी जिले की शुरूआत होती है यह तो बिशम्बर बाल्मिकी जी ने ठीक कहा। मैं यह कहना चाहता हूं कि नैशनल हाई–वे कोटपुतली से नांगल चौधरी, नांगल चौधरी से नारनौल, नारनौल से महेन्द्रगढ़, महेन्द्रगढ़ से दादरी और दादरी से हांसी मिलाना था। इस हाई–वे का बजट भी सैंक्शन हो गया था परन्तु हुड्डा साहब उसको दादरी से कलानौर लाना चाहते थे उस समय इनकी एकमात्र मंशा यही थी कि हरियाणा प्रदेश को मिलने वाला कोई भी हाई–वे रोहतक से ही होकर जाये इसलिए उस हाईवे के कलानौर तक न आने के कारण उस हाईवे का सैंक्शन बजट वापिस करवा दिया गया।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, जिस हाईवे का जिक्र राम बिलास शर्मा जी कर रहे हैं उसके लिए हमारी सरकार के समय में जमीन एक्वॉयर हो गई थी, पेमैंट भी हो गई थी और जहां–जहां आवश्यकता थी वहां–वहां पर पेड़ों की कटाई का कार्य भी हो चुका था। राम बिलास शर्मा जी जिम्मेदार मंत्री हैं पता नहीं कहा–कहां से ये ऐसी आधी–अधूरी जानकारी ले आते हैं। इनको ऐसा करना शोभा नहीं देता इसलिए इनको ऐसी निराधार बातें नहीं करनी चाहिएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बिशंबर सिंह बाल्मिकी : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने खैरड़ी मोड़ से लेकर भिवानी तक फोरलन की मंजूरी देकर बजट का प्रावधान भी किया है उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं । अध्यक्ष महोदय, कहने का मतलब यह है कि इस बजट में "सबका साथ–सबका विकास" के नारे पर चलते हुये राज्य के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है । अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से अपने विधान सभा

क्षेत्र बवानीखेड़ा की कुछ मांगों को सदन के सामने रखना चाहता हूं । भिवानी जिले में जो मैडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है, उस मैडिकल कॉलेज की भिवानी शहर के साथ लगते गांव प्रेमनगर में 10.6.2016 को मुख्यमंत्री जी ने आधारशिला रखी थी । मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि उसका कार्य जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाये । इसी प्रकार से गांव खरक व कलिंगा, सिरसा, रिवाडी, सैम, चांग तथा ढाणी हरसरू आदि गांवों की सैकड़ों छात्राओं को कॉलेज में पढ़ने के लिए भिवानी या रोहतक जाना पड़ता है इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन गांवों की परिधि में एक महिला कॉलेज खोला जाए । अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बवानीखेड़ा कस्बे के सरकारी अस्पताल में स्टाफ व अन्य उपकरणों की कमी है । यहां अल्ट्रासाऊंड की मशीन भी नहीं है जिसके कारण गरीब लोगों को बाहर प्राइवेट अस्पतालों से महंगे रेट पर अल्ट्रासाऊंड करवाना पड़ता है । इस अस्पताल में पिछले कई सालों से केवल एक ही डॉक्टर है । मेरा आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध है कि बवानीखेड़ी अस्पताल में प्राथमिकता के आधार पर उपकरणों व डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए । अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मेरे विधानसभा क्षेत्र बवानीखेड़ा की नहरों में पिछले काफी समय से नियमानुसार पानी नहीं आ रहा है । किसानों की मांग है कि इस इलाके की नहरों में कम से कम 7 दिन पानी का शिड्यूल शुरू किया जाए । इसके अतिरिक्त बवानीखेड़ा हल्के में 10 हजार की आबादी से ज्यादा जनसंख्या वाले गांवों में सरकारी अस्पतालों की स्थापना की जाए । अध्यक्ष महोदय, बवानीखेड़ा हल्के में कोई भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, मेरी मांग है कि इस हल्के के गांव खरक के आसपास स्पैशल औद्योगिक जोन की स्थापना की जाए ताकि इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिल सके । हमारे प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछले अढ़ाई साल में सड़कों की मरम्मत के लिए काफी पैसा दिया है । मेरा आपके माध्यम से लोक निर्माण मंत्री जी से अनुरोध है कि अब बवानीखेड़ा हल्के के कच्चे रास्तों को भी पक्का किया जाए । अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे द्वारा सदन में बवानीखेड़ा हल्के की रखी गई मांगों को पूरा किया जाए ताकि जनता में सरकार के प्रति विश्वास को और अधिक मजबूती मिल सके । अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मंदिर जैसे इस पवित्र सदन में मेहरबानी करके विधायकगण छींटाकशी न करें । किसी कवि ने कितना सुन्दर कहा है कि :–

एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है,
इंसान हर रोज मंदिर जाता है फिर भी पत्थर ही रहता है।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

श्री भगवान दास कबीरपंथी (नीलोखेड़ी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । वित्त मंत्री जी वर्ष 2017–18 के लिए बिना किसी टैक्स बढ़ोतरी के 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट लेकर आये हैं उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी का भी बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं । अध्यक्ष महोदय, इस बजट में हर क्षेत्र के लिए बजट दिया है चाहे वह किसानों की भलाई की बात हो, प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ–साथ बेरोजगारों को रोजगार मिलने की बात हो, चाहे हमारे सीमा पर जो जवान शहीद हो जाते हैं उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा होने की बात हो, गरीब से गरीब आदमी को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिल सके। इन सभी बातों का माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रावधान किया है । अध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रदेश में समान रूप से कार्य हो रहे हैं । चाहे सड़कों की बात है जिस तरह से सड़कों की इतनी दयनीय हालत थी आज हर सड़क पर चाहे वाईडनिंग करने की बात हो, चाहे उसको बनाने की बात हो । आज सड़कों का हर प्रकार का काम चल रहा है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और बच्चो को शिक्षा के लिये दूर न जाना पड़े उसके लिये मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 21 कॉलेजों का एक दिन में शिलान्यास किया है । आज उन कॉलेजों को बनाने के लिये सरकार द्वारा 12–12 करोड़ रूपये दे दिये गये हैं । यह बनने के बाद इनमें लैक्चरर और स्टाफ की व्यवस्था भी हो जाएगी क्योंकि जो कॉलेज बनाए गय हैं उनको इस तरह से बनाकर खाली नहीं छोड़ेंगे । उनके लिये पैसे आदि सभी चीजों का प्रावधान किया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : मंत्री जी, हमने हमारी सरकार के समय में दादरी हल्के में मोती लाल नेहरू कॉलेज के लिये ढ़ाई करोड़ रूपये दान में दिये गये थे उसका तो अभी तक कुछ नहीं हुआ ।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, एक कॉलेज हमारे गांव मातनहेल में बनाया गया था लेकिन वह अभी तक चालू नहीं हुआ है। वहां पर अभी तक टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टॉफ के लिये कोई भी पोस्ट सैंग्शन नहीं हुई हैं ।

श्री अध्यक्ष : गीता जी, कोई बात नहीं हो जाएंगी । अगर आप इतने सीनियर मैंबर भी इसी तरह से बीच में बोलते रहोगे तो कैसे काम चलेगा ।

श्री भगवान दास कबीरपंथी: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और कृषिमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में जो गेहूं और धान की फसल के संकट से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिये हमारे नीलोखेड़ी हल्के के अन्जनथली गांव में एक बागवानी विश्वविद्यालय बनाने की सौगात दी है जिससे वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलेगी और वहां के किसानों का बागवानी की तरफ रूझान भी बढ़ेगा । मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमारे क्षेत्र तरावड़ी में एक इंजीनियर कॉलेज और एक गवर्नमैंट कॉलेज बनाने का आश्वासन दिया है । समय कम होने के कारण मैं अपनी बात को संक्षिप्त करते हुए मेरे हल्के की कुछ मांगों के बारे में कहना चाहूंगा जो बरसों से लम्बित हैं। नीलोखेड़ी में जो अनाज मंडी है वह बिल्कुल शहर के बीच में है । वहां जगह कम होने की वजह से जब किसान अपनी फसल लेकर आता है तो उसको अपनी फसल सड़कों पर डालनी पड़ती है । जिससे आम जन तो परेशान होता ही है और किसानों को भी बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है । मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं और माननीय करणदेव जी भी वहां का दौरा करके उस अनाज मण्डी की हालत को देख चुके हैं । इसलिये मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस मंडी को शहर से बाहर निकालने का समाधान किया जाए । इसके साथ–साथ तरावड़ी में हमारा एक ऐतिहासिक गुरूद्वारा है जिसके लिये हमारे सिख समुदाय की भी और पूरे समाज के लोगों की भी यह मांग है कि सोंकड़ा रोड़ से अनाज मंडी की तरफ से जो रोड़ गुरूद्वारा की तरफ जाता है उस पर गुरू तेगबहादुर के नाम से एक गेट बनवाया जाए । हमारे सभी विधायकों के लिये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे जो ड्राईवर और गनमैन हैं जिनको हम अपने साथ लाते हैं लेकिन हम जब विधान सभा में अन्दर आते हैं तो उनको बाहर छोड़कर आते हैं गर्मी हो या सर्दी हो, उनके बैठने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । मेरा निवेदन है कि उनके लिये भी यहां विधान सभा में बैठने की व्यवस्था की जाए ।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, श्री भगवान दास कबीर पंथी जी की यह बात बिल्कुल सही है इसलिये ड्राइवर और गनमैन के लिये भी कोई गैरेज बनाई जाए ।

श्री भगवान दास कबीरपंथी : अध्यक्ष महोदय, हमारा निसिंग कस्बा एक बहुत बड़ा कस्बा है । वहां पर बहुत बड़ी अनाज मंडी है और बहुत बड़ा चावल का एक्सपोर्ट होता है यह निसिंग कस्बा कैथल और करनाल रोड़ पर पड़ता है । इस समय निसिंग एक सब तहसील है, उसका दर्जा बढ़ाकर उसे तहसील का दर्जा दिया जाए । निसिंग शहर बहुत भीड़भाड़ का क्षेत्र है इसलिये इस भीड़ को कम करने के लिये शहर से बाहर एक बाई पास निकाला जाए ताकि आम जनता को इसकी सुविधा मिल सके । इसके अलावा निसिंग में लड़कियों के लिये एक कॉलेज बनवाने की भी मांग कई सालों से है क्योंकि निसिंग करनाल से 35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और तरावड़ी से भी यह लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इसलिये वहां पर एक कॉलेज बनाया जाए। इसी के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये आपका बहुत–बहुत धन्यवाद ।

डॉ0 पवन सैनी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय साथी श्री भगवान दास कबीरपंथी जी ने कहा है, मैं भी एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे सभी पुलिस कर्मचारी बाहर चौक पर आधा–आधा पौना–पौना घण्टा खड़े रहते हैं । उनको जाने के लिये कोई सवारी नहीं मिलती । इसलिये उनके लिये भी कोई बस की व्यवस्था की जाए ।

श्री अध्यक्ष : यह तो आप वैसे ही बता देते । इस बात को यहां कहने की आवश्यकता नहीं थी ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमें भी तीन मिनट बोलने का मौका दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : आप तीन मिनट तो बोलती नहीं हो जब बोलती हो तो 44 मिनट बोलती हो । आपके हाथ में माइक आने के बाद 44 मिनट बोलती हो इसलिये आप अपनी एडजस्टमैंट कर लो । मैंने 20 मिनट में पांच सदस्य बुलवा दिये ।

बैठक का समय बढ़ाना

16:00 बजे

श्री अध्यक्षः यदि सदन की सहमति हो तो हाउस का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये?

आवजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः ठीक है, हाउस का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा एवं वित्त मंत्री द्वारा उत्तर

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): आदरणीय अध्यक्ष जी, बजट पर जितनी भी तमाम तरह की चर्चाएं सदन में माननीय सदस्यों ने की हैं, मेरा सोचना यह है कि उनमें तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, उनके बारे में स्पष्टता और ज्यादा बढ़े। कई बार जानकारियों के अभाव में बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं जिसकी वजह से अपनी–अपनी जानकारी के हिसाब से ही माननीय सदस्य योजनाओं के संबंध में विभिन्न प्रकार का अपना–अपना मंतव्य रखते हैं, इसलिए किसी भी योजना में सुधार की गुंजाइश, बेहतरी की अपेक्षा और संतुलन की भावना बहुत ही महत्व रखती है। अध्यक्ष महोदय, जिस विजन पर वर्तमान बजट तैयार किया गया है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा वित्त मंत्री जी को धन्यवाद व बधाई देता हूँ। बाकायदा तौर पर सोच समझकर योजनाएं बनाई गई हैं। केवल एक्टैम्पोर, कुछ बातें सोच ली गई हों और उसके आधार पर कुछ योजनाएं तैयार कर ली गई, ऐसा नहीं है? जो योजनाएं बनाई गई है, उन पर बहुत सारे सवाल माननीय सदस्यों ने खड़े किए हैं, कुछ बातें सुझाव के तौर पर भी सामने आई हैं और कुछ बातें जो सामने निकलकर आई हैं, उनमें मुझे लगता है कि स्पष्टता की जरूरत है? इन सबमें ग्रामीण विकास का क्षेत्र बहुत ही महत्व रखता है और निःसंदेह यह हमारी सरकार की प्राथमिकता का विषय भी है और यह प्राथमिकता बजट आबंटन में पूरी तरह से परिलक्षित भी होती है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनेकों योजनाएं इस सरकार के समय में शुरू की गई हैं, चाहे वह ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित हो, चाहे ग्रामीण सचिवालय की बात हो या फिर गांव तक वाई–फाई ले जाने की बात हो, कहने का मेरा मतलब यह है कि इन सब चीजों के साथ ग्रामीण क्षेत्र का जो इंफ्रॉस्ट्रक्चर है, वह बहुत सशक्त रूप से खड़ा होना चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्री होने के नाते मैं भी इस बात को महसूस करता था और यही कारण है कि मैं इन

सभी चीजों को गांवों में उपलब्ध करवाने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी से बार–बार आग्रह और अनुरोध करता था ताकि बजट में इन सभी चीजों को उचित स्थान प्राप्त हो। अध्यक्ष महोदय, अब तक ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितना बजट आबंटित होता था है वह पर्याप्त नहीं होता था, लेकिन इस बार के बजट में जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बजट आबंटन किया गया है उसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा। ग्रामीण विकास के लिए किसी बजट में एक वर्ष में 56 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ोतरी करने का कोई भी उदाहरण दिखाई नहीं देता। बजट में ग्रामीण विकास के लिए बजट आबंटन को 3167 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 4963 करोड़ रूपये करना, सरकार की सुस्पष्ट प्राथमिकता का ही एक उदाहरण है जो स्पष्ट करता है कि हमारी सरकार ग्रामीण ढांचे को पूरी तरह से बदलना चाहती है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, जिसके तहत गांवो में शहरों जैसी सुविधायें देने का लक्ष्य रखा गया है, को आगे बढ़ाते हुए यह प्रावधान किया है कि इस क्षेत्र में विकास के लिए 60 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार मुहैया करवायेगी और 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार मुहैया करवायेगी। अब हालत यह है कि हरियाणा प्रदेश में अर्बन मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में आठ प्रोजैक्ट सलेक्ट हो गए हैं। बड़ी बड़ी आई.आई.टीज., यूनिवर्सिटिज ने तथा श्रीराम कॉलेज जैसे कॉलेजों ने ग्रामीण क्षेत्र को बेहतर ढंग से परिवर्तित व विकसित करने की दिशा में मैप बनाये हैं, योजनाएं बनाई हैं और अर्बन क्षेत्र में हरियाणा सरकार द्वारा चयनित आठ क्षेत्रों के लिए 80 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त अब मैं महाग्राम योजना के अंतर्गत बजट आबंटन के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी व वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत सारे बड़े–बड़े गांव ऐसे है जिनकी आबादी 10000 से भी ज्यादा है और जिनमें कई–कईं पंचायतें होती है। इस तरह के तकरीबन 116 गांव प्रदेश में हैं जहां पर इतनी ज्यादा आबादी रहती है। इन सभी बड़े गांवों को शहरों जैसी सुविधायें जैसे सीवरेज लाइन बिछाने व यहां पर स्वच्छता का स्तर बढ़ाने के लिए महाग्राम योजना बनाई गई है और इसके लिए कहा गया है कि 400 करोड़ रूपये आने वाले तीन साल में खर्च होंगे और 100 करोड़ रूपये इस वर्ष के बजट में आबंटित किए गए हैं और प्राथमिकता के तौर पर इस वर्ष 16 गांवों को महाग्राम योजना में लिया गया है ताकि इन गांवों का स्वरूप पूरी तरह परिवर्तित हो। हम यही नहीं रूके और हमने 3 हजार से 10 हजार तक

की आबादी के 16 सौ गांवों को ढांचागत सुविधाएं देने और स्वच्छता के स्तर को बढ़ाने के लिए नाबार्ड से 5 हजार करोड़ रूपये लेकर एक योजना बनाई है । हमने इस वर्ष के लिए पहली बार में 6 सौ गांवों को लिया है और इनके लिए बजट में 12 सौ करोड़ रूपये का प्रोविजन किया है । हम इन गांवों में यह काम इसी वर्ष शुरू करेंगे । यह हमारी बहुत बड़ी पहल है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का इसके लिए धन्यवाद करता हूं और उनका अभिनन्दन करता हूं । अभी माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश जी एक सवाल पूछ रहे थे कि सरकार पहले वर्ष में इस स्कीम के तहत कितने गांवों को कवर कर रही है ? हम शुरू में 6 सौ गांवों को इस स्कीम के तहत ले रहे हैं । स्वच्छता हमारी सरकार की प्राथमिकता है और उसके लिए हम आंदोलन के रूप में कार्य कर रहे हैं । हम 2 हजार गांवो में 3 पौंड सिस्टम और 5 पौंड सिस्टम शुरू कर रहे हैं । हमें इस बात की खुशी है कि स्वर्ण जयंती वर्ष में हम सम्पूर्ण हरियाणा को खुले में शौच से मुक्त बना रहे हैं । हमें खुशी है कि हरियाणा का स्वर्ण जयंती वर्ष एक ऐसा वर्ष होगा जिसके बाद कोई लोटा या बोतल लेकर खुले में शौच करने के लिए नहीं जाएगा । सरकार के इस अभियान में पंचायतों, आम जनों और जनप्रतिनिधियों ने खूब हिस्सेदारी की है । सरकार ने इस अभियान के लिए 6 सौ करोड़ रूपये का आबंटन किया है । गांव एक उपेक्षित इकाई हो चुका था और गांव की आबादी के लिए एक पुश फैक्टर था कि वह शहरों की तरफ जाती थी । गांव की लोकेशन के हिसाब से 10–20–30 परसेंट आबादी गांवों को छोड़ने लग गई थी । हम गांवो को टिकाऊ विकास का केन्द्र बनाते हुए उसके स्वरूप को बदलना चाहते हैं । माननीय सदस्या श्रीमती प्रेमलता ने अपने उद्बोधन में उल्लेख किया कि गांव में रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, दवाई, पढ़ाई, बिजली, सामाजिक जोखिम प्रबंधन और टिकाऊ विकास का लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं । यह बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है । यह बजट ग्रामीण विकास के लिए एक विजन है । इस नाते से हम ग्रामीण क्षेत्र के विकास का रास्ता बना रहे हैं । हम हरियाणा के गांवों को पुश फैक्टर की बजाय पुल फैक्टर बना रहे हैं । हम इस प्रकार से हरियाणा के गांवों को फिर से बसाना चाहते हैं । इसी मुद्दे पर मनरेगा से जुड़ा हुआ एक सवाल आया था कि उनकी पेमेंट्स नहीं हो रही है । यह सवाल भी उसी विभाग से जुड़ा हुआ विषय है । मैं बताना चाहूंगा कि हमने इस मद के लिए बजट में सौ करोड़ रूपये का प्रावधान किया है । इसके साथ ही हम चीजो में संतुलन बनाने का भी

प्रयास कर रहे हैं । कुछ समय पहले हरियाणा में खाद की कमी आ गई थी तो मैंने विभाग से पूछा कि हमारा खाद का स्टॉक कितना है ? मुझे पता चला कि पहले खाद का कुल स्टॉक 35 हजार टन होता था लेकिन अब हमने अपना स्टॉक 2 लाख टन तक कर दिया है। अगर हमें कभी केन्द्र सरकार से खाद मिलने में दिक्कत आई तो हमें अपने पास अच्छा स्टॉक होने से कभी खाद की कमी का सामना करना नहीं पड़ेगा । इसी तरह जिन चीजों की प्राप्ति में कोई डिले होती है हम उनके लिए फंड्स की व्यवस्था कर रहे हैं । इसके लिए हमने बजट में सौ करोड़ रूपये का प्रावधान किया है । भारत सरकार के पास हमारे जो 71 करोड़ रूपये बकाया थे उनको 7 मार्च को सैंक्शन कर दिया गया है । मैं सदन को यह जानकारी मनरेगा मजदूरों के विषय में दे रहा था । इसके अतिरिक्त एग्रीकल्चर सैक्टर का विकास हमारी प्राथमिकता है । कृषि के विषय में माननीय सदस्य श्री आनन्द सिंह दांगी बड़े मन से बोल रहे थे । मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में हमें काफी परिवर्तन करने और कंक्रीट सुझावों की आवश्यकता है । इनसे सरकार को सहयोग मिलता है । एग्रीकल्चर सैक्टर के लिए जो बजट एक हजार करोड़ रूपये का रखा गया था अब वह डेढ़ हजार करोड़ रूपये का कर दिया गया है । हमने केवल ऐग्रीकल्चर सैक्टर में ही 50 फीसदी बजट की वृद्धि की है । हमने कृषि क्षेत्र के लिए माइक्रो इरीगेशन प्रणाली को प्राथमिकता में रखा है । कुछ समय पहले पराली को जलाने का विषय भी बहुत उठाया गया था । हमने वेस्ट मैनेजमैंट के उपकरण खरीदने के लिए 50 परसेंट सब्सिडी का प्रावधान किया है और 63 हजार रूपये का कैप रखा है । हमारा विचार है कि खेत में पराली का जलाना धरती माता के गर्भ को जलाना है । हम किसान को पराली इत्यादि के जलाने की प्रथा से हटाकर अलग रास्ते पर ले जाना चाहते हैं । इस प्रकार की चुनौती पानी की है इसलिए माइक्रो इरीगेशन की प्राथमिकता रखी है। अध्यक्ष महोदय, हमारा सपना है कि किसान खुशहाल रहे इसलिए किसान का अपना बीमा हो, किसान के पशुओं का बीमा हो, किसान की फसल का बीमा हो आदि सब चीजों पर हमारी नजर है। किसान के पशु का 100 रूपये में तीन साल का बीमा कर रहे हैं। भेड़–बकरी के लिए 25 रूपये में तीन साल का बीमा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, फसल अवशेष जलाने की रोकथाम तथा इसके प्रबंधन के लिए वर्ष 2017–18 के लिए हमारी सरकार ने भूसा प्रबंधन उपकरणों, प्रशिक्षण और प्रदर्शन के लिए 303.15 करोड़ रूपये की एक कार्य योजना का बजट में प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, कई

बार जानकारी की स्पष्टता न होने के कारण सूचनाएं आ जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2016 में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ फसल में स्थानीय दावों के लिए जैसे ओलावृष्टि और जलभराव के कारण किसानों को 9.86 करोड़ रूपये वितरित किए जा चुके हैं। लगभग 2400 गांवों में क्रॉप कटिंग एक्सपीरिएंस के माध्यम से जो फसल के उत्पादन में कमी आई है, उसका लगभग 200 करोड़ या इससे अधिक मुआवजा अभी किसानों में वितरित होना बाकी है। लेकिन अस्पष्टता के कारण बहुत से माननीय सदस्यों द्वारा फसल बीमा के बारे में लोगो के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है कि यह फसल बीमा किसान के हित के लिए नहीं है। क्योंकि वे कहते हैं कि इस फसल बीमा योजना में किसानों का पैसा तो इतना गया और मुआवजा केवल इतना मिला है। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि क्रॉप कटिंग एक्सपैरिमेंट करने वाली बीमा कम्पनियों ने आज तक अपने ऑफिस ही नहीं खोले हैं। जबकि एग्रीमैंट के अनुसार बीमा कम्पनियों के ऑफिस खुल जाने चाहिए थे। इस तरह से क्रॉप कटिंग एक्सपैरिमेंट हुआ ही नहीं तो बीमा कम्पनी मुआवजा कहाँ देगी?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैंने बहुत दिनों से माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल की बातों का जवाब देना बंद कर दिया है क्योंकि दलाल जी हाउस में सबसे अविश्वसनीय सदस्य हैं। दलाल जी, सरकार पर कोई ना कोई झूठे आरोप लगाकर सदन से चले जाते हैं और किसी भी आरोप पर टिकते नहीं है। सिर्फ यह कहते रहते हैं कि मैं इसके लिए वहाँ जाऊँगा या ज्ञापन देने यहाँ आऊँगा। अगर यह नहीं हुआ तो मैं वह कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, दलाल जी का काम केवल अखबारों में खबर देना है, दूसरा कोई मकसद नहीं है। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अगर मेरी बातों का जवाब नहीं देते हैं तो क्या मेरे ऊपर ये कोई एहसान करेंगे ?

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, दलाल जी को माननीय मंत्री जी से बात करने का सलीका नहीं आता है– करेगा का क्या मतलब होता है। दलाल जी, माननीय मंत्री के साथ आपको बोलने की तहजीब भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, दलाल जी का माननीय मंत्री जी को संबोधन करने का तरीका ठीक नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः दलाल जी, आप बैठ जाइये। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, दलाल जी इस सदन के सबसे ज्यादा समय बर्बाद करने वाले और अविश्वसनीय सदस्य हैं, यह बात मैं दोबारा से कहता हूँ। (विघ्न) दलाल जी, अपनी बात पर कहीं पर भी टिकते नहीं है। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी सरकार के सबसे भ्रष्ट मंत्री हैं। बीजों और दवाई खरीद में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। (विघ्न)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, दलाल जी को ये बातें साबित करनी पड़ेगी कि माननीय मंत्री जी ने कौन से बीजों में भ्रष्टाचार किया और कौन सी दवाओं में भ्रष्टाचार किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सबूत है। यदि सदन कहे तो मैं उन सबूतों के दस्तावेज सदन के पटल पर रख दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री दलाल अपना जैसा सभी को भ्रष्ट समझते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से मांग करता हूँ कि वे विधानसभा की एक कमेटी बनाकर जांच कराएं। चुनाव के शपथ पत्र में दर्शाई संपत्ति के अलावा, तीन गाएं, तीन बछड़े और कुछ स्मृति चिन्ह के अलावा कुछ भी मेरे पास मिल जाए तो वह प्रदेश सरकार की संपत्ति होगी। अध्यक्ष महोदय, उस कमेटी में मीडिया के लोगों को भी शामिल कर लें, यह भी मैं घोषणा करता हूँ। दलाल जी, अपनी तरह सभी को चोर समझते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूँ कि सदन इनकी संपत्ति की जांच करवाएं।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं भी सदन में कह रहा हूं।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी नहीं है और ये सदन में झूठ बोलते हैं और भाग जाते हैं। इसके लिए इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाए और ये आज फिर सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य धमकियां दे रहे हैं। मैं तो जन प्रतिनिधि होने के नाते लोगों की तरफ से कह रहा हूं अगर हमारी किसी बात का जबाव नहीं देना है तो न दें।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, देखिये यह सबके ध्यान में आ गया है, यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि एक अच्छी योजना पूरे देश में चल रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पूरे देश के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इससे इनको तकलीफ हो गयी है और इनके खिलाफ झूठ बोलने पर पहले ही एक प्रिविलेज मोशन आया हुआ है और इनकी तकलीफ मैं नहीं मिटा सकता। (शोर एवं व्यवधान) क्योंकि सबको मालूम है इस बात के बारे में कि ये झूठ बोलकर फंस गये हैं यह इनकी एक निजी तकलीफ है और यह इनको पूरी उम्र रहेगी। मैं इस समस्या को हल नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के हर गांव में क्रॉप कैटिंग एक्पीरियंस हुआ है। इनको जानकारी नहीं है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है जो ए.डी.ओज. व बी.ओज. ने किया है। वह क्रॉप कैटिंग एक्सपीरियेंस 6646 विलेजिज में किया गया है और 2428 गांवों में 36 प्रतिशत में उन्होंने यह पाया है कि जो फसल जितनी होनी चाहिए थी उससे कम हुई है। इसलिए ऐसे सभी गांवों के किसानों को 200 करोड़ से अधिक मुआवजा दिया जाएगा। यह मैं इस सदन के माध्यम से जानकारी दे रहा हूं, खासकर के कांग्रेसी बन्धु इस बात को ध्यान से सुने। क्योंकि कल माननीय हुड्डा साहब का लेख अखबार में छपा हुआ था जिसमें 9.86 करोड़ रूपये के मुआवजे की राशि के बारे में छपा हुआ था उसमें आगे की जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने इसमें यह एड कर दिया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, अखबार में मैंने इतना ही कहा था कि सरकार ने किसानों को कितना कंपनसेशन दिया है उस बात को स्पष्ट कर दिया कि सरकार किसानों को इतना कंपनसेशन दे रही है। यह एक अच्छी बात है, मेरा एक सवाल माननीय कृषि मंत्री जी से है कि क्या वे फसल बीमा योजना को किसान हितैषी मानते हैं?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के समय में जो किसानों के लिए योजनाएं चलायी थी वे सभी योजनाएं किसान हितैषी थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी यह मानते हैं कि यह योजना किसान हितैषी है तो पंजाब में बी.जे.पी. और अकाली गठबंधन की सरकार है वहां पर क्यों नहीं लागू किया गया है? मंत्री जी इस बात का जबाव दें।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, देखिए पंजाब का उत्तर मैं नही दे सकता हूं। मैं एक बात हुड्डा साहब को बताना चाहता हूं कि आप भी किसान परिवार से आते हैं मैं कहता हूं यह किसानों के लिए बहुत बेहतरतम योजना है। यह किसान के लिए बेहतर योजना है। जब–2 किसानों को कोई नुकसान होगा। आंध्र प्रदेश में जब किसानों को नुक्सान हुआ उनका प्रीमियम 800 करोड़ रूपये था और आंध्र प्रदेश को कंपनियों ने 1200 करोड़ रूपये दिये। इसके अतिरिक्त छतीसगढ में जब आपदा आयी तो उनका प्रीमियम 250 करोड़ रूपये था लेकिन बीमा कम्पनियों को 275 करोड़ रूपये देने पड़ रहे हैं। ये बीमा कंपनियां ऐसे नहीं रूक सकती क्योंकि यह मुआवजा नुकसान का है। यह कोई अदला–बदली का मुआवजा नहीं है। इस मामले में हरियाणा प्रदेश सबसे बेहतर है कि हमारे प्रीमियम की दर सबसे कम रही है जो सरकार द्वारा घोषित दर थी उससे भी कम प्रीमियम पर हम कंपनियों को लेकर आए हैं हुड्डा साहब को मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले सत्र में भी इनको याद दिलाया था कि वे तुलसीदास राजा वाली कहानी की किताब पढ लेते। आपने यह योजना पहले ही चार जिलों में लागू की थी और अब हमारी सरकार ने इसको पूरे हरियाणा में लागू कर दिया है। इससे पूरे हरियाणा के किसानों को लाभ होगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः मंत्री जी, ठीक है हमारे शासन में भी यह योजना लागू की गयी थी। हमने इस योजना को किसी पर जबरदस्ती लागू नहीं किया बल्कि इस योजना को किसान की मर्जी पर छोड़ा गया था। मैंने पिछली बार भी कहा था वह योजना किसान हितैषी नहीं थी और आज भी कहा रहा हूं यह फसल बीमा योजना किसान हितैषी नहीं है लेकिन आपकी सरकार ने इस योजना को कंपलसरी किया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जो स्कीम लागू की गई है वह किसान हितैषी नहीं है। यह तो रिकॉर्ड की बात है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब के समय में प्रीमियम की राशि सात या साढ़े सात परसेंट तक चली जाती थी। इनके समय में जो विनियमित राशि थी, वह 17–18 हजार तक रहती थी और जिस बात को ये कह रहे हैं कि इनके समय में छूट थी तो मैं एक बात इनको बताना चाहता हूं कि इनके समय में छूट नहीं थी। यहां पर मुद्दा यह है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी तरह का लोन देते हैं और अगर उस लोन के बदले में किसी भी तरह की बीमा करने वाली कोई संस्था है तो वह लोन के समय बीमा जरूर करते हैं। इसमें

सरकार के पक्ष की छूट की बात नहीं है। बैंक जब क्रॉप लोन देते हैं तो उनको एक फैसिलिटी मिल जाती है कि जब बीमा हो रहा है तो वे लोन को बीमा करके ही देंगे। हुड्डा साहब अपने समय के दस्तावेज देख लें और हम दोनों साथ बैठकर इस बारे में चैक कर लेंगे। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार के समय में किसान अगर एग्रीमेंट नहीं करता था तो उसके पैसे नहीं कटते थे और आज ऐग्रीमेंट हो चाहे नहीं हो, सबके पैसे काटे जा रहे हैं और एक नहीं कामर्शियल बैंक अलग काट रहे हैं, को–ऑपरेटिव बैंक अलग काट रहे हैं। आप इसमें सुधार लायें, इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। यह जो फसल बीमा योजना है यह अच्छी योजना है किसान को मिलनी चाहिए लेकिन आपने इसमें इस प्रकार के पैरामीटर रखे हैं, जिसके कारण इसका जो इम्प्लीमैंटेशन है वह ठीक से नहीं हा सकता। आप इसमें सुधार लायें, हम आपका साथ देंगे।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि यह सब किसानों के लिए कंप्लसरी नहीं होना चाहिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसी बात है तो हरियाणा सरकार किसानों का 2 साल का सारा प्रीमियम दे दे, यह कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इस विषय पर कॉल अटेंशन नहीं था और इतनी लंबी बहस इसी विषय पर हो रही है। केवल और केवल इसी विषय पर हो रही है, क्या आप सब लोग इसे भी एस.वाई.एल कैनाल का मुद्दा बनाओगे?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री श्याम सिंह राणा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि 6–7 हजार एकड़ जमीन यमुना के किनारे पर है, 400 रुपए का प्रीमियम देकर किसान अपनी फसल का बीमा कराता है और अगर उसकी फसल मर जाती है तो उसे 25,000 रुपये मुआवजे के मिल जाएंगे तो इसमें बुरी बात क्या है। मैं मानता हूं कि रोहतक में फसल नहीं मरती, लेकिन आप देखिए यमुना का एरिया, दिल्ली का एरिया जहां हजारों एकड़ जमीन है।(विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना बहुत बेहतर योजना है और उसको बहुत अच्छाई के साथ और बहुत ही कुशलता के साथ इस सरकार ने बहुत कम समय में इम्प्लीमैंट किया है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता

हूं कि मैं यह सवाल नहीं पूछ पाया था, इसलिए मैं हाउस को एक बात बताना चाहता हूं वरना किसी दिन फिर माननीय सदस्य प्रैस में कहेंगे कि वैदर बेस्ड क्यों नहीं किया और यह क्यों कर दिया। वैदर बेस्ड बहुत समय से चला हुआ था साढ़े 12 हजार से ऊपर उसमें विनियमित राशि नहीं थी, उसमें उससे ज्यादा किसी को मिलता नहीं था और वह यहां पहले से था जो कामयाब नहीं हो पाया था। इसमें 25000 रुपये तक विनियमित राशि है, ये किसानों के फेवर में ज्यादा है और उसमें 8 किलोमीटर में एक वैदर स्टेशन लगता था, जो पूरे इलाके की ठीक जानकारी नहीं दे सकता था, इसलिए इस सरकार ने बहुत विचार–विमर्श करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का चयन किया।

श्री अध्यक्ष : आपने जब अपनी बात रख ली तो अब प्वॉइंट ऑफ आर्डर क्या है। ये तीसरी या चौथी बार जवाब दे रहे है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, उनको पूरी तरह से तसल्ली करना मेरी जिम्मेवारी है।

श्री अध्यक्ष : धनखड़ जी, आपने कई बार उनको तसल्ली करा दी है, फिर भी उनको तसल्ली नहीं होती है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : आदरणीय अध्यक्ष जी, हम पूरे देश में गन्ने का सर्वश्रेष्ठ भाव दे रहे हैं । किसी माननीय सदस्य ने यह भी सवाल उठाया था कि प्रदेश में गन्ने की पैदावार इस बार ज्यादा हुई है । यह बात बिलकुल सही है । पहले प्रदेश में 93 हजार हैक्टेयर पर गन्ना उगाया जाता था, इस बार 1.11 लाख हैक्टेयर पर गन्ना उगाया गया है । इस बार 18 हजार हैक्टेयर भूमि पर ज्यादा गन्ना उगाया गया है जिसके कारण 21 लाख क्विंटल ज्यादा गन्ना पैदा हुआ है लेकिन सभी शुगर मिलों को गन्ना आवंटित किया हुआ है और सभी किसानों का गन्ना खरीदा जायेगा । इसके लिए सरकार पूरी तरह से सजग है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से वाटर लोगिंग एरियाज की बात भी आई थी । चाहे वह सेम की समस्या की बात हो, चाहे अलकाईन की समस्या की बात हो । इस तरह की प्रदेश में जितनी भी भूमि है उसके उपाय के लिए बजट में पैसे का प्रावधान किया गया है । इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं । इसी तरह से ऑगेर्निक खेती को बढ़ावा देने का भी विषय आया था । इसके लिए भी माननीय वित्तमंत्री जी ने बजट में पैसे का प्रोविजन किया है उसके लिए भी बधाई देता हूं । इसी तरह से दांगी साहब ने दूध

के ईनाम का विषय उठाया था। यह बात सही है कि शुरू में 8 किलो दूध पर ईनाम दिया जाता था । उसके बाद 10 किलो पर इनाम दिया जाने लगा । उसके बाद 11 किलो पर इनाम दिया जाने लगा और फिर 13 किलो पर इनाम दिया जाने लगा । अब 18 किलो दूध पर इनाम दिया जाता है । इसमें इनाम की राशि पहले 20 हजार रुपये होती थी लेकिन अब 30 हजार रुपये इनाम की राशि दी जाती है।

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, अब 30 हजार रुपये केवल एक आदमी को ही ईनाम दिया जाता है । पहले 11 किलो, 12 किलो, 13 किलो, 14 किलो, 16 किलो और 18 किलो दूध देने वाले पशुओं के मालिकों को अलग–अलग ईनाम दिए जाते थे । मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि यह स्कीम पहले की तरह कर दी जाये ताकि छोटे किसानों को भी लाभ मिल सके । इससे ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, देसी गाय ज्यादा मात्रा में पाली जायें उसके लिए हमने माननीय साथी का आग्रह माना हुआ है और उसमें 10 हजार, 12 हजार और 15 हजार रुपये के तीन ईनाम दिए जाते हैं । उसमें 6 से 8 लीटर, 8 से 10 लीटर और 10 से 12 लीटर दूध की लिमिट रखी हुई है । अब प्रदेश में घरेलू पशु पालन कम होता जा रहा है और डेयरी बनाना ज्यादा महत्व का काम हो गया है । आज के दिन दूध की आपूर्ति डेयरियों के माध्यम से ज्यादा हो सकती है। इसलिए 50 पशु तक की डेयरी के लिए सरकार सबसिडी देगी इस तरह की योजना इस बजट में हम ले आये हैं । यह बहुत ही अभिनंदनीय योजना है इसके लिए भी मैं वित्तमंत्री जी को बधाई देता हूं । इसी तरह से गौ सेवा आयोग का पैसा भी बढ़ाया गया है ताकि बेसहारा पशुओं से लोगों को जल्दी निजात मिल सके। अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन को यह जानकर खुशी होगी कि हर गांव में एक कैटल क्रेश बनाया जाये ताकि वहां पशुओं को दवाई दी जा सके । इसके लिए भी बजट में पैसे का प्रावधान किया गया है । क्योंकि कई बार महिलाएं दवाई देने में शर्माती हैं । इसके बनने से पशुओं को दवाई देने में सुविधा होगी । इस तरह से हरियाणा प्रदेश दूध के उत्पादन में नम्बर एक पर आ जाये हम इस विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं । इसके लिए मैं माननीय वित्तमंत्री जी को बधाई देता हूं ।

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आदमियों के हॉस्टिल्ज में सुविधाएं दी जाती हैं उसी तरह से पशुओं के हॉस्पिटल्ज में भी सुविधाएं दी जानी चाहिंए ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य का सुझाव नोट कर लिया है । अध्यक्ष महोदय, हमने सिंचाई के क्षेत्र में भी कई नई पहल की हैं । पहले माईक्रो इरीगेशन से सिंचाई नहीं होती थी अब हम माईक्रो इरीगेशन की सिंचाई को बढ़ावा दे रहे हैं । हमारा काडा विभाग इसके लिए कार्यवाही कर रहा है तथा इसके लिए 265 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है । इसके लिए भी मैं वित्तमंत्री जी को बधाई देता हूं । अगर हम सिंचाई के क्षेत्र में पूरी तरह से माईक्रो इरीगेशन पर आ जायें तो यह बहुत अच्छा होगा । इसी तरह से वाटर लोगिंग के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है ताकि नहर विभाग इसमें काम कर सके । पहले नहर विभाग और कृषि विभाग के बीच कुछ चलता रहता था । लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं होगा और वाटर लौगिंग की समस्या का समाधान भी अवश्य होगा । अध्यक्ष महोदय, जो हमारा कैनाल सिस्टम है वह बहुत पुराना हो गया है तथा वह 30 प्रतिशत पानी खुद पी जाता है । वित्तमंत्री जी ने कैनाल सिस्टम के पुनर्निर्माण के लिए 180 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जिससे 125 चैनल और 400 जल मार्गों का पुनर्निर्माण किया जायेगा । इसके लिए भी मैं वित्तमंत्री जी को बधाई देता हूं क्योंकि यह बहुत अच्छी पहल है । अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी कैनाल्ज पर पुल की मांग भी आती है और 50 करोड़ रुपये उनके लिए भी रखे गये हैं । हम प्रैशराइज पाइप नैटवर्क नई चीज लेकर आ रहे हैं ताकि ड्रेन के लिए जो पानी कहीं से निकालना है और जमीन नहीं मिल रही है तो जमीन के अंदर से पाइप डाल कर उसके माध्यम से पानी को निकाला जाये । हम यह नई शुरूआत इस साल से करने जा रहे हैं ताकि जहां पर जमीन नहीं मिल रही वहां पर पूरी की पूरी कैनाल पाइप लाइन के माध्यम से निकाली जाये । इस तरह से इस बजट से हम पाइप लाइन कैनाल भी शुरू कर रहे हैं । इसी तरह से अंडर ग्राउंड वाटर इन्फॉर्मेशन का सिस्टम कहां–कहां पर कितना–कितना है यह जानकारी भी सिंचाई विभाग को रहे इसकी भी शुरूआत करने जा रहे हैं । इसी तरह से रियल टाईम पानी की व्यवस्था की जानकारी लेने के लिए भी शुरूआत कर रहे हैं ताकि सिंचाई विभाग को पता चल सके कि किस नहर में कितने क्यूसिक पानी चल रहा है, कौन सी नहर बंद है और कौन सी नहर चल रही है । इसके

लिए भी 50 करोड़ रुपये का प्रारंभिक प्रावधान बजट में किया गया है । इसके लिए मैं वित्तमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं कि यह बहुत ही विजन के साथ उठाया गया कदम है ताकि हर खेत को पानी मिल सके । अध्यक्ष महोदय, जिस समय मैं मंत्री बना था उस समय मत्स्य विभाग का पूंजीगत व्यय 5 करोड़ रुपये का था जो कि अब 79 करोड़ रुपये हो गया है ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अगर सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 40 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक का समय 40 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा एवं वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : स्पीकर सर, इस प्रकार से हम इस दिशा में भी अपने प्रदेश के किसानों को तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक बहुत ही सुविचारित मद के साथ जो हमारा हौर्टीकल्चर का विजन है अर्थात शहरी–अर्बन कंसैप्ट है उसमें आने वाले तीन वर्षों में खर्च करके पूरे प्रदेश में 340 कलस्टर बनाकर इस दिशा में बड़ी मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसकी मार्किटिंग अच्छी प्रकार से हो इसलिए हमने इसके लिए 50 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान रखा है। जिन सदस्यों ने आलू, गोभी, टमाटर और प्याज के मुद्दे उठाये हैं उनकी जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार द्वारा एक कॉरपस फण्ड बनाया गया है कि किस प्रकार से इनकी कीमतों में कमी आने की स्थिति में इनका उत्पादन करने वाले किसानों को सहयोग किया जा सके। इसी प्रकार से हर जिले में एक्सीलैंसी सैंटर खोलते हुए हरियाणा बागवानी का हब बने उस रास्ते पर हम दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं निश्चित रूप से यह कहता हूं कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से एक स्पष्ट विज़न के साथ और विज़न के हिसाब से बजट का आबंटन करते हुए इस रास्ते पर आगे बढ़ रही है जिसके कारण आने वाले समय का हरियाणा एक पूरी तरह से बदला हुआ हरियाणा होगा। यह इस बजट में से दिखाई देता है। सभी का बहुत–बहुत अभिनंदन।

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्री वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमानों पर हुई चर्चा का उत्तर देंगे।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत–बहुत आभार व्यक्त करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस सरकार का लगातार तीसरा, विशेष रूप से स्वर्ण जयंती वर्ष का बजट और उससे भी ऊपर हरियाणा सरकार के इतिहास का पहला एक लाख करोड़ रूपये से भी आगे बढ़कर यह बजट प्रस्तुत करने का मुझे अवसर और सौभाग्य दिया। मैं इस बात के लिए भी आपका आभारी हूं कि जो बजट की पूरी प्रक्रिया है इसमें इतनी लम्बी, इतनी वृह्द और इतनी विस्तृत चर्चा आपने यहां पर करवाई है जिसके तहत बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस बजट के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी है और अपनी तरफ से इसको सराहा भी है। जहां कहीं पर इसमें कोई कमियां भी हैं उनकी आलोचना भी की है, अपने–अपने सुझाव भी दिये हैं और अपनी–अपनी तरफ से सुविधानुसार हिदायतें भी दी हैं। जहां तक हमारे प्रयास है जितने भी माननीय सदस्यों ने, मीडिया के मित्रो ने और दूसरे समीक्षकों ने इस बजट के ऊपर जो अपना फीड–बैक दिया है। कुल मिलाकर के उस फीड–बैक से मैं इस नाते संतुष्ट हूं कि इतने महत्वपूर्ण लोगों ने अपना बहुमूल्य समय इस बजट को पढ़ने में लगाया है। अपने–अपने तरीके से अपना–अपना दिमाग लगाकर अपने–अपने तरीके से इसकी समीक्षा करके अपनी प्रतिक्रियायें दी हैं। मैं पूरे हाउस का और सभी साथियों का पुनः–पुनः बहुत–बहुत आभार करता हूं जो साथी यहां पर नहीं हैं क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही थी और हम भी यही चाहते थे कि उनकी सारी की सारी बातों का हम जवाब दें लेकिन वे यहां पर नहीं हैं इसलिए हमें उनकी कमी यहां पर जरूर महसूस होगी। इसी प्रकार से आज किरण चौधरी जी ने एक शेर–ओ–शायरी का माहौल भी यहां पर शुरू किया है। मैं भी यहां पर अपना रिस्पांस उनकी पार्टी के नेता श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के परिप्रेक्ष्य में देना चाहूंगा कि –

'ले गया मेरी जान रूठ कर जाना तेरा,
ऐसे आने से तो बेहतर था न आना तेरा।'

स्पीकर सर, हम चाहते थे कि वे यहां पर हमारे बीच में रहते और हमारे रिस्पांस को सुनते क्योंकि यह तो एक निरंतर प्रक्रिया है। (विघ्न) स्पीकर सर, जब हमारी इस

विधान सभा का प्रथम सैशन हुआ था उस समय हुड्डा साहब ने ही हमें मार्गदर्शन दिया था कि यहां पर सदन के अंदर पुरानी यादों को ताज़ा करते रहने के साथ ही साथ हंसी–मज़ाक का माहौल भी बनाये रखा जाना चाहिए। इसलिए हम उनकी उस नसीहत को ध्यान में रखते हुए इसका प्रयास करते हैं। अध्यक्ष जी, इस बजट के दृष्टिगत हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को लेकर हमने जो प्रयास किया था कि हम इस बजट में हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक वर्ग की पूरी की पूरी चिंता करेंगे। इसी के ध्यान में रखते हुए एक लाख करोड़ रूपये की धनराशि का हरियाणा प्रदेश के हर वर्ग चाहे वह किसान हो, चाहे वह कमेरा, मजदूर, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, महिलायें, युवा, बेरोजगार, विद्यार्थी, व्यापारी, कर्मचारी, उद्योगपति सभी वर्गों को लाभ कैसे पहुंचे, इस बात की हमने कोशिश की है। यह जो बजट है यह केवल मात्र आंकड़ों का संतुलन ही नहीं होता। यह बजट प्रदेश की कुल कितनी आमदनी है और किसकी क्या आवश्यकता है, आज समाज की क्या आवश्यकता है और सरकार की प्रॉयोरिटीज़ क्या हैं इन सभी बातों का समावेश करने का प्रयास इस बजट में किया गया है। जो सुझाव, जो टिप्पणियां और जो आलोचनाएं अलग–अलग तरीके से आई हैं हर साथी ने यहां पर जो विषय रखा उसका हरेक का जवाब देने में तो शायद समय बहुत ज्यादा लगेगा और यह सम्भव नहीं होगा लेकिन प्रमुख जो बातें हैं उनका जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा । जिनका जवाब मैं यहां पर नहीं दे पा रहा हूं व्यक्तिगत तौर पर चाहे मुझे उनको रीचआउट करना पड़े, मैं उनको पर्सनली जवाब अवश्य दूंगा । सुझाव और हिदायतें मिली हैं उनको भी नोट करके सरकार में हर विभाग के स्तर पर उनको पहुंचा कर आगे की योजनाओं में जो भी सकारात्मक सुझाव आये हैं उनका समावेश करने की हम कोशिश करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मुख्य तौर पर इस बजट में अगर देखें तो बजट के ऊपर आलोचना का कोई कारण नहीं मिल रहा है कि एक लाख करोड़ रुपये का बजट इतना बढ़ गया तो जो आलोचना के शब्द मैंने देखे या पढ़े या सुने हैं कि यह आंकड़ों की जादूगरी है । यह कहा गया कि डैट ट्रैप में हरियाणा को फंसाया जा रहा है और फिस्कल डेफिसिट और रिवैन्यू डेफिसिट बढ़ रहा है और बड़ी–बड़ी बातें इस कर्जे को लेकर कही गई हैं । ऐसी भी टिप्पणी की गई है कि हरियाणा आर्थिक तौर पर कमजोर हो रहा है। मैं केवल आंकड़ों के आधार पर बात करूंगा क्योंकि आंकड़े ही सच बोलते हैं और आंकड़े ही प्रमाण हैं । अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो आंकड़ों के माध्यम से ही किसी सरकार का काम बोलता

है । अपनी सरकार की वर्तमान वर्ष की जी.डी.पी. की ग्रोथ 9 प्रतिशत दर्शाई है । हमने शुरू कहां से किया था, 2014–15 का साल पिछली सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट और हमने एक बड़ी हिम्मत की कि हरियाणा प्रदेश की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करें, एक ईमानदार डायग्नोसिस करें और इस सच्चाई को जानने की कोशिश करें कि हरियाणा की वित्तीय स्थिति, वित्त प्रबंधन की स्थिति क्या है और 48 वर्ष में हरियाणा कहां पहुंचा है? इस दौरान बहुत अच्छे काम भी हुये हैं । हम हरियाणा की वित्तीय स्थिति पर एक व्हाइट पेपर भी लेकर आये थे । हमने उसमें तमाम बातें लिखी । बहुत सारे साथियों ने सरकार में भी सुझाव दिया कि व्हाइट पेपर एक ऐसा महत्वपूर्ण डॉकूमैंट है अगर आप यह देंगे तो आप इससे बंध जायेंगे । इसके अनुसार आपकी सरकार के 5 साल के कार्यकाल का आंकलन भी इसी के आधार पर होगा लेकिन हमने संकल्प किया कि एक ईमानदार डायग्नोसिस करेंगे और उसके बेसिज पर हम अपने हरियाणा की वित्तीय स्थिति का जो ईलाज है उसको प्रारम्भ करेंगे । मैं उस पर आता हूं। हमारा 2014–15 का जो जी.डी.पी. ग्रोथ रेट था वह 5.7 प्रतिशत था जो बढ़ कर पिछले वर्ष 8.7 प्रतिशत था और इस बार 9 प्रतिशत प्रोजैक्टिड है । इसी तरह से पर कैपिटा इन्कम की बात की जाये तो हरियाणा के अढाई करोड़ से अधिक लोगों को उस जी.डी.पी. का कितना हिस्सा मिल रहा है और आज उसकी हर आदमी की क्या स्थिति है? वर्ष 2014–15 में जो 4 प्रतिशत की ग्रोथ रेट थी वह बढ़ कर 7.5 प्रतिशत और इस साल 7.2 प्रतिशत ग्रोथ रेट प्रति व्यक्ति की प्रोजैक्टिड है । एक सवाल हमारे विधायकों में से भी पूछा गया था । मुझे विशेष रुप से याद है कि श्री जयप्रकाश जी ने चर्चा की थी कि जी.डी.पी. तो बढ़ रही है और सरकार कृषि में पैसा भी लगा रही है और कृषि का उत्पादन भी बढ़ रहा है लेकिन किसान को इसका लाभ कितना पहुंचा, वे आंकड़े भी हमारे पास उपलब्ध हैं । जब वर्ष 2014–15 में श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी थी तो कृषि की विकास दर था 2014–15 में –2 प्रतिशत घट गई थी । उसी –2 प्रतिशत से बढ़ कर कृषि की विकास दर आज 2 साल बाद 7 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि के साथ बढ़ी है । आज कृषि और संबंधित क्षेत्र बढ़ा है और प्रति व्यक्ति जो उसका लाभ मिलना चाहिए जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र में जो व्यक्ति लगे हैं उनके बारे में हरियाणा के जो स्टैटिस्टिक हैं जो आंकड़े हैं मैं यह विधान सभा के पटल पर कह रहा हूं कि कृषि में जो 7 प्रतिशत का ग्रोथ लाभ था 11 प्रतिशत प्रति व्यक्ति उस व्यक्ति को मिला है जो कृषि करता है । यह कृषि की

ग्रोथ से भी ज्यादा मिला है । (शोर एवं व्यवधान) आदरणीय अध्यक्ष जी ये मेरी बात पूरी होने दें । हमने आराम से इनकी बात को सुना है ।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार किसानों को खाद के ऊपर सब्सिडी देगी या नहीं देगी ?

श्री अध्यक्षः जय प्रकाश जी, आप बैठिये, आपकी बात पूरी हो गई है।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, हमारा हरियाणा प्रदेश हो या देश का कोई भी प्रदेश हो उसकी वित्तीय स्थिति के कुछ मानदंड तय किये जाते हैं और ये मानदंड फॉरटीन्थ फाईनैंस कमीशन ने तय किये हैं । फिस्कल रिस्पोंसिब्लिटी एंड बजट्री मैंनेजमैंट एक्ट के तहत 14 वे फाईनैंस कमीशन ने कुछ मानदन्ड तय किये हैं और उन्होंने लिख कर के दिया है कि हरियाणा राज्य अपनी कुल सकल घरेलू उत्पाद जी.एस.डी.पी. का 25 प्रतिशत तक वह अपने स्टेट की टोटल बोरोइंग जो डैट है, जो लोन है वह ले सकता है । आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कल प्रैस कॉन्फ्रैंस की है और आज वह अखबार में छपा है । उनको शायद किसी ने लिख कर दिया है या उनको ध्यान नहीं रहा । उन्होंने कहा है कि यह एफ.आर.बी.एम. की लिमिट सरकार पार कर गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह लिमिट 20.5 प्रतिशत थी । जो आज के सभी अखबारों में यह छपा है । मैंने सोचा कि एक अखबार में गलती हो गई होगी कि 25 प्रतिशत की जगह 20.5 प्रतिशत लिखा गया होगा लेकिन मैंने सभी अखबारों में पढ़ा सभी में 20.5 प्रतिशत ही लिखी हुई थी । इसलिये मैं उनकी और सदन की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि यह सीमा 25 प्रतिशत है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह 25 प्रतिशत की लिमिट अभी हुई है लेकिन पहले यह लिमिट 20.5 प्रतिशत ही थी । पहले यह रिवाईज टारगेट था वह मैंने कहा था । मुझे मालूम है कि अब यह एफ.आर.बी.एम. की लिमिट बढ़कर 25 प्रतिशत हो गई है ।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, यह एफ.आर.बी.एम के नार्म्स हैं । यह अब नहीं बढ़े हैं । माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बहुत काबिल हैं उन्होंने दस साल तक हरियाणा प्रदेश को चलाया है । इसमें उनके समय के एफ.आर.बी.एम नार्म्स भी हैं । बजट के पृष्ठ संख्या 190 पर 14वें फाईनैंस कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है –

> "Fiscal deficit of all States will be incurred to an annual limit of 3% of GSDP. The States will be eligible for flexibility of .25% over and above this for any given year for which the borrowing limits are to be fixed if their debt GSDP ratio is less then or equal to 25% in the preceding year."

Sir, now it is 25%. माननीय अध्यक्ष जी, दो साल हो गये हैं और बताया जा रहा है कि लिमिट क्रोस हो गई । वर्ष 2014–15 में श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी । प्रैस के मित्रों को भी मैं निवेदन करूंगा कि वे भी अच्छी तरह से समझ लें क्योंकि एक साथी ने उसमें एक डैट ट्रैप शब्द भी यूज किया है । डैट ट्रैप की स्थिति नहीं है । हरियाणा की स्थिति वित्तप्रबंधन के क्षेत्र में हिन्दुस्तान के सबसे बेहतर राज्य की है। मैं यह सदन के पटल पर कहता हूं । मैं इसका जवाब दूंगा और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि सी.ए.जी. ने जो कहा है उसकी ही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और बजट को अच्छी तरह से पढ़ कर समझना चाहिए । सी.ए.जी. की रिपोर्ट को पहले पी.ए.सी. एग्जामिन करेगी । सी.ए. जी. ने बड़ा स्पष्ट करके कहा है कि लोन लेने की लिमिट बढ़ी है लेकिन लिमिट पार नहीं हुई है । मैं पहले भी इस महान सदन में जवाब दे चुका हूं जो रिकॉर्ड पर है मैं अपने पुराने जवाब भी रिकॉर्ड पर लेकर आया हूं । जो बातें आज मैं कह रहा हूं यह सारी बातें इस महान सदन में पहले ही कही जा चुकी हैं कि उदयपौंड को सबस्क्राईब करने के बाद दो वर्ष तक एफ.आर.बी.एम. की लिमिट ऐप्लीकेबल नहीं होंगी । उसके बावजूद भी हमने एफ.आर.बी.एम. की लिमिट को पार नही किया है। पहले साल केवल फिस्कल डैफिसिट की लिमिट है। मान्यवर, इनके प्रश्न में ही इनका उत्तर छिपा है । जो वर्ष 2014–15 की सरकार थी उस समय जो बजट पेश किया गया था उसमें 70 हजार करोड़ रूपये का लोन प्रस्तावित किया था जो इन्होंने प्रैस कॉन्फ्रैंस में भी कहा है । अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त हमने सरकार को टेक–ओवर किया तो पाया कि बिजली कंपनी व डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के नाम पर कांग्रेस सरकार ने बहुत बड़ा कर्जा लिया हुआ था। (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, इसका कारण यह है कि उस समय हरियाणा प्रदेश में बहुत ज्यादा प्रोजैक्ट लगाए गए थे तो वाजिब सी बात है कि इस तरह के कार्य के लिए अगर कर्जा लिया था तो क्या गलत था? (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, चाहे प्रोजैक्ट लगाये गये लेकिन कर्जा तो लिया ही हुआ था? (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कादियान जी को बैठ जाना चाहिए

और मेरी बात सुननी चाहिए। मैं उनकी एक–एक बात का जवाब दूंगा इस तरह वक्ता के बीच में व्यवधान डालना ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने प्रदेश हित में काम करते हुए कर्जा लिया था, लेकिन इनकी सरकार में विकास के कोई भी कार्य नहीं किए गए फिर भी कर्जा लिया जा रहा है। कैग ने हरियाणा प्रदेश के हर विभाग में बरती जा रही अनेक अनियमित्तताओं पर सवाल उठाये हैं। कैग की रिपोर्ट बताती है कि एक साल से प्रदेश की 2865 करोड़ रूपये की राजस्व वसूली अधर में लटकी हुई है और प्रदेश में स्थित सभी बिजली कम्पनियां लगभग 2126 करोड़ रूपये के घाटे में चल रही हैं।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, कादियान जी मेरी बात को सुनना नहीं चाह रहे हैं। मेरी आपकी माध्यम से डॉक्टर साहब से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उनको मेरी बात सुननी चाहिए। मैं उनकी हर बात का जवाब दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, वित्त मंत्री जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, अतः आपको एक बार उनकी बात को सुन लेना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मेरी बात को भी तो सुना जाना चाहिए? कैग की रिपोर्ट बताती है कि एक साल से प्रदेश की 2865 करोड़ रूपये की राजस्व वसूली अधर में लटकी हुई है और प्रदेश में स्थित सभी बिजली कम्पनियां लगभग 2126 करोड़ रूपये के घाटे में चल रही हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः डॉक्टर साहब, आप एक बार मंत्री जी को अपनी बात रख लेने दें उसके बाद आप अपनी बात रख लेना।(शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कादियान साहब को सदन की दुहाई देकर कहता हूँ कि उन्हें मेरी बात सुननी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) मैं कादियान जी को सदन की मर्यादाओं की दुहाई देकर पुनः अनुरोध करूंगा कि उन्हें मेरी बात को सुनना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) मैं इनकी पूरी बात का जवाब दूंगा।

उसे लगता है, उसकी चालाकियां मुझे समझ नहीं आती ।
मैं बड़ी खामोशी से देखता हूँ, उसे अपनी नज़रों से गिरते हुए।।

(इस समय मेजें थपथपाई गई।)

अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो पाया कि कांग्रेस सरकार के समय में 26,000 करोड़ रूपया जिसकी वास्तविक फिगर 25,950 करोड रूपये है। इसमें जो 50 करोड़ रूपये का फर्क है उसका प्रयोग मैं राउंड फिगर में लाने के लिए कर रहा हूँ, यानि 26,000 करोड़ रूपये का कर्जा कांग्रेस सरकार के शासन काल में विभिन्न बिजली कंपनियों के नाम से उनके खाते में चढ़ा हुआ था। हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए 70 हजार करोड़ रूपये का नया लोन लिया और इस नये लोन की जितनी ब्याज दर कम हो सकती थी, कराई और पूरे हिन्दुस्तान में सबसे सस्ता लोन लेकर एक मिसाल कायम की। 70 हजार करोड़ रूपये पर कम ब्याज दर के कारण 800 करोड़ रूपये प्रति वर्ष का लाभ हरियाणा प्रदेश के अढ़ाई करोड़ लोगों को हो रहा है और यदि अगले दस साल के हिसाब से देखें तो हरियाणा प्रदेश को 8000 करोड़ रूपये का फायदा होगा। **(इस समय मेजें थपथपाई गई।)** इस फैसले की वजह से राउंड फिगर में 3000 करोड़ रूपये के लगभग प्रति वर्ष बिजली कंपनियों पर कर्ज का बोझ कम हुआ है और वास्तविक फिगर में यदि देखें तो यह कर्ज का बोझ 2700–2800 करोड़ रूपये के करीब कम हुआ है। इसका सुपरिणाम यह हुआ है कि अब हम बिजली कंपनियों के लाभ को आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में हम स्वयं को सक्षम पा रहे हैं। 26000 करोड़ रूपये का कर्जा कांग्रेस सरकार ने लिया था, हमारी सरकार ने नहीं लिया था और हमने सरकार में आने के बाद 70,000 करोड़ रूपया लोन लिया और वह भी बेहद ही कम ब्याज दर पर, इस प्रकार टोटल कर्जा 96,000 करोड़ रूपये हो जाता है। जब हम सत्ता में आये और जबकि कांग्रेस ने 26,000 करोड़ का लोन लिया हुआ था तो उस समय जी.एस.टी.पी. की लिमिट 22.15 हुआ करती थी लेकिन यदि हम इनके लोन को तथा हमारी सरकार द्वारा लिए गए लोन को जमा करते हैं तो यह 96,000 करोड़ रूपये बनते हैं तो ऐसी हालत में भी हमारी जी.एस.टी.पी. की रेट बोरोईंग लिमिट 22 प्रतिशत है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय जी.एस.टी.पी. की लिमिट 22.9 प्रतिशत है अर्थात 23 प्रतिशत।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी.पी. की लिमिट 23 प्रतिशत नहीं है बल्कि 22 प्रतिशत की लिमिट है और यह भी अभी प्रस्तावित ही है। पिछले वर्ष जो कर्ज प्रस्तावित किया था, हमारी सरकार ने उससे भी 2000 करोड़ रूपये कम कर्ज लिया है। यह हमारे बेहतर कुशल वित्तीय प्रबंधन की वजह से संभव हुआ है।

मान्यवर, मैं एक–एक आंकड़े पर बात करूंगा। आज किरण जी, ने हमारे अंदर का शायर जगाया है। इस मौके पर एक शेर सुनाता हूँ:–

चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है मुझ पर बेवफाई का। जिन्होंने रौंद डाला इस चमन को, वही दावा करते हैं इसकी रहनुमाई का।

(इस समय मेजें थपथपाई गई।)

श्री अध्यक्षः आज तो कमाल कर दिया वित्त मंत्री जी ने। (हंसी)

कैप्टन अभिमन्युः आदरणीय अध्यक्ष जी, जब हम सत्ता में आए तो शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी हमें एक पुरानी रमलू वाली कहानी का एक पुराना किस्सा सुनाया करते थे कि ताई चालती जा और देखती जा। (हंसी) जब हम सत्ता में आये तो उस समय हमारी यही हालत हुआ करती थी और यही कारण है कि कांग्रेस के लोगों द्वारा खोदे गए गढ्ढों यानि हरियाणा प्रदेश पर चढ़ाये गए कर्ज को उतारने के लिए हमारी सरकार ने बहुत ही सस्ते रेट पर कर्जा लेकर हरियाणा प्रदेश को बचाने का काम किया है। सस्ता कर्ज लेकर हम पैसे बचा रहे हैं लेकिन बावजूद इसके हम पर इल्जाम लगाये जाते है। यह देखकर मुझे खुशी भी होती है और हैरानी भी होती है। खुशी इस बात की होती है कि विषय उठेगा और हम जवाब देंगे तो सच्चाई सबके सामने उभरकर सामने आयेगी और हैरानी इस बात से होती है कि आदमी इतना मगरूर कैसे हो सकता है कि जिनको इस बात का भी कोई गम नहीं कि उनके अपने शासनकाल में क्या हालत हुआ करते थे। वह यह सोचे बिना भी हम पर आरोप लगा रहे हैं।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई मगरूर कैसे हो सकता है। मैंने यही बात कही थी कि वित्त मंत्री जी ने अपनी सरकार के पिछले अढ़ाई साल के शासन काल में भी यही बात कही थी कि I will inherit fiscal आज अढ़ाई वर्ष का समय बीत जाने पर भी वही बात कह रहे है। अब तो सरकार को सत्ता में आए अढ़ाई साल हो गए हैं how can he hide behind the same wail.

Captain Abhimanu: Speaker Sir , not at all. I am not and I would not. I assure Madam Kiran Choudhry that I would not. अध्यक्ष महोदय, मैं वही बात नहीं कह रहा हूँ। आदरणीय किरण जी ने चूंकि इंटरवेशन किया है, मैं

सोच रहा था कि बाद में बताउंगा लेकिन उन्होंने मुझे बीच में इंट्रप्ट किया है इसलिए इस मौके पर मुझे एक शेर याद आ गया है और वक्त की नजाकत को देखते हुए मैं इसे सुनाना जरूरी समझता हूँ। शेर है किः–

मत कर खाक के पुतले पे, गरूर– ओ– बेनियाजी इतनी
खुद को खुदी में झांक कर देख, के तुझमें रखा क्या है?

(इस समय मेजें थपथपाई गई।)

Smt. Kiran Choudhry: Speaker Sir, next time I will also bring some poems and then will ask Capt. Sahib to have a competition.

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष जी, हम तो सीधे–सादे फौजी की तरह बात करते थे लेकिन आज माननीय सदस्या ने हमें इतनी बार हुजूर कहकर सम्बोधित कर दिया कि मैं इनका मुरीद हो गया । (विघ्न)

Education Minister (Shri Ram Bilas Sharma): Speaker Sir, Madam Kiran Choudhry is a scholar from Cambridge University and our Hon'ble Finance Minister is a scholar from Harvard University. This is a difference.

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ बताना चाहता हूं । हरियाणा प्रदेश के अढाई करोड़ लोग किसान, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति आदि सभी वर्ग वर्ष के 365 दिन और रात लगाकर जो पैदावार करते हैं और जो चीजें बनाते हैं उसको जी.एस.डी.पी. या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं । सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर मानदण्ड तय किया जाता है कि सरकार के खाते में कितना राजस्व आना चाहिए और कितना टैक्स आना चाहिए । उसी के हिसाब से हम लोन लेने की सीमा तय करते हैं कि कितना लोन ले सकते हैं । उसी के आधार पर तय होता है कि लोन का सालाना ब्याज कितना होना चाहिए । मैंने व्हाइट पेपर से रिलेटिड एक आंकड़ा आपके सामने रखा है । अभी माननीय सदस्या किरण जी ने हमारी सरकार से सवाल किया है कि आपने क्या किया है ? मैं इनको जी.एस.डी.पी. की ग्रोथ रेट बता चुका हूं कि हम इसे 5.7 से 9 परसेंट पर लेकर आए हैं और कृषि की विकास दर माइनस 2 से 7 परसैंट पर लेकर आए हैं। मैं इनको फिस्कल पैरामीटर्स के भी सारे आंकड़े देना चाहूंगा । (विघ्न) Speaker Sir, I assure Madam Kiran Choudhry that every point that

she has raised will be very respectfully responded to and anything that is left she is most welcome to ask me to explain anything any time and wherever she says, I will come and explain to her. (Interruption) I assure her. (Interruption) It is my utmost responsibility towards the people of Haryana through the Members. (Interruption) आदरणीय अध्यक्ष जी, सरकार की टोटल जी.डी.पी. का सरकार के खजाने में जो राजस्व आना चाहिए जिसको टोटल रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं जिसमें टैक्स और नोन टैक्स होता है वह वर्ष 2014–15 में 9.33 प्रतिशत था । टैक्स और नोन टैक्स का अमूमन रेश्यो 75:25 होता है । इसमें 3/4 टैक्स रेवेन्यू होता है और 1/4 नोन टैक्स रेवेन्यू होता है । जी.डी.पी. की टोटल रेवेन्यू रिसीट्स जो वर्ष 2014–15 में 9.33 प्रतिशत थी वह वर्ष 2017–18 में 11.12 प्रतिशत प्रोजैक्ट की गई है । मैं इन आंकड़ों की पिछली सरकार के 10 वर्षों के कालखण्ड के आंकड़ों से तुलना करना चाहूंगा । जब भारत सरकार ने वैट शुरू किया था तो हरियाणा सरकार को उसका लाभ मिला था और उस समय रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति थी । वर्ष 2006–07 में टोटल रेवेन्यू रिसीट्स जो हॉयेस्ट अचीव हुई थी वह 13.95 परसेंट रेवेन्यू ऑफ टोटल जी.डी.पी. था यानि कि उस साल सरकार के खजाने में जी.डी.पी. का लगभग 14 प्रतिशत कुल राजस्व आया था । अध्यक्ष जी, मैंने ईमानदारी से ईयर–ओन–ईयर कैलकुलेशन करके पिछले दस साल की रिकवरी काउंट की थी । अगर वर्ष 2006–07 का 13.95 परसैंट रेवेन्यू ऑफ जी.डी.पी. कलैक्ट होने का ट्रेंड हर साल कंटीन्यू रहता तो पिछले दस साल में सरकार के कर राजस्व और गैर कर राजस्व में 95 हजार करोड़ रूपये की कमी आनी चाहिए थी । अगर ऐसा होता तो सरकार को 95 हजार करोड़ रूपये की बचत होती और इसके अतिरिक्त 96 हजार करोड़ रूपये का लोन भी नहीं लेना पड़ता । मैं ऐसा नहीं कहता कि लोन लेना नहीं पड़ता, लोन लेना जरूरी है। किसी भी बढ़ती हुई विकास की अर्थव्यवस्था में किसी भी कम्पनी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिवार को या किसी भी संस्था को लोन लेकर ही अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार करके अपनी आमदनी को बढ़ाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2014–15 में 9.33 प्रतिशत थी और वर्ष 2015–16 में ये 9.80 प्रतिशत थी। इस तरह से एक दिन में कोई बदलाव नहीं होता है। ऐसा कोई बटन नहीं है कि यह 9.33 प्रतिशत से बढ़कर सीधे 13.95 पर आ जायें। इस तरह से फिर तो

एक लाख करोड़ रूपये निकाल लो लेकिन ऐसा नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2015–16 में पहले हम 9.80 प्रतिशत पर लेकर गये और ग्रोथ थी 16.57 प्रतिशत। वर्ष 2016–17 जो 31 मार्च को पूरा हो रहा है, 26.85 प्रतिशत ग्रोथ के साथ 11.02 प्रतिशत पर लेकर आए हैं। (**इस समय मेजें थपथपाई गई।**) अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017–18 में हमने अनुमान किया है कि 14.06 प्रतिशत बढ़ाकर सकल राज्य घरेलू उत्पाद को 11.12 प्रतिशत पर ले जायेंगे। इसका इफैक्ट यह होगा कि कुल मिलाकर के लगभग 22603 हजार करोड़ रूपये का अतिरिक्त रिर्सोस जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर गई थी उसमें जुटाया है ताकि लोन कम लेना पड़ेगा लेकिन डिवैल्पमैंट के लिए पैसे की कोई कमी न आए इसके लिए हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा रहता है कि जो हमारा लोन है और उसके ऊपर जो सालाना ब्याज दिया जाना है वह कितना है? यानी साल में जो कमाया उसमें से ब्याज के रूप में कितनी राशि गई? इसको साधारण वित्तीय भाषा में Acid Test Ratio या Liquidity Ratio कहते **हैं** कि कितना नकद आया और कितना ब्याज देना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण रेशो होती है। एफ.आर.बी.एम. एक्ट में कहा हुआ है कि 10 प्रतिशत से कम आ जायेगी तो हमें 0.25 प्रतिशत पर यदि दो कंडीशन पूरी कर देंगे तो और ऐडीशन लोन ले सकते हैं। इसका मतलब आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष कहता है कि सरकार की वित्तीय स्थिति खराब है। वर्ष 2014–15 में कुल राजस्व प्राप्तियां (टी.आर.आर.) 17 प्रतिशत थी। यानी की कुल राजस्व प्राप्तियां का 17 प्रतिशत ब्याज में जाता था। अध्यक्ष महोदय, मैं हमारी सरकार का तीन साल का ब्यौरा देना चाहता हूँ कि आज 17 प्रतिशत से घटाकर के 14.03 प्रतिशत पर लेकर के आ चुके हैं। (**इस समय मेजें थपथपाई गई।**) अध्यक्ष महोदय, यह आंकड़ा मैं सदन के पटल पर जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, साल दर साल जो लोन बढ़ रहा था वह वर्ष 2010–11 में 21 प्रतिशत, वर्ष 2011–12 में 20. 09 प्रतिशत और वर्ष 2013–14 में बढ़कर 25.05 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2014–15 में 24.05 प्रतिशत हो गया। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने इस लोन को घटाकर के वर्ष 2015–16 में 17.09 प्रतिशत, वर्ष 2016–17 में 17.6 प्रतिशत और वर्ष 2017–18 में प्रस्तावित 20.7 प्रतिशत तक किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने इसमें सुधार करके 25.05 से घटाकर के 20.07 प्रतिशत तक किया है। (**इस समय मेजें थपथपाई गई।**) अध्यक्ष महोदय, बजट में जो कैपिटल एक्सपैंडिचर की बात है

उसके बारे में सभी माननीय सदस्यों के सुझाव आए हैं कि कैपिटल एक्सपैंडिचर बढ़े। माननीय सदस्या श्रीमती प्रेम लता जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह 40 प्रतिशत तक हो जाना चाहिए। यह तो आदर्श स्थिति है, यदि 40 प्रतिशत हो जाये तो हमारी बहुत बढ़िया स्थिति हो जायेगी लेकिन हमारी सरकार ने इसको इस बार 21 प्रतिशत तक ले जाने की कोशिश की है। वर्तमान साल में 7400 करोड़ रूपये से 14900 करोड़ रूपये और बाकी मदो को मिलाकर के हमने इसको लगभग 20 हजार करोड़ रूपये तक पहुँचाने की योजना बनाई है। मान्यवर, इस प्रकार से एक ऐतिहासिक वृद्धि हमने इसमें की है।

17:00बजे **वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु):** अध्यक्ष महोदय, डॉ0 रघुबीर सिंह कादियान जी ने रैवेन्यू डैफिसिट के बारे में बड़ी चिन्ता व्यक्त की है। यह फिस्कल डैफिसिट मुझे लगता है कि उनको इसकी जगह लॉयबिलिटी का शब्द नहीं मिला परन्तु उनका अभिप्राय यह था कि जो टोटल फिस्कल डैफिसिट है उसके बारे में सदन के माध्यम से हरियाणा की जनता को बताया जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, रैवेन्यू डैफिसिट और टोटल रिसीट ये दोनों चीजें अलग–अलग हैं। मैं माननीय सदस्य की जानकारी को सलाम करता हूं।

डॉ0 रघुबीर सिंह कादियान: मेरी बात में कोई फर्क है तो मैं इसके बारे में आपको आंकड़े देता हूं।

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, डॉ0 साहब विद्वान हैं, मैं इनसे सीखना चाहता हूं ये सिर्फ सदन से जाने की बात करते हैं, बुलाने की बात नहीं करते हैं। (विघ्न) आज खाने का निमंत्रण मैं इनको देता हूं। मान्यवर, रैवेन्यू डैफिसिट कायदे से 2012 में जीरो हो जाना चाहिए था जबकि वर्ष 2013–14 में रैवेन्यू डैफिसिट 3875 करोड़ रूपये था। कांग्रेस की सरकार ने वर्ष 2014–15 का जो बजट प्रस्तुत किया था उसमें रैवेन्यू डैफिसिट में 114 प्रतिशत की वृद्धि की गयी थी यानी दुगुना से भी ज्यादा किया गया और उसे 8319 करोड़ रूपये किया गया है। वर्ष 2013–14 से वर्ष 2014–15 में अगर एक साल में इतनी बढोतरी नहीं की गयी होती तो रैवेन्यू डैफिसिट काबू में आ चुका होता। हमने जब व्हाईट पेपर प्रस्तुत किया और कहा कि हमारी गिरती हुई अर्थव्यवस्था की स्थिति है, उसको पहले रोकना होगा उसके बाद फिर कोर्स करक्शन और दिशा परिवर्तन करके आगे बढना होगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी जी ने पिछली बार अपने इन्टरवैंशन

में वही शब्द प्रयोग किये थे। उन्होने तब भी यही कहा था कि it is a rudderless ship लेकिन मैंने तब भी कहा था कि यह शिप पूरी तरह से तूफान झंझावत में जरूर है लेकिन इसकी कमान एक काबिल कप्तान के हाथ में है। हम इस किश्ती को तूफानों से निकालकर ले जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं बल्कि तथ्यों पर आधारित बातें कर रहा हूं कि रैवेन्यू डैफिसिट वर्ष 2014–15 में 114 प्रतिशत बढाकर पिछली सरकार ने 8319 करोड़ रूपये किया था। वर्ष 2015–16 में हमने उसको घटाकर 7787 करोड़ रूपये किया। उसके बाद अगले बजट में वर्ष 2016–17 में 7266 करोड़ रूपये किया। इस साल वर्ष 2017–18 में फिर घटाकर हमने 5816 करोड़ रूपये किया है। मान्यवर, जो रैवेन्यू डैफिसिट और जी.एस.डी.पी. की रेशो 1.9 प्रतिशत पिछली सरकार नें हमें विरासत में दी है। हमने उसको इस साल सुधार कर 1 प्रतिशत से नीचे यानी .94 लाने का लक्ष्य रखा है। जो हम निश्चित तौर पर लेकर आएंगे और हमने वर्ष 2019 तक लक्ष्य रखा है कि हम इसको शून्य पर लेकर आएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, फिस्कल डैफिसिट की बात आती है। जैसे हमारे माननीय सदस्य डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान ने बताया था कि टोटल खर्चा और टोटल रिसीट को मिला लो और जो बाकी बच जाए उसके लिए लोन लेना पड़ जाए वह फिस्कल डैफिसिट होगा। वर्ष 2013–14 में 8314 करोड़ रूपये थे ये एफ.आर.बी.एम. कांग्रेस के समय पर लागू था जो आज हमको अखबार के माध्यम से ज्ञान दिया जा रहा है ये माननीय सदस्य सदन में न बोलकर ये बाहर नो बाल और वाईड बाल फेंक रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2013–14 में 8314 करोड़ रूपये बढाकर 12580 रूपये वर्ष 2014–15 यानी 51 प्रतिशत किया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, अगर नाम लिया जाए तो सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी का नाम लेकर संबोधित नहीं किया। यह आरोप झूठा है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लिया गया है कि मुझे सदन में बोलने का मौका नहीं दिया गया। मैं आपका आभारी हूं मैंने जब बोलने के लिए समय मांगा, आपने मुझे समय दिया। मुझे मालूम है जिसके आगे बीन बजाने से समझ में नहीं आता मैं उसके सामने बीन नहीं बजाता। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय किरण जी बहुत अनुभवी नेता हैं और ये कांग्रेस का नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने हुजूर कहकर आज मेरा मान–सम्मान बढ़ाया है।

श्री करण सिंह दलाल : कैप्टन अभिमन्यु जी, ये गलतफहमी मत रखिएगा। (हंसी)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिंदगी का अगर लेना है शुरूर, जिंदगी का अगर लेना है शुरूर और तोड़ना ये अपना है गुरूर, तो बस एक बार करो जरूर, गुनाह जानकर अपने आप को माफ करो जरूर। (विघ्न) अध्यक्ष जी, उनको विरासत में जो फिस्कल डैफिसिट जो मिला, अगर 2013–2014 में और 2014–2015 में 51 परसेंट की फिस्कल डैफिसिट की वृद्धि नहीं की गई होती तो आज फिस्कल डैफिसिट की हालत इतनी खराब नहीं होती। जैसे डॉ कमल गुप्ता जी ने कहा हम आज भी 3 प्रतिशत तक लोन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अप्रत्याशित वृद्धि सीधा 51 प्रतिशत बढ़ जाना, ये कहीं न कहीं वित्तीय प्रबंधन की कुशलता में कोई न कोई कमी तो जरूर है। अध्यक्ष महोदय, 2014–2015 में 12,580 है और हमने इसको आज 2.61 की रेंज में लाने का काम किया। अध्यक्ष जी, हम इसमें 0.39 भी कर सकते हैं। किरण जी, आपने ठीक कहा है, मैं उसी बात पर आना चाहता हूं, आपने हमारा मार्गदर्शन कर दिया है। अध्यक्ष जी, मैंने टी.आर.आर रिसीप्ट्स के बारे में बताया और जो किरण जी ने बात कही वह है असली बात। ये किरण जी की बात सही है लोन तो लो लेकिन उसका कुछ करो तो सही। अध्यक्ष जी, पहले की हमारी सरकार जो लोन लेती थी, उसका कितना हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता था, वह मैं आंकड़ों के साथ बता कर रहा हूं। इसी सरकार के समय में वर्ष 2014–2015 में नेट बॉरोइंग 10,631 करोड़ रुपए की थी और कैपिटल एक्सपेंडिचर 42.87 परसैंट था। अब मैं बता रहा हूं कि जो नया लोन लिया जा रहा है उसका कुल कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है हमने वर्ष 2015–2016 में 42.87 परसैंट को बढ़ाकर 50.04 परसेंट किया हो और इस साल 2017–2018 में हमने यह प्रौजेक्ट किया है कि जो नया कर्जा लिया जाए, वह किसी ओर मद में खर्च न किया जाए, वह किसी ब्याज बट्टे में नहीं जाए, किसी तनख्वाह या किसी पेंशन में नहीं जाए बल्कि 88. 26 परसैंट वह कैपिटल एक्सपैंडिचर में जाए। अध्यक्ष जी, यह हमने तय किया है। इनकी सरकार के समय में इनके पास भी समय था, इन्होंने भी एक समय में अचीव किया था लेकिन ये कहीं न कहीं मंझधार में ही फंसकर रह गए। इनके समय की

नीतियों में भी परिवर्तन और ऊंच–नीच होते रहे लेकिन आज जो गलतियां हैं हम उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक बात आई कि जब हरियाणा में बच्चा अपनी मां की कोख से पैदा होता है और उसके ऊपर इतना कर्जा होता है। डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान जी का चेहरा मुझे याद है कि उस समय उनका चेहरा कैसा बना था ? मुझे लगा था कि पता नहीं हमने कौन सा बड़ा पाप कर दिया। अध्यक्ष जी, कुछ बातें है जो सदन से बाहर ही कहनी उचित रहेगी।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि सदन की सहमति हो तो सदन का समय 20 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये ।

आवाजें : ठीक है, जी ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन का समय 20 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है ।

वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा एवं वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भ)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, जहां तक पर कैपिटा ग्रोथ की बात है । वह इनकी सरकार के समय में बहुत अच्छी चल रही थी लेकिन 2014–15 में वह कम होकर 7.36 प्रतिशत रह गई थी । यानि जिस समय हमारी सरकार आई, उस समय हमें पिछली सरकार से पर कैपिटा ग्रोथ 7.36 प्रतिशत ही मिली थी । अध्यक्ष महोदय, हर आदमी की सालाना आमदनी साल दर साल बढ़ती है । जिस समय हमारी सरकार आई उस समय 7.36 प्रतिशत पर कैपिटा ग्रोथ मिली थी लेकिन उसके बाद लगातार बढ़ी है । वर्ष 2016–17 में 11.2 प्रतिशत थी और 2017–18 में 11.23 प्रतिशत हो जायेगी । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से कांग्रेस के साथियों ने कहा है कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति खर्चा हमारी सरकार आने के बाद बढ़ा है जबकि प्रति व्यक्ति खर्चा पिछली सरकार के समय में हर साल बढ़ रहा था । उस समय 2012–13 में 20.66 प्रतिशत और 2013–14 में 17.35 प्रतिशत की ग्रोथ से प्रति व्यक्ति खर्चा बढ़ रहा था । हम उसको 2016–17 में कम करके 15.63 प्रतिशत और 2017–18 में 15.46 प्रतिशत पर ले आये हैं । इस तरह से हमने प्रति व्यक्ति खर्चा 5 प्रतिशत कम किया है ।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े सही नहीं हैं ।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, यह घर की बही नहीं है बल्कि यह हरियाणा की अढ़ाई करोड़ जनता का हिसाब–किताब है। यह सवैंधानिक बजट है । यह संवैधानिक खत–किताब है। इसको कम्पट्रोलर एण्ड ऑडीटर जनरल वैट करेगा । इन कागजों को झूठ का पुलिंदा कहना संसदीय लोकतंत्र का अपमान है । जो यह कहता है कि सरकार का बजट झूठ का पुलिंदा है वह संसदीय लोकतंत्र और भारत के संविधान का अपमान करने का काम कर रहा है । यह बजट झूठ का पुलिंदा नहीं है । इसमें जो आंकड़े हैं, ये सच्चाई बोलते हैं । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से कहा गया कि नोट बंदी से फैक्ट्रीज बंद हो गई और लाखों लोगों के रोजगार चले गये । विपक्ष के साथियों की इस तरह की बातें हम अखबारों में पढ़ते थे और हमने सोचा कि यह उनकी राजनैतिक बयानबाजी होगी और सदन में आयेंगे तो जो सभी के सामने लिखा हुआ है उसको पढ़ लेंगे। बाहर की बातें बाहर ही रह जायेंगी । यह सदन हरियाणा की जनता का लोकतंत्र का मन्दिर है । यहां तो सभी को सच बोलना चाहिए क्योंकि आंकड़े अपने आप में सच बोलते हैं । ये आंकड़े किसी के बनाये हुए नहीं हैं । ये आंकड़े वे हैं जिनसे सरकार के खाते में राजस्व आया है । 2015–16 की तुलना में नवम्बर महीने तक 16.7 प्रतिशत की वृद्धि राजस्व की हुई है । अगर फैक्ट्रीज बंद हो जाती और लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जाता तो राजस्व में वृद्धि बिलकुल नहीं होती क्योंकि प्रोडक्शन रुक जाती और वैट नहीं मिलता । वैट से संबंधित कमेटीज में आदरणीय किरण चौधरी जी ने कई बार हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया है । उसमें इन्होंने बहुत अच्छा स्टैण्ड लिया था, जिसका आगे हमें लाभ भी मिला है । इनको पूरी बातों का ज्ञान है कि वैट की वृद्धि 16.7 प्रतिशत पिछले वर्ष नवम्बर तक किन कारणों से हुई थी और आर्थिक उन्नति और तरक्की का वही प्रमाण है । अध्यक्ष महोदय, 2015–16 की तुलना में पिछले वर्ष 2016–17 में दिसम्बर महीने तक राजस्व में 12.88 प्रतिशत की वृद्धि यह दर्शाती है कि नोट बंदी के दौरान हमारा आर्थिक तंत्र कमजोर नहीं हुआ बल्कि हमारे राजस्व में बढ़ोत्तरी हुई है । हमें कोई दिक्कत नहीं हुई बल्कि हमारा आर्थिक तंत्र मजबूत हुआ है । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, करण सिंह दलाल जी को हिंदी पढ़ाने के लिए राम बिलास शर्मा जी की कक्षा में भेजना पड़ेगा क्योंकि ये इनकी बात ज्यादा मानते हैं । मुख्यमंत्री जी भी ईब नहीं पढ़ने वाली कहानी सुनाते हैं और कुछ लोग बचपन में ही स्कूल से भाग लिये थे । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जो बचपन में नहीं पढ़े उनको कादियान जी ने पढ़ा दिया है ।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि एग्रीकल्चर और ऐलाईड सैक्टर का बजट घटा दिया गया । मैं उनकी बात को रिकॉर्ड पर लाने के लिए बताना चाहूंगा कि वर्ष 2016–17 के बजट का एग्रीकल्चर और ऐलाईड सैक्टर का टोटल शेयर 2.98 प्रतिशत था, जिसको हमने इस साल बढ़ाकर 3.13 प्रतिशत किया है । इसी प्रकार से रूरल डिवैल्पमैंट का जो वर्ष 2016–17 के बजट में शेयर था उसको हमने 3.50 परसैंट से बढ़ाकर वर्ष 2017–18 में 4.85 परसैंट किया है। इस प्रकार से हमने इन मदों के तहत बजट में शेयर को घटाया नहीं है, अपितु बढ़ाया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये बहुत सारे सुझाव और सवाल माननीय मित्रों के थे। मैं इन सभी का यहां पर जवाब नहीं दे सकता इसलिए इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में दो बातें अपनी तरफ से जरूर कहना चाहूंगा कि साल भर से हरियाणा प्रदेश में जो गलतब्यानी का दौर चल रहा था मैं उम्मीद करता हूं कि अब यह बजट आने से वह स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। अध्यक्ष जी, जिन माननीय सदस्यों ने यहां पर डैट रैप्ट का जिक्र किया मैं उनकी जानकारी के लिए डैट रीपेमेंट की परिभाषा बताना चाहूंगा। मैं उनको बताना चाहूंगा कि डैट रीपेमेंट का मतलब क्या होता है? मैं उनको यह भी बताना चाहूंगा कि डैट रीपेमेंट की अपनी एक टैक्नीकल परिभाषा है। (विघ्न) हरियाणा प्रदेश डैट रीपेमेंट की श्रेणी में नहीं आता है बल्कि हरियाणा प्रदेश हैल्दी सिचुएशन मे हैं। (विघ्न) अध्यक्ष जी, डैट रैप्ट का मतलब यह होता है कि जब कोई प्रदेश उसके द्वारा लिये गये लोन का मूल और उसका ब्याज भी अदा न कर पाये। इस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय में जो सालाना मूल और ब्याज वापिस किया जाता था हमने उसको जी.डी.पी. की तुलना में प्रति वर्ष घटाया है। एक माननीय सांसद ने यह ट्वीट किया कि हमारी सरकार 11 हज़ार करोड़ रूपये तो इंट्रस्ट पे किये चले जा रही है। मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार जो आज इंट्रस्ट पे कर रही है ये उनकी सरकार के समय का लिया हुआ लोन का इंट्रस्ट है। मैं यह मानता हूं कि यह ब्याज की अदायगी हमारी सरकार की जिम्मेदारी है लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह बढ़ाया नहीं है बल्कि हमने इस लॉयबिलिटी को घटाया है। अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में मैं एक शेयर इस आशय का ट्वीट करने वाले उस माननीय सांसद के लिए कहना चाहूंगा कि –

क्या इस बात का अहसास उसे हुआ है,

कि उसके ही हाथों से कत्ल यह हुआ है।

स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण विकास की और ग्रामवासियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए रहबरे–आज़म दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी के नाम पर हमारी सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। सरकार के स्तर पर इस योजना के नामकरण को लेकर बड़ी चर्चाएं और बहस हुई। मैं केवल रिकार्ड पर लाने के लिए यह कहना चाहता हूं कि चौधरी छोटू राम जी वे क्रांतिकारी समाज सुधारक थे जिनके प्रयासों से किसान–कमेरा–बेज़मीन मजबूर मज़दूर आज पगड़ी पहनने वाला ज़मीदार बना है। उन्हीं के प्रयासों से साहूकार–पंजीकरण एक्ट, 1938 पास हो पाया था। इसी प्रकार से उन्हीं के प्रयासों से ही गिरवी ज़मीनों की मुफ्त वापिसी एक्ट, 1938 हो पाया था। कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम भी उन्होंने ही पास करवाया था। हरियाणा प्रदेश में आज जो इतनी संख्या में एग्रीकल्चर मार्किट्स हैं ये हमारे हरियाणा प्रदेश के किसानों को चौधरी छोटू राम जी की ही अनूठी देन हैं। इनसे सम्बंधित अधिनियम भी उन्होंने 1938 में पास करवाया था। ऐसे ही उन्हीं के द्वारा व्यवसाय श्रमिक अधिनियम 1940 में पास करवाया गया। यह अधिनियम इसलिए पास करवाया था ताकि जो किसान मज़दूर हैं उनके अधिकारों को कोई भी छीन न सके। जो कर्ज़ माफी अधिनियम था वह उन्होंने 1934 में पास करवाया था। आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर भाखड़ा–नंगल डैम के माध्यम से केवल हरियाणा प्रदेश ही नहीं अपितु पंजाब, दिल्ली और पूरा राजस्थान तक के इलाके की प्यास बुझ रही है तो इसका पूरा श्रेय भी चौधरी छोटू राम जी को ही जाता है जिन्होंने राजा बिलासपुर के साथ एक समझौता करवाकर के भाखड़ा–नंगल डैम के लिए ज़मीन एक्वॉयर करवाई थी। अध्यक्ष जी, चौधरी छोटू राम जी ने समस्त हरियाणा प्रदेश के लिए एक मसीहा बनने का काम किया इसीलिए इस स्वर्ण जयंती वर्ष में हरियाणा प्रदेश के अढाई करोड़ लोग आज उस महान आत्मा व महान शख्सियत को हमेशा–हमेशा के लिए याद करें इसी के लिए हमने अपनी ग्रामीण विकास की नई स्कीम का नाम उनके नाम पर रखने का निर्णय किया।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि इन्होंने अपने पिछले बजट में हरियाणा प्रदेश में अनेकों योजनायें शुरू करने की घोषणा की थी लेकिन उनमें से अधिकतर योजनाओं पर

अभी तक कोई काम शुरू नहीं हो पाया है। उनके बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने न तो कोई चर्चा की है और न ही कुछ बताया है। क्या वित्त मंत्री जी इस बारे में भी स्थिति स्पष्ट करने की कृपा करेंगे?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, वे बहुत सारी बातें हैं अगर मैं उन सभी का जवाब यहां पर देने लगूंगा तो उसमें बहुत समय लग जायेगा लेकिन मैं फिर भी बताने के लिए तैयार हूं, मैं जवाब देना चाहता हूं, मेरे पास आंकड़े हैं और मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं । मैं आंकड़ों के साथ पूरा जवाब देने के लिए तैयार हूं लेकिन हमारे कांग्रेस के साथी नहीं चाहते कि सी.एल.पी. लीडर साहिबा के प्रश्नों का मैं जवाब दूं । मैं जवाब देना चाहता हूं लेकिन ये जवाब सुनना नहीं चाहते । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल माननीय वित्त मंत्री जी से पूछे थे उनके बारे में मंत्री जी ने कुछ नहीं बताया है । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं लेकिन ये सुनना नहीं चाहते हैं। इनको हरियाणा की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुये मेरा जवाब सुनना चाहिए । मेरी कांग्रेस के साथियों से प्रार्थना है कि ये सदन को छोड़ कर न जायें बल्कि अपने सारे सवालों का जवाब सुनें । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवालों का जवाब नहीं आया है । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं इनके सवालों का जवाब दे रहा हूं । किरण जी इतनी सीनियर लैजिस्लेटर हैं इनको मालूम होना चाहिए कि यह बजट के प्रस्तावों पर जवाब है, यह कोई प्रश्नकाल या शून्यकाल नहीं है । यह कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब नहीं है । यह बजट के प्रावधानों पर जवाब है, यह बजट के प्रस्तावों पर जवाब है, मैं एक–एक बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं ।

Dr. Raghuvir Singh Kadian : Hon'ble Speaker Sir, it is only the jugglery of statistics. (Interruption)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं डॉ. कादियान से कहना चाहता हूं कि–

दरिया हैं हम, हमें अपना हुनर मालूम है,

गुजरेंगे जिधर से, रास्ता बन जायेगा ।

मैं एक–एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं । स्वर्गीय डॉ. मंगलसैन जी के नाम पर हमने "मंगल नगर विकास योजना" प्रारम्भ की है । हरियाणा ही नहीं हिन्दुस्तान के इतिहास में इतनी बड़ी योजना कभी शुरू नहीं हुई होगी । डॉ. मंगलसैन जी एक महान राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, वे भारतीय संस्कृति के सजग प्रहरी थे। वे हरियाणा के निर्माता थे, हरियाणा को बनाने के लिए हिन्दी आंदोलन में वे जेल में भी गये थे । उन्होंने गौहत्या को बंद करने के लिए भी आंदोलन किया था। कश्मीर के मुद्दे से लेकर हरियाणा के अनेक हितों के लिए उन्होंने आंदोलन किये थे और वे 15 बार जेल गये थे। इमरजेंसी को मिला कर उन्होंने अपनी जिन्दगी के कुल 6 साल जेल में काटे हैं । उनको शेर–ए–हरियाणा कहा जाता है। आज उनको स्मरण करते हुये हमने "मंगल नगर विकास योजना" शुरू की है। मैं हरियाणा की अढ़ाई करोड़ जनता को इस "मंगल नगर विकास योजना" को समर्पित करता हूं और इसमें आप सबका साथ मांगता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवालों के जवाब माननीय मंत्री जी नहीं दे रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से श्री जगबीर मलिक जी ने पुलिस के बजट पर चिन्ता जाहिर की थी मैं उनका जवाब देना चाहता हूं । मैं उनको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2015–16 में पुलिस का बजट 2736 करोड़, 2016–17 में 3372 करोड़ और वर्ष 2017–18 में 3838 करोड़ रुपये किया गया है । इसी प्रकार से आदरणीय सी.एल.पी. लीडर साहिबा श्रीमती किरण चौधरी जी ने कहा था कि पी.पी.पी. का क्या हुआ मैं उनको बताना चाहता हूं कि पी.पी.पी. के तहत 10 ट्रांजैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति हो चुकी है । पी.पी.पी. मॉडल पर सीटी स्कैन, एम.आर.आई. तथा सड़कों का निर्माण तक होना शुरू हो गया है तथा पी.पी.पी. मॉडल आगे बढ़ रहा है । मैं श्रीमती किरण चौधरी के लिए कहना चाहता हूं कि–

तू इधर–उधर की बात न कर,

बता ये कारवां क्यों लुटा ?

आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय हमारी बड़ी बहन जी ने वह सवाल उठाया था । अगर वह बैठें तो मैं जवाब दे दूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह हम नहीं कह रहें हैं । यह तो आपकी पार्टी के ही विधायक कह रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय सी.एल.पी. लीडर ने जो सवाल किया था । अगर ये बैठें तो मैं जवाब दे दूं ।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, क्या आप अपनी पार्टी के खिलाफ है ? आप अपनी पार्टी के साथ नहीं हैं क्या ?

श्रीमती शकुन्तला खटक : अध्यक्ष महोदय, इस बात पर मुझे भी एक बात याद आ गई कि एक गांव के अन्दर एक शादी थी जिसमें गांव में एक–एक आदमी का निमंत्रण तो देते ही हैं । निमंत्रण दे दिया और निमंत्रण देने के बाद जैसे पहले नीचे बैठाकर पत्तल पर खाना खिलाया करते थे । जब वह खाना डालने लगे तो चावल डाल दिये, दाल डाल दी और दो लड्डू रख दिये । सबको ऐसे ही डालते चले गये। एक मेरे जैसा उत था वह उसकी बाजू पकड़कर कहने लगा कि अरे खाना खिलावे है कि रूवावे है । सरकार चला रहे हो कि रो रहे हो । (हंसी)

वाक–आउट

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी हमारे द्वारा उठाए गए प्वायंट्स का जवाब नहीं दे रहे हैं इसलिए हम इसके विरोध में सदन से वाक आउट करते हैं ।

(इस समय सदन में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य वित मंत्री द्वारा बजट के संबंध में उनके कुछ प्वायंटों का जवाब न देने के विरोध में वाक आउट कर गये।)

वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा एवं वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भ)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने बजट के प्रावधानों के माध्यम से, इस बजट के प्रस्तावों के माध्यम से और हमने दो साल में सभी पक्ष और विपक्ष के साथ मिलकर जो सीखा है क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखाने वाले के संबंध में भी यह नहीं होता कि हमने केवल इसी से सीखना है इसलिये हम तो सभी से सीख रहे हैं और सिख कर के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पूरी कैबिनेट की तरफ से और हरियाणा सरकार की तरफ से बजट के प्रस्ताव विधान सभा के पटल पर रखे हैं । हमने यह बजट प्रस्ताव हरियाणा के ढाई करोड़ जनता के हित में रखे हैं ।

आज का हरियाणा यह स्वर्ण जयंती वर्ष इस संकल्प के साथ मना रहा है कि हम भविष्य के उस हरियाणा का निर्माण करें जिस हरियाणा की तुलना हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों से न होकर के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रों से हो । उस उद्देश्य से आज हमने ये बजट के प्रस्ताव रखे हैं । सभी माननीय विधायकों ने पक्ष और विपक्ष में कितनी ही प्रकार की नोंक झोंक हुई होंगी, ऊंच–नीच कही होंगी । मेरी तरफ से अगर कोई गलती हुई हो तो मैं उसकी माफी मांगते हुए सभी विधायकों का आभार और अभिनन्दन करता हूं और सबसे निवेदन करत हूं कि इस बजट को पास कराने में हमारा साथ दें, हमारा सहयोग दें । इस बजट के स्वप्नों को साकार कराने में हमारा साथ और सहयोग दें । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

वर्ष 2017–2018 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2017–18 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान होगा ।

पिछली प्रथानुसार और सदन का समय बचाने के लिये आर्डर पेपर पर रखी गई (डिमांड्ज नं0 1 से 45) एक साथ पढ़ी तथा पेश की गई समझी जायें । माननीय सदस्यगण किसी भी डिमांड्ज पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन बोलने से पहले वे अपनी डिमांड्ज का नं0 बता दें, जिस पर वे बोलना चाहते हैं ।

कि राजस्व खर्च के लिए **72,05,00,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 1–विधान सभा** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **130,07,00,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 2–राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **275,99,69,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 3–सामान्य प्रशासन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **1189,31,03,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 4–राजस्व** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **245,26,45,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 5–आबकारी व कराधान** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **6679,34,48,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 6– वित्त** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **40,16,72,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **415,00,00,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 7–आयोजना तथा सांख्यिकी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **1397,04,50,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **3484,30,50,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 8–भवन तथा सडकें** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **13414,09,35,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **100,00,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 9–शिक्षा** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **437,84,00,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 10–तकनीकी शिक्षा** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **456,84,20,000** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **50,00,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि, राज्यपाल महोदय को उन खर्चों

को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं.11—खेलकूद तथा युवा कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017—2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **15,48,04,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 12—कला एवं संस्कृति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017—2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **3399,42,87,000** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **516,60,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 13—स्वास्थ्य** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017—2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **103,94,35,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **1000,00,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 14—नगर विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017—2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **3869,63,50,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 15—स्थानीय शासन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017—2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **50,84,95,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **2,00,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 16—श्रम** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017—2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **78,78,80,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 17—रोजगार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017—2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **351,54,18,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **38,86,17,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 18—औद्योगिक प्रशिक्षण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017—2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **709,97,10,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **14,98,02,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 19–अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **4864,49,75,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **12,92,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 20–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **1074,84,10,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **172,41,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 21–महिला एवं बाल विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **122,94,42,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 22–भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **577,48,18,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **9846,51,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 23–खाद्य एवं पूर्ति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **1910,15,66,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **764,17,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 24–सिंचाई** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **363,55,91,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **10,01,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 25–उद्योग** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **55,90,00,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल

महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 26–खान एवं भू–विज्ञान** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **1927,32,00,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 27–कृषि** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **731,71,65,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **15,00,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 28–पशुपालन एवं डेरी विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **87,92,09,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 29–मछली पालन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **456,11,80,000** रूपये से अनधिक धनराशि, राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 30–वन एवं वन्यप्राणी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **8,69,90,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 31–परिस्थिति विज्ञान एवं पर्यावरण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **4166,64,45,750** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **1200,00,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 32–ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **226,21,85,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **128,71,50,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों

को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 33–सहकारिता** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **2284,47,15,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **272,35,50,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 34–परिवहन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **4,54,10,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **67,20,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 35–पर्यटन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **3866,06,36,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **255,00,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 36–गृह** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **49,47,05,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 37–निर्वाचन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **1941,66,00,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **1443,18,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 38–लोक स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **163,54,00,000** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **40,00,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि, राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 39–सूचना तथा प्रचार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **10254,00,20,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **1605,34,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 40–ऊर्जा तथा विद्युत** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **125,56,70,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 41–इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **548,52,99,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 42–न्याय प्रशासन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **233,31,10,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 43–कारागार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **40,11,03,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **5,75,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 44–मुद्रण एवं लेखन सामग्री** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि पूंजीगत खर्च के लिए **1326,06,60,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 45–राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

(कोई भी सदस्य बोलने के लिये खड़ा नहीं हुआ)

श्री अध्यक्ष : अब विभिन्न डिमांड्ज सदन में मतदान के लिये रखी जाती हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है :–

कि राजस्व खर्च के लिए **72,05,00,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 1–विधान सभा** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **130,07,00,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 2–राज्यपाल तथा**

मंत्रीपरिषद के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **275,99,69,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 3–सामान्य प्रशासन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **1189,31,03,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 4–राजस्व** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **245,26,45,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 5–आबकारी व कराधान** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **6679,34,48,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 6– वित्त** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **40,16,72,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **415,00,00,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 7–आयोजना तथा सांख्यिकी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **1397,04,50,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **3484,30,50,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 8–भवन तथा सडकें** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **13414,09,35,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **100,00,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 9–शिक्षा** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **437,84,00,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 10–तकनीकी शिक्षा** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **456,84,20,000** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **50,00,00,000**

रूपये से अनधिक धनराशि, राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं.11—खेलकूद तथा युवा कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017—2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **15,48,04,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 12—कला एवं संस्कृति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017—2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **3399,42,87,000** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **516,60,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 13—स्वास्थ्य** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017—2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **103,94,35,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **1000,00,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 14—नगर विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017—2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

3

कि राजस्व खर्च के लिए **3869,63,50,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 15—स्थानीय शासन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017—2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **50,84,95,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **2,00,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 16—श्रम** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017—2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **78,78,80,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 17—रोजगार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017—2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **351,54,18,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **38,86,17,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 18—औद्योगिक प्रशिक्षण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017—2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **709,97,10,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **14,98,02,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की

जाए जो **मांग सं. 19–अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **4864,49,75,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **12,92,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 20–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **1074,84,10,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **172,41,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 21–महिला एवं बाल विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **122,94,42,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 22–भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **577,48,18,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **9846,51,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 23–खाद्य एवं पूर्ति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **1910,15,66,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **764,17,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 24–सिंचाई** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **363,55,91,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **10,01,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 25–उद्योग** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **55,90,00,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 26–खान एवं भू–विज्ञान** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **1927,32,00,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 27–कृषि** के अधीन

व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **731,71,65,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **15,00,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 28–पशुपालन एवं डेरी विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **87,92,09,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 29–मछली पालन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **456,11,80,000** रूपये से अनधिक धनराशि, राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 30–वन एवं वन्यप्राणी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **8,69,90,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 31–परिस्थिति विज्ञान एवं पर्यावरण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **4166,64,45,750** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **1200,00,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 32–ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **226,21,85,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **128,71,50,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 33–सहकारिता** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **2284,47,15,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **272,35,50,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 34–परिवहन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **4,54,10,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **67,20,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 35–पर्यटन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **3866,06,36,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **255,00,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 36–गृह** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **49,47,05,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 37–निर्वाचन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **1941,66,00,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **1443,18,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 38–लोक स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **163,54,00,000** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **40,00,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि, राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 39–सूचना तथा प्रचार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **10254,00,20,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **1605,34,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 40–ऊर्जा तथा विद्युत** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **125,56,70,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 41–इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **548,52,99,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 42–न्याय प्रशासन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **233,31,10,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 43–कारागार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **40,11,03,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **5,75,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 44–मुद्रण एवं लेखन सामग्री** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष

2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि पूंजीगत खर्च के लिए **1326,06,60,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 45–राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2017–2018 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2017 प्रातः 10:00 बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है ।

***17:27 बजे**

(तत्पश्चात् सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2017 प्रातः 10:00 बजे तक के लिये *स्थगित हुई ।)